रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 1979/भाद्रपद 10, 1901
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 1979/BHADRA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1979

का० आ० 2871—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार-विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 252-गुरुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पंडित सिंह, ग्राम परैया खुर्द, पो० परैया, जिला गया, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पंडित सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/252/77(72)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 3rd July, 1979

S.O. 2871.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pandit Singh, Village Paraiya Khurd, P.O. Paraiya, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general Election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 252-Gurua connstituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pandit Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/252/77(72)]

का० आ० 2872—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 256-अतरी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार

श्री नागेन्द्र सिंह, ग्राम एवं पो० जठियन, थाना अतरी, जिला गया, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नागेन्द्र सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/256/77(73)]

S.O. 2872.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nagendra Singh, Village and P.O. Jethian, Thana Atri, District Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 256-Atri constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nagendra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/256/77(73)]

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1979

का० आ० 2873.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-बेलगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कामता सिंह, ग्राम एवं पोस्ट डेमा फतेहपुर, थाना खिजरसराय, जिला गया, बिहार-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कामता सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/247/77(74)]

New Delhi, the 4th July, 1979

S.O. 2873.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamta Singh, Village and P.O. Dema Fatehpur, Thana Khiparsarai, District Gaya Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 247-Belaganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kamta Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/247/77(74)]

का० आ० 2874.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-बेलागंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कौशल किशोर शर्मा, ग्राम एवं पो० कोरमूथ, थाना बेलागंज, जिला गया, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कौशल किशोर शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/247/77(75)]

S.O. 2874.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kaushal Kishore Sharma, Village and P.O. Koramthu, Thana Belaganj, District Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 247-Belaganj Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kaushal Kishore Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council or a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/247/77(75)]

का० आ० 2875.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 247-बेलागंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नथुनप्रसाद सिंह, ग्राम चिरैला टोला रामबालक बिगहा, डाकघर बेलहाडी, थाना बेलागंज, जिला गया, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नथुन प्रसाद सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/247/77(76)]

S.O. 2875.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nathun Prasad Singh, Village Chiraila Tola-Rambalak Bigaha, P.O. Bailhari, Thana Belaganj, District Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 247-Belaganj constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all|as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nathu Prasad Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/247/77(76)]

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1979

का० आ० 2876—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 196-नालन्दा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अयोध्या प्रसाद, ग्राम बारा, पोस्ट करजारा, जिला नालन्दा, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अयोध्या प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/196/77(83)]

New Delhi, the 10th July, 1978

S.O. 2876.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ayodhya Prasad, Village Bara, P.O. Karjara, District Nalanda, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 196-Nalanda constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all|as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ayodhya Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/196/77(83)]

का० आ० 2877—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 163-गोड्डा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री साहेबराम मरंडी, ग्राम नयावाद, पत्रालय मोतीया, जिला संथाल परगना, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री साहेबराम मरंडी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/163/77(92)]

S.O. 2877.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Saheb Ram Marandi, Village Nayawad, P.O. Motiya, District Santhal Parganas, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 163-Godha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all|as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Saheb Ram Marandi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/163/77(92)]

का० आ० 2878—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 198-हिलसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लखन सिंह, ग्राम हसनपुर, पोस्ट कोरामा, जिला नालन्दा, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लखन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० सं०/198/77 (93)]

S.O 2878.—Whereas the Election Coommission is satisfied that Shri Lakhan Singh, Village Hasanpur, P.O. Korama, District Nalanda, Bihar, a cortesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977

from 198-Hilsa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lakhan Singh to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/198/77(93)]

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1979

का० आ० 2879.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 244-मखदुमपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उदय नारायण सिंह, ग्राम असिआवां पो० पिंजौरा, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उदय नारायण सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/244/77(84)]

New Delhi, the 11th July, 1979

S.O. 2879.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Udaya Narain Singh, Village Asiawan, P.O. Pinjoura, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 244-Makhdumpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Udaya Narain Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/244/77(84)]

का० आ० 2880.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 244-मखदुमपुर, निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री धर्मनारायण शर्मा, ग्राम पलेया, पो० मखदुमपुर, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है, ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री धर्मनारायण शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/244/77(85)]

S.O. 2880.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dharam Narain Sharma, Village Paleya, P.O. Makhdumpur, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 244-Makhdumpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/ as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dharam Narain Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/244/77(85)]

का० आ० 2881—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 197-इसलामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ठाकुर ओंकार सिंह ग्राम एवं पो० कोविल, जिला नालन्दा बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए /गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लि कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ?

अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ठाकुर ओंकार सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/197/77(86)]

S.O. 2881.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Thakur Onkar Singh, Village and P.O. Kovil, District Nalanda, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 199-Islampur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said

Shri Thakur Onkar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-I A/197/77(86)]

का० आ० 2882.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 197 इस्लामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामकेश्वर सिंह, ग्राम पो० एकंगरसराय, जिला नालन्दा, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामकेश्वर सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स० 197/77(87)]

S.O. 2882.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Keshwar Singh, Village-Post Ekangersarai, District Nalanda, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 197-Islampur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Keshwar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/197/77(87)]

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 1979

का० आ० 2883.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 199-चंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पारसनाथ प्रसाद, ग्राम कैथिर, पो० सोराडीह, जिला नालन्दा, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पारसनाथ प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/199/77(88)]

New Delhi, the 12th July, 1979

S.O. 2883.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Paras Nath Prasad, Village Kaithir, P.O. Soradeeh, District Nalanda, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 199-Chandi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Paras Nath Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/199/77(88)]

का० आ० 2884.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 199-चंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पुनेश्वर प्रसाद सिंह, राजापुर, पटना-1, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पुनेश्वर प्रसाद सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/199/77 (89)]

S.O. 2884.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Puneshwar Prasad Singh, Rajapur, Patna-1, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 199-Chandi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Puneshwar Prasad Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[BR-LA/199/77(89)]

का० आ० 2885.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 199-चंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामेश्वर चौहान, विष्णुपुर टोला बेलदारी, डाकखाना, हरनाव, जिला नालन्दा, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामईश्वर चौहान को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/199/77 (90)]

S.O. 2885—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Ishwar Chauhan, Vishnupur Tola Beldari, P.O. Hargaonwa, District, Nalanda Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 199-Chandi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Ishwar Chauhan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/199/77(90)]

का० आ० 2886—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 199-चंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती शकुन्तला देवी माथुर, पटना सिटी, ग्रीन फार्मेसी, पटना सिटी अस्पताल, पटना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती शकुन्तला देवी माथुर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/199/77(91)]

S.O. 2886.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Shakuntla Devi Mathur, Patna City, Green Pharmacy, Patna City Hospital, Patna, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June,, 1977 from 199-Chandi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Shakuntla Devi Mathur to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/199/77(91)]

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1979

का०आ० 2887—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 283–निरसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमीरजीत सिंह कपूर, तालडागा कालोनी, सरसापहाड़ी, पो० चिरकण्डा, जिला धनबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमीरजीत सिंह कपूर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि० स०/283/77(94)]

New Delhi, the 13th July, 1979

S O. 2887.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amirjeet Singh Kapoor, Taldaga Colony, Sarsapahari, P.O. Chirkunda District Dhanbad, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 283-Nirsa constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amirjeet Singh Kapoor to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA(283/77(94)]

का०आ० 2888—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 283–निरसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेश तिवारी, कवम कुआं, पटना-1, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेश तिवारी को संसद् के किसी भी सदन

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि० स०/283/77/(95)]

S.O. 2888.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahesh Tiwari, Kadam Kaun, Patna-1, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 283-Nirsa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/ as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahesh Tiwari to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/283/77(95)]

का०आ० 2889.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 283–निरसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मु० अमीरुला, गोपीनाथपुर, पो० मोगमा, थाना निरसा, जिला धनबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मु० अमीरुला को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि० स०/283/77(96)]

S.O. 2889.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri M. Amirrula, Gopinathpur, P.O. Mogma, Thana Nirsa, District Dhanbad, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 283-Nirsa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri M. Amirula to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/283/77(96)]

का०आ० 2890.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 283–निरसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अमलापाड़ा झरिया, पोस्ट झरिया, जिला धनबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्याम सुन्दर शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि० स०/283/77(97)]

S.O. 2890.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shyam Sunder Sharma, Amlapara, Jharia, P.O. Jharai, District Dhanbad, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 283-Nirsa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shyam Sundar Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/283/77(97)]

का०आ० 2891.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 283–निरसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के० सी० प्रसाद, कुमारडुवी, पोस्ट कुमारडुवी, थाना चिरकुण्डा, जिला धनबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के० सी० प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि० स०/283/77(98)]

S.O. 2891.—Whereas the Election Commission is satisfied thtat Shri K. C. Prasad, Kumarduwi, Thana Cherkunda, District Dhanbad, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 283-Nirsa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri K. C. Prasad to be disqualified for being chosen as,

and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/283/77(98)]

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1979

का०आ० 2892.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 65—बेलसण्ड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवशंकर सिंह, ग्राम भौड़ीहा, पोस्ट औरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिवशंकर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/65/77(99)]

New Delhi, the 16th July, 1979

S.O. 2892.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shiv Shankar Singh, Village Bhaudiha, P.O. Aura, District Sitamarhi, Bihar, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 65-Belsand constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Shankar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three yars from the date of this order.

[No. BR-LA/65/77(99)]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1979

का०आ० 2893.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 71—सुरसण्ड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामपवित्र तिवारी, ग्राम पोस्ट राधाउर, थाना सुरसण्ड, जिला सीतामढ़ी, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामपवित्र तिवारी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

सं० बिहार-वि० स०/71/77(100)]

New Delhi, the 18th July, 1979

S.O. 2893.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Pavitra Tiwari, Village-Post Radhaur, Thana Sursand, District Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 71-Sursand constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Pavitra Tiwari to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/71/77(100)]

का०आ० 2894.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 71—सुरसण्ड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामस्वार्थ पासवान, ग्राम पो० सुरसण्ड, जिला सीतामढ़ी, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामस्वार्थ पासवान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/71/77(101)]

S.O. 2894.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Swarth Paswan, Village Post Sursand, District Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 71-Sursand constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Swarth Paswan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/71/77(101)]

का०आ० 2895.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 82—काकडाहा सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अर्धेन्दु गुप्ता, पी०—7/242 कल्याणी, डाक० कल्याणी, जिला नदिया, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अर्धेन्दु गुप्ता को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० प० बं०-वि० स०/82/77]

S.O. 2895.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ardhendu Gupta, P-7/242 Kalyani P.O. Kalyani, District Nadia, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 82-Chakdah assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas thesaid candidate, even after the notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ardhendu Gupta, to be disqualified far being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/82/77]

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1979

का०आ० 2896—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 187—सूरजगढ़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्रवण कुमार अग्रवाल, ग्राम व पोस्ट सूरजगढ़ा, जिला मुंगेर, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्रवण कुमार अग्रवाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/187/77(102)]

New Delhi, the 19th July, 1979

S.O. 2896.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shrawan Kumar Agarwal, Village and P.O. Surajgarha, District Monghyr, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 187-Surajgarha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shrawan Kumar Agrawal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/187/77(102)]

का०आ० 2897.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 187—सूरजगढ़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुबोध महतो, ग्राम लगमा, पोस्ट शिवकुण्ड, थाना मुफस्सिल मुंगेर, जिला मुंगेर, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुबोध महतो को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/187/77(103)]

S.O. 2897.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Subodh Mahto, Village Lagma, P.O. Shibkund, Thana Muffasil Monghyr, District Monghyr, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 187-Surajgarha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Subodh Mahto to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/187/77(103)]

का०आ० 2898—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 60—डोमकल सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नगेन्द्र नाथ कुण्डु, ग्राम रमना एटाबार नगर, डाक० डोमकल, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नगेन्द्र नाथ कुण्डू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० प० ब०-वि० स०/60/77]

S.O. 2898.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nagendra Nath Kundu, Village Ramna Etabarnagar, P.O. Domkal, District Murshidabad, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 60-Domkal assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nagendra Nath Kundu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a Period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/60/77]

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1979

का०आ० 2899—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 324-हुसेनाबाद निर्वाचन-क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री युगेश्वर महतो, ग्राम डाबकला, पो० बभण्डीह, जिला पलामू, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री युगेश्वर महतो को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/324/77(104)]

New Delhi, the 20th July, 1979

S.O. 2899.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Yugeshar Mahto, Village Dhabkala, P.O. Babhandih, District Palamau, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 324-Hussainabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Yugeshar Mahto to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years fim the date of this order.

[No. BR-LA/324/77(104)]

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1979

का०आ० 2900—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 10-पीलीबंगा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मनोहर लाल कसवा पुत्र उमाराम, सा० 34-एस०टी०जी०, तहसील सूरतगढ़, राजस्थान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मनोहर लाल कसवा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०-वि० स०/10/77(31)]

New Delhi, the 21st July, 1979

S.O. 2900.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manohar Lal Kaswa S/o Shri Uma Ram R/o 34-S.T.G., Tehsil Suratgarh, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 10-Pilibanga constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manohar Lal Kaswa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/10/77(31)]

का०आ० 2901.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 10-पीलीबंगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री साजन, पुत्र श्री पूरबीराम, सा० 34-एस०टी०जी०, तहसील सूरतगढ़, राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री साजन को संसद के किसी भी सदन के या

किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०-वि० स०/10/77(32)]

S.O. 2901.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sajan S/o Shri Purvi Ram, R/o 32-S.T.G., Tehsil Suratgarh, Rajasthan, a contesting candidate for general election to the Rajasthan, egislative Assembly held in June,, 1977 from 10-Pilibanga constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sajan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/10/77(32)]

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1979

का०आ० 2902.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 179—तारापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम बैजलपुर, पोस्ट अमैया, जिला मुंगेर, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ओम प्रकाश सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/179/77/(109)]

New Delhi, the 23rd July, 1979

S.O. 2902.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Om Prakash Singh, Village Baijalpur, P.O. Amaiya, District Monghyr, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 179-Tarapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the people Act, 1951, and th Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Om Prakash Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Coucil of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/179/77(109)]

का० आ० 2903 – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 179-तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बद्रीयादव, ग्राम पड़भरा, पोस्ट भगलपुरा देवगांव, जिला मुंगेर, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए पर्याप्त कारण का न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बद्रीयादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/179/77/(110)]

S.O. 2903.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Badri Yadav, Village Parbhara, P.O. Bhagalpura, Deogaon, District Monghyr, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 179-Tarapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Badri Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/179/77(110)]

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1979

का० आ० 2904.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-कुडलिगी सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अक्की रुद्रप्पा, थामलेराहल्ली, तालुक हागारीबोमनाहल्ली, जिला बेल्लारी (कर्नाटक), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अक्की रुद्रप्पा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० कर्ना०-वि० स०/36/78(7)]

New Delhi, the 24th July, 1979

S.O. 2904.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Akki Rudrappa, Thamabrahalli, Haga-ribomanahalli Taluk, Bellary District (Karnataka), a contesting candidate

for general election to the Karnataka Legislative Assembly held in February, 78 from 36-Kudligi asasembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justificaon for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Akki Rudrappa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-I A/36/78(7)]

का० आ० 2905.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-कुडलिगी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० कोटरप्पा, हागारीबोमनाहल्ली, जिला बैल्लारी (कर्नाटक), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० कोटरप्पा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[कर्ना०-वि० स०/36/78(8)]

S.O. 2905.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. Kotrappa, Hagribommanahalli, Bellary District (Karnataka), a contesting candidate for general election to the Karnataka Legislative Assembly held in February, 78 from 36-Kudligi assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. Kotrappa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-LA/36/78(8)]

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1979

का० आ० 2906.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1979 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 66-गौवरीबिदनुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के० एल० रमैय्याह, इलैक्ट्रिक कालोनी के समीप, गौवरीबिदनुर, जिला कोलार (कर्नाटक), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के० एल० रमैय्याह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[स० कर्ना०-वि० स०/64/78(10)]

New Delhi, the 25th July, 1979

S.O. 2906.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. L. Ramaiah, Near Electric Colony, Gauribidanur, District Kolar (Karnataka), a contesting candidate for general election to the Karnataka Legislative Assembly held in February, 78 from 64-Gowribidanur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri K. L. Ramaiah to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-LA/64/78(10)]

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1979

का० आ० 2907.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 5-चौपाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मंगल सिंह, ग्राम बागी (चड़ौल), डाकघर चीमा (चड़ौल), तहसील चौपाल, हिमाचल प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मंगल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० हि० प्र०-वि० स०/5/77(4)]

New Delhi, the 26th July, 1979

S.O. 2907.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mangal Singh, village Bagi (Charoli), P.O. Chima, (Charoli) Teh. Chopal (Himachal Pradesh) a contesting candidate for general election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly held in 1977 from 5-Chopal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the

Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mangal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HP-LA/5/77/(4)]

का० आ० 2908—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 13-आदापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रणजीत सिंह, ग्राम पोस्ट दरपा, थाना छोड़ादानो, जिला पूर्व चम्पारण, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रणजीत सिह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/13/77/(111)]

S.O. 2908.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ranjeet Singh, Village and Post Darpa, Thana Chhoradano, District East Champaran, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 13-Adapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ranjeet Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/13/77(111)]

का० आ० 2909.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 13-आदापुर निर्वाचन-क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लक्ष्मीकान्त प्रसाद, ग्राम झिटकहिया, पो० आ० टिकुलिया, थाना छोड़ादानों, जिला पूर्व चम्पारण, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लक्ष्मीकान्त प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/13/77(112)]

S.O. 2909.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Laxmi Kant Prasad, Village Jhitkatiya, P.O. Tikulia, via Chhoradano, District East Champaran, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 13-Adapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Laxmi Kant Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/13/77(112)]

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1979

का० आ० 2910.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है, कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 131-सिकटी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गयासुद्दीन अहमद, ग्राम झाला, पोस्ट थिरानीगंज, जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई श्री लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गयासुद्दीन अहमद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/131/77(113)]

New Delhi, the 27th July, 1979

S.O. 2910.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gayasuddin Ahmad, Village Jhala, P.O. Thirani ganj, District Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 131-Sikti constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gayasuddin Ahmad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/131/77(113

का०आ० 2911.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 131–सिकटी निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बेचन अली, ग्राम पड़रिया, पोस्ट पड़रिया, जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यत, उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बेचन अली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार–वि०स०/131/77(114)]

S.O. 2911.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bechan Ali, Village Pararia, P.O. Pararia District Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 131-Sikti constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bechan Ali to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/131/77(114)]

का०आ० 2912.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 131–सिकटी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्याम सुन्दर विश्वास, ग्राम पोढिया, पोस्ट मैनाहट, जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्याम सुन्दर विश्वास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/131/77(115)]

S.O. 2912.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shyam Sundar Biswas, Village Podhiya, P.O. Mainahat, District Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 131-Sikti constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shyam Sundar Biswas to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No BR-LA/131/77(115)]

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1979

का०आ० 2913.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 275-इलाहाबाद उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम चन्द्र मालवीय, 264 अतरसुईया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10–क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम चन्द्र मालवीय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०–वि०स०/275/77(34)]

New Delhi, the 31st July, 1979

S.O. 2913.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramchandra Malaviya, 264-Atarsuiya, Allahabad, Uttar Pradesh a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assesmbly held in June, 1977 from 275-Allahabad North constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramchandra Malviya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/275(34)]

का०आ० 2914.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, के लिए 275-इलाहाबाद उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम नारायण लाल, 74–फतेहपुर बिछवा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम नारायण लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०सं०/275/77(35)]

S.O. 2914.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Narain Lal, 74, Fatehpur Bichwa, Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 275-Allahabad North constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Narain Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/275/77(35)]

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1979

का०आ० 2915.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 306-भरथना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोरे लाल यादव, ग्राम रामपुर, पोस्ट बरौनाकलां, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त गोरे लाल यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/306/77(32)]

New Delhi, the 3rd August, 1979

S.O. 2915.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gore Lal Yadav, Village Rampur, Post Baraunakalan, District Etawa Uttar Pradesh a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 306-Bharthana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gore Lal Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/306/77(32)]

का०आ० 2916.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 306-भरथना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री यदुनाथ सिंह, ग्राम दासीपुर, पोस्ट बाहरपुर, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री यदुनाथ सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/306/77(33)]

S.O. 2916.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Yadu Nath Singh, village Dasipur, Post Baharpur, District Etawa, Uttar Pradesh a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 306-Bharthana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Yadu Nath Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/306/77(33)]

का०आ० 2917.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 172-भीनमाल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री खिमे खां, ग्राम बारलावास, पोस्ट सियाणा, तहसील जालोर, राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री खिमे खां को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०-वि०स०/172/77(33)]

S.O. 2917.—Whereas the Election Commision is satisfied that Shri Khime Khan, Village Barlawas, Post Siyana, Tehsil Jalore, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 172-Bhinmal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Khime Khan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/172/77(33)]

का०आ० 2918.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार-विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 261–हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भागवत सिंह, ग्राम गारो बिगहा पो० धनवां, जिला नवादा, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भागवत सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/261/77(119)]

S.O. 2918.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagwat Singh, Village Garo Bigaha, P.O. Dhanwan, District Nawada, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 261-Hisua constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagwat Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/261/77(119)]

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1979

का० आ० 2919.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 138-रुदौली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अकबर, अली ग्राम व पोस्ट मवई, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अकबर अली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य तथा विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/138/77(36)]

New Delhi, the 4th August, 1979

S.O. 2919.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Akbar Ali, vilage and Post Mawai, Bara Banki (Uttar Pradesh) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 138-Raudauli constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Akbar Ali to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/138/77(36)]

का० आ० 2920.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 138-रुदौली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चौधरी मोहम्मद सईद, मौहल्ला सालार, कस्बा सपौली, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चौधरी मोहम्मद सईद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/138/77(37)]

S.O. 2920.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Choudhary Mohammad Sayead, Mohalla Salar, Town Rudauli, Bara Banki (Uttar Pradesh) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 138-Rudauli constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder.

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Choudhary Mohammad Sayead to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/138/77(37)]

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1979

का० आ० 2921.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए बिहार में लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 39-बिक्रमगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डे, ग्राम- पो० मरार, थाना रामगढ़, जिला हजारी बाग, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उसका पता मालूम न होने के कारण उनकी असफलता के लिए कारण अथवा स्पष्टीकरण की सूचना अवितरित वापिस आ गई है

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-लो० स०/39/77(12)]

New Delhi, the 6th August, 1979

S.O. 2921.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Birendra Kumar Pandey, Village and P.O. Marar, P.S. Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar), a contesting candidate for general election to the House of the People held in Bihar in March, 1977 from 39-Bikramganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the notice to show reason or explanation for the failure has been received back undelivered as his whereabouts are unknown ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Birendra Kumar Pandey to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/39/77(12)]

का० आ० 2922.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए बिहार में लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 49-रांची निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डे, ग्राम और डाकखाना मरार थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, उसका पता मालूम न होने के कारण उनकी असफलता के लिए कारण अथवा स्पष्टीकरण की सूचना अवितरित वापिस आ गई है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-लो० स०/49/77(13)]

S.O. 2922.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Birendra Kumar Pandey, Village and P. O. Marar, P. S. Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar), a contesting candidate for general election to the House of the People held in Bihar in March, 1977 from 49-Ranchi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the notice to show reason or explanation for the failure has been received back undelivered as his where abouts are unknown ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Birendra Kumar Pandey to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/49/77(13)]

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1979

का० आ० 2923.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 411-कैराना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जय प्रकाश गोयल, कस्बा कैराना, पट्टोवाली गली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जय प्रकाश गोयल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०411/77(38)/]

New Delhi, the 8th August, 1979

S.O. 2923.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jai Prakash Goyal, Kasba Kairana, Pattowali Gali, Muzaffarnagar district, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 411-Kairana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jai Prakash Goyal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative

Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/411/77(38)]

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979

का० आ० 2924.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 82-मुजफ्फरनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्याम सिंह, ग्राम सिकन्दरपुर खुर्द, पोस्ट खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री श्याम सिंह को संसद के किसी सभी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० लो० स०/82/77(2)]

New Delhi, the 10th August, 1979

S.O. 2924.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shyam Singh, village Sikandarpur Khurd, Post Khatauli, District Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the House of the People held in March, 1977 from 82-Muzaffarnagar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shyam Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/82/77(2)]

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

का० आ० 2925.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 48-आंवला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उमराव प्रसाद गाटिया, किशनपुर, डा० रेवती आंवला, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उमराव प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/48/77(39)]

New Delhi, the 16th August, 1979

S.O. 2925. Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Umrai Prasad, Gamtiya Kishanpuru, P.O. Reoti, Aonla, Bareily (Uttar Pradesh), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 48-Aonla constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Umrai Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/48/77(39)]

का० आ० 2926.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 391-हापुड़ (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चरण सिंह, मोहल्ला सादकपुरा, हापुड़, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चरण सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/391/77(40)]

S.O. 2926.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Charan Singh, Moholla Sadakpura, Hapur, Disrtict Ghaziabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 391-Hapur (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Charan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/391/77(40)]

का०आ० 2927.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 29-महजोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाल किशन, ग्राम फतेहपुर शमशोई, तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाल किशन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०29/77(41)]

S.O. 2927.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bal Kishan, Village Fatehpur Samshoi, P.O. & Tehsil Sambhal, District Moradabad (Uttar Pradesh), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 29-Behjoi constituency, has failed to lodge an acount of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bal Kishan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/29/77(41)]

का०आ० 2928.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 49-सुन्हा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरेन्द्र सिंह, 35/सी-7, रामपुर बाग, सिविल लाइन, बरेली, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नरेन्द्र सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स० 49/77(42)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

S.O. 2928.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narendra Singh, 35/C-7, Rampur Bagh, Civil Lines, Barelli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 49-Sunha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And wrereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narendra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/49/77(42)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979

का०आ० 2929.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 64-खन्ना (अ० जा) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बलदेव सिंह, ग्राम मालोद, तहसील लुधियाना, जिला लुधियाना (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बलदेव सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० पंजाब-वि०स०/64/77]

आर० डी० शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th August, 1979

S.O. 2929.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Baldev Singh, Village Maloud, Tehsil Ludhiana, District-Ludhiana (Punjab) a contesting candidate for general election to the Punjab Legislative Assembly held in June, 1977 from 64-Khanna (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Baldev Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

R. D. SHARMA, Under Secy.

[No. PB-LA/64/77]

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1979

का०आ० 2930—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की बाबत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) पांचवां संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 में, नियम 7 के उपनियम (3)7 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात —

"(4) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अभिदाता उस मास के लिए, जिसमे वह सेवा निवृत्त होने वाला है, निधि में अभिदाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त मास के आरम्भ के पूर्व कार्यालय के प्रधान को उस मास के लिए अभिदाय करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना न दे दे।"

[सं० फा० 19(15)पेन/76-सा०भ०नि०]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 9th August, 1979

S.O. 2930.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Fifth Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in rule 7, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing his option to subscribe for the said month."

[No. F. 19(15)-Pen/76-GPF]

का०आ० 2931—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की बाबत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंशदायी भविष्य निधि (भारत) तीसरा संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 में, नियम 7 के उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(5) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अभिदाता उस मास के लिए, जिसमे वह सेवा निवृत्त होने वाला है, निधि में अभिदाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त मास के आरम्भ के पूर्व कार्यालय के प्रधान को उस मास के लिए अभिदाय करने के अपने विकल्प की लिखित सूचना न दे दे।"

[सं० फा० 19(15)-पेन/76-अ०भ०नि०]

सीताराम अग्रवाल, अवर सचिव

S.O. 2931.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Third Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, in rule 7, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing his option to subscribe for the said month."

[No. F. 19(15)-Pen/76-CPF]

S R AGRAWALA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1979

(आय-कर)

का०आ० 2932.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री रमणाश्रमम, तिरुवन्नामलाई, तमिल नाडु" को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 2704/फा०सं० 176/7/79-आ०क० (ए-1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st January, 1979

(INCOME-TAX)

S.O. 2932—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, Tamil Nadu" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Section.

[No. 2704/F. No. 176/7/79-IT(AI)]

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1979

का०आ० 2933—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'आर्मेनियन चर्च, कलकत्ता' को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य में सर्वत्र विख्यात लोकपूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 2727/फा० सं० 176/6/79-आ० क० (ए1)]

New Delhi, the 7th February, 1979

S.O. 2933.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Armenian Church, Calcutta', to be a place of public worship of renown throughout the State of West Bengal for the purposes of the said Section.

[No. 2727/F. No. 176/6/79-IT(AI)]

नई दिल्ली, 14 जून, 1979

का०आ० 2934—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि मालंकर ऑर्थोडाक्स सीरियन चर्च' को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 2855/फा० स० 197/126/78 आ० क० (ए1)]

New Delhi, the 14th June, 1979

S.O. 2934.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Malankara Orthodox Syrian Church" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1973-74.

[No. 2855/F. No. 197/126/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 30 मई, 1979

का०आ० 2935—अधिसूचना सं० 1262 (फा० सं० 203/184/75-आईटी ए II) तारीख 26 मार्च, 1976 के क्रम में, का० आ० सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए दो वर्ष की और अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि सावता अनुसंधान केन्द्र मुम्बई प्राकृतिक या अनुप्रयोगिक विज्ञान (कृषि/पशुपालन मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगा।

(ii) यह कि उक्त केन्द्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाए और उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

सावित्रा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई

यह अधिसूचना 16-12-78 से 15-12-1980 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[सं० 2833/फा०सं० 203/21/79-आई टी ए (ii)]

New Delhi, the 30th May, 1979

S.O. 2935.—In continuation of notification No. 1262 (F. No. 203/184/75-ITA.II) dated 26th March, 1976, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved for a further period of two years by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) that the Savita Research Centre, Bombay, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than Agriculture/Animal husbandry/fisheries & medicines);

(ii) That the said Centre will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Prescribed Authority for even financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

SAVITA RESEARCH CENTRE, BOMBAY

This notification will be valid for a period of two years from 16-12-78 to 15-12-1980.

[No. 2833/F. No. 203/21/79-ITA.II.]

का०आ० 2936—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिये चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में 'वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था' प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगी।

(2) यह कि संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई, तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिये अधिकथित किये जाये और उसे सूचित किये जायें।

संस्था

चिकित्सा अनुसंधान सोसाइटी, नागपुर यह अधिसूचना 10-5-1979 से 9-5-81 तक की दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी।

[सं० 2882/फा०स० 203/79/79-आई०टी०ए०-II]

S.O. 2936. It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of 'Scientific research association' in the field of medical research, subject to the following conditions :—

(i) That the Institution will maintain separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(ii) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the council for each financial year by 31st May, each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

Institution

SOCIETY FOR MEDICAL RESEARCH

This notification is effective for a period of two years from 10-5-1979 to 9-5-1981.

[No. 2882/F. No. 203/79/79-ITA.II]

नईदिल्ली, 18 जून, 1979

का०आ० 2937.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिये चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में 'वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था' प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त राशियों का पृथक हिसाब रखेगी।

(2) यह कि संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 15 मई तक ऐसे प्रारूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिये अधिकथित किये जायें और उसे सूचित किये जायें।

संस्था

राजकोट कैंसर सोसाइटी, राजकोट।

यह अधिसूचना 24-4-1979 से 23-4-1981 तक की दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी।

[सं० 2883/फा०सं० 203/75-79-आई०टी०ए०-II]

New Delhi, the 18th June, 1979

S.O. 2937.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (ii) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules 1962 under the category of "Scientific research association" in the field of medical research, subject to the following conditions :—

(i) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of the medical research.

(ii) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the council for each financial year by 15th May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

Institution :— Rajkot Cancer Society, Rajkot

This notification is effective for a period of two years from 24-4-1979 to 23-4-1981.

[No. 2883/F. No. 203/75/79-ITA.II]

नई दिल्ली, 30 जून, 1979

आय-कर

का०आ० 2938.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "अंजुमान-ए-इस्लामिया, कर्नूल" को निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिये और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 2899(फा०सं० 197/7/79-आ०क० (एI)]

जे०पी० शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 30th June, 1979

INCOME-TAX

S.O. 2938.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Anjuman-e-Islamiah, Kurnool" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1977-78.

[No. 2899/F. No. 197/7/79-IT(A1)]

J. P. SHARMA, Director

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

आदेश

स्टाम्प

का०आ० 2939.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (i) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा अगस्त 1979 में प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किये जाने वाले पैंतालीस करोड़ और दस लाख रुपये मूल्य के बन्धपत्रों पर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं० 25/79-स्टाम्प-फा०सं० 33/38/79-वि०क०]

एस०डी० रामस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 16th August, 1979

ORDER

STAMP

S.O. 2939.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of forty-five crores and ten lakhs of rupees, issued during the month of August, 1979 by the Industrial Credit and Investment Corporation of India, are chargeable under the said Act.

[No. 25/79-Stamps-F. No. 33/38/79-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क समाहर्ता का कार्यालय

बंगलौर, 7 अगस्त, 1979

सीमा-शुल्क

का०आ० 2940.—1962 के सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क कर्नाटक समाहरणालय बंगलौर, एतद्द्वारा मैसूर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहरणालय बंगलौर द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सी०सं०

111/48/65/67 सीमा शुल्क दिनांक 23-9-68 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के कालम (4) से (6) बाट संख्या 29 के सामने निम्नलिखित शब्द तथा अंक उपाबद्ध सारणी में प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

4	5	6
उत्तर से दक्षिण को 797 फीट मापन का मरित यार्ड। केवल शुल्क न देय मछलियों के अवतरण भाण्डारण के लिये मत्स्य उद्योग विभाग के स्वामित्व के दो उडन् (जेटिज) 1(69'×11'तथा 102'×11') (पूर्व से पश्चिम 80' (2) 161' 2/3'×125 1/3' (17 फीट विस्तार 125 1/2' पूर्व पश्चिम) उत्तर तथा दक्षिण : पीछे पानी पूर्व तथा उत्तर सार्वजनिक मार्ग (घोषित बाट संख्या 20 की कुल लंबाई 957 से बन्दरगाह भूमि क्षेत्र मापन 160' को अनुसूचित किया गया है)।	केवल शुल्क न देय मछलियों के लिये घाट/जेट्टी कायर लमक, शुल्क देय मछली तथा खजूर सरकारी बोरे/टाट तथा विस्फोटक दहनीय अनिष्टकर वस्तुएं तथा सामग्रिया	उतारना तथा लादना उतारना तथा लादना

[अधिसूचना सं० 3/79-सी०सं० 8/48/123/78-सीमा-शुल्क]

टी० एस० स्वामीनाथन,
समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क

OFFICE OF THE CONTROLLER OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Bangalore, the 7th August, 1979

CUSTOMS

S.O. 2940.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Customs Act, 1962, the Collector of Central Excise and Customs, Karnataka Collectorate, Bangalore hereby makes the following amendment in the notification C. No. VIII/48/65/67 Cus. dated 23-9-68 issued by the Mysore Central Excise Collectorate, Bangalore, namely :—

In the Table annexed to the said notification for words and figures mentioned in column (4) to (6) against wharf No. 20 in the said Table the following shall be substituted namely :—

(4)	(5)	(6)
The Marine yard measuring 797 feet North to South. Two wooden jetties owned by Fisheries Department for landing shipping of non-dutiable fish only. (Jetties : 1) 69'×11' & 102'×11' (East to West 80') (2) 161 2/3'×125 ½' (17 ft. wide, 125 ½'/East to West). W & S : Backwaters. E & N : Public road. (Denotified the Port land area measuring 160' out of total length 1957 feet of the declared wharf. No. 20)	Jetty for non-dutiable fish only. Coir, Salt dutiable fish and date Govt. gunnies and explosives combustible dangerous substances and articles.	Un-loading and loading Un-loading and loading

[Notification No. 3/79-C. No. VIII/48/123/78 Cus.,]

T. S. SWAMINATHAN,
Collector of Central Excise and Customs.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

का०आ० 2941.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (1) और (2) के उपबन्ध, 16 मई, 1980 तक की अवधि के लिये यूनियन बैंक आफ इंडिया तथा इंडियन बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक कि उक्त उपबन्ध, इन बैंकों के अध्यक्षों एवं प्रबन्ध निदेशकों के, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि० के निदेशक बनने पर रोक लगाते हैं, क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है।

[संख्या एफ० 15(39)-बी०ओ०-III/77]

एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 16th August, 1979

S.O. 2941.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of th Reserve Bank of India, hereby declares that the provision of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply upto 26th May, 1980 to the Union Bank of India and Indian Bank in so far as the said provisions prohibit their Chairmen and Managing Directors from being directors of the Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd. being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(39)-B.O. III/77

N. D. BATRA, Under Secy

(वित्त विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

का०आ० 2942—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अनुसरण में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में,—

(1) नियम 3 के खंड (क) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में, जहां समेकित वित्त सलाह स्कीम प्रवृत्त है, उस विभाग का समेकित वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय के पर्यवेक्षणाधीन और ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जो वह मंत्रालय इस विषय में जारी करे उस मंत्रालय की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग उनके अतिरिक्त करेगा, जो उक्त विभाग को इन नियमों द्वारा या इनके अधीन प्रत्योजित की गई हैं;"

(2) नियम 10 में, उपनियम (6) के खंड (क) का लोप किया जायेगा ;

(3) अनुसूची 3 के स्तम्भ 2 में, "अन्य विभाग" संबंधित मद (ii) में "में 2750 रु० प्रतिमास से कम वेतन वाले पद" शब्दों और

शब्दों के स्थान पर "2750 रु० प्रति मास तक वेतन वाले पद" शब्द और अंक रखे जायेंगे; और

(4) अनुसूची 7 के स्तम्भ 3 में, "मोटर यानों और मोटर साइकिलों का निष्प्रयोज्य ठहराया जाना" से संबंधित प्रविष्टि में "25,000 रु० 0" अंक और अक्षर के स्थान पर "1,00,000 रु०" अंक और अक्षर रखे जायेंगे ।

[संख्या एफ० 1(21)-ई०II(ए०)/78]
एस०के० दास, अवर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 16th August, 1979

S.O. 2942.—In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (Second Amendment) Rules, 1979

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Delegation of Financial Powers Rules, 1978,—

(i) in rule 3, in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in any Department of the Central Government where the Integrated Finance Advice Scheme is in force, the Integrated Financial Adviser of that Department will, subject to supervision by the Ministry of Finance and subject to such general or special orders as may be issued in this behalf by that Ministry, exercise all or any of the powers of that Ministry, beyond those delegated to the said Department by or under these rules";

(ii) in rule 10, the clause (e) of sub-rule (6) shall be omitted ;

(iii) in Schedule III, in column 2, in item (ii) relating to "Other Departments", for the words, letters and figures "on pay less than Rs. 2750/-", the words, letters and figures "on pay upto Rs. 2750/-" shall be substituted ; and

(iv) in Schedule VII, in column 3, in the entry relating to "Condemnation of motor vehicles and motor cycles", for the letters and figures "Rs. 25,000/-", the letters and figures "Rs. 1,00,000/-" shall be substituted.

[No.F. 1(21)-E.II(A)/78]
S. K. DAS, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1978

शुद्धि-पत्र

(आय-कर)

का०आ० 2943.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की आयुक्त, (अपील) कलकत्ता की अधिकारिता संबंधी अधिसूचना सं० 2382 (फा०सं० 261/8/78-आई०टी०जे०) तारीख 7 जुलाई, 1978 में,—

पृष्ठ 3 पर अनुसूची के स्तम्भ 1 में, आय-कर आयुक्त (अपील) 13-के सामने,—

"XXX"के स्थान पर, "XXX और कटक" रखें ।

[सं० 2570—फा०सं० 261/13/78-आई०टी०जे०]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 3rd November, 1978

CORRIGENDUM

INCOME-TAX

S.O. 2943.—In the Notification of the Central Board of Direct Taxes No. 2382 (F. No 261/8/78-ITJ) dated the 7th July, 1978 for the jurisdiction of Commissioner (Appeals) at Calcutta.

In Column 1 of the Schedule at page 3 against Commissioner of Income-tax (Appeals)-XIII.

Substitute "XXX and Cuttack" in place of "XXX".

[No. 2570/F. No. 261/13/78-ITJ]

आय-कर

का०आ० 2944.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० 2383 (फा० सं० 261/7/78-आई०टी०जे) तारीख 7-7-78 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करना है, अर्थात्:—

अनुसूची में

नीचे लिखी रेंजों के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
रेंज 1	1. कम्पनी जिला—1
	2. कम्पनी जिला—5
रेंज 4	1. कम्पनी जिला—2
	2. कम्पनी जिला—4
रेंज 5	1. कम्पनी जिला—3
	2 विशेष सर्किल—8, कम्पनी जिला—5
	3. कम्पनी जिला—6
	4. विदेशी कम्पनी रेंज—1
	5. विदेशी कम्पनी रेंज—2
	6. विदेशी कम्पनी सर्किल—1
	7. विदेशी कम्पनी सर्किल—2
	8. सहकारिता भवन सर्किल
	9. जूट सर्किल
	10. सहकारिता समिति सर्किल
	11 विशेष अन्वेषण रेंज
	12. विशेष अन्वेषण रेंज—1
	13. विशेष अन्वेषण सर्किल
	14. विशेष अन्वेषण सर्किल
	15 विशेष अन्वेषण रेंज-3
	16. विशेष अन्वेषण सर्किल—3
रेंज 8	1. जिला 4(3)
	2. जिला 3(1)
	3. व्यास सर्किल
	4. जिला 1(2)
	5. हावड़ा
	6. विशेष सर्किल—4 हावड़ा
	7. विशेष सर्किल—5, हावड़ा
	8. विशेष सर्वेक्षण सर्किल—9
रेंज 6	1. जिला 5(2)
	2. जिला 3(2)
	3. विशेष सर्किल—3, जिला 5(2)
	4. जिला 5(1)
	5. विशेष सर्वेक्षण सर्किल—8

जहां कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है, वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिसमें वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लम्बित अपीलें उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएंगी और उनके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना 1-11-78 से प्रभावी होगी।

[सं० 2571(261/13/78-आई०टी०जे०)]

Whereas the Income-tax Circle, Ward or Distt.) or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income tax Circle, Ward or Districts or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the A.A.C. of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the A.A.C. of the Range to whom the said Circle, Ward or Distirct or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-11-78.

[No. 2571(261/13/78-ITJ)]

INCOME-TAX

S.O.2944.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following amedments to the Schedule appended to its Notification No. 2383(F. No. 261/7/78-ITJ) dated 7-7-78.

In the Schedule

The following shall be substituted against the ranges mentioned below:

Column 1	Column 2
Range I	1. Compl Dist. I.
	2. Compl Dist. V.
Range IV	1. Compl Dist. II.
	2. Comp Dist. IV.
Range V.	1. Comp Dt. III
	2. Special Circle-VIII, Comp. Dist. V.
	3. Comp. Dist. VI.
	4. Foreign Companies Range-I
	5. Foreign Companies Range-II
	6. Foreign Companies Circle-I.
	7. Foreign Companies Circle-II.
	8. Co-operative Housing Circle
	9. Jute Circle.
	10. Co-operative Societies Circle.
	11. Special Investigation Range.
	12. Special Investigation Range.
	13. Special Investigation Circle
	14. Special Investigation Circle
	15. Spl. Investigation Range-I.
	16. Spl. Investigation Circle-I.
Range VIII	1. Dist. IV(3)
	2. Dist. III(1)
	3. Trust Circle.
	4. Dist. I (2)
	5. Howrah.
	6. Spl. Circle-IV, Howrah
	7. Spl. Circle-V, Howrah.
	8. Spl. Survey Circle-IX.
Range VI	1. Dist. V(2).
	2. Dist. III(2)
	3. Spl. Circle-III, Dist. V(2)
	4. Dist. V(1)
	5. Spl. Survey Circle-VIII.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1978

आयकर

का०आ० 2945.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० 2471 (फा० सं० 261/22/78-आई०टी०जे०) तारीख 18-8-78 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन और परिवर्धन किए जाएंगे अर्थात्:—

क्र० सं०	भारसाधन और मुख्यालय	आयकर सर्किल और वार्ड	सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण का रेंज
1	2	3	4
1	आयुक्त (अपील-1 अहमदाबाद	प्रविष्टि सं० 1 का लोप किया जाएगा	प्रविष्टि सं० 1 और 2 का लोप किया जाएगा

क्रम सं० 4 के पश्चात् निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएंगे।

5	आयुक्त (अपील) 3, अहमदाबाद	1 सहकारिता सर्किल—3, अहमदाबाद	ए भार 9, अहमदाबाद
		2 — 4 ,,	
		3 — 10 ,,	
		4 — 11 ,,	
		5 — 12 ,,	
		6 — 13 ,,	
		7 — 14 ,,	
6	आयुक्त (अपील) —4, अहमदाबाद	1 सह० सर्किल 1, अहमदाबाद	ए भार 8, अहमदाबाद
		2 — 2 ,,	
		3 — 5 ,,	
		4 — 6 ,,	
		5 — 7 ,,	
		6 — 8 ,,	
		7 — 9 ,,	
		8 — 15 ,,	

जहां कोई आयकर सर्किल, वार्ड, जिला या रेंज या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक आयकर आयुक्त अपील के भार साधन से किसी अन्य आयकर आयुक्त अपील के भार साधन को अन्तरित हो जाता है, वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड, जिले या रेंज या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस भार साधन के जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या रेंज या उसका भाग अन्तरित हुआ है, आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के

ठीक पूर्व लंबित अपीलें उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस भारसाधन के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड, जिला या रेंज या उसका भाग अन्तरित हुआ है आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना 4-11-78 से प्रभावी होगी।

[सं० 2581-फा०सं० 261/22/78-आई०टी०जे]

New Delhi, the 15th November, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2945.—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 121A of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 2471(F. No. 261/22/78-ITJ) dated 18-8-78.

In the said Schedule the following alterations and additions shall be made :

Sl. No.	Charge with Headquarters	Income-tax Circle and Wards	Ranges of Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax
1	2	3	4
1.	Commissioner (Appeals)-I, Ahmedabad.	Entry No. 1 to be deleted.	Entries No. 1 & 2 to be deleted.

After Sr. No. 4, the following additions shall be made :—

5.	Commissioners (Appeals)-III, Ahmedabad.	1. Co. Circle III, A' bad. 2. Co. Cir IV, A' bad. 3. Co. Cir. X, A' bad. 4. Co. cir XI A' bad 5. Co. Cir. XII, A' bad. 6. Co. Cir. XIII, A' bad. 7. Co. Cir. XIV, A' bad.	A.R. IX, Ahmedabad
6.	Commissioner (Appeals)-IV, Ahmedabad.	1. Co. Cir. I, A' bad. 2. Co. Cir. II, A'bad. 3. Co. Cir. V, A'bad. 4. Co. Cir. VI, A' bad. 5. Co. Cir. VII, A' bad. 6. Co. Cir. VIII, A' bad. 7. Co. Cir. IX, A' bad. 8. Co. Cir. XV, A' bad.	A.R. VII, Ahmedabad.

Where I.T. Circles, Wards, Districts or Ranges or part thereof stand transferred by this Notification from one Commissioner of Income-tax (Appeals) Charge to another Commissioner of Income-tax (Appeals) Charges, Appeals arising out of assessments made in that I.T. Circles, Wards, Districts or Ranges or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax (Appeals) from whom that I.T. Circles, Wards, Districts or Ranges or part there of are transferred, shall from the date of this Notification shall take effect be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the Commissioner of Income-tax (Appeals) charge to whom the said Circles, Wards, Distts. or Ranges or part thereof are transferred.

This Notifications shall take effect from 4-11-78.

[No 2581/F. No. 261/22/78-ITJ]

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1979

आयकर

का०आ० 2946—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पहले जारी की गई अधिसूचना का आंशिक उपान्तरण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट भारसाधन करने वाले आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) में तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वार्डों, जिलों और रेंजों में ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में जिन पर आयकर या अतिकर या ब्याजकर निर्धारित किया गया है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ज), कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1), ब्याजकर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में वर्णित किसी आदेश से व्यथित है तथा ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति वर्ग के बारे में भी, जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निर्देश दे, अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

भारसाधन और मुख्यालय	आयकर वार्ड, सर्किल और जिला	सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का रेंज
1	2	3
आयुक्त (अपील)- 1, नई दिल्ली	सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), रेंज 1-क, 1-ख, 1-ग, 1-घ और 1-ङ, नई दिल्ली की अधिकारिता में के सभी वार्ड/सर्किल	आयकर आयुक्त दिल्ली-1 की अधिकारिता में रेंज 1-क, 1-ख, 1-ग, 1-घ और 1-ङ
आयुक्त (अपील)- 2, नई दिल्ली	सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज 2-क, 2-ख और 2-घ नई दिल्ली की अधिकारिता में के सभी वार्ड/सर्किल	आयकर आयुक्त दिल्ली-2 की अधिकारिता में रेंज 2-क, 2-ख और 2-च
आयुक्त (अपील)-6, नई दिल्ली	सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज-3क, 3ख, 3ग, 3घ और 3ङ, नई दिल्ली की अधिकारिता में के सभी वार्ड/सर्किल	आयकर आयुक्त दिल्ली-4 की अधिकारिता में रेंज 3-क, 3-ख, 3ग, 3घ और 3ङ
आयुक्त (अपील)- 7, नई दिल्ली	सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज 5-क, 5ख, 5ग, 5घ और 5ङ, नई दिल्ली की अधिकारिता में के सभी वार्ड/सर्किल	आयकर आयुक्त दिल्ली-5 की अधिकारिता में रेंज 5-क, 5-ख, 5ग, 5घ और 5ङ

यह अधिसूचना 15-11-78 से प्रभावी होगी।

[सं० 2588/फा०सं० 261/2/78—आई०टी०जे०)]

New Delhi the, 21st November, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2946.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the notification issued earlier, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Commissioner of I.T. (Appeals) of the Charges specified in Col. (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to income-tax or surtax or interest tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in columns (2) and Col. (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961, in sub-section (1) of Section II of Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of Sections 15 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (i) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

Charges with Head-quartes	Income-tax Wards/ Circles and Distts.	Ranges of I.A.Cs. of Income-tax
1	2	3
Commissioner (Appeals)-I, New Delhi.	All Wards/Circles within the jurisdiction of IAC of Income-tax ranges-I-A, I-B I-C, I-D, and I-E, New Delhi.	Ranges—I-A, I-B, I-C, I-D & I-E, within the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Delhi-I.
Commissioner (Appeals)-II, New Delhi	All Wards/Circles within the jurisdiction of IACs of I.T. Ranges-II-A, II-B, & II-F, New Delhi.	Ranges—II-A, II-B and II-F within the jurisdiction of Commissioner of Income tax, Delhi-II.
Commissioner (Appeals)VI, New Delhi.	All Wards/Circles within the jurisdiction of IACs. of I.T. Ranges-III-A, III-B, III-C, III-D & VII-E, New Delhi.	Ranges-III-A, III-B, III-C, III-D & III-E within the jurisdiction of C.I.T Delhi-IV.
Commissioner (Appeals)-VII, New Delhi	All Wards/Circles within the jurisdiction of IACs. of I.T. Ranges, V-A, V-B, V-C, V-D & V-E. New Delhi.	Ranges—V-A, V-B, V-C, V-D, and V-E within the jurisdiction of C.I.T. Delhi-V.

This notification shall take effect from 15-11-78.

[No. 2588 (F. No. 261/2/78-ITJ]

का०आ० 2947.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस संबंध में सभी पूर्ववत् अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में, विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) ऐसे सभी व्यक्तियों और आयों को छोड़कर, जिनकी बाबत अधिकारिता आयकर आयुक्त (अपील में विहित है, अन्य सभी व्यक्तियों और आयों के संबंध में जिन पर उसके स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वार्डों और जिला में आयकर या अतिकर निर्धारित किया गया है, अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

रेंज	आयकर, सर्किल, वार्ड और जिला
1. पटियाला रेंज	सभी आयकर सर्किल, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालय निम्न स्थान पर है :— (1) बरनाला, (2) आयकर सर्किल चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, और पालमपुर स्थित ऊना जिले, (3) मलेर कोटला, (4) मंडी, (5) पटियाला, (6) रूपनगर, (7) शिमला, (8) सोलन, (9) संगरूर, (10) चन्डीगढ़ और (11) पटियाला और चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय सर्किल।
2. लुधियानारेंज	(1) सभी आयकर सर्किल, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालय खन्ना और लुधियान में हैं। (2) सभी केन्द्रीय सर्किल, जिनके मुख्यालय लुधियाना में है।

जहां कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है, वहां उस आयकर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लंबित अपीलें उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है सहायक आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यदि किसी विशिष्ट स्थान पर मुख्यालय रखने वाले सभी सर्किल, वार्ड और जिले किसी एक सहायक आयुक्त (अपील) को समनुदेशित कर दिए जाते है तो उसकी अधिकारिता, उन मुख्यालयों के ऐसे सर्किलों, वार्डों और जिलों पर भी उनके उत्पाद के समय से होगी।

यह अधिसूचना 20-11-1978 से प्रभावी होगी।

[सं० 2589/फा० सं० 261/11/78-आईटी जे०]

INCOME-TAX

S.O. 2947.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in columnn (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding all persons and income assessed to income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles/Wards and District
1	2
1. Patiala Range.	All Income-tax Circles, Wards and Districts having headquarters (i) Barnala, (ii) Income-tax Circle, Chamba, Kangra, Hamirpur and Una Districts at Palampur, (iii) Malerkotla, (iv) Mandi, (v) Patiala (vi) Rupnagar, (vii) Simla, (viii) Solan, (ix) Sangrur, (x) Chandigarh and (xi) Central Circles at Patiala and Chandigarh.,

1	2
2. Ludhiana	(1) All Income-tax Circles, Wards and Districts having headquarters at Khanna and Ludhiana.
	(2) All Central Circles having headquarters at Ludhiana.

Whereas the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stand transferred by this Notification from one Range to another Ranges, appeals arised out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this Notifications takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom these Circle, Ward or District part there of is transferred.

Where all Circles, Wards and Districts having headquarters at a particular place have been assigned to an Appellate Assistant Commissiner he will have jurisdiction in respect of Circles, Ward and Districts at these headquarters, abolished also.

This notification shall take effect from 20-11-78.

[No. 2589(F. No. 261/11/78-ITJ]

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1979

का०आ० 2948.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पहले जारी की गई अधिसूचना सं० 2382 (फा० सं० 261/8/78-आई टी जे) तारीख 7-7-78 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट भार साधनों वाले आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वार्डों जिलों और रेंजों में सभी ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन पर आयकर या अधिकर या ब्याजकर निर्धारित किया गया है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ज) तक कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1), ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में वर्णित किसी आदेश से व्यथित है और ऐसे व्यक्तियों का व्यक्ति वर्गों के बारे में भी, जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दे, अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

भारसाधन और मुख्यालय	आयकर वार्ड और सर्किल	सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण का रेंज
1	2	3
आयकर आयुक्त (अपील) लुधियाना	आयकर आयुक्त पटियाला की अधिकारिता में के (संपदाकर सर्किल और केन्द्रीय सर्किल को छोड़कर) लुधियाना और खन्ना में स्थित सभी वार्ड/सर्किल	1 स०आ० (नि०) रेंज-1 लुधियाना 2. स०आ० (नि०) रेंज-2, लुधियाना
	(2) केन्द्रीय सर्किल 1 से 6 (लुधियाना)	3 स०आ० (नि०) (केन्द्रीय) रेंज-1 लुधियाना
	(3) केन्द्रीय सर्किल, पटियाला	4 स०आ० (नि०) (केन्द्रीय) रेंज-2, लुधियाना
	(4) केन्द्रीय सर्किल, चंडीगढ़	5 स०आ० (नि०) (केन्द्रीय) अमृतसर
	(5) केन्द्रीय सर्किल करनाल	
	(6) केन्द्रीय सर्किल, 1, 2 और 3, अमृतसर	
	(7) केन्द्रीय सर्किल 1 और 2 जलंधर	

यह अधिसूचना 1-11-78 से प्रभावी होगी।

[सं० 2599(फा०स० 261/31/78-आई०टी०जे०]

INCOME-TAX

S.O. 2948.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121, of the Income-tax, Act, 1961(43 of 1961) and in supersession of previous Notification No. 2382 (F No. 261/8/78-ITJ) dated 7-7-78 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals) of the Charges specified in column(1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or surtax or interest-tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column(2) and column (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961 in sub-section (1) of section II of Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), and in sub-section (1) of section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (i) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

Charges with Headquarters	Income-tax Wards and Circles	Ranges of Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax
1	2	3
Commissioner of Income-tax (Appeals) Ludhiana.	(1) All Wards/Circles (excluding ED Circle and Central Circle) located at Ludhiana and Khana within the jurisdiction of CIT, Patiala	1. I.A.C. Range I Ludhiana.
	(2) Central Circles I to VI, Ludhiana.	2. I.A.C. Range II, Ludhiana.
	(3) Central Circles, Patiala.	I.A.C. (Central) Range I (Ludhiana.)
	(4) Central Circle, Chandigarh.	4. I.A.C. (Central) Range II Ludhiana.
	(5) Central Circles, Karnal.	S. I. C (Central) Amritsar.
	(6) Central Circle I, II, III Amritsar.	
	(3) Central Circle I & II Jullundur.	

This notification shall take effect from 1-11-78

[No. 2599 (F. No. 261/31/78-ITJ]

(आय कर)

का०आ० 2949.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिसूचना स० 2383 (फा०सं० 261/7/78-आई०टी० जे०) तारीख 7 जुलाई, 1978 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, निदेश देता है कि पृष्ठ 2 पर अनुसूची के स्तम्भ (2) में क्रम स० 7 के पश्चात्, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के सामने निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् —

क्रम स०	आय-कर सर्किल/वार्ड और जिला
8	अतिरिक्त-ख और अतिरिक्त-ग वार्ड, जयपुर
9	ट्रस्ट सर्किल, जयपुर

यह अधिसूचना 6-11-78 से प्रभावी होगी।

[स० 2600(फा०स० 261/16/78-आई०टी०जे०]

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

(INCOME TAX)

S.O. 2949.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Notification No. 2383 (F. No. 261/7/78-ITJ) dated 7th July, 1978 the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the following words would be inserted in Col. 2 of the Schedule on Page 2 against the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, A-Range, Jaipur after S. No. 7 :—

S. No.	Income-Tax Circle/Wards & district
8.	Addl B and Addl. C Wards, Jaipur.
9.	Trust Circle, Jaipur.

This notification shall take effect from 6-11-78.

[No. 2500 (F. No. 261/167/8-ITJ)]
S. RAMASWAMI, Under Secy

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 7 मई, 1979

(आयकर)

का०आ० 2950.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना स० 679 (फा०सं० 187/2/74-आ०क० (ए1) तारीख 20 जुलाई, 1974 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

2 क्रम स० 13क के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
13क केरल-II	एर्नाकुलम	1 वेतन सर्किल, एर्नाकुलम 2 आय-कर सर्किल I अल्वय 3 आय-कर सर्किल, I कालीकट 4. आयकर सर्किल-II, कालीकट 5 आय-कर सर्किल, कन्नानौर 6. आयकर सर्किल, कोट्टायम 7 आयकर सर्किल, मट्टनचेरी 8 आयकर सर्किल, पालघाट 9 आयकर सर्किल, त्रिचूर 10 विशेष सर्किल, एर्नाकुलम 11 आयकर सर्किल, कासरगोड

3 यह अधिसूचना 27-4-1977 से प्रभावी होगी।

[स० 2803, फा०स० 189/21/78-आ०क०(ए-I)]

पी०एम० झिंगन, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi the 7th May, 1979

(INCOME TAX)

S.O. 2950.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 679 (F. No. 187/2/74-ITJ(A1) dated 20th July, 1974 as amended from time to time.

2 Existing entries under cloumn (1), (2) and (3) against Serial No. 13A shall be substituted by the following :—

Commissioner of Income-tax	Head-Quarter	Jurisdiction
1	2	3
13A Kerala-II	Ernakulam	1. Salary Circle, Ernakulam 2. Ime-tax Circle-I, Alwaye, 3. Income-tax Circle-I, Calicut, 4. Income-tax Circle-II, Calicut, 5. Income-tax Circle, Cannanore, 6. Income-tax Circle, Kottayam, 7. Income-tax Circle, Mattancherry, 8. Income-tax Circle, Palghat, 9. Income-tax Circle, Trichur, 10. Special Circle, Ernakulam, 11. Income-tax Circle, Kasargod.

3 This Notification shall take effect from 27-4-1979.

[No. 2803/F.No. 189/21/78-IT/(AI)]

P. N. JHINGON, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

बंगलौर 22 मार्च, 1979

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का०आ० 2951.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इस अधिसूचना द्वारा, इस समाहर्तालय में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक समाहर्ताओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 173-सी०(1) के अधीन निर्धारितियों द्वारा यथामूल्य निर्धारणीय माल के संबंध में मूल्य

सूचियों को फाइल करने के संबंध में, समाहर्ता की शक्तियां प्रदान करता हूं ।

[केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं० 1/79]

आर०एन० शुक्ला, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता

OFFICE OF THE CENTRAL COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Bangalore, 22nd March, 1979

S.O. 2951.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the Assistant Collectors of Central Excise in this Collectorate to exercise the powers of the Collector under Rule, 173-C(1) of the Central Excise Rules, 1944 in regard to fling of Price Lists of good assessable to advalorem by the assessees.

[Central Excise Notification No. 1/79]

R. N. SHUKLA, Collector of Central Excise

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1979

का० आ० 2952—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन चैम्बर आफ कामर्स, हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चैम्बर को गुड़ की अग्रिम संविदाओं के बारे में 10 अगस्त, 1979 से 9 अगस्त, 1980 (जिसमे ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) तक एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद् द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त चैम्बर ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें ।

[एफ० सं० 12(1)-आई० टी० 79]

के० एस० मैथ्यू, उप सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 8th August, 1979

S.O. 2952.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Chamber of Commerce, Hapur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period of one year from the 10th August, 1979 upto the 9th August, 1980 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12(1)-IT/79]

K. S. MATHEW, Dy. Secy.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

बम्बई, 7 अगस्त, 1979

विषय :— सर्वश्री एन० एम० एंटरप्राइसेस, बम्बई को जारी किए गए लाइसेन्स सं० पी० के 1897915 दिनांक 18-2-78 मूल्य 45177 रुपये की सीमाशुल्क निकासी प्रति को रद्द करने के लिये आदेश ।

का० आ० 2953—सर्वश्री एन० एम० एंटरप्राइसेस, बोटावाला बिल्डिंग, 2 री माला, 47, पीकेट रोड, कालबादेवी रोड के सामने, बम्बई-2 को 1977-78 की लाइसेंस अवधि के आयात नियंत्रण नीति खंड II के परिच्छेद 30(3) और 32(2) भाग बी अनुभाग 1 के अंतर्गत इस आदेश के पीछे दी गई मद के आयात के लिए आयात लाइसेन्स सं० पी० के०/1897915 दिनांक 18-2-78 मूल्य 45177/ रुपये के लिए जारी किए गए थे ।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि, लाइसेन्स की सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है और आगे यह भी उल्लेख किया है कि उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था ।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने मैट्रोपोलीटिन मैजेस्ट्रेट बम्बई द्वारा विधिवत सांख्यांकित स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है ।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेन्स सं० पी० के०/1897915 दिनांक 18-2-78 मूल्य 45177/ रुपये की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि, इनकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जाए । उक्त लाइसेन्स सं० पी० के०/1897915 दिनांक 18-2-78 मूल्य 45177 रुपये की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या 1795/23687/ए० एम्-78/जे० एम्-77/एल०/आर०-ई० पी० I बी]

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

Bombay, the 7th August, 1979

Subject.—Order for cancellation of Customs purpose copy of import licence No. P/K/1897915/C/XX/66/B/77/K. I, dated 18-2-78 issued to M/s. N. M. Enterprises, Botawala Bldg., 2nd Floor, 47-Picket Road, Off Kalbadevi Road, Bombay-2.

S.O. 2953. M/s. N. M. Enterprise, Botawala Bldg., 2nd Floor, 47-Picket Road, Off Kalbadevi Road, Bombay-2. Obtained import Licence No. P/K/1897915 dt. 18-2-78 for import of Raw Materials, Components, Consumable Stores and Packing materials in accordance with the provisions made in para 30(3) and 32(2) of Part B Section I of Policy Book Vol. II for 1977-78. They have applied for duplicate Customs Purpose copy of the above mentioned licence on the ground that the original customs purpose copy of the licence has been lost or misplaced. It is further stated that the original customs purpose copy of the licence was not registered with any custom authority and not utilised.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit on stamped paper duly attested by the Metropolitan Magistrate, Bombay. I am satisfied that the original Customs Purpose copy of the import licence No. 1897915 dt. 18-2-78 has been lost or misplaced and direct that a Duplicate Customs purpose copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs purpose copy of the import licence No. 1897915 dated 18-2-78 may be deemed to have been cancelled.

[F. No. 1795/23687/AM. 78/JS. 77/L/REPIB]

विषय :— सर्वश्री पैरागांन टेक्सटाईल मिल, बम्बई, 13, को जारी किए गए लाइसेन्स सं० पी०यू०/ 2789863 दिनांक 28-2-77 मूल्य 54187 रुपये की मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा शुल्क निकासी प्रतियों को रद्द करने के लिए आदेश ।

का० आ० 2954 —सर्वश्री पैरागॉन टैक्सटाईल मिल, ग्लोब मिल पैसेज, बम्बई-400013, को सामान्य मुद्रा क्षेत्र में अप्रैल-मार्च-77 की लायसेन्स अवधि के लिए आयात नियंत्रण नीति के अंतर्गत डाईज तथा केमिकल्स के पूंजीगत माल के आयात के लिए आयात लाइसेन्स सं० पी० यू०/2789863 दिनांक 28-2-77 मूल्य 54187 रुपये के लिए जारी किए गए थे ।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी प्रतियों की अनुलिपि प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि, लाइसेन्स की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी प्रतियां खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई हैं । और आगे यह भी उल्लेख किया है कि उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था ।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने मेट्रोपोलीटिन मैजेस्ट्रेट बम्बई द्वारा विधिवत् सांक्याकित स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेन्स सं० पी० यू०/2789863 दिनांक 28-2-77 मूल्य 54187 रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण और सीमा-शुल्क निकासी प्रतियां खो गई हैं और निदेश देता हूं कि, इनकी अनुलिपि प्रतियां आवेदक को जारी की जाए । उक्त लाइसेन्स सं० पी० यू०/ 2789863 दिनांक 28-2-77 मूल्य 54187 रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां और सीमा शुल्क निकासी प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या 1213/16741/ए-एम-77/जे एस-76/एस/आर-ई-पी-1 बी]

ओम् प्रकाश, उप-मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात

Subject.—Order for cancellation of Customs Purpose and Exchange Control purpose copy of import licence No. P/U/2789863/C/XX/62/B/43-44 W. 1, dated 28-2-77 issued to M/s. Paragon Textile Mills, Globe Mills, Passage, Bombay-400013.

S.O. 2954.—M/s. Paragon Textile Mills, Globe Mills Passage, Bombay obtained import licence No. P/U/2789863 dated 28-2-77 for import of Dyes and Chemicals as per AM. 77 policy book for the Licensing period AM-77 from G.C.A. They have applied for duplicate Customs & Exchange Control Purposes copies of the above mentioned licence on the ground that the original Customs and Exchange Control purpose copies of the licence, have been lost or misplaced. It is further stated that the original Customs and Exchange Control purpose copy of the licence was registered with Bombay Custom authority and is partly utilised.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit on stamped paper duly attested by the Metropolitan Magistrate, Bombay. I am satisfied that the original Customs purpose copy and Exchange Control purpose copy or the import licence No. 2789863 dated 28-2-77 has been lost or misplaced and direct that a Duplicate Customs & Exchange Control purpose copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs & Exchange Control purpose copies of the Import licence No. 2789863 dt. 28-2-77 may be deemed to have been cancelled.

[No. 1213/16741/AM. 77/IS. 76/L/REPIB]

विषय :—सर्वश्री झकेरिया शहीद इम्पैक्स प्रा० लि० को जारी किए गए लाइसेन्स सं० पी० के०/1900593 दिनांक 29-3-78 मूल्य 30202 रुपये की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करने के लिये आदेश ।

का० आ० 2955.—सर्वश्री झकेरिया शहीद इम्पैक्स प्रा० लि०, 97, अली उमर स्ट्रीट, बम्बई-3 को 1977-78 की लाइसेन्स अवधि के आयात नियंत्रण नीति खंड II के परिच्छेद 30(3) और 32(2) भाग बी अनुभाग 1 के अंतर्गत कच्चे माल तथा संघटक उपभोज्य वस्तुएं और संवेष्टन सामग्री के आयात के लिए आयात लाइसेन्स सं० पी०/के०/1900593 दिनांक 29-3-78 मूल्य 30202 रुपये के लिए जारी किए गए थे ।

उन्होंने उक्त लाइसेन्स की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि, लाइसेन्स की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई अथवा अस्थानास्थ हो गई है और आगे यह भी उल्लेख किया है कि उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था ।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है ।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेन्स सं० पी०/के०/1900593 दिनांक 29-3-78 मूल्य 30202 रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि, इनकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जाए । उक्त लाइसेंस सं० पी०/के०/1900593 दिनांक 29-3-78 मूल्य 30202 रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या 1764/23409/ए-एम-78/जे एस-77/एस/आर ई पी-1 बी]

पी० गोवन्दा राजू,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात

Subject.—Cancellation of Licence No. P/K/1900593 dt. 29-3-78 for Rs. 30202 (Exchange Control purpose copy) issued to M/s. Zakaria Shahid Impex Pvt., Bombay-3.

S.O. 2955.—M/s. Zakaria Shahid Impex Pvt. Ltd., 97-Ali Umer Street, Bombay-3, has been granted Licence No. 1900593 dt. 29-3-78 for Rs. 30202 (Rupees Thirty thousand Two hundred and Two only) for import of Raw materials, components, consumbale stores and packing materials in accordance with the provisions made in paras 30(3) and 32(2) of Part B Section I of Policy Book (Vol. II) for 1977-78.

They have applied for duplicate copy of Exchange Control purposes copy of the said Licence on the ground that the original licence has been lost/misplaced.

It is further stated that the said original licence is not registered with any Customs Authority and is not utilised.

In support of their claim applicant have filed an affidavit.

I am satisfied that the original copy of Exchange Control purposes copy of Licence No. 1900593 dt. 29-3-78 has been lost/misplaced and direct that the duplicate of the licence should be issued to the applicant firm.

The original Exchange Control purposes copy is cancelled.

[No. 1764/23409/AM. 78/IS. 77/L/REPIB]

OM PRAKASH, Dy. Cheif Controller of Imps. & Exps.
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

(तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण)

का० आ० 2956 —तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 (1975 का 4) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० बी० संत, मुख्य कृषि विकास अधिकारी, कृषि निदेशालय महाराष्ट्र सरकार, पूना को, डा० आर० एल० नागपाल के सेवा निवृत्त होने से खाली हुए स्थान पर तम्बाकू बोर्ड के

सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 100(अ) दिनांक 19-2-1979 में और आगे निम्नोक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में क्रमांक 21 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"21. श्री एम० वी० संत मुख्य रुई विकास अधिकारी, कृषि निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, पूना।	सदस्य	महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।"

[सं० 8/11/79-ई० पी० (कृषि-6)]
ओम प्रकाश गुप्त, डेस्क अधिकारी

(Department of Commerce)

New Delhi, the 16th August, 1979

(Tobacco Industry Development Control)

S.O. 2956.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (4) of section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby appoints Shri M. V. Sant, Chief Cotton Development Officer, Directorate of Agriculture, Government of Maharashtra, Pune, as a Member of the Tobacco Board in the vacancy caused by the retirement of Dr. R. L. Nagpal and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Department of Commerce) No. S.O. 100(F) dated 19-2-1979, namely :—

2. In the said notification for Sl. No. 21 and the entries relating thereto the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :—

"21. Shri M. V. Sant, Chief Cotton Development Officer Directorate of Agriculture, Government of Maharashtra, Pune.

Member.—To represent the Government of Maharashtra.

[No. 8/11/79-EP(Agri. vi)]
O. P. GUPTA, Desk Officer

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1979

का० आ० 2957.—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) अधिसूचना संख्या एस० 22014/3/77-एम० एस०, दिनांक 7 जुलाई, 1978 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या एस० 22014/3/77-एम० एस०]
एन० ए० सुब्रामणि, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th July, 1979

S.O. 2957.—The notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare (Department of Health) No. S. 22014/3/77-MS dated the 7th July, 1978 is hereby cancelled.

[No. S. 22014/3/77-MS]
N. A. SUBRAMONEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1979

का० आ० 2958.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उप धारा के खंड (क) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श करने पर डा० के० एन० टंडन के स्थान पर डा० एन० बी० मिश्रा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लखनऊ को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 138 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन मनोनीत" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाए, नामत :—

"2 डा० एन० बी० मिश्रा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

[संख्या वी० 11013/25/79-एम० ई० (पी०)]
के० एल० भाटिया, अवर सचिव

New Delhi, the 17th August, 1979

S.O. 2958.—Whereas the Central Government have in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (4) of section 7 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), nominated, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, Dr. N. B. Mishra, Director of Health Services, Lucknow, to be a member of the Medical Council of India vice Dr. K. N. Tandon.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Health No. S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3", for Serial No. 2 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be substituted, namely :—

"2. Dr. N. B. Mishra,

Director of Health Service,

Lucknow. (U.P.)"

[No. V. 11013/25/79-M.E. (Policy)]
K. L. BHATIA, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1979

का०आ० 2959.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3458 तारीख 15 नवम्बर, 1978 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्रों

की 1615.00 एकड़ (लगभग) या 653.55 हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना देती है :—

(क) इससे उपाबद्ध अनुसूची "क" में वर्णित 1211 एकड़ (लगभग) या 490.06 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि; और

(ख) इससे उपाबद्ध अनुसूची "ख" में वर्णित 404.00 एकड़ (लगभग) या 163.49 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि में खनिजों के निष्कासन, खुदाई करने और ले जाने के लिए खनन, खदान, बेचने, खोदने और खोजने के अधिकार ।

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त, गिरिडीह (बिहार) के कार्यालय या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण 2 : कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध हैं :—

8. अर्जन की बाबत आपत्तियां : (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्ही अधिकार का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हैं, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हिस्से का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते ।

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को इस अधिनियम के अधीन कारी सक्षम प्राधि के रूप में नियुक्त किया है ।

अनुसूची "क"

गोविन्दपुर खण्ड

(पूर्व बोकारो कोयला क्षेत्र)

ड्राइंग सं० राजस्व 7/79
तारीख 12-3-79

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि वर्णित की है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	आर्मो	नवाडीह	11	गिरिडीह		भाग
2	गोविन्दपुर	,,	15	,,		,,

कुल क्षेत्र : 1211.00 एकड़ (लगभग)
या 490.06 हेक्टेयर (लगभग)

आर्मो ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट की सं० : 758 (भाग)
1 गोविन्दपुर ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की सं० :—

1 (भाग), 2 से 91, 93 (भाग), 219, 220 (भाग), 221 (भाग), 222 (भाग), 223 (भाग), 224, 231 (भाग), 248 (भाग), 249 से 570, 571 (भाग), 572 (भाग), 573 से 578, 579 (भाग), 580 (भाग), 581 से 674, 682 (भाग), 683 से 696, 700 से 702, 703, 704, 710 से 748, 749 (भाग), 825 (भाग), 831 से 839, 840 (भाग), 841 से 935, 936 (भाग), 937 से 1383, 1384 (भाग), 1385, 1386, 1387, 1388 (भाग), 1389 से 1525, 1531 से 1558, 1567 (भाग), 1568 से 1572, 1573 (भाग), 1660 (भाग), 1661 से 1662, 1663 (भाग), 1667, 1679 से 1742, 1744 से 1750, 1753, 175 1755 (भाग), 1794, 1829 से 1862, 1863 (भाग), 1864 (भाग), 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782 और 2783 ।

सीमा वर्णन :

क—ख — लाइन आर्मो और गोविन्दपुर ग्रामों में कुनार नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है ।

ख—ग — लाइन गोविन्दपुर ग्राम के प्लाट सं० 1384 में से होकर और प्लाट सं० 1384 और प्लाट सं० 1388 की सम्मिलित सीमा के एक भाग के साथ-साथ प्लाट सं० 1388 और 1384 में से होकर और तब प्लाट सं० 1763, 1761, 1760 और 1756, 1445 और 1756, 1455 और 1756 सहित प्लाट सं० 1384 और 1765, 1384 और 1764, 1426 और 1764, 1426 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ प्लाट सं० 1755 में से प्लाट सं० 1755 और 1752, 1753 और 1752, 1753 और 1751, 1751 और 1750 प्लाट सं० 1744 और प्लाट सं० 1751, 1791, 1792 और 1743 की सम्मिलित सीमा, प्लाट सं० 1743 और 1732 सहित सामान्य सीमा, प्लाट सं० 1742 और प्लाट सं० 1743, 179 , 1795, 1793, 1794, से सम्मिलित सीमा से होकर जाती है । प्लाट सं० 1798 और 1833, 1798 और 1832, 1827 और 1832, 1827 और 1831, 1827 और

1830, 1828 और 1829, 1825 और 1863 की सम्मिलित सीमा, प्लाट सं० 1863 और 1864 में से, प्लाट सं० 1856 1689, 1688, 1687, 1685, 1682, 1661 सहित प्लाट सं० 1660 की सामान्य सीमा, प्लाट सं० 1660 में से, प्लाट सं० 1660 और 1667 और 1668, 1667 और 1670, 1667 और 1666, 1667 और 1665, 1667, 1664 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं० 1663 में से प्लाट सं० 1663 और 1679, 1678 और 1679, 1678 और 1691, 1678 और 1573 की सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट सं० 1573 और 1567 में से प्लाट सं० 1567 और 1571, 1567, 1570, 1557 और 1566, 1557 और 1565, 1558 और 1559, 1531 और 1530, 1531 और 1529 की सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट सं० 1528 और 1527, 1522 और 1527 1523 और 1527, 1523 और 1527, 1524 और 1526, 1525 और 1526 सहित प्लाट सं० 1522, प्लाट सं० 825 में से प्लाट सं० 830 और 831, 836 और 839, 837 और 838 की सम्मिलित सीमा, प्लाट सं० 828, 827 और 826 का भाग सहित प्लाट सं० 840 (सड़क) की सम्मिलित सीमा' प्लाट सं० 840 (सड़क) में से, प्लाट सं० 878, 879, 733, 738 739 सहित प्लाट सं० 840 (सड़क) की सम्मिलित सीमा, प्लाट सं० 739 और 749 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ प्लाट सं 749 में से, प्लाट सं० 739 और 741 सहित प्लाट सं० 749 (सड़क) की सम्मिलित सीमा, प्लाट सं० 749 में से, प्लाट सं० 781, 780, 778, 777, 776, 775, 774, 773 और 751 सहित प्लाट सं० 749 की सम्मिलित सीमा से होकर जाती है।

लाइन गोबिन्दपुर ग्राम के सड़क प्लाट सं० 840 में से होकर तब प्लाट सं० 748 और 749, 748 और 709, 711 और 709, 710 और 709, 710 और 708, 707 और 710, 711 और 707, 704 और 707, 706 और 704, 704 और 701, 704 और 705, 703 और 701, 702 और 701 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं० 936 सड़क में से, प्लाट सं० 696 और 697, 695 और 697, 694 और 687 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ होकर जाती है।

ख—ङ लाइन गोबिन्दपुर ग्राम के प्लाट सं० 694, 693, 692, 691, 690, 683, 674 और 581 सहित प्लाट सं० 682 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं० 682, 580, 579 में से प्लाट सं० 578 और 572 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं० 571, 572 और 248 में से होकर जाती है।

ङ—च—छ—ज—झ—ञ—ट और ठ लाइन गोबिन्दपुर ग्राम के प्लाट सं० 248, 221, 220, 221 में से होकर, प्लाट सं० 231 और 248 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ होकर जाती है।

ठ—क लाइन गोबिन्दपुर ग्राम के प्लाट सं० 231 और 223 में से होकर तब प्लाट सं० 224 और 225 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं० 1 में से होकर, ग्रामों ग्राम के प्लाट सं० 758 में से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

अनुसूची "ख"

गोबिन्दपुर ब्लाक

(पूर्व बोकारो कोयला क्षेत्र)

गिरिडीह (बिहार)

ड्राइंग सं० राजस्व 7/79

तारीख 13-3-79

(जिसमें खनिजों के निष्कासन, खोदने और ले जाने के लिए खनन, खदान, बेधने, खोदने और खोजने के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)।

खान खोदने के अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	गोबिन्दपुर	नवाडीह	15	गिरिडीह	भाग	

कुल क्षेत्र 404.00 एकड़ (लगभग)
या 163.49 हेक्टेयर (लगभग)

गोबिन्दपुर ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :—

749 (भाग), 750, 751 (भाग), 752 से 824, 825 (भाग), 826, 827, 828, 829, 830, 840 (भाग), 1384 (भाग), 1388 (भाग), 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1559 से 1566, 1567 (भाग), 1573 (भाग), 1574 से 1659, 1660 (भाग), 1663 (भाग), 1664, 1665, 1866, 1668 से 1678, 1743, 1751, 1752, 1755 (भाग), 1756 से 1793, 1795 से 1828, 1863 (भाग), 1864 (भाग), 1865 से 1922, 1925 से 2416, 2417 (भाग), 2418 (भाग), 2419 (भाग), 2420, 2421, 2422, 2423 (भाग), 2424 (भाग), 2425 (भाग), 2426 से 2430, 2431 (भाग), 2433 (भाग), 2444 (भाग), 2445 (भाग), 2446 से 2451, 2452 (भाग), 2453 (भाग), 2454 (भाग), 2456 (भाग) 2457 (भाग) 2458 (भाग), 2459 (भाग) 2461 (भाग), 2533 (भाग), 2582 (भाग) 2583 (भाग), 2584, 2585, 2586 (भाग), 2587, 2588, 2589, 2590, 2592 (भाग), 2598, 2599, 2600 (भाग), 2601 से 2660, 2661 (भाग), 2662 से 2666, 2667 (भाग), 2668 (भाग), 2669, 2670 (भाग), 2671 (भाग), 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793 (भाग) और 2795।

सीमा वर्णन :

ख—ठ लाइन गोबिन्दपुर ग्राम में कुनार नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है।

ठ—ड लाइन गोबिन्दपुर ग्राम में बोकारो नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है ।

ड—ग लाइन गोबिन्दपुर ग्राम के प्लाट सं० 2661, 2671, 2661, 2670, 2668, 2667, 2600, 2793, 2592, 2600 में से होकर, प्लाट सं० 2589 और 2590 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं० 2586, 2582, 2583, 2600, 2417, 2533, 2418, 2419, 2423, 2424, 2425, 2431, 2433, 2445, 2444, 2452, 2453, 2454, 2456, 2457, 2458, 2461, 2459 (सड़क), 751 और 719 (सड़क) में से होकर जाती है ।

ग—ख लाइन सर्वाधिकार सीमा (ब्लाक "ए") के साथ-साथ जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

[सं० 19(43)/79-सी० एल०]

एम० आर० ए० रिज़वी, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 17 August, 1979

S.O. 2959 Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. 3458 dated the 15th November, 1978, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 1615.00 acres (approximately) or 653.55 hectares (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule appended to that Notification ;

And, whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said land ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire :—

(a) the land measuring 1211.00 acres (approximately) or 490.06 hectares (aproximately) described in Schedule 'A' appended hereto ; and

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the land measuring 404.00 acres (approximately) or 163.49 hectares (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto.

Note 1. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) which provides as follows :—

Objection to acquisition :—

8. "(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation :—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act".

Note 3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE 'A'

GOBINDPUR BLOCK
(EAST BOKARO COALFIELD)
GIRIDIH (BIHAR)

Drg. No. Rev/7/79
Dated 12-3-79.
(Showing lands to be acquired)

All Right

Serial number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Armo	Nawadsh	11	Giridih		Part
2.	Gobindpur	,,	15	,,		,,

Total area 1211.00 acres (approximately) or 490.06 hectares (approximately)

Plot number, to be acquired in village Armo :—758(Part).

Plot numbers to be acquired in village Gobindpur :—

1 (Part), 2 to 91, 93 to 219, 220 (Part), 221 (Part), 222 (Part), 223 (Part), 224, 231 (Part), 248 (Part), 249 to 570 571 (Part), 572 (Part), 573 to 578, 579 (Part), 580 (Part), 581 to 674, 682 (Part), 683 to 696, 700 to 702, 703, 704, 710 to 748, 749 (Part), 825 (Part), 831 to 839, 840 (Part),, 841 to 935, 936 (Part), 937 to 1383, 1384 (Part), 1385, 1386, 1387, 1388 (Part), 1389 to 1525, 1531 to 1558, 1567 (Part), 1568 to 1572, 1573 (Part), 1660 (Part), 1661, 1662, 1663 (Part), 1667, 1679 to 1742, 1744 to 1750, 1753, 1754, 1755 (Part), 1794, 1829 to 1862, 1863 (Part), 1864 (Part), 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782 & 2783.

BOUNDARY DESCRIPTION :—

A—B line passes along the left bank of River Kunar in villages Armo and Gobindpur.

B—C line passes through plot number 1384 and along the part common boundary of plot numbers 1384 & 1388, through plot number 1388 and plot number 1384 and then passes along the common boundary of plot numbers 1384 & 1765 1384 & 1764, 1426 & 1764, 1426 with plot numbers 1763, 1761, 1760 and 1756, 1445 & 1756, 1455 & 1756, through plot number 1755, common boundary with plot numbers 1755 & 1752, 1753 & 1752, 1753 & 1751, 1751 & 1750, plot number 1744 with plot numbers 1751, 1791, 1792 & 1743. Common boundary with plot numbers 1743 & 1732, plot number 1742 with plot numbers 1743, 1792, 1795, 1793 & 1794. Common boundary with plot numbers 1798 & 1833, 1798 & 1832, 1827, & 1832, 1827 & 1831, 1827 & 1830, 1828 & 1829, 1825 & 1863 through plot numbers 1863 and 1864, common boundary of plot number 1660 with plot numbers 1856, 1689, 1688, 1687, 1683, 1682, 1661, through plot number 1660, along common boundary with plot numbers 1660 1667, 1667&1668 1667&1670, 1667&1666, 1667&1665, 1667 & 1664, through plot number 1663, along common boundary with plot numbers 1663 & 1679, 1678 & 1679, 1678 & 1691, 1678 & 1573, through plot number1573 and 1567, along common boundary of plot numbers 1567 & 1571, 1567, & 1570, 1557 & 1566, 1557 & 1565, 1558 & 1559, 1531&1530, 1531&1529, Plot number 1522 with plot numbers 1528 & 1527, 1522 & 1527, 1523 & 1527, 1523 & 1527, 1524 & 1526, 1525 & 1526, through plot number 825, common boundary with plot numbers 830 & 831, 836 & 839, 837 & 838, common boundary of plot number 840 (Road) with plot numbers 828, 827, & part of 826, through plot number 840 (Road), common boundaryfof plot number 840 (Road) with plot numbers 878, 879, 733, 738, 739 along common boundary of plot numbers 739 & 749, through plot number 749, common boundary of plot number 749 (Road) with plot number 739 & 741 through plot number 749, common boundary of plot number 749 with plot numbers 781, 780, 778, 777, 776, 775, 774, 773, & 751 of village Gobindpur.

C—D line passes through Road plot Number 840, then along the common boundary of plot numbers 748, 749 & 748 709, 711 & 709, 710 & 709, 710 & 708, 707 & 710, 711 & 707, 704 & 707, 706 & 704, 704 & 701, 704 & 705, 703 & 701, 702 & 701, through plot number 936 Road, along common boundary of plot numbers 696 & 697, 695 & 697, 694 & 697 of village Gobindpur.

D—E line passes along the common boundary of plot number 682, with plot numbers 694, 693, 692, 691, 690, 683, 674 & 581, through plot numbers 682, 580 & 579, along the common boundary of plot numbers 578 & 572 through plot number, 571, 572 & 248 of village Gobindpur.

E-FG-H-I-J-K & L lines pass through plot numbers 248, 221, 220, 221 along common boundary with plot number 231 & 248 of village Gobindpur.

L—A line passes through plot numbers 231 & 223 then along the common boundary of plot numbers 224 & 225, throug plot number 1 of village Gobindpur through plot number 758 of village Armo and meets at starting point 'A'.

SCHEDULE 'B'

GOBINDPUR BLOCK

(East Bokaro Coalfield)

GIRIDIH (BIHAR)

Drg. No. Rev/7/79

Dated 12-3-79

(Showing lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work & carry away minerals are to be acquired)

Mining Rights

Serial number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Gobindpur	Nawadih	15	Giridih		Part

(Total area 404.00 acres (approximately) or 163.49 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Gobindpur :—

749 (Part),750, 751 (Part), 752 to 824, 825(Part), 826, 827, 828, 829, 830, 840 (Part), 1384 (Part), 1388 (Part), 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1559 to 1566, 1567 (Part), 1573 (Part), 1574 to 1659,1660 (Part), 1663 (Part), 1664, 1665, 1666, 1668 to 1678, 1743, 1751, 1752, 1755 (Part), 1756 to 1793, 1795 to 1828, 1863 (Part), 1864 (Part), 1865 to 1922, 1925 to 2416, 2417 (Part),2418 (Part), 2419 (Part), 2420, 2421, 2422, 2423 (Part), 2424 (Part), 2425 (Part), 2426 to 2430, 2431 (Part), 2433 (Part), 2444 (Part), 2445 (Part), 2446 to 2451, 2452 (Part), 2453 (Part), 2454 (Part), 2456 (Part), 2457 (Part), 2458 (Part), 2459 (Part), 2461 (Part), 2533 (Part), 2582 (Part), 2583 (Part) 2584, 2585, 2586 (Part), 2587, 2588, 2589, 2590, 2592 (Part), 2598, 2599, 2600 (Part), 2601 to 2660, 2661 (Part), 2662 to 2666, 2667 (Part), 2668 (Part), 2669, 2670 (Part), 2671 (Part), 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793 (Part) & 2795.

BOUNDARY DESCRIPTION :

B-M line passes along the left bank of Kunar River in village Gobindpur.

M-N line passes along the left bank of Bokaro River in village Gobindpur.

N-C line passes through plot numbers 2661, 2671, 2661, 2670 2668, 2667, 2600, 2793, 2592, 2600 along northern boundary of plot numbers 2589 & 2590 through plot number 2586, 2582, 2583, 2600, 2417, 2533, 2418, 2419, 2423 2424, 2425, 2431, 2433, 2445, 2444, 2452, 2453, 2454, 2456, 2457, 2458, 2461, 2459 (Road), 751 & 74 (Road) in village Gobindpur.

C-B line passes along the All Rights Boundary (Block 'A') and meets at starting point 'B'.

[F. No. 19(43)78-CL]

का० आ० 2960.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3554, तारीख 20 नवम्बर, 1978 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्रों की लगभग 4935 00 एकड़ या 1997 10 हेक्टेयर भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित लगभग 4100 00 एकड़ या 1659.19 हेक्टेयर भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

टिप्पण-1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण कलेक्टर मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस रांची (बिहार) के कार्यालय या कोयला नियंत्रक के 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण-2. कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंधित है ।

अर्जन की बाबत आपत्तियां :

(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता का स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते ।

टिप्पण-3 : केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची

काकरी खण्ड

(सिंगरौली कोयला क्षेत्र)

जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

रेखांकन सं० राजस्व/23/79

तारीख 23-4-1979

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	काकरी	दुद्धी	सिंगरौली	77	मिश्र (ओंरवा)	मिर्जापुर	भाग	
2.	परासी	,,	,,	,,	,,	,,	,,	
3.	रेहटा	,,	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	
4.	बांसी	,,	,,	,,	,,	,,	भाग	
5.	पंथसागर	,,	,,	,,	,,	,,	भाग	
				कुल क्षेत्र	1950 00 एकड़ (लगभग)			
				या	789.13 हेक्टेयर (लगभग)			

ग्राम काकरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

9(पी), 10(पी), 11(पी), 12(पी), 14(पी), 15(पी), 16 से 33 तक, 34(पी), 35, 36(पी), 39(पी), 41(पी), 51(पी), 53(पी), 54(पी), 55, 56(पी), 57(पी), 58(पी), 59, 60(पी), 61 से 114 तक, 115(पी), 116(पी), 117(पी), 139(पी), 140, 141, 142(पी), 143(पी), 149(पी), 151(पी), 153(पी), 156(पी), 157(पी), 158 से 163 तक, 164(पी), 165 से 348 तक, 349(पी), 350 से 614 तक ।

ग्राम परासी में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

17(पी), 859(पी), 860 से 867, 868(पी), 869(पी), 870(पी), 873(पी), 874, 875(पी), 879(पी), 880(पी), 881(पी), 882(पी), 884(पी), 885(पी), 886(पी), 887(पी), 888 से 928 तक, 929(पी), 932(पी), 933, 934, 935, 936(पी), 937 से 941 तक, 942(पी), 943(पी), 944(पी), 983(पी), 984 से 997 तक, 998(पी), 1020(पी), 1021, 1022, 1023, 1024(पी), 1025(पी), 1042(पी), 1044(पी), 1045, 1046(पी), 1047, 1048, 1049(पी), 1082(पी), 1083 से 1108 तक, 1109, 1110 और 1117 ।

ग्राम रेहटा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

1 से 356 तक

ग्राम बासी में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या

1 से 6 तक, 73(पी), 74, 75(पी), 76 से 100 तक, 220 से 277 तक, 282 से 294 तक, 326 से 332 तक, 336, 337, 345, 346, 347, 353 और 502 ।

पंथसागर में अर्जित की जाने वाली भूमि :—

पंथसागर (भाग)

सीमा विवरण

क—ख	रेखा ग्राम काकरी में प्लाट सं० 3, 6, 34, 9, 10, 11, 12, 13 से होकर जाती है ।
ख—ग	रेखा काकरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के एक भाग (जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का एक भाग है) से होकर जाती है ।
ग—घ	रेखा काकरी ग्राम में प्लाट सं० 14, 15, 349 से होकर, फिर प्लाट सं० 6 और 15, 6 और 13, 6 और 12 की भागतः सम्मिलित सीमा होकर प्लाट नं० 75, 73 से होकर जाती है और फिर प्लाट नं० 78 और 103, 80, और 102, 81 और 102, 99 और 102, 98 और 101, 100 और 101, 100 और 107, 95 और 107, 94 और 107 की भागतः सम्मिलित सीमा ; प्लाट नं० 93, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 236, 239, 241, 277, 276 के साथ प्लाट सं० 219 की सम्मिलित सीमा और पंथसागर से होकर जाती है और फिर पथसागर के प्लाट स० 278, 280, 281, प्लाट स० 281, 356 और 354 के साथ प्लाट सं० 282 से होकर प्लाट सं० 354 और 353, 353 और 352, 353 और 351, 347 और 348 और 347 और 314, 344 और 345, 346 और 344, 337 और 388, 335 और 336, 333 और 332, 333 और 331, 325 और 330, 328 और 325, 326 और 325, 326 और 323, 321 और 294, 294, और 295 की सम्मिलित सीमा से होकर जाती है और फिर पतसागर से ग्राम बासी में प्लाट सं० 295, 296, 297, 298 और 300 से होकर (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित जोगी चौरा ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा भी बनाती है) जाती है ।
घ—ङ	रेखा प्लाट सं० 301 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ पंथसागर क्षेत्र से होकर जाती है ।
ङ—च	रेखा ग्राम रेहटा और पंथसागर की भागत. सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।
च—छ	रेखा पंथ सागर से होकर गुजरती है ।
छ-ज—झ—ञ	रेखा ग्राम रेहटा और पंथसागर की भागतः सम्मिलित सीमा और पंथसागर से होकर जाती है ।
ञ—ट	रेखा पंथसागर और ग्राम परासी के प्लाट सं० 1082, 1025, 1024, 1042 और 1044 से होकर जाती है ।
ट—क	रेखा प्लाट सं० 1045 के साथ प्लाट सं० 1046, 1049, 1020, 998, 983, 942, 943, 944 और 936 से होकर, प्लाट सं० 935 और 934 की उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 932, 929, 887, 884, 886, 885, 882, 881, 880, 879, 875, 873, 870, 869, 868, 859 से होकर प्लाट सं० 860 की भागतः उत्तरी सीमा से होकर प्लाट सं० 862, 863 की उत्तरी सीमा के साथ ग्राम परासी में प्लाट सं० 17 से होकर जाती है ।

फिर ग्राम काकरी में प्लाट सं० 151, 157, 156, 153, 149, 164, 143, 142, 139, 117, 115, 116, 60, 51, 58, 57, 56, 53, 54, 41, 39 और 36 से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

अनुसूची

मराक खण्ड

(सिंगरौली कोयला क्षेत्र)

जिला मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

रेखांकन सं० राज०/24/79
तारीख 24-4-79

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	भैरवा	दुद्धी	सिंगरौली	—	मिश्रा (भैरवा)	मिर्जापुर	भाग	
2.	मिश्रा	,,	,,	101	,,	,,	,,	

क्रम सं०		तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
3.	कोहरोलिया	दुद्धी	सिंगरौली	85	मिश्रा (खैरवा)	मिर्जापुर	भाग	
4.	कोहरोल	,,	,,	84	,,	,,	,,	
5.	जोगी चौरा	,,	,,	46	,,	,,	,,	
6.	मराक	,,	,,	91	,,	,,	पूर्ण	
7.	परसवार राजा	,,	,,	—	,,	,,	भाग	
8.	खादिया	,,	,,	115	,,	,,	,,	
9.	चिलकन्दर	,,	,,	49	,,	,,	,,	

कुल क्षेत्र 2150.00 एकड़ (लगभग)
या 870.06 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम भैरवा में अंकित किए जाने वाले प्लाटों की सं० 21(पी), 22 से 141 तक ।

ग्राम मिश्रा में अंकित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 91(पी), 20 से 86 तक ।

ग्राम कोहरोलिया में अंकित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 1(पी), 3(पी), 4 से 97 तक ।

ग्राम कोहरोल में अंकित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 1(पी), 2 से 53 तक और 54 ।

ग्राम जोगी चौरा में अंकित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 1(पी), 2 से 46 तक, 47, 48 और 49 ।

ग्राम मराक में अंकित किए जाने वाले प्लाटो की संख्या 1 से 191 तक ।

ग्राम परसावर में अंकित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 3(पी), 5(पी), 6(पी), 7(पी), 8(पी), 9(पी), 10 से 134 तक ।

ग्राम खादिया में अंकित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 51(पी), 53(पी), 54(पी), 55, 56, 57(पी), 58, 59, 60(पी), 61 (पी), 84(पी) 111(पी), 116(पी), 117(पी), 118 से 125 तक, 126(पी), 127(पी), 129(पी), 134, 135, 136(पी), 137 से 147 तक, 149(पी), 151(पी), 152(पी), 153(पी), 154, 155, 156(पी), 157(पी), 158 से 275 तक, 276(पी), 278(पी), 279(पी), 280 से 283 तक 284(पी), 285(पी), 286(पी), 287(पी), 288, 289(पी), 290, 291, 292, 293(पी), 294(पी), 295(पी), 296 से 425 तक, 432, 433, 434, 438 और एक बिना नम्बर का प्लाट ग्राम चिलकन्दर में अंकित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 436(पी), 437(पी), 438 से 441 तक, 442 (पी), 443(पी), 677(पी), 679(पी), 680 से 684 तक, 685(पी), 690(पी), 691(पी), 692 से 706 तक ।

सीमा विवरण

क–ख	रेखा ग्राम भैरवा के प्लाट सं० 21 से होकर ग्राम जोगी चौरा और परसावर राजा की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ, और फिर ग्राम जोगीचौरा के प्लाट सं० 1 और ग्राम परसावर राजा में प्लाट सं० 3, 6, 5, 7, 8 से होकर, जो कोयला अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन दुद्धी चौरा ब्लाक की सम्मिलित सीमा भी बनाती है, जाती है ।
ख–ग	रेखा ग्राम परसावर राजा के प्लाट सं० 8, 9 से होकर, ग्राम खादिया के प्लाट सं० 295, 294, 293, 292, 289, 287, 286, 285, 284, 279, 278, 276, 153, 152, 156, 157, 151, 149, 53, 54, 51, 57, 60, 61, 84, 136, 137, 126, 129, 117, 116, 111 होकर और फिर ग्राम चिलकन्दर के प्लाट सं० 677, 679, 685, 690, 691, 442, 443, 437, 436 से होकर जाती है ।
ग–घ	रेखा ग्राम चिलकन्दर और कोटा की भागत: सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।
घ–ङ	रेखा ग्राम चिलकन्दर और परसावर चौबे की भागत: सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।
ङ–च	रेखा ग्राम खादिया और परसावर चौबे की भागत: सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।
च–छ–ज–झ–ञ	रेखा ग्राम खादिया और पंथसागर, परसावर राज और पंथसागर, मराक और पंथसागर, जोगीचौरा और पंथसागर भैरवा और पंथसागर, मिश्रा और पंथसागर, कोहरोल और पंथसागर तथा कोहरोलिया और पंथसागर की भागत: सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।
ञ–ट	रेखा ग्राम कोहरोलिया और धरसारी की भागत: सम्मिलित सीमा से होकर जाती है ।
ट–ठ	रेखा ग्राम कोहरालिया के प्लाट सं० 3 और 1 से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अंकित जोगी-चौरा खण्ड विस्तार की भागत: सम्मिलित सीमा भी बनाती है)
ठ–ड–ढ–ण–क	रेखा ग्राम कोहरोल के प्लाट सं० 1 से होकर, फिर ग्राम मिश्रा के प्लाट सं० 19, ग्राम भैरवा का प्लाट सं० 21 से होकर जाती है जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अंकित जोगी चौरा खण्ड की भागत: सम्मिलित सीमा भी बनाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 19(44)/78–सी०एल (ii)]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

S.O. 2960.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3554 dated the 20th November, 1978, under sub-section (i) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intension to prospect for coal in 4935.00 acres (approx.) or 1997.10 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 41.00 acres (approximately) or 1659.19 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1 : The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Collector, Mirzapur, (Uttar Pradesh), or at the Office of the Central Coalfields Ltd. (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar) or at the office of the Coal Controller, Council House Street, Calcutta.

Note 2.—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows :—

8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to under take mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority sha give the objector an apportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

Kakari Block

(Singrauli Coalfield)

Distt. Mirzapur

(Uttar Pradesh)

Drg. No. Rev/23/79 dt. 23-4-1979 (Showing lands to be acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Tahsil	Pargana	Pargana	Thana	Distt. Area	Remarks
1.	Kakari	Dudhi	Singrauli	77	Misra (Khairwa)	Mirzapur	Part
2.	Parasi	-do-	-do-	—	-do-	-do-	Part
3.	Rehata	-do-	-do-	—	-do-	-do-	Full
4.	Banshi	-do-	-do-	8	-do-	-do-	Part
5.	Panth Sagar	-do-	-do-	—	-do-	-do-	Part

Total area—1950.00 acres (approx.)
or 789.13 hectares (Approx.)

Plot numbers to be acquired in village Kakari :—

9(P), 10(P), 11(P), 12(P), 13(P), 14(P), 15(P), 16 to 33, 34(P), 35, 36(P), 39(P), 41(P), 51(P), 53(P), 54(P), 55, 56(P), 57(P), 58(P). 59, 60(P), 61 to 114, 115(P), 116(P), 117(P), 139(P), 140, 141, 142(P), 143(P), 149(P), 151(P), 153(P), 156(P), 157(P), 158 to 163, 164(P), 165 to 348, 349(P), 350 to 614.

Plot numbers to be acquired in village Parasi :—

17(P), 859(P), 860 to 867, 868(P), 869(P), 870(P), 873(P), 874, 875(P), 879(P), 880(P), 881(P), 882(P), 884(P), 885(P), 886(P), 887(P). 888 to 928, 929(P), 932(P), 933, 934, 935, 936(P), 937 to 941, 942(P), 943(P), 944(P), 983(P), 984 to 997, 998(P), 1020(P), 1021, 1022, 1023, 1024(P), 1025(P), 1042(P), 1044(P), 1045, 1046(P), 1047, 1048, 1049(P), 1082(P), 1083 to 1108, 1109, 1110 & 1117.

Plot numbers to be acquired in village Rehata :—

1 to 356.

Plot numbers to be acquired in village Banshi :—

1 to 6, 73(P), 74, 75(P), 76 to 100, 220 to 277, 282 to 294, 326 to 332 336, 337, 345, 346, 347, 353, & 502.

Land to be acquired in Panth Sagar :—

Panth Sagar (part).

Boundary Description :—

A—B line passes through plot nos. 36, 34, 9, 10, 11, 12, 13 in village Kakari.

B—C line passes along the part western boundary of village Kakari (which forms part common boundary with U.P and M.P.)

C—D line passes through plot nos. 14, 15, 349 in village Kakari again along the part common boundary of plot nos. 6 and 15, 6 and 13, 6 and 12 and 6 and 7 through plot nos. 75, 73, again passes along the part common boundary of plot nos. 78 and 103, 80 and 102, 81 and 102, 99 and 102, 98 and 101, 100 and 101, 100 and 107, 95 and 107 94 and 107, common boundary of plot no. 219 with plot nos. 93, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 236, 239, 241, 277, 276 and Panth Sagar again Panth Sagar with plot nos. 278, 280, 281. Plot no. 282 with plot nos.

281, 356 and 354 along common boundary of plot no. 354 and 353, 353 and 352, 353 and 351, 347 and 348, 347 and 344, 344 and 345, 346 and 344, 337 and 388, 335 and 336, 333 and 32, 333 and 331, 325 and 330, 328 and 325, 326 and 325, 326 and 323, 321 and 294, 294 and 295, again Panth Sagar with plot nos. 295, 296, 297 298 and 300 in village Banshi (which also forms part common boundary of Jogichowra block acquired u/s 9(1) of the Coal Act).

D—E line passes along the western boundary of plot no 301 and through Panth Sagar area.

E—F line passes along the part common boundary of village Rehata and Panth Sagar.

F—G line passes through Panth Sagar.

G—H—I—J line passes along the part common boundary of village Rehata and Panth Sagar and through Panth Sagar.

J—K line passes through panth Sagar and through plot nos. 1082, 1025, 1024, 1042 and 1044 in village Parasi.

K—A line passes along the northern boundary of plot no. 1045 through plot nos. 1046, 1049, 1020, 998, 983, 942, 943, 944 and 936 along northern boundary of plot nos. 935 and 934 through plot nos. 932, 929, 837, 884, 886, 885, 882, 881, 880, 879, 875, 873, 870, 869, 868, 859, along part norther boundary of plot no. 860 along northern boundary of plot no. 862, 863, through plot no. 17 in village Parasi.
through plot nos. 151, 157, 156, 153, 149, 164, 143, 142, 139, 117, 115, 116, 60, 51, 58, 57, 56, 53, 54, 41, 39 and 36 in village Kakari and meets at Starting point 'A'.

SCHEDULE
Marrak Block
(Singrauli Coal field)
Distt. Mirzapur
Uttar Pradesh
Drg. No. Rev/24/79 dt 24-4-79 (Showing lands to be acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Tahsil	Pargana	Pargana no.	Thana	Distt.	Area	Remarks
1.	Bhairwa	Dudhi	Singrauli	—	Misra (Khairwa)	Mirzapur		Part
2.	Mishra	-do-	-do-	101	-do-	-do-		Part
3.	Koharoulia	-do-	-do-	85	-do-	-do-		Part
4.	Koharoul	-do-	-do-	84	-do-	-do-		Part
5.	Jogichoura	-do-	-do-	46	-do-	-do-		Part
6.	Marrak	-do-	-do-	91	-do-	-do-		Full
7.	Paraswar Raja	-do-	-do-	—	-do-	-do-		Part
8.	Khadia	-do-	-do-	115	-do-	-do-		Part
9.	Chilkadanr	-do-	-do-	49	-do-	-do-		Part

Total area ~2150.00 acres (approx).
or 870.06 hec (approx.)

Plot nos. to be acquired in village Bhairwa :—
21(P), 22 to 141.

Plot nos. to be acquired in village Mishra :—
19(P), 20 to 86.

Plot no. to be acquired in village Kaharoulia :—
1(P), 3(P), 4 to 97.

Plot nos. to be acquired in village Koharoul :—
1(P), 2 to 53, & 54.

Plot nos. to be acquired in village Jogichoura :
1(P), 2 to 46, 47, 48 & 49.

Plot nos. to be acquired in village Marrak :—
1 to 191

Plot nos. to be acquired in village Paraswar Raja :—
3(P), 5(P), 6(P), 7(P), 8(P), 9(P), 10 to 134

Plot nos. to be acquired in village Khadia :

51(P), 53(P), 54(P), 55, 56, 57(P), 58(P), 59, 60(P), 61(P), 84(P), 111(P), 116(P), 117(P), 118(P) to 125, 126(P), 127(P), 129(P), 134, 135, 136(P), 137 to 147, 149(P), 151(P), 152(P), 153(P), 154, 155, 156(P), 157(P), 158 to 275, 276(P), 278(P), 279(P), 280 to 283, 284(P), 285(P), 286(P), 287(P), 288, 289(P), 290, 291, 292(P), 293(P), 294(P), 295(P), 296 to 425, 432, 433, 434, 438 and one un-numbered plot.

Plot nos. to be acquired in village Chilkadanr :

436(P), 437(P), 438 to 441, 442(P), 443(P), 677(P), 679(P), 680 to 684, 685(P), 690(P), 691(P), 692 to 706.

Boundary Description : -

A—B line passes through plot no. 21 in village Bhairwa. along the part common boundary of village Jogichoura and Paraswar Raja, then through plot no. 1 in village Jogichoura through plot nos. 3, 6, 5, 7, 8 in village Paraswar Raja which is also forms common boundary of Dudhichua block u/s 4 (1) of the Coal Act.

B—C	line passes through plot nos. 8, 9 in village Paraswar Raja through plot nos. 295, 294, 293, 292, 289, 287, 286, 285, 284, 279, 278, 276, 153, 152, 156, 157, 151, 149, 53, 54, 51, 57, 60, 61, 84, 136, 137, 125, 129, 117, 116, 111 in village Khadia, then through plot nos. 677, 679, 685, 690, 691, 442, 443, 437, 436 in village Chilkadanr.
C—D	line passes along the part common boundary of village Chilkadanr and Kota.
D—E	ine passes along the part common boundary of village Chilkadanr and Paraswar Chaube.
E—F	line passes along the part common boundary of Village Khadia and Paraswar Chaube.
F—G—H—I—J	line pass along the part common boundary of village Khadia and Panth Sagar Paraswar Raja and Panth Sagar Marrak and Panth Sagar Jogichoura and Panth Sagar Bhairwa and Panth Sagar Mishra and Panth Sagar, Koharoul and Panth Sagar and Koharoulia and Panth Sagar.
J—K	line passes along the part common boundary of villages Koharoulia and Dharsari.
K—L	line passes through plot nos. 3 and 1 in village Koharoulia (which is also part commonl boundary of Jogichoura block extn. acquired u/s 9(1) of the Coal Act)
L—M—N—A	line passes through plot nos. 1 in village Koharoul then through plot no. 19 in village Mishra, through plot no. 21 in village Bhairwa which is also part common boundary of Jogichowra block acquiredu/s 9(1) of the Coal Act and meets at starting point 'A'.

[F. No. 19(44)/78-CL(ii)]
S.R.A. RIZVI, Director

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1979

का० आ० 2961—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), (नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 634-क तारीख 28 फरवरी, 1957 में निम्नांकित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

(1) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 से संबंधित भाग 2 में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड "उपशीर्षक के नीचे प्रविष्टि (7) के पश्चात् प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5
इंजीनियरिंग खण्ड (तकनीकी)				
सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक नहीं है।	अधीक्षक इंजीनियर	अधीक्षक इंजीनियर	सभी	मुख्य इंजीनियर
सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक है।	मुख्य इंजीनियर	मुख्य इंजीनियर	सभी	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड
भूजल विज्ञान खण्ड (तकनीकी/वैज्ञानिक)				
सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक नहीं है।	निदेशक (मुख्यालय)	निदेशक (मुख्यालय)	सभी	मुख्य भूजल विज्ञानी
सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक है।	मुख्य भूजल विज्ञानी	मुख्य भूजल विज्ञानी	सभी	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड
अनुसचिवीय खण्ड				
सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक नहीं है।	निदेशक (मुख्यालय)	निदेशक (मुख्यालय)	सभी	मुख्य भूजल विज्ञानी
सभी पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 640 रु० से अधिक है।	मुख्य भूजल विज्ञानी	मुख्य भूजल विज्ञानी	सभी	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड

(2) साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 से संबंधित भाग 3 में "केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड" उपशीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

इंजीनियरी खण्ड (तकनीकी)				
सभी पद	अधीक्षण इंजीनियर	अधीक्षण इंजीनियर	सभी	मुख्य इंजीनियर
भूजल विज्ञान खण्ड तकनीकी/वैज्ञानिक				
सभी पद	निदेशक (मुख्यालय)	निदेशक (मुख्यालय)	सभी	मुख्य भूजल विज्ञानी
अनुसचिवीय खण्ड				
सभी पद	निदेशक (मुख्यालय)	निदेशक (मुख्यालय)	सभी	मुख्य भूजल विज्ञानी

[सं० 25-2/77—एम० आई० (ए)]
के० एम० चड्ढा, उपसचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

New Delhi, the 19th April, 1979

ORDER

(Department of Agriculture)

S. O. 2961.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of the rule 9, clause (b) of the sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (1) of the rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, No. SRO. 634-A, dated the 28th February, 1957, namely :—

(i) In the Schedule to the said notification, in Part II, relating to General Central Service, Class III, under the sub-heading "Central Ground Water Board", after the entry (vii), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"Engineering Wing (Technical) :				
All posts having a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs. 640.	Superintending Engineer	Superintending Engineer	All	Chief Engineer
All posts having a scale of pay, the maximum of which exceeds Rs. 640.	Chief Engineer	Chief Engineer	All	Chairman, Central Ground Water Board
Hydrogeological Wing (Technical/Scientific) :				
All posts having a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs. 640.	Director (Headquarters)	Director (Headquarters)	All	Chief Hydrogeologist.
All posts having a scale of pay, the maximum of which exceeds Rs. 640	Chief Hydrogeologist	Chief Hydrogeologist	All	Chairman, Central Ground Water Board.
Ministerial Wing :				
All posts having a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs. 640.	Director (Headquarters)	Director (Headquarter)	All	Chief Hydrogeologist
All posts having a scale of pay, the maximum of which exceeds Rs. 640.	Chief Hydrogeologist	Chief Hydrogeologist	All	Chairman, Central Ground Water Board

(ii) In Part III, relating to General Central Service, Class IV, under the sub-heading "Central round Water Board" for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Engineering Wing (Technical) :				
All posts	Superintending Engineer	Superintending Engineer	All	Chief Engineer
Hydrological Wing : (Technical/Scientific)				
All posts	Director (Headquarters)	Director (Headquarters)	All	Chief Hydrogeologist
Ministerial Wing :				
All posts	Director (Headquarters)	Director (Headquarters)	All	Chief Hydrogeologist."

[No. 25-22/77-MI(A)]

K. M. CHADHA, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1979

का०आ० 2962—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की स० 61) की धारा 52 की उपधारा (1) जिसे इसी अधिनियम की धारा 46 एवं धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पढ़ा जाये, के अन्तर्गत उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली विकास प्राधिकरण निदेश देता है कि इसके कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ ऋण प्रदान करने, अग्रिम देने के अनुबन्ध करने और सभी अनुमतियों, आदेशों, निर्णयों, सूचनाओं और प्राधिकरण के अन्य कागजातों को प्राधिकृत करने से सम्बन्धित शक्तियों का प्रयोग इसके निदेशक (कार्मिक) द्वारा भी किया जाये ।

[स० एफ० 1(1)/79-कार्डी/44-1979]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 13th August, 1979

S.O. 2962.—In exercist of the powers vested in it under sub-section (1) of section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), read with sub-section (2) of section 3 and section 46 ibid, the Delhi Development Authority hereby directs its power to contract with its employees/officers in connection with the grant of loans, advances and to authenticate all permissions, orders, decisions, notices and other documents of the Authority may also be exercised by its Director (Personnel).

[No. F. 1(1)/79-Coordn./44-1979]

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1979

सार्वजनिक सूचना

का. आ. २९६३—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/जोन-डी-१ (कनाट प्लेस तथा इसके विस्तार) के क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के ३० दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ५वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली, के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें ।

संशोधन

"लगभग 1.821 है. (4.5 एकड़) का क्षेत्र जो कनाट प्लेस (आन्तरिक सर्किल रोड), रेडियल रोड सं.-8, कनाट सर्किल रोड (बाहरी सर्किल) तथा रेडियल रोड सं.-1 द्वारा घिरा हुआ है, इसे अब "मनोरंजन" से "व्यवसायिक" (भूमिगत शापिंग सैंटर) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

2. शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि.वि.प्रा. कार्यालय, (मुख्य योजना अनुभाग) 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा।

[सं.-एफ 20(11)/77-एम.पी.]

हरी राम गोयल, सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st September, 1979

S.O. 2963.—In following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan for Zone D-1 (Connaught Place & its Extension), is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within 30 days from the date of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and full address :

MODIFICATION

"The land use of an area measuring about 1.821 hect. (4.5 acres), bounded by Connaught Place (Inner Circle Road, Radial Road No. 8 Connaught Circus Road (Outer Circle) and radial road No. 1, is proposed to be changed from 'Recreational' to 'Commercial' (underground shopping centre)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, (Master Plan Section), 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(11)/77-MP]

H. R. GOEL, Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1979

का०आ० 2964.—केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 के नियम 4(ख) के अनुसरण में, की गई पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों की 1 मार्च, 1977 के दिन की अधिकृत स्थायी संख्या नियत करती है :—

ग्रेड	अधिकृत स्थायी संख्या	
प्रथम श्रेणी		
चयन ग्रेड	—	
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड		
(सीनियर स्केल)	5	
(जूनियर स्केल)	7	
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	25	
ग्रेड 1	135	
ग्रेड 2	75	137
प्रथम श्रेणी के पदों के 10 प्रतिशत के हिसाब से छुट्टी रिजर्व जोड़	25	
द्वितीय श्रेणी के पदों के 15 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व जोड़	37	
द्वितीय श्रेणी		
ग्रेड 3	276	
ग्रेड 4	255	334
द्वितीय श्रेणी के पदों के 10 प्रतिशत के हिसाब से छुट्टी रिजर्व जोड़	53	
द्वितीय श्रेणी के पदों के 5 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व जोड़	26	
कुल संख्या	919	

2. केन्द्रीय सूचना सेवा की 1 मार्च के दिन की कुल अधिकृत स्थायी संख्या 919 नियत की गई है।

[फाइल संख्या ए० 11011/6/77-सी आई एस]

एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 17th August, 1979

S.O. 2964.—In pursuance of rule 4(b) of the Central Information Service Rules, 1959 the Central Government as the result of the review undertaken, hereby fixes the authorised permanent strength of the following grades of the Central Information Service as on the March 1, 1977.

Grade	Authorised Permanent Strength	
Class-I	—	
Selection Grade		
Senior Administrative Grade		
(Senior Scale)	5	
(Junior Scale)	7	
Junior Administrative Grade	25	
Grade-I	135	
Grade-II	75	137
Add leave reserve @ 10% of class I posts	25	
Add deputation reserve @ 15% of class I posts	37	
Class-II		
Grade-III	276	
Grade-IV	255	334
Add leave reserve @ 10% of class-II posts	53	
Add deputation reserve @ 5% of class-II posts	26	
Total Strength	919	

2. The total authroised permanent strength of the Central Information Service has been fixed at 919 as on the 1st March 1977.

[F. NO A-11011/6/77-CIS]

M. L. TANDON, Under Secy.

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली 16 अगस्त, 1979

का०आ० 2965—जबकि पाण्डिचेरी टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(iii)(ख) में अपेक्षित है, पाण्डिचेरी में परिचालित होने वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव समाचार-पत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मांगें गए थे, जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता था ।

और जबकि उक्त सूचना दैनिक "थांथी" में दिनांक 8-8-78 को, और दैनिक 'न्यू टाइम्स आब्जरवर' में दिनांक 7-8-78 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ।

और जबकि उक्त सूचना के उत्तर में जो साधारण से मिली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(iii)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में महानिदेशक डाक-तार एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि तारीख 1-9-1979 से पाण्डिचेरी का परिवर्तित स्थानीय क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

पाण्डिचेरी टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

पाण्डिचेरी का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि पाण्डिचेरी नगर निगम के अन्तर्गत पड़ता है, जैसा कि अधिसूचना की तिथि को विद्यमान था किन्तु टेलीफोन प्रयोगकर्ता जो कि पाण्डिचेरी नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित है, किन्तु जिन्हें पाण्डिचेरी टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्रदान होती है, वे इस प्रणाली के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस प्रणाली से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे ।

[सं० 3-13/76-पी एच बी]

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 16th August, 1979

S.O. 2965.—Whereas a public notice for revising the local area of Pondicherry Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Pondicherry, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 8-8-78 in Daily "Thanthi" and on 7-8-78 in Delhi "New Times Observer".

And whereas objections and suggestions received from the public on the said notice have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegrahs herebpy declares that with effect from 1-9-1979 the revised local area of Pondicherry shall be as under ;

Pondicherry Telephone Exchange System

The local area of Pondicherry shall cover an area falling under the jurisdiction of Pondicherry Municipality ; as existing on the date of Notification Provided that the telephone subscribers located outside Pondicherry Municipal limits but who are served from Pondicherry Telephone Exchange system shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 KM from any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-13/76-PHB]

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1979

का०आ० 2966.—जबकि भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434(iii)(ख) के अनुसार बेलगाम टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन करने के लिए बेलगाम में प्रचलित समाचार-पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवाया गया था जिसमें प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से नोटिस के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे । और जबकि उक्त नोटिस तारीख 13-3-79 को कन्नड़ दैनिक "संयुक्त कर्नाटक" तथा तारीख 20-2-79 को कन्नड़ दैनिक "कन्नडम्मा" के द्वारा जनता के ध्यान में लाया गया था ।

और जबकि उक्त नोटिस के उत्तर में कोई सुझाव या आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है अतः अब उक्त नियमों के नियम 434(iii)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महानिदेशक यह घोषणा करते हैं कि तारीख 1-9-79 से बेलगाम का संशोधित क्षेत्र निम्न प्रकार होगा —

बेलगाम टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

बेलगाम टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत बेलगाम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके शामिल होंगे जैसा कि अधिसूचना की तिथि को विद्यमान था बशर्ते कि बेलगाम नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित टेलीफोन उपभोक्ता तब तक शुल्क देते रहेंगे जब तक कि वे इस टेलीफोन प्रणाली के किसी एक्सचेंज के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और इसके साथ जुड़े रहते हैं।

[सं० 3-5/77-पी एच बी]

New Delhi, the 17th August, 1979

S.O. 2966.—Whereas a public notice for revising the local area of Belgaum Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Belgaum, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 13-3-79 in Kannada Daily "Samyukta Karnataka" and on 20-2-79 in Kannada Daily "Kannadamma".

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-9-79 the revised local area of Belgaum shall be as under ;

Belgaum Telephone Echange System

The local area of Belgaum Telephone Exchange System shall cover an area falling under the jurisdiction of Belgaum Municipal Corporation as existing on the date of notification provided further that the telephone subscribers located outside Belgaum Municipal Corporation will continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 KMs of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-5/77-PHB]

का०आ० 2967.—जबकि भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434(iii)(ख) के अनुसार भिमुलीपत्तनम के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन करने के लिए भिमुलीपत्तनम में प्रचलित समाचार-पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवाया गया था जिसमें प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से नोटिस के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे ।

और जबकि उक्त नोटिस 29-5-78 को "इण्डियन एक्सप्रेस" के विजयवाड़ा संस्करण तथा तेलुगु दैनिक "एनेड" के द्वारा जनता के ध्यान में लाया गया था ।

और जबकि उक्त नोटिस के उत्तर मे कोई सुझाव या आपत्तिया प्राप्त नही हुई है,

अत: अब, उक्त नियमो के नियम 434(iii)(खख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महानिदेशक घोषणा करते है कि चित्तवलासा भिमुनोपत्तनम टेलीफोन एक्सचेज प्रणाली के बन्द होने की तारीख से भिमुनोपत्तनम का संशोधित स्थानीय क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :—

भिमुनोपत्तनम के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत भिमुनापत्तनम पालिका के अधिकार क्षेत्र मे पडने वाले इलाके शामिल रहेंगे जैसा कि अधिसूचना की तिथि को विद्यमान था बशर्ते कि भिमुनोपत्तनम पालिका की सीमा से बाहर के टेलीफोन उपभोक्ता, लेकिन जो भिमुनोपत्तनम टेलीफोन प्रणाली से लाभ उठाते है, तब तक शुल्क देते रहेंगे जब तक कि वे इस टेलीफोन प्रणाली के किसी एक्सचेज के 5 कि०मी० के दायरे में स्थित है तथा इससे जुड़े हुए है ।

[सं० 3-2/76-पी एच बी]

S.O. 2967.—Whereas a public notice for revising the local area of Bhiminipatnam Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Bhimunipatnam, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 29-5-78 in 'The Indian Express" Vijayawada Edition and on 29-5-78 in Daily "Eenadu".

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declared that with effect from the date of closure of Chittiwalasa exchange the revised local area of Bhimunipatnam shall be as under ;

Bhimunipatnam Telephone Exchange System

The local area of Bhimunipatnam shall cover an area falling under the jurisdiction of Bhimunipatnam Municipality as existing on the date of Notification provided that the the Telephone Subscribers located outside Bhimunipatnam Municipal limits but who are served from Bhimunipatnam Telephone System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 KMs of any Exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-2/76-PHB]

का०आ० 2968.—जबकि राजकोट टेलीफोन एक्सचेज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र मे परिवर्तन लाने के लिए एक सार्वजनिक सूचना, जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(iii)(खख) में अपेक्षित है, राजकोट में परिचालित होने वाले समाचार-पत्रों मे प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियो से आपत्तियां और सुझाव समाचार-पत्रो में सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे, जिन पर इनका प्रभाव पड़ सकता था ।

और जबकि उक्त सूचना दैनिक "फूलछाब" मे दिनाक 23-8-78 को दैनिक "जय हिन्द" में 23-8-78 को, दैनिक "लोकमान्य" में 23-8-78 को और दैनिक "वैस्टर्न टाइम्स" में 23-8-78 को उपलब्ध करा दी गई थी ।

और जबकि उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से मिली आपत्तियो और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(iii)(खख) द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अनुपालन में महानिदेशक, डाक-तार एतद्द्वारा घोषित करते है कि तारीख 1-9-79 से राजकोट का परिवर्तित स्थानीय क्षेत्र इस प्रकार होगा —

राजकोट टेलीफोन एक्सचेज प्रणाली

राजकोट का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि राजकोट नगर निगम के अन्तर्गत पड़ता है, जैसा कि अधिसूचना की तिथि को विद्यमान था किन्तु टेलीफोन उपभोक्ता जो कि राजकोट नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित है, किन्तु जिन्हे राजकोट टेलीफोन एक्सचेज प्रणाली से सेवा प्रदान होती है, वे इस प्रणाली के किसी भी एक्सचेज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस प्रणाली से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे ।

[स० 3-4/78-पी एच बी]

एम० बी० रामामूर्ति, निदेशक

S.O. 2968.—Whereas a public notice for revising the local area of RAJKOT Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Rajkot, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 27-8-78 in Daily "Phulchhab", on 23-8-78 in Daily "Jansatta", on 23-8-78 in Daily "Jai Hind", on 23-8-78 in Daily "Lokmaniya" and on 23-8-78 in Daily "Western Times".

And whereas objections and suggestions received from the public on the said notice have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-9-1979 the revised local area of Rajkot shall be as under ;

Rajkot—Telephone Exchange System

The local area of Rajkot Telephone Exchange System shall cover an area falling under the jurisdiction of Rajkot Municipality as existing on the date of notification provided that the Telephone Subscribers located outside Rajkot Municipality limit but who are served from Rajkot Telephone System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 KMs of any Exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-4/78-PHB]

M. B. RAMAMURTHY, Director

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1979

का०आ० 2969—केन्द्रीय सरकार, रेल यात्री सीमाकर अधिनियम, 1956 (1956 का 69) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट स्थानों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 22 अगस्त, 1979 से 10 सितम्बर, 1979 तक की (जिसमे ये दोनो तारीखें भी सम्मिलित है) अवधि के लिए "अधिसूचित स्थान" घोषित करती है ।

2. यह अधिसूचना 22 अगस्त, 1979 से प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

(1) कोव्वुर
(2) गोदावरी
(3) राजमुन्द्री

[सं० एफ० (एक्स) 1-79/5/4/1]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 21st August, 1979

S.O. 2969.—In pursuance of Clause (6) of Section 2 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956), the Central Government hereby declares the places specified in the Schedule annexed here to be "notified places" for the purposes of the said Act for the period from the 22nd August, 1979 to the 10th September, 1979 (both days inclusive).

2. This notification shall come into force with effect from 22nd August, 1979.

SCHEDULE

(1) KOVVUR.
(2) GODAVARI,
(3) RAJAHMUNDRY.

[No. F(X)I-79/5/4/1]

का० आ० 2970—केन्द्रीय सरकार, रेल यात्री सीमा कर अधिनियम, 1956 (1956 का 69) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :—

(क) इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट दरों को उन दरों के रूप में नियत करती है, जिन पर उक्त अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट अधिसूचित स्थानों से 22 अगस्त, 1979 से 10 सितम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान रेल द्वारा ले जाए जाने वाले सभी यात्रियों पर, प्रत्येक रेल टिकट (चाहे एक ओर का हो या वापसी) की बाबत सीमा कर उद्गृहीत किया जाएगा, और

(ख) निदेश देती है कि पूर्वोक्त सीमा कर 22 अगस्त, 1979 से उद्गृहणीय होगा ।

2. यह अधिसूचना 22 अगस्त, 1979 को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

अधिसूचित स्थानों के नाम	दर्जा	एक ओर के प्रत्येक टिकट पर सीमा कर की दरें							
		वयस्क				5 से 12 वर्ष तक के बच्चे			
		थोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए		लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए		थोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए		लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए	
		66 कि०मी० से 242 कि०मी० तक		242 कि०मी० से आगे		66 कि० मी० से 242 कि०मी० तक		242 कि०मी० से आगे	
		रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
(1) कोव्वुर	वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित 2 टियर शयनिका	1	40	1	50	0	70	0	75
(2) गोदावरी	द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कुर्सी कार	0	90	1	00	0	45	0	50
(3) राजमुन्द्री	द्वितीय श्रेणी	0	40	0	50	0	20	0	25

स्पष्टीकरण : वापसी टिकट पर सीमाकर इसमें नियत दरों के अनुसार होगा ।

[सं० एफ (एक्स) 1-79/5/4/2]

के० एन० नारायणस्वामी, संयुक्त सचिव

S.O. 2970.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of the Terminal Tax on Railway passengers Act, 1956 (69 of 1956), the Central Government hereby :—

(a) fixes the rates as mentioned in column II of the Schedule annexed hereto as the rates, at which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket (whether single or return) on all passengers carried by railway from notified places specified in column I of the said Schedule, for the period from 22nd August, 1979 to the 10th September, 1979 (both days inclusive); and

(b) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the 22nd August, 1979.

2. This notification shall come into force on the 22nd August, 1979.

SCHEDULE

I		II			
S.No.	Names of Notified Places.	Class of accommodation	Rates of terminal tax per single ticket.			
			Adults		Children between 5and 12 years age	
			Short distance passengers (66-242 Kms)	Long distance passengers (beyond 242 Kms)	Short distance passengers (66-242Kms)	Long distance passengers (beyond 242Km)
			Rs.P	Rs.P	Rs. P	Rs.P
(1) KOVVUR (2) GODAVARI (3) RAJAHMUNDRY		A.C.C/IST Class/ A C. 2-Tier Sleeper.	1.40	1 50	0 70	0.75
		II A.C. Chair Car	0.90	1.00	0.45	0 50
		II Class.	0 40	0.50	0 20	0.25
		Explanation : The Terminal Tax on a return ticket shall be the same as fixed herein.				

[No F (X) I-79/5/4/II]

K.N. NARAYANASWAMY Jt. Secy

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1979

का०आ० 2971.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में उप-सचिव के रूप में कार्य कर रहे, श्री बी० बी० शर्मा को, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संयुक्त मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, तत्काल प्रभाव से उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 6(21)/77-एस० एस०-1]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 8th August, 1979

S.O. 2971.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoists Shri B. B. Sharma, Deputy Secretary in the Department of Rehabilitation as Joint Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Joint Chief Settlement Commissioner by or under the Said Act with immediate effect.

[No. 6(21)/77-SS.I.]

का०आ० 2972.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 33 के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पुनर्वास विभाग के उप सचिव श्री बी० बी० शर्मा द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा ।

2. इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से इस विभाग की अधिसूचना संख्या 6(21)/77-एस०एस०-1 दिनांक 11 जनवरी, 1979 प्रभावी नहीं रहेगी

[सं० 6(21)/77-एस० एस०-1(i)]

मोहन लाल मैदिरत्ता, अवर सचिव

S.O. 2972.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that the powers exerciseable by it under Sub-section (4) of Section 24 and Section 33 of the said Act shall be exerciseable also by Shri B. B. Sharma, Deputy Secretary in the Department of Rehabilitation.

2. This Department's Notification No. 6(21)/77-SS I dated the 11th January, 1979, will cease to be effective with effect from the date of issue of this notification.

[No. 6(21)/77-SS.I.(I)]

S. L. MEDIRATTA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 10th August, 1979

S.O. 2973.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employer in relation to the management of North Jambad Unit of Bahula Colliery, Bahula Sub-Area of Coal Mines Authority Limited, District Burdwan and their workmen which was received by the Central Government on 8th August, 1979.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 4 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the Management of North Jambad Unit of Bahula Colliery, Bahula Sub-Area.

AND

Their Workmen

APPEARANCES

On behalf of Employers

Shri N. Das, Advocate, with Shri M P. Roy, Sr. Personnel Officer

On behalf of Workmen

Shri B E Azad, General Secretary of the Union.

State West Bengal Industry: Coal Mine

AWARD

By Order No L-19012/45 75-D III (B)/D IV(B) dated 24th February, 1977, the Government of India, Ministry of Labour referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of North Jambad Unit of Bahula, Colliery Bahula Sub-Area and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads:

"Whether the action of the management of North Jambad Unit of Bahula Colliery of Coal Mines Authority Limited (Now Eastern Coalfields Limited) Post Office Bahula, District Burdwan, in stopping from work the workmen whose names and designations are mentioned in the schedule attached hereto with effect from 5-4-74 is justified ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?

1. Narayan Ch. Gorai, Mason Supervisor.
2. Bhoga Bouri, Mason Mazdoor
3. Samulla Mia, Mason Mazdoor
4 Ramabatar Prasad, Mason Supervisor
5 Gola Martuna, Mason
6 Jagannath Singh, Mason
7. Narain Turi, Mason
8. Rabi Majhi, Mason Mazdoor
9. Brihaspati Bhuia, Mason Mazdoor,
10 Mangla Bouri, Mason Mazdoor"

2. The case of the workmen as pleaded by the Union may be indicated. It is contended that the concerned workmen are employees of North Jambad Unit, Bahula Colliery. Narayan Ch Gorai, one of the concerned workmen and 19 other Mason-Supervisors, Masons and Mason Mazdoors are employees of the principal employer, that is to say, the management of the colliery, and they received their wages and other benefits from the principal employer. As Ramabatar Prasad, another concerned workman and the aforesaid Narayan Ch Gorai had received their wages, bonus etc. from the management, they are employees under the management of the colliery and are not independent contractors They were stopped from working with effect from 5th April, 1974 The workmen approached the management and demanded employment with effect from the date of stoppage of work and claimed full wages for the period of unemployment The management failed and neglected to employ them.

3 In their written statement, the management stated that the Union lacks representative capacity and is therefore not competent to espouse the cause of the concerned workmen. The Tribunal, it has been submitted, has therefore no jurisdiction to entertain the dispute under the Reference In paragraph 3 of the written statement field on behalf of the management, it is pleaded that the concerned workmen, not having been persons appointed or employed by the employers the alleged dispute in relation to them is not an industrial dispute The objection on the ground of non-representative character of the Union was not pressed at the hearing.

4 Without prejudice to the aforesaid contention, the management stated that the erstwhile management in relation to the North Jambad Unit which functioned as an independent colliery, prior to the take over of the mine by the Central Government, in the name of North Jambad colliery, had no mason mazdoor or mason in their rolls and all masonry work in the colliery was being done by mason contractors Sri Narayan Ch. Gorai and Sri Ramabatar Prasad by engaging casual mason mazdoors recruited by them whenever such contracts were given to them After take over of the North Jambad colliery the said contractors were given contract jobs whenever required and they use to execute the said contracts by employing casual employees under them. The said contractors had different sets of casual employees to work as masons and mazdoors Later the management employed 13 such casual employees of the aforesaid contractors as casual piece-rated workers to do necessary jobs. The management submitted in their pleadings that those 18 persons who have been employed as casual workers have been working as piece-rated casual mason mazdoors and there is no vacancy for further employment of others.

5 It is also pleaded that Narayan Ch. Gorai and Ramabatar Prasad never worked as mason supervisors. Having been contractors themselves, the dispute as regards them is not maintainable in law. One of them Narayan Ch. Gorai even after 5-4-74 undertook contract work from the company in some other collieries. Out of the remaining 8 persons the persons named in Sl Nos. 2 and 3 named in the Schedule to the order of reference, namely Bhoga Bouri and Samulla Mia were employees of Narayan Ch. Gorai, Mason contractor and the remaining six were employees of the contractor Ramabatar Prasad.

6. In paragraph 15 of the written statement it is stated that to eliminate mal-practices in the matter of payment of dues of the employees of contractors, such payments were at times made to the contractors' employees in the presence of the Company's representaives as per payment sheets prepared on the basis of the quantum of work. It is categorically denied that the persons named in the order of reference were or are employees of the North Jambad Unit of Bahula Colliery. They were never appointed by the management.

7. On a consideration of the pleadings the question arises whether Narayan Ch. Gorai and Ramabatar Prasad were independent contractors or direct employees under the management and whether others were employees under the aforesaid contractors or direct employees under the management. The management contends that as none of the concerned workmen were their employees, they are under no obligation to employ any workmen.

8. Ramabatar Prasad deposed at the hearing of the reference. He said he was working as mason supervisor and mason from 1972 in North Jambad colliery along with 21 mason mazdoors and kamins . Out of those, nine have been retained in service by the colliery and the rest have been denied employment since 5th April, 1974. His case was that he was getting Rs 60 per week One Hari Babu ussed to make the payment. He also received bonus for the year 1973 All those payments were recorded in one wage sheet. He claimed that he was not a contractor but a workman under the management. He was illiterate and could not sign his name He could only subscribe his thumb impression. There are 600 workmen working in North Jambad colliery out of which 200 are members of the Khan Shramik Congress In cross-examination he said that he was not given any letter of appointment by the erstwhile owners. Prior to his appointment in the colliery he was working as a mason in the colliery on daily wages. When he started working in 1972 his hazria was at the rate of Rs 6 to Rs. 7 per day. The management also paid him Puja bonus. During private management, he got Puja bonus once. Twentyone persons worked with him all these years Whenever necessary he worked with all the twentyone persons. The colliery Manager used to direct what work he had to do. The actual place of work was shown to him by the Surveyor Sri A N. Chakravorty He had never seen Mr Chakravorty taking measurements He said he never received any identity card. Identity cards were issued for the first time in 1975. Narayan Ch. Gorai did exactly the same work as he did. The people who worked with him did not work with Narayan Ch. Gorai. Among the concerned workmen, Jagannath Singh, Narain Turi, Golam Murtaza, Rabi Majhi, Brihaspati Bhuia and Mangla Bouri were in his group. Bhoga Bouri and Samulla Mia were working with Narayan He said he never made any application to the management in writing in connection

with this matter. He did not know whether Narayan Gorai is literate or not. He was never granted leave nor did he ever apply for leave. His weekly earning was Rs. 62. He did not know whether any Provident Fund contribution was deducted from his wages nor did he know whether he had made any Provident Fund contribution. He worked in the pits. Those who go underground have to enter their names in the C Form register. He denied that he was a contractor of the colliery and claimed that he was an employee. He did not prepare wage sheet for payment to his employees who were masons, mazdoors and kamins. He denied that the signature on the wage sheet purported to be put by him were his. He also denied that he prepared bills and received payments in respect of jobs done by him as a contractor. When the question was asked he said that people who have been absorbed were not formerly employed by contractors. They were all direct employees of the colliery all along He deposed that all the ten concerned workmen were employees of the colliery. They were not contractor's employees.

9. One Parmatha Nath Acharjee, Office Secretary of the concerned union gave evidence. He deposed that the Union has 200 members at North Jambad colliery. He know Narayan Ch. Gorai and Ramabatar Prasad. They were members of the concerned union from 1972. They along with other workmen came to him with their grievance on account of stoppage of work. He drafted a letter on their behalf. He read over and explained the letter and then Narayan Ch. Gorai and Ramabatar Prasad put their thumb impressions on the letter.

10. The letter has been made Ext. W-1. By this letter, the General Secretary of the Union contended that 20 workmen including the concerned workmen were all employees of the colliery and the management had unjustly stopped them from working. The Manager was therefore requested to consider the matter and allow the workmen to resume their work. The letter, he said, was drafted and typed by him. By letters dated 28th November, 1974, Ext. W-2 and W-2(a) the same request was made by some of the concerned workmen. The officer deposed that the description of Narayan Gorai and Ramabatar Prasad as mason supervisor was given at the instance of those persons themselves. He said that Ramabatar and Narayan Gorai signed on membership receipts. In re-examination he added that by signatures he meant thumb impressions. Then in cross-examination he said that there are both signatures and thumb impressions on the receipts given by members.

11. Narayan Gorai gave evidence at the trial. Bhoga Bauri and Samullah Mia, two of the concerned workmen, he said, were working with him. Out of eighteen persons working as masons nine were stopped from working and the rest were allowed to continue in their work. He claimed that he was illiterate. He said he worked as mason and also supervised the work of other workers underground. He was getting weekly wages of Rs. 60 to Rs. 70. Hari Babu, the Cashier, used to pay the wages. He received quarterly bonus twice in the year 1973. He was not a contractor, he was a workman. He never received any letter of appointment. Before nationalisation, the system of issue of letters of appointment did not exist. The persons who were working were Muktipada Gorai, Rabi Pada Seal, Mongal Das, Raju Kora, Fatik Bauri, Bhagirath Bauri and Arun Bauri. All the 18 workmen used to be paid their wages by one paysheet. He said he was getting a commissnon of 10 percent of the total amount of remuneration of workers working under his supervision for supervising the job of the workers. He was also a worker himself. In cross-examination he said that he used to draw his dues against receipts on which he affixed his thumb impression. Ramabatar also used to be paid 10 per cent commission on the total remuneration of the workers under his supervision. He said that he used to supervise the work of 18 persons. Out of those 18, 7 are parties to the present referenec. Those are Bhoga Bauri, Samulla, Sukur Moni, Rashmoni Majheian, Nilmoni Majheian, Amulya Gora and himself. The commission for supervision used to vary. On account of hazri he used to get Rs. 60 to Rs. 70 per week. He denied that he is literate or that he signed on the back of voucher No. 1768 dated 15-12-73 in Bengali and put the date in English He was shown the petition in Hindi dated 20th June, 1974 which bears the signature in Bengali purported to be his. He disputed the signature and said he did not know how to sign. This letter which bears the date 20th June, 1974 is in Hindi. A free English translation of the letter reads as follows.

"To

The Manager, Bahula Colliery,

(North Jambad Unit).

Sir,

I beg to state that I was working in this colliery as Mason contractor. For working as mason I was getting commission but for the last three months my commission has been stopped because all the people working under me have been regularly employed under the Government. From the date my commission has been stopped, my economic condition has become very bad.

Therefore it is prayed that I may also be given the work of mason somewhere so that I can carry on my livelihood.

It is not only my hope but it is my firm belief that you will definitely consider my prayer at a very early date.

And for this I will remain grateful.

Yours faithfully,

Sd/- Narayan Gorai

Mason Contractor

Dated 20-6-74

Copy—Deonarayan Chaurasia,

Secretary, C.M.C., HMS."

The letter has been made Ext. M-2. He was then shown the Register of wages in Form III for the month of February, 1974. For the week 4-2-74 to 10-2-74 and for the week 11-2-74 to 17-2-74 which purport to bear his signatures. He denied that the signatures were his, Ext. M-5 and M-5(a). He said Anil Bauri, Rabi Pada Seal and Mongal Das were Mazdoors. Bhagirath was a mason working under him. He himself also did some work. He received bonus twice after the take over of the mine. He denied he was a contractor. His case was that he was a supervisor and also working as a mason. The people who worked under his supervision were brought by him. Similarly masons and mazdoors used to work under the supervision of Ramabatar for which Ramabatar used to be paid commission. Apart from those two, that is to say, Narayan Gorai and Ramabatar Prasad no one did the work of supervision on commission.

12. Sri Rabi Manjhi in his evidence stated that he had been working as mason mazdoor in North Jambad colliery since 1972. He used to earn a weekly remuneration of Rs. 47 to Rs. 48. He used to get his remuneration from office after affixing his thumb impression in the presence of the Cashier. He said Ramabatar was not a contractor. In the last quarter of 1973 he received one bonus. He had never seen Ramabatar reading or writing. In cross-examination he said that Ramabatar was his supervisor. He personally met the Manager and got employment. He did not receive any appointment letter. He never applied for Provident fund nor was he aware that Provident fund exists.

13. On behalf of the management Sri Niranjan Swarup the Manager of the colliery from June, 1974 to 30th November, 1974 gave evidence. He joined the colliery again on 1st November 1975. North Jambad colliery is one of the three units of Bahula colliery. He was shown the petition dated 29th November, 1974 from Ramabatar Prasad in Hindi, Ext. M-1. The writer himself handed it up to him. He deposed that he knew the signature of Narayan Gorai. He identified the signature of Narayan Gorai on the application dated 20th June, 1974, Ext. M-2. Ramabatar Prasad told him that he was working as a contractor and at that point of time he had no job. So he requested the deponent to forward his case to the Sub-Area Manager for consideration. In his application i.e. Ext. M-1 he prayed that he should be absorbed as a regular worker. He simply forwarded the application without any comment. As regards Narayan Gorai he said he knew Narayan and ascertained that he was working formerly as a mason contractor. During his time neither Narayan Gorai nor Rambatar was working in the colliery. In cross-examination he said that he had seen the signature of Narayan Gorai in old wage-sheets of contractors. When Ramabatar Prasad handed over his application to him he looked into his signature in the old records. He also looked

into Narayan Gorai's signature. He had no personal knowledge of Narayan Gorai's signature but when he looked up old wagesheets the Cashier told him that the other signature was one of Narayan Gorai. The signature on the application tallies with the old signature of Narayan Gorai in wagesheets. Ramabatar Prasad was a mason contractor. Ramabatar Prasad and Narayan Gorai were stopped from working before he joined the colliery. When he joined Bahula colliery there was no contractor working except for surface construction. At the time he joined there were about 26 mason mazdoors working directly in the colliery. The isolation and ventilation stoppings are mostly done departmentally at present and only in case of extreme emergency contractors are engaged. 22 masons and mason contractors are working on piece rate basis. There are also some time-rated workmen. He said that before he joined, some mason and mason mazdoors were taken on the roll of the colliery. He had no knowledge whether any bonus was paid to Ramabatar Prasad or Narayan Gorai. The posting in Bonus Register, Form 10, Ext. W-5 is made from the Wagesheet. There is an entry in the bonus register from 2-7-73 to 30-9-73 against Narayan Gorai. These entries have been taken from Wagesheets. The bonus amount of Rs. 37.10 P is shown as payable to Narayan Gorai but no bonus appears to have been paid to him. In the week ending 30th June, 1973 there is attendance for 5 days recorded in the register but it is not authenticated by anyone. The bonus amount is shown as Rs. 3.50 for Narayan Gorai in the week ending on 7-11-73. There is attendance of Narayan Gorai of one day. It does not appear from the bonus register that any bonus had been paid to Narayan Gorai. It appears however that bonus had been calculated. At page 34 of the Bonus Register the name of Narayan Gorai is entered and his designation is shown as contractor. No bonus appear to have been paid to Ramabatar but calculation of bonus for 3rd and 4th quarter has been made. His designation is also shown as a contractor at page 45 of the Bonus Register. These calculations must have been done on the basis of wage sheets. At page 23 of the Bonus register the name of Golam Murtaza is entered. Some calculations are shown but no bonus appears to have been paid. He is designated as mason. It is nowhere mentioned that he was employed by a contractor. There is an entry in respect of Brihaspati Bhuia and he is described as mazdoor. It is nowhere mentioned that he was a contractor's employee. The amount paid in 3rd quarter is Rs. 17.50 and in 4th quarter Rs. 4 only. If bonus is payable but is not paid, intimation has to be given to the Regional Labour Commissioner. He did not remember whether any information was sent to the Regional Labour Commissioner intimating that bonus had not been paid. In the Bonus Register no workman is described as a contractors employee. Ext. W.6 a bonus card bears the name of Golam Murtaza According to that Card Golam Murtaza received his bonus. He deposed that when charge was taken over by the new management, the management looked into the mine plan, the cash register and cash and coal stock. As regards records and registers, there was a large quantity which it was not possible to inspect properly. At the colliery level, the management maintains only the records of people who go underground and the materials issued. Measurements are also recorded. No other record is maintained. When a contractor submits his bill the measurements are verified and the bill is sent to the Sub-area Manager. The circular dated 8th August, 1974, Ext M-3, is signed by the Managing Director It is addressed to all A.G Ms with copies to others. The first paragraph of the circular reads as follows :

> "There are still 12,844 contractor's labour. Since contract system has been abolished completely in this division except for transporting sand and coal, I fail to understand how and why contractor's labour are being shown in your return. Please confirm by return that there is no contractor's labour at your colliery except those who are engaged in transporting sand and coal. In any case they are not our employees and there is reason to show them on your return submitted on man power. If some contract work is still continuing in the collieries, please take immediate steps to terminate such contracts forthwith and confirm but no contractor's men should be taken on the roll of the Company without my prior approval.

He deposed that in emergency cases in the North Jambad colliery, contractors are engaged. It is done only on the approval of the Sub-Area Manager.

14. Sri Anadi N. Chakravorty, Surveyor in the North Jambad Colliery deposed at the hearing. He knew Ramabatar and Narayan Gorai, Mason contractors. Ramabatar was working as a contractor under the erstwhile owners. Narayan Gorai joined the colliery after the take over. The contractors submitted bills for work done by their masons and received payments on the basis of measurements taken by him. He tendered the bill book for the period beginning from 1-11-73, Ext. M-4. The book was maintained by him. The book contained the measurements of the contract jobs done by those contractors. They used to get commission at the rate of 10 per cent on the basic amount. He pointed out the pages of the bill book where Ramabatar's and Narayan Gorai's names appear. He could not say if either of the contractors received any wages from the colliery. He took measurements, prepared the bills and thereafter payment was received by the contractors from the Cashier. Then he tendered the Register in Form III under Payment of Wages Act. It is signed by the contractor Narayan Gorai. It shows payment to Narayan Gorai's employees for the week ending on 11-2-74. The names of employees are specified. The employees have signed or subscribed their thumb impressions in acknowledgement of payment, Ext. M-5. Then he tendered another Form III register under the Payment of Wages Act for the week ending on 10th February, 1975. This is also signed by Narayan Gorai. Narayan Gorai's men have also subscribed their thumb impressions or signatures in acknowledgement of payment, Ext. M-5A. Similarly, in another Form III register, marked Ext. M-6. Rambatar has signed. His employees' names are mentioned there. They subscribed their thumb impressions in acknowledgement of payment. Some have put in signatures. Another Form III register for the week ending on 16-12-73 in respect of Ramabatar was tendered by the deponent. It is signed by Ramabatar. It also consists of names of his employees. Those employees have also signed or subscribed their thumb impressions in acknowledgement of receipt of payment, Ext. M-6A. Then he tendered a pay order dated 19-12-73 issued in favour of Ramabatar by the Manager. It contains the words "Debit account contractor". Another pay order dated 15-12-73 issued in favour of Narayan Gorai was tendered, Ext. M8. It is signed on the reverse by Narayan Gorai on revenue stamp. He admitted that Narayan Gorai did not sign in his presence and he did not know the signature. He admitted that the pay order was not issued by the Management in his presence. Narayan Gorai and Ramabatar were contractors and their contract related to underground work, such as ventilation, stopping or underground repairs. In Ext. M-4 i.e. the measurement book, there is no mention of Ramabatar or Narayan Gorai as contractors. At page 32 of the management's book there is a reference to stone cutting by hand. This work done for foundation. The work was done by Narayan Gorai and by his men. The bill was prepared in the name of Narayan Gorai. He deposed that Narayan Gorai and Ramabatar received contractor's commission, At pages 34 and 35 there is mention of payment of 10 percent commission. The deponent was responsible for preparing the bills for commission. Ten per cent commission was paid on the basic wages to Narayan Gorai and Ramabatar and 90 percent was paid to their workmen. They did not ordinarily do the work themselves but in some cases, when necessary they showed how the work was to be done. To do that they did a little work and thereafter left it off. Measurements were taken in the presence of the contractors and recorded on loose papars. Measurement sheets were not signed by them. From those sheets he recorded the measurements figures in the measurement book. The deponent did not know of any contract in writing entered with the contractors. The Manager told him that Ramabatar and Narayan Gorai were contractors and commissions were payable to them at the rate of 10 percent.

15. The Cashier, Sri Hariprosad Agarwal, gave evidence. He tendered payment vouchers, Ext.M-7 and M-8, by which payment was made to Ramabatar and Narayan Gorai. They signed on the back of the vouchers in his presence. In these paysheets they are described as contractors. Then he produced the Cash Book, Ext. M-9, of the colliery for 1974. In entries under 9th February 1974 there is a reference to four vouchers in respect of payment made to Ramabatar and two in respect of payment made to Narayaan Gorai. In the cash book they are described as contractors. He tendered

another Cash book, Ext. M-10, for the period from 28-10-73 to 20-1-74. At page 95 thtere are records of payment made to Narayan Gorai and Ramabatar. There are three vouchers of Narayan Gorai and three of Ramabatar. The payment shown in this Cash Book, Exts. M-5, M-5A, M-6 and M-6A, were made either by him or by the Pay clerk. The signatures on Exts. M-6 and M-6A are of Ramabatar. The signatures of Narayan Gorai appear to be the same as the one he subscribed in his presence on Ext. M-8A.

16. In cross-examination Agarwal said that prior to the take-over of the colliery he was working as Cashier-cum-Supervisor. The combined strength of the gangs of Narayan Gorai and Ramabatar was about 45. About 20 or 22 persons out of those gings have been absorbed. Ramabtar and Narayan Gorai sometimes used to work themselves They also used to supervise others' work. He referred to the bill book, Ext. M-6 and deposed that they were paid 10 per cent of the basic wages of their labourers by way of commission for supervising their work. They used to work under the orders of the Manager. Contractors and contractors' labourers did not enjoy festival holidays. He was shown Cash book, Ext. M-19, page 27 and entries regarding vouchers Nos. 1540 and 1541, it was pointed out to him that according to those entries these contractors as well as their workmen were paid Kalipuja holiday wages. He said that the names of workmen who received their wages, were entered in the Bonus Register Form 10, Ext. W-5. At page 45 of the Bonus register Ramabatar's name has been entered. At page 34 the name of Narayan Gorai also appears. As regards Bonus card in the name of Gulam Murtaza, Ext. W-6, he said that Murtaza was a member of either of the two gangs. He said Ramabatar and Narayan Gorai were getting hazri. By hazri, he intended to mean, a part of wages. He did not remember Murtaza nor was he in a position to say whether there was some other Golam Murtaza working in the colliery.

17. The last witness who deposed on behalf of the management was Satyadev Tiwari, the Register keeper. He said that he maintained the underground register in Form C. The register contains the names of persons going underground. He tendered four such register, Exts. M-1, M-11A, M-11B and M-11C. In Ext. M-11A under entries dt. 26-6-73 to 2-7-73 the name of Narayan Gorai, Contractor appears. There are also the names of workmen of his gang who went under ground. In Ext. M-11C, in the entries under the dates 7-10-73 to 15-10-73 the name of Ramabatar, Contractor and his workmen are mentioned. In cross-examination he said that in Ext. M-11C Narayan Gorai, is described as Contractor in some places and as cleaning mazdoor in others. Rest of the workmen are shown as cleaning mazdoors. He deposed that Ext. M-11C is exclusively maintained for the purpose of recording the work of contractor's workmen. In Ext. M-11A, the underground register, for the week 12-6-73 to 18-6-73 Narayan Gorai has been described as Raj Mistri. In Ext. M-11B which is in respect of the period 14-8-73 to 20-8-73, Narayan Gorai has again been described as Raj Mistri. He said that the Manager had intimated to him in writing that the two persons Ramabatar and Narayan Gorai were contractors and other workmen were contractors' workmen. He had lost that piece of writing. The underground register was maintained according to the Manager's said intimation for a long period. The designations of Ramabatar and Narayan Gorai were taken from the intimation in writing. He knew that Narayan Gorai and Ramabatar were contractors and their names were therefore entered as such. As regards other designations he wrote those as per slips received from the Manager.

18. Although the management in their written statement questioned the locus standi of the concerned union to sponsor the dispute, the objection was not pressed by the learned advocate at the hearing of the reference. The real issue, as he rightly pointed out, is whether the concerned workmen were employees of the colliery or not. The issue may be sub-divided into two, (i) were Ramabatar Prosad or Narayan Gorai contractors or employees under the employers ? and (ii) were other concerned workmen employees of colliery or were they employed by Ramabatar or Narayan Gorai ?

19. It is significant that in their written statement, the Union has described the Management as the principal employers there were two employers, the Management and the contractors. The concerned workmen other than the contractors were therefore employed by the contractors. The question is whether their ultimate employer was the Management.

20. Learned advocate appearing on behalf of the employers strongly relied on two petitioner dated 29-9-74 and 20-6-74 purported to be signed by Ramabatar Prosad and Narayan Gorai respectively The first one is addressed to the Sub-Area Manager, Kenda Group, Area No. IV and the other to the Manager, Bahula Colliery, North Jambad Unit. The petitions are in Hindi. In it Ramabatar signs as Mason contractor and states that he was working as a mason contractor and was also working underground for which he was being paid wages though a paysheet. He then complained that the entire gang of workmen working under him having been absorbed as regular workmen, he had become unemployed and was not getting any employment. He therefore prayed that he might also be taken into regular employment under the Government, in the same way as those working under him, have been taken in employment. Narayan Gorai also described himself as Mason contractor in his petition. He was getting commission but for the last three months his commission had been stopped because the people working under him had been absorbed by the Government in regular employment. He was therefore no longer receiving any commission . He also prayed that he might be given the work of these petitions and maintained that they were illiterate Ramabatar and Narayan Gorai disclaimed all knowledge of these petitions and maintained that they were illeterate and therefore they could not and did not sign any petition. Sri Niranjan Swarup, Manager of the colliery deposed that Ramabatar Prosad personality handed up the petition to him. He indetified the signature of Narayan Gorai in Bengali on the application, Ext.M-2. When Ramabatar handed over his application, Ext M-2, to him he looked in to his signatures in old records. He also looked into Narayan Gorai's signature. Although he had no personal knowledge of Narayan Gorai's signature, when he looked up old wagesheets. The Cashier told him that the signature was one of Narayan Gorai. He also deposed that the signature on the application tallied with the old signature of Narayan Gorai in the paysheets. It is quite clear from the comparison of the two signatures of Narayan Gorai on paysheets and on the petition that they are the same. Both Narayan Gorai and Ramabatar have signed in more than one instance in the exhibits. The signatures tally There is also evidence that they could and did sign a number of documents. In the absence of any plausible explanation as to why their signatures in the exhibits should not be accepted as genuine, I hold that Ramabatar Prosad and Narayan Gorai were capable of signing their names and their signatures in the exhibits are genuine. Ability to sign is not inconsistent with illiterary A person may be illiterate and yet be capable of signing his name. Hariprosad Agarwal, the Cashier, deposed that both Ramabatar and Narayan Gorai signed on the back of payment vouchers, Ext. M-7 and M-8 in his presence He also said that in the Cash Book, Ext. M-10, the signature of Narayan Gorai appears to be the same as the signature in Ext. 8A. Anadi Nath Chakravorty deposed that in the Register in Form III maintained under the Payment of Wages Act, Ext. W-5, Narayan Gorai has subscribed his signature.

21. In their evidence Ramabatar Prosad and Narayan Gorai denied that they were contractors and claimed to be mason supervisors and masons. As I hold that Exts. M-1 and M-2 are genuine, it necessarily follows that according to the tenor of those exhibits, they were contractors. It is true that in his petition Ramabatar says that he was a mason as well as a contractor. In his evidence he admitted that he was a mason supervisor but not a contractor. On the question of probabilities it seems to me that if he were a contratcor or even a mason supervisor, he could hardly have been employed as a mason. There is evidence that Ramabatar was not a member of the Provident Fund. Under the Coal Mines Provident Fund Scheme if a workman works for 48 days in a quarter, he is entitled Provident Fund. If Ramabatar had been working regularly, as he claims, as a workman, the question arises why he did not enjoy provident fund benefits.

22. It was not disputed that Ramabatar and Narayan Gorai had their own gangs and they themselves brought in their

own workmen. This also lends colour to the view that they were contractors. Anadi Nath Chakravorty proved from the bill book, the measurements of the contract jobs done by Ramabatar Prosad and Narayan Gorai and referred to entries in their names in the relevant pages of the bill book, Ext. M-4. He also referred to the Registers in Form III maintained under the Payment of Wages Act, Ext. M-5 and M-5A. In these registers the workmen in the gang of Narayan Gorai have subscribed their thumb impressions in acknowledgement of payment of money received by them. Narayan Gorai himself has signed at the foot of these registers. Likewise in Exts. M-6 and M-6A and other Form III registers Rambatar's gangmen have subscribed their thumb impressions in acknowledgement of having received the payment and Ramabatar himself has signed at the foot of the registers. In Ext. M-7 which is a pay order for Rs 225.68 P issued by the Manager in favour of Ramabatar Prosad, he is described as a contractor and he has subscribed his signature on the back of the pay order on revenue stamp in acknowledgement of receipt of payment. Similarly, in Ext. M-8A a pay order issued in favour of Narayan Gorai for Rs. 137.02, Narayan Gorai has been described as a contractor and he has subscribed his signature on the back of the pay order on a revenue stamp in acknowledgement of receipt of payment. In the Cash Book Ext M-9, at page 23 there are entries as regards payments made to Ramabatar Prosad, contractor, under four vouchers and also to Narayan Gorai, contractor, under two vouchers under the heading "Contractor's Account". Hariprosad Agarwal, the Cashier, deposed that the entries were all made by him to record the payments made to the contractors. Similarly, at page 27 of the other Cash Book, Ext. M-10, there are entries under "Contractor's Account" of payments made to Ramabatar Prosad and Narayan Gorai, contractors In the underground Registers, Exts. M-11, M-11A, M-11B and M-11C the names of Narayan Gorai contractor and the workmen of his gang appear in the entries in respect of week commencing from 26-6-73 and ending on 2-7-73. Similarly, in the Form C register from 31-7-73 to 3-9-73, Ext. M-11B, the name of Narayan Gorai, contractor and his workmen appear in the entries in respect of the week commencing from 20-8-73 and ending on 28-8-73. In Ext. M-11C in entries made in respect of week commencing from 9-10-73 and ending on 15-10-73 the names of Ramabatar Prosad contractor and the workmen of his gang are mentioned. In these entries Narayan Gorai and Ramabatar Prosad are described as contractors. The workmen of the respective gangs are described as cleaning mazdoors, mason mazdoors or simply mazdoors. It was pointed out in cross-examination that in Ext. M-11C Narayan Gorai has been described as contractor as well as cleaning mazdoor in the entries in respect of the week commencing from 18-9-73 and ending on 24-9-73. It appears from a close examination of the underground registers, Ext M-11, M-11A, M-11B and M-11C that Ramabatar Prosad and Narayan Gorai have been consistently described as contractors although in one or two places they have been described by other designations.

23. Be that as it may, the documentary evidence in this case is overwhelmingly in favour of holding that Ramabatar Prosad and Narayan Gorai were contractors. By their signatures as well as by their petitions they accepted the proposition that they were contractors It is also clear that the other concerned workmen were members of the contractor's gangs and were employees of the contractors and not employees of the employers in relation to the management of the North Jambad Unit of Bahula Colliery.

24. Sri B. S. Azad, General Secretary of the Union, appearing on behalf of the concerned workmen relied on the Bonus Register, Ext W-5 and pointed out that at pages 34 and 45 the names of Narayan Gorai and Ramabatar Prosad have been entered and the amount of bonus payable to them have been calculated. It is however significant that in the bonus register they have been described as contractors. There is evidence that after wages are paid to workmen their names are entered in the bonus register. Sri Azad also relied on the bonus card of Golam Murtaza, Ext. W-6 in support of the case that Golam Murtaza was a workman. The entry of one's name in the bonus register or the issue of a bonus card or payment of wages stray occasions by itself cannot be conclusive on the question whether one is a workman or not. Taking the entire evidence, there can be no manner or doubt that Ramabatar Prosad and Narayan Gorai were contractors and not employees of the colliery. The men in their gangs were brought in by the Contractors to execute Contract jobs. They were not in the employment of the colliery. In the face of the weight of the entire evidence in this case, particularly of the documents which have been made exhibits, it must be held that Ramabatar Prosad and Narayan Gorai were contractors and not workmen in the employment of the colliery and the other concerned workmen were not workmen employed by the management but were engaged by the contractors Ramabatar Prosad and Narayan Gorai to execute Contract jobs.

25. Sri Azad relied on the decision of the Supreme Court in Hussainbhai vs The Alath Factory Tezhilali Union & Or 1978 AIR 1410. There it was held that where a worker or group of workers labours to produce goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact, the employer. He has economic control over the workers' subsistence, skill and continued employment. The presence of intermediate contractors with whom alone the workers have immediate or direct relationship ex-contract is of no consequence when, on lifting the veil or looking at the conspectus of facts governing employment, it is found, though draped in different perfect paper arrangement, that the real employer is the Management, not the immediate contractor. In that case a factory owner manufacturing ropes entered into contracts with contractors who hired workmen to make ropes in the factory. The petitioner contended that the workmen were not his workmen but contractor's workmen. It was not in dispute in that case that the work done by the contractor's workmen was an integral part of the industry concerned ; the factory premises belonged to the management ; Finished product was taken by the management for its own trade. The workmen were under the control of the management and defective articles were directed to be rectified by the management. The judgment of the Supreme Court has to be understood on the context of the facts of that case. In this case there is no veil to be pierced. The concerned workmen, who are masons do not manufacture any goods, finished, processed or semi-processed. The nature of work done by the concerned workmen is not of the kind for which there is no scope elsewhere. Taking into consideration, the mining of coal in the colliery as a whole, the work of these few concerned workmen who were masons or mason mazdoors was a small and minor part of the work in the colliery. They were brought in by the contractors ; supervision was admittedly done by the contractors although the work was allotted by the management to the contractors. It cannot therefore be held that, in the facts and circumstances of this case, the management of the colliery were the real employers. The concerned workmen were not only brought in and employed by the contractors to execute the contract jobs but the manner in which the work was to be done was decided by the contractors. The contractors also supervised the work of the concerned workmen for which they earned a commission. To hold that the concerned workmen were direct employees of the colliery will be to ignore realities of the situation. In my opinion, the Supreme Court did not intend to lay down general proposition that contractors or their employees are in all circumstances, employees of the undertaking by which the contractor is engaged.

26 Sri Azad also relied on the case of Dharangadhra Chemical Works, Ltd., and State of Saurashtra and Ors., 1957 I LLJ, p. 477. In that case it was held that the prime test which applies in order to determine the relationship between employer and employee is the existence of right to control in respect of the manner in which the work has to be done. There is a distinction between a contract for service and contract of service. In the first case the master can order or require what is to be done while in the second case he can not only order or require what is to be done but how it shall be done In the facts of the present case it has not been disputed that the supervision was exercised by the contractors. In fact, the contractors claimed that they were mason supervisors and they used to supervise the work done by their respective gangs. It is true that satisfaction had to be given to the management that the work had been done properly. But that by itself does not mean that the management exercised the right of control in respect of the manner in which the work was to be done. The case is therefore of no assistance to the concerned workmen.

27. In the view I have taken, I hold that the action of the management of North Jambad Unit, Bahula Colliery of Eastern Coal Fields Limited, in stoppoing from work the workmen whose names and designations are mentioned in the Schedule attached to the order of reference with effect from 5-4-74 is justified. The concerned workmen are not entitled to any relief.

Dated : Calcutta, the 30th July, 1979.

S. K. MUKHERJEA, Presiding Officer
[No. L-19012/45/75-D.III(B)/D.IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1979

का०आ० 2974.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री सी० एल० नरसिम्हा राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के समक्ष लंबित पड़े हैं ;

और उक्त श्री सी० एल० नरसिम्हा राव की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं ;

अत, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 ख की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० सदाशिव रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा तथा उक्त श्री सी० एल० नरसिम्हा राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के समक्ष लंबित पड़े उक्त विवादों से संबद्ध कार्यवाही को वापिस लेती है और उसे श्री जी० सदाशिव रेड्डी, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद को इस निदेश के साथ स्थानान्तरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्रवाई उसी प्रक्रम से करेगा, जिस पर वह उसे स्थानान्तरित की जाए और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा ।

अनुसूची

लंबित पड़े केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद

क्रमांक	औद्योगिक विवाद संख्या	आदेश की संख्या और तारीख	पक्षकारों के नाम
1.		श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का आदेश संख्या एल-21012 (19)/79-डी० 4 (बी), तारीख 16-3-1979	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, रामागुन्डम डिवीजन 1, गोदावरी खानी, जिला करीमनगर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
2.		श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21012(21)/79 डी० 4(बी), तारीख 12-3-79	कर्मकार श्री जी० नारायाना और रामागुन्डम डिवीजन 1 की सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०, गोदावरी खानी, जिला करीमनगर के प्रबन्धतंत्र ।

[फा० स० एस०11025(1)/79—डी० 4(बी) पार्ट-2]
शशि भूषण, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1979

S.O. 2974.—Whereas, the Industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri C. L. Narasimha Rao, the Presiding officer Industrial Tribunal, Hyderabad;

And, Whereas, the services of Shri C. L. Narasimha Rao are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A, read with sub-section (1) of the Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri G. Sadasiva Reddy, with Headquarters at Hyderabad and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before the said Shri C. L. Narasimha Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad and transfers the same to Shri G. Sadasiva Reddy, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Central Government's Industrial Disputes Pending

S.No.	I.D.No.	No. and date of the Order	Name of the Parties
1.		Order No. L.21012 (19)/79-D. IV (B), dt. 16-3-79 from Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, Govt. of India, New Delhi.	Workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Div. I, Godavari Khani, Karimnagar District.
2.		Order No. L-21012 (21)/79-D.IV(B), dated 12-3-79, from Ministry of Labour Employment & Rehabilitation, Govt. of India, New Delhi.	Workman Shri G. Narayana and the Management of Singareni Collieries Co. Ltd., of Ramagundam Div. I, Godavari Khani, Karimnagar District.

[F. No. S.11025(1)/79-D. IV(B)Pt.II]
SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

New Delhi, the 13th August, 1979

S.O. 2975.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi in respect of an application under section 33A of the said Act filed by Shri Sher Singh, Chargeman Spl., B. S. L. Project which was received by the Central Government on 8th August, 1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I. D. No. 96 of 1978

In re :

Sher Singh Token No. 582-C,
Chargeman SPL II O&M,
BSL Project Sundernagar,
District Mandi,
Himachal Pradesh.

....Petitioner

Versus

The Chief Engineer,
BSL Project Sundernagar,
District Mandi,
Himachal Pradesh.

....Respondent

AWARD

By this Order I propose to dispose of application filed u/s 33-A by Shri Sher Singh, challenging his retrenchment on the

allegations that the same was bad having not been made after seeking requisite permission from the Industrial Tribunarl before whom a reference u/s 36A was pending between the workman and the BSL Project. The said application was registered as I.D. No. 96 of 1978.

2. The application is opposed on behalf of the Management on the ground that in fact no dispute was pending before the Industrial Tribunal so as to attract the provisions of Section 33(2)(b) and hence no application lies u/s 33-A.

3. In as much as after filing of the application except for one hearing none had been appearing for the workman, Ex-parte proceedings were ordered against the workman and ex-parte evidence was ordered to be recorded. Ex-parte evidence of the Management consists of statement of Shri O. P. Gupta, Personnel Officer of the Management which reads as under:

> This petition has been filed u/s 33A of I. D. Act on the plea that a reference u/s 36A is pending before this Tribunal which has arisen out of a reference I. D. No. 2C of 1971 and his retendent during the pendency of reference u/s 36-A without permission of this Court is illegal. This Court has already decided this question in petition u|s 33A in re: Jai Ram Vs. BSL. So the case is also to follow but I file copy of earlier award of this Tribunal.

4. I have gone through the evidence produced by the Management and have gone through the pleadings of the parties and after giving my considered thought to the matter before me I have come to the conclusion that the retrenchment of the workman was valid and as such no petition u|s 33A is maintainable.

5. According to this petition the Central Govt. as appropriate Govt. had made a reference No.2-C of 1971 to Chandigarh Industrial Tribunal in which the award was given on 15th May, 1974 by that Tribunal and award was implemented to some extent of the said award. Tht Central Govt. vide its Order No. I-42011/4/76/D-II(9B), dated the 23rd April,1976 made a reference u|s 36-A for clarification of the said award and it was thereafter that the workman in this petition was retrenched and this petition has been filed u|s 33-A on the ground that on account of the pendency of subsequent reference u/s 36-A the retrenchment was invalid as no permission or sanction or approval was obtained from the Tribunal.

6. These facts have not been denied. Only question to be considered for the purposes of disposal of objection of maintainability is as to whether the retrenchment during the pendency of reference u/s 36-A of I D. Act is valid or not.

7. The contention of the Management is that the original reference having already been disposed of by an award by the Industrial Tribunal, Chandigarh the provisions of Section 3(2)(b) and in consequence there was no need for any permission sanction or approval of the Industrial Tribunal before services of this workman could be terminated.

8. In so far as the reference u/s 36-A of I.D. Act is pending before this Tribunal now and is registered as No. 10-C|76|177 of 1977. the said file was summoned for the purposes of disposal of this application. The orginal file of the award is also avaliable to this Tribunal alongwith the reference No. 10-C|76|177 of 1977.

9. It is in the light of these admissions of the parties, representatives as that this petition has to be determined.

10. From the perusal of the petition I find that the contention of the workman in the application is that he was a workman under the Industrial Dispute Act employed with the Beas Sutlej Link Project and his services were terminated by way of retrenchment without any concurrence having been previously obtained from the Industrial Tribunal, Chandigarh before whom a reference u|s 36-A I. D. Act was pending and as such it was inviolation of Section 33(2)(b) of I. D. Act and hence this application.

11. It is contended by the Management that the original reference had already been disposed of by an award by Industrial Tribunal, Chandigarh and it was only a reference with regard to scope of the said award which was pending u/s 36-A before the Industrial Tribunal, Chandigarh and that did not attract the provisions of Section 33(2)(b) of the I D. Act bifore the services of the workman were terminated by retremchment and hence this petition was not maintainable.

12. It may be mentioned here that the reference u|s 36-A of the I. D. Act is pending before this Tribunal now and is registered as No. 10-C|76|177 of 77 and as such the said file was summoned for the purposes of disposal of this application. The original file of the award was also available to this Tribunal alongwith the reference No. 10-C|76|177 of 77.

13. In order to appreciate the arguments addressed at the bar it would be appropriate to narrate the events in sequence starting with original reference. The Central Govt. in the Ministry of Labour and Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment as appropriate Govt. referred an Industrial Dispute between the employers in relation to the Beas Sutlej Link Project and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule to the said order No 4/86/70/LR. III, dated the 4th March, 1971 u/s 10 of the I. D. Act to Shri P. P. R. Sahney, the Industrial Tribunal, Chandigarh The said Schedule read as under :

1. Revision of pay scales of work charged employees.

2. Regularisation of the services of the work charged employees.

3 Accident and retrenchment compensation to the workmen drawing over Rs. 500 P. M.

4. Gratuity Scheme.

14. The said reference was registered as reference No. 2-C of 1971 by the Tribunal Shri H. R. Sodhi, the successor of Industrial Tribunal, Chandigarh gave an award in the said reference vide his order, dated the 15th May, 1974 which was duly published by the appropriate Govt. Thereafter some dispute arose between the workmen and the Management on the scope of the said award and as a result thereof the Central Govt. in the Ministry of Labour. vide its Order No. L-42011|4|76|D.II(B) dated the 23rd April, 1976 made a reference u|s 36-A of the I. D. Act, 1947 to Industrial Tribunal, Delhi in the following terms :

> 'Whether the direction given by the Industrial Tribunal, Chandigarh in the award in reference No. 2-C of 1971 governed the case of the category of employees discussed in the award only or the said award is in respect of all categories of employees of the Project wherever either of the principals enunciated in the award was lacking.'

15. This subsequent reference u/s 36-A was registered as No. 10 of 1976 by the Industrial Tribunal, Delhi. This reference was however later on transferred to this Tribunal and has been registered as No. 177 of 1977 and is still under determination.

16. During the pendency of this subsequent reference made on 23rd April, 1976 number of workmen have been retrenched by the Project and the present workmen are some of those. It would not be inappropriate to mention here that the said retrenchment has been effected in consequence of a settlement arrived at between the representaives of the workmen and the Management in this behalf and that necessary retrenchment compensation and other dues to which the retrenchment employees were entitled are stated to have been paid before retrenchement in accordance with the said settlement.

17. The contention of the workman now is that in so far as Industrial Dispute No. 10/76/177 of 1977 was pending at the time of retrenchment and in as much as the Management had not sought the concurrence of the Industrial Tribunal u|s 33(2)(b) of the I. D. Act the said retrenchment is invalid and hence this petition.

18. In view of the circumstances narrated above the maintainability of this petition would depend on the answer to the question as to whether the provisions of Section 33(2)(b) are attracted, Section 33 of the I.D. Act provides as under :

> 'Conditions of Service. etc. to remain UNCHANGED UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES. (1) During the pendency of any conciliation officer or a

Board of any proceeding before (an arbitrator or) a Labour Court or Tribunal or National Tribunal in respect of an industrial dispute, no employer shall—

(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter, to the prejudice of the workmen concerned in such dispute, the condition of service applicable to them immediately before the commencement of such proceeding; or

(b) for any misconduct connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise any workman concerned in such dispute, save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.

(2) During the pendency of any such proceeding in respect of any industrial dispute, the employer may, in accordance with the standing orders applicable to a workman concerned in such dispute, for, where there are no such standing orders, in accordance with the terms of the contract, whether express or implied, between him and the workman)—

(a) alter in regard to any matter not connected with the dispute, the conditions of service applicable to that workman immediately before the commencement of such proceeding; or

(b) for any misconduct not connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise, that workman :

Provided that no such workman shall be discharged or dismissed, unless he has been paid wages for one month and an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of the action taken by the employer.

(3) Notwithstanding anything contained in such section to no employer shall during, the pendency of any such proceeding in respect of any industrial dispute, take any action against any protected workman concerned in such dispute—

(a) by altering, to the prejudice of such protected workman, the conditions of service applicable to him immediately before the commencement of such proceedings; or

(b) by discharging or punishing, whether by dismissal or otherwise, such protected workman, save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending.

Explanation for the purposes of this sub-section, a 'Protected workman', in relation to an establishment means a workman who, being (a member of the executive or other office bearer) of a registered trade union connected with the establishment, is recognised as such in accordance with rules made in this behalf.

(4) In every establishment, the number of workmen to be recognised as protected workmen for the purposes of sub-section (3) shall be one per cent, of the total number of workmen employed therein, subject to a minimum number of five protected and a maximum number of one hundred protected workmen and for the aforesaid purpose, the appropriate Government may make rules providing for the distribution of such protected workmen among various trade unions, if any, connected with the establishment and the manner which the workmen may be chosen and recognised as protected workmen.

(5) Where an employer makes an application to a Conciliation Officer, Board (an Arbitrator) Labour Court, Tribunal or National Tribunal under the proviso to sub-section (2) for approval of the action taken by him the authority concerned shall, without delay, hear such application and pass, as expeditiously as possible, such order in relation thereto as it deems fit.

19. In order to attract the provisions of Section 33 of the I. D. Act, it is essential for the workman to establish that proceedings referred to in that section were pending in the instant case before the Industrial Tribunal and it is urged on behalf of the workman that this reference u/s 36-A is in continuation of a reference u/s 10 of the I. D Act and as such, for the purpose of Section 33, he original reference No. 2-C/71 would be deemed to be pending and hence the retrenchment was invalid. I do not find much weight in this contention of the workman. The original reference No. 2-C/71 stood disposed of by the award dated 15-5-74 of Shri R.P. Sodhi Industrial Tribunal, Chandigarh. The said award had been duly published. With the publication of the award the reference No. 2-C/77 had been determined finally If some dispute regarding the extent or implication of the award was raised it would not revive the original dispute in which an award had already been made and the said award having been already published. Further more the subsequent reference is a reference u/s 36-A of the I.D. Act and Section 36-A is intended only for the purposes of removal of difficulties and it provides as under :

36A. Power to remove difficulties—(1) if, in the opinion of the appropriate Government, any difficulty or doubt arises as to interpretation of any provision of any award of settlement, it may refer the question to such Labour Court, Tribunal or National Tribunal as it may think fit.

(2) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal to which such question is referred shall, after giving the parties an opportunity of being heard, decide such question and its decision shall be final and binding on all such parties

20. Thus the scope of subsequent reference u/s 36A is limited and is limited to interpretation of the provisions of the award dated 15-5-1974 and cannot travel beyond it. By no stretch of imagination the said reference opens the original reference so as to attract the provisions of Section 33 in the instant case. The reference u/s 36-A cannot be equated for all intent and purposes to a reference u/s 10 of the I.D. Act. The scope of reference u/s 36-A is limited by the words used in that section by the legislature.

21. In this context I would like to refer to ruling of Supreme Court of India entitled Ballarpur Colliery Company Versus Presiding Officer, Dhanbad and another reported as 1972(2)LLJ-90. However the question of law involved in that case was altogether different than the one which arises in this case and as such this ruling is not attracted by the facts of this case, Section 23-A is not in parimeteria with Section 33 of the I.D. Act and as such it cannot be accepted that any industrial dispute was pending on the date of retrenchment of the workman so as to attract the provisions of Section 33 of the I.D. Act. Even otherwise right of strike can be equated with lock out as has in fact been done under section 23 of the I. D Act and it cannot extend to the right of retrenchment. Sec. 23 itself makes clear that it refers either to strikes or lock-outs and nothing beyond that and it cannot be accepted that merely because a reference u/s 36-A attracts section 23, it also would attract section 33. Sections 23 and 33 are based upon altogether different concepts Section 36-A would not enable the Tribunal to review, modify or alter the original award. It is only to get the provisions clarified or the doubt removed and therefore it cannot be relegated to the position of original reference. Under no circumstances can it be accepted that the original reference No. 2-C/71 under Sec. 10 of the I.D. Act 1947 was revived by the subsequent reference u/s 36-A and therefore I hold that provisions of Section 33 of I.D. Act have not been attracted or contravened in the instant case.

22. In so far as I have held above that provisions of Section 33(2)(b) of the I.D. Act were not attracted at the time of termination of the services of this workman it would follow that this petition u/s 33-A of the I.D. Act is not maintainable and rather if at all the workman feels aggrieved against the termination of his services he may raise an industrial Dispute in the ordinary manner so that a proper reference is made by the appropriate Govt. and the questions raised cannot be considered in this petition.

23. In view thereof the petition is hereby dismissed. Parties are left to bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[No. L-42014(1)/79-D.II(B)]

Dated : the 21st July, 1979 Asadha 30, 1901.

S.O. 2976.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th August, 1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT.

INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT

NEW DELHI.

I.D. No. 23 of 1979

The General Secretary,
Air Corporation Employees Union, ..Petitioner
19/100 Scindia House (Back),
Janpath, New Delhi

Versus

The Regional Director.
Indian Airlines,
124, Janpath, Thapar House.
New Delhi.

AWARD

The Central Govt has appropriate Govt. made a reference vide its Order No L-11012(4)/75-D.II(B) dated the 3rd September, 1975 in the following terms to Industrial Tribunal, Delhi :

> Whether the action of the management of the Indian Airlines in removing Shri R. S. Grewal, Flight Steward, from service with effect from 28-8 1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. After the reference was received it was ordered to be registered and notices were ordered to be issued to the respective parties and in pursuance thereof the workman filed a statement of claim and in reply thereto the Management filed its written statement and finally in pursuance of the contentions of the respective parties the following one issue was framed by Industrial Tribunal, Delhi :

> Whether the domestic inquiry held by the Management is vitiated for any reason?

3. Thereafter the case was fixed for evidence and evidence of the parties was recorded and arguments was heard and the order was passed vitiating the enquiry of the Management and then the following issues on merits was framed :

As in the terms of reference.

4. It was thereafter that this case was transferred to this Tribunal by the appropriate Govt.

5. On receipt of the reference it was ordered to be registered and notices were issued to the parties and the case was fixed for 17th July, 1979. To-day none appeared for the workman but Shri Davinder Singh, Advocate with Shri P. N. Sinha Deputy Manager (Personnel Services) for the Management appeared before me. I filed a settlement C/1 and stated that the parties have compromised this case vide Ex. C/10 no dispute award be made in this case. In pursuance of the said settlement the file was put up beore me and I have recorded the settlement vide statement of Shri Davinder Singh, Advocate and Shri P N Sinha, Dy. Manager (Personnel Services) for the Management. From the perusal of the settlement Ex. C/1 I do find that certainly parties have arrived at a settlement The settlement is Ex: C/1 and bears the signatures of Manager, Personnel Services and is just and reasonable and accordingly an award in terms of the settlement is hereby made The settlement is Ex. C/1 would form part of this award and shall be read as Annexure thereof. Parties are left to bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated, the 17th July, 1979
26 Asadha, 1901

509GI/79—8

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT

INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

C.G.I.D. No. 57 of 1975

BETWEEN

The Management of Indian Airlines.

AND

Their workmen.

An application by the management for an award in terms of the settlement dated 24-10-1977, in C.G.I.D. No. 25 of 1975, C.G.I.D. No. 42 of 1975 and C.G.I.D. No. 55 of 1975.

It is respectfully submitted by the Management as under :

1. That the abovementioned Reference is pending before this Hon'ble Tribunal for adjudication.

2. That besides the abovementioned Reference 3 other References were pending before this Hon'ble Tribunal being C.G.I.D. No 25 of 1975 in relation to Shri Tara Chand C. G. I. D. No. 42 of 1975 in relation to Shri Mukhtiar Singh and C. G. I. D. No. 55 of 1975 in relation to Shri P. S. Jassal. It is stated that this Hon'ble Tribunal has already been pleased to pass awards in terms of Settlements dated 24-10-1977 arrived at between the Management and their workmen through Air Corporation Employees Union, hereinafter referred to as A.C.E.U. on 31-10-1977.

3. It is stated that during the pendency of the 4 References before this Hon'ble Tribunal, mutual discussions were held between the Management and their workmen through A. C. E. U. with a view to resolve these pending cases as a package deal so that all the disputes before this Hon'ble Tribunal could be disposed of accordingly It was agreed that certain benefits will be granted to Sarvashri Tara Chand, Mukhtiar Singh and P. S. Jassal but in the case of Shri R S Grewal, which is the subject matter of the present Reference, no relief will be granted by virtue of the Settlement and it was further agreed that since the 4 cases are separately referred to and are pending before this Hon'ble Tribunal, 3 separate settlements shall be signed with regard to the cases of Sarvashri Tara Chand Mukhtiar Singh and P S. Jassal in whose cases certain benefits were agreed to be given as aforementioned.

4. That along with the Settlement in the case of Sarvashri Tara Chand, Mukhtiar Singh and P. S Jassal, the A. C. E. U have pursuant to the Settlements, already filed a statement that they do not intend to continue to espouse the case of Shri R. S Grewal and as such A C. E U. may be allowed to withdraw the case.

5. It is submitted that in view of the aforementioned settlements and the statement of A. C. E. U., this Hon'ble Tribunal be pleased to pass a 'no dispute' award in the Reference.

It is, therefore prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to pass a 'no dispute' award in Terms of Settlements dated 24-10-1977 in C G I. D No. 25 of 1975 in relation to Shri Tara Chand, C G I D. No 42 of 1975 in relation to Shri Mukhtiar Singh and C. G. I D No 55 of 1975 in relation to Shri P. S. Jassal in terms of which this Hon'ble Tribunal has already passed awards in those References and in terms of which 'no dispute' survives between the Management and the workmen as represented by A. C E U. And this Hon'ble Tribunal be pleased to pass such other and further orders as may be deemed just and proper.

For and on behalf of the Management of Indian Airlines

C. G. JAGANNATH RAO, Manager, Personnel Services
Delhi Region.

[No. L-11012(4)/75-D.II(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer

New Delhi, the 18th August, 1979

S.O. 2977.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Corporation Bank Limited, 3/1/2, Armenian Street, Calcutta and their workmen over termination the consent Award of the Indusrtial Tribunal, Bangalore relating to the policy of appointment of Special Assistants and promotion of Clerks to officer's cadre in the grade of Accountants provided therein, which was received by the Central Government on 1-8-79.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,

CALCUTTA

Reference No. 29 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of the Corporation Bank Limited, Calcutta.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Sri N. C. Shah, Advocate, with Sri A. K. Dhar, Advocate.

On behalf of Workmen—Sri P. K. Chatterjee, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Banking.

AWARD

By Order No. L-12011/42/77-D II.A dated 10th/16th March, 1978, the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management, of the Corporation Bank Limited, Calcutta and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The Reference reads as :

"Whether the action of the management of Corporation Bank Limited, 3/1/2 Armenian Street, Calcutta-700001 in terminating the consent award of the Industrial Tribunal, Bangalore relating to the policy of appointment of Special Assistants and promotion of Clerks to officer's cadre in the grade of Accountants provided therein is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2 It is common case that the Schedule to the Order of Reference is inaccurate in so far as it states that the consent award of the Industrial Tribunal, Bangalore relating to the policy of apointment of Special Assistant and promotion of Clerks to officer's cadre in the grade of Accountants provided therein was terminated by the management of Corporation Bank Limited 3/1/2, Armenian Street, Calcutta. In fact the said consent award was terminated by the management of Corporation Bank Limited, Mangalore by a notice dated February 15, 1977 under Section 19(6) of the Industrial Disputes Act, 1947. The management of the corporation Bank Limited, Calcutta did not terminate the said award.

3. Sub-section (3) of Section 19 of the Industrial Disputes Act, 1947, provides as follows :

"An award shall, subject to the provisions, of this section, remain in operation for a period of one year from the date on which the award became enforceable under section 17A.

Provided that the appropriate Government may reduce the said period and fix such period as it thinks fit ;

Provided further that the appropriate Government may, before the expiry of the said period, extend the period of operation by any period not exceeding one year at a time as it thinks fit so, however, that the total period of operation of any award does not exceed three years from the date on which it came into operation."

Sub-section (4) provides :

"Where the appropriate Government, whether of its own motion or on the application of any party bound by the award, considers that since the award was made, there has been a material change in the circumstances on which it was based, the appropriate Government may refer the award or a part of it to a Labour Court, if the award was that of a Labour Court or to a Tribunal, if the award was that of a Tribunal or of a National Tribunal for decision whether the period of operation should not, by reason of such change, be shortended and the decision of Labour Court or Tribunal, as the case may be, on such reference shall *** final."

Sub-section (6) provides :

"Notwithstanding the expiry of the period of operation under sub-section (3), the award shall continue to be binding on the parties until a period of two months has elapsed from the date on which notice is given by any party bound by the award to the other party or parties intimating its intention to terminate the award."

4. It is therefore clear that any party bound by an award has a statutory right to terminate the award by due notice on the expiry of the period of operation of the award under sub-section (3) or sub-section (4).

5. In that view of the matter the question arises as to whether an industrial tribunal is competent to go into questions of justifiability of termination of an award by a party in terms of sub-section (6) of Section 19 of the Industrial Disputes Act.

6. This very question came up for determination before the Labour Appellate Tribunal of India in the case of Lister Antiseptic and Dressing Co. (1928) Ltd., v. Their workmen. Indian Factories Journal, Volume V, 1953-54, p. 286. In that case one of the issues referred for adjudication by an industrial tribunal was in the following terms :

(1) Are the Management justified in terminating the award of the Tribunal given effect to by Government Order No. 3433-Lab., dated 23rd June, 1950 ?

The Industrial Tribunal held that the termination of the award by the management was not justified. The management preferred an appeal to the Labour Appellate Tribunal. Learned advocate appearing in support of the appeal contended inter-alia that no question of justification could arise, because the company exercised a statutory right which in law had the effect of terminating the award. The Appelliate Tribunal observed in its judgment ;

". . . We may at once say that the reference as embodied in the first issue is misconceived. In any event, the decision of the Tribunal on this issue is wrong in law. Section 19 of the Industrial Disputes Act, defines the period of settlements and awards. The first two sub-sections deal with settlements arrived at in conciliation proceedings. Sub-sections (3) to (6) to the section deal with awards given by tribunals. Sub-section (3) says that an award shall, subject to the other provisions of section 19, remain in operation for a period of one year. There are two provisos to that sub-section, one which empowers the appropriate Government to reduce the period of operation to a period less than one year and the other to extend, before the expiry of the said period of one year, the period of operation by a year at a time provided that the maximum period did not exceed three years from the date when the award became operative. The meaning of sub-section (5) is that sub-section (3) and its provisos would not be applicable to any award which by its nature, terms or other circumstances does not impose any continuing after it has been given effect to. Sub-section (6) which is the relevant sub-section enacts that "Notwithstanding the expiry of the period of operation under sub-section (3), the award shall continue to be binding on the parties until a period of two months has elapsed from the date on which notice is given by any party bound by the award to the other party or parties intimating its intention to terminate the award". This sub-section obviously contemplates continuous or recurring obligation created by an award. Reading this sub-section with sub-sections (3) and (5) the effect is that an award other than an award of the nature mentioned in sub-section (5) would continue to remain in operation notwithstanding the periods mentioned in sub-section

(3), that is to say, one year or such period as may be fixed under the two provisos to that sub-section had expired, but after the expiry of that period a party, bound by the award, would be at liberty to give notice to the other party of his intention to terminate the award. The right to give notice is thus a statutory right conferred on the parties bound by the award. As soon as the notice is given in pursuance of this sub-section the law takes its course which is that the life of the award, which was then continuing, automatically comes to an end as soon as the period of two months expires from the date of the notice. Such being the statutory provisions, the question whether the employer or the workmen bound by the award was justified in giving the notice or not is a matter which cannot in our opinion form the subject-matter of investigation. It is for this reason that we say that the reference in so far as Issues Nos. 1 and 2 as set out in the schedule of the order of reference is misconceived. ..."

7. Sri P. K. Chatterjee appearing on behalf of the workmen submitted that the real dispute which the Union sought to raised is not reflected in the order of reference. Be that as it may, the tribunal cannot travel beyond the relevant order of reference.

8. In agreement with the views expressed by Labour Appellate Tribunal in the judgment to which reference has been made, I hold that the Reference is misconceived and is not maintainable. The reference is, therefore, rejected.

Dated, Calcutta,
The 26th July, 1979.

S. K. MUKHERJEA, Presiding Officer

[No. L-12011/42/77-D.II. (A)]
S. K. MUKERJEE, Under Secy.

New Delhi, the 20th August, 1979

S.O. 2978.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th August, 1979.

BEFORE SHRI J. P. SINGH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 8 of 1979

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post office, Jamadoba, District Dhanbad.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri S. S. Mukherjee, Advocate

On behalf of the workman : Shri C. P. Rai Sharma, Asstt. Secretary, R. C. Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

AWARD

Dhanbad, 2nd August, 1979

The Government of India, Ministry of Labour is of opinion that an industrial dispute exists between the employer in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limtied, Post office Jamadoba, District Dhanbad and their workman. Accordingly they, by order No. L-20012/16/79-D.III(A) dated 24th February, 1979 referred the said dispute to this Tribunal u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication with the following issue framed :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jamadoba colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, post office Jamadoba, District Dhanbad in terminating the services of Shri S. P. Shukla, Watchman with effect from 21st April 1977 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled."

After receipt of the reference written statement was filed by the employers and the workman prayed for time for filling the same. Ultimately on the next date of hearing i.e. on 2-8-79 the parties filed an amicable settlement incorporating therein the terms of settlement arrived at between them in respect of the industrial dispute pending for adjudication in this Tribunal. The concerned workman went on leave for 20 days w.e.f. 31-3-1977 when he was on temporary employment of the company and he did not resume his duty on the expiry of his leave nor any information was received from him. Since he was in temporary employment of the company and did not extend his leave nor joined his duty on the expiry of the leave, the management terminated the services of the concerned workman w.e.f. 21-4-1977. Now a settlement has been filed in this case under which he has been taken into service. I heard the parties on the joint petition and it is prayed before me that an award may be passed in terms of the settlement filed. The terms of the settlement, beneficial as they are to the parties, are accepted. Nothing therefore stands in the way of an award being passed on the basis of the settlement. Accordingly, I pass the award in terms of the settlement which do form a part of the award as annexure A.

J. P. SINGH, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2,

DHANBAD

Reference No. 8 of 1979

Employers in relation to the Management of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamadoba, District Dhanbad.

AND

Their Workman.

That without prejudice to the respective contentions of the parties contained in the Written statements, the parties have arrived at an amicable settlement on the dispute referred to the Hon'ble Tribunal for adjudiaction on the following terms :—

1. That Sri S. P. Sukla shall be taken on permanent roll of the Company as Watchman with immediate effect.

2. That for the purpose of his seniority he shall be given his date of appointment as 21-1-1977, the date on which his batch of Temporary Watchmen were made permanent.

3. That for the period from 21-4-1977 to the date o his joining, Sri S. P. Sukla shall not be entitled t any wages or other benefits.

4. That the parties will bear their own respective cost of the proceedings.

5. That the terms of settlement are fair and there remained no dispute between the parties which needs any further adjudication by the Honourable Tribunal.

It is, therefore, humbly prayed that the above terms of settlement may kindly be accepted and an Award passed in terms thereof.

	For workmen	For Employers
(S. P. Sukla) Concerned-Workmen.	(C. P. Rai Sharma) Asst. Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Jamadoba Branch, At. & P.O. JAMADOBA, Dist. Dhanbad,	M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P.O. JAMADOBA, Dist. Dhanbad.

[No. L-20012/16/79-D.III(A)]

S.O. 2979.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Muraidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th August, 1979.

BEFORE SHRI I. P. SINGH, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

(NO. 2) DHANBAD

Reference No. 38 of 1979

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Muraidih colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., Post office Nawagarh, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—None.

On behalf of the workmen.—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 10th August, 1979

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Muraidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad and their workmen. Accordingly they, by order No. L-20012/22/79-D.III(A) dated 20-6-79 referred the said dispute to this Tribunal under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 for adjudication with the following issue framed :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Muraidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad is not regularising the services of Shri Devi Mahato and Bhukhal Mahato as Carpenter/Timber Mistry and Pump Khalasi in Category-IV and II respectively, is justified. If not, to what relief are the said workmen entitled ?".

Soon after the notices were issued the Tribunal received through post on 26-7-79 a memorandum of settlement signed by both the parties incorporating therein the terms of settlement arrived at between them in respect of the industrial dispute pending for adjudication in this Tribunal. It appears that the settlement in its turn has been signed by the authorised representative of Bharat Coking Coal and by Shri A. B. Prasad, President, Rastriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad representing the workmen. The terms of the settlement, beneficial as they are to the parties, are accepted. Nothing therefore stands in the way of an award being passed on the basis of the memorandum of settlement. Accordingly, I pass the Award in terms of the memorandum of settlement which do form a part of the Award as Annexure 'A'.

J. P. SINGH, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

Form 'H'

(See rule 58)

Form of Memorandum of settlement between the management of Muraidih Colliery and RCMS on 7-7-79.

Representing employer.—(1) Shri B. N. Jha, Supdt, Muraidih Colliery.

(2) Shri S. N. Sahni, Sr. P.O., Barora Area.

Representing workmen.—(1) Shri Mahendra Singh, Branch Secretary, RCMS.

(2) Shri A. B. Prasad, Vice-President, RCMS.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Shri Bhukhal Mahato and Shri Debi Mahato have raised an Industrial dispute before A.L.C.(C) under Ref. No. 1/141/78-D-3

As no agreement could arrive at, the conciliation failed. Subsequently the dispute was reviewed at the Hqrs. level and it was decided to settle out the issue mutually between management and representatives of the concerned union on the following :

Terms of Settlement

(1) That Shri Bhukhal Mahato and Shri Debi Mahato have been redesignated as Pump Khalasi, Cat. II and Timber Mistry Cat., IV respectively.

(2) That the regularisation in respect of Shri Bhukhal Mahato has been effected on and from 1-4-78 and in respect of Shri Debi Mahato it will be with immediate effect.

(3) That it was agreed that union/workmen shall not claim any wages/dues prior to the dates* period of regularisation as in Sl. No. 2.

(4) That the dispute has been resolved finally.

(5) That the settlement shall be sent to appropriate authorities.

SIGNATURE OF THE PARTIES

Representing employer :	Representing workmen :
1. Shri B. N. Jha, Supdt., Muraidih Colliery.	1. Shri Mahendra Singh, Branch Secretary, RCMS.
2. Shri S. N. Sahni, Sr. P.O., Barora Area.	2. Shri A. B. Prasad, Vice-President, RCMS.
Witnesses :	Witnesses :
(1) Sd/- (illegible)	(1) Sd./- (illegible)
(2) Sd/- (illegible)	(2) Sd./- (illegible)

[No. L-20012/22/79-D.III(A)]

New Delhi, the 21st August, 1979

S.O. 2980.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Coalfields Limited, Giridih Colliery, Post Office and District Giridih and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th August, 1979.

BEFORE SHRI S. N. JOHRI, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Indusrtial Disputes Act, 1947

Reference No. 82 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Coalfields Limited, Giridih Colliery, Post Office & District Giridih.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 10th August, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012/113/77-DIII-(A) dated 22nd August, 1977 for the adjudication of the following industrial dispute :

"(1) Whether the demand of the United Coal Workers Union that the four Loading Munshies and 80 Tripping Truck Loaders mentioned in Annexure A employed for loading work in Giridih Colliery, Post Office Giridih, Giridih in Central Coalfields Limited should be paid as per rates of National Coal Wage Agreement dated 11th December, 1974, is justified ? If so, to what relief are the said workmen entitled ?

(2) Whether the action of the management of Giridih Colliery in rendering the 84 workmen mentioned in Annexure A idle with effect from 1st April, 1977 amounts to illegal lock-out ? If so, to what relief are the said workmen entitled ?"

ANNEXURE 'A'

1	2
1. Md. Ayub Ali	Loading Munshi.
2. Ashok Kumar	-do-
3. Md. Muslim	-do-
4. Md. Sahid	-do-
5. Shyamlal	Dumper Loader.
6. Kishun	-do-
7. Hurwa	-do-
8. Paltu	-do-
9. Panchu Saw	-do-
10. Govardhan	-do-
11. Somar Saw	-do-
12. Gulab Kolh	-do-
13. Sahdeo	-do-
14. Ishwar Kolh	-do-
15. Savitri	-do-
16. Santi	-do-
17. Kunti	-do-
18. Ramlal	-do-
19. Basanti	-do-
20. Shanti	-do-
21. Parvati	-do-
22. Lakhia	-do-
23. Kunti Bhuni	-do-
24. Aziz	-do-
25. Phulmani	-do-
26. Bahadur Mian	-do-
27. Gudada Manjhi	-do-
28. Jairun	-do-
29. Sukra Kolh	-do-
30. Govind Das	-do-
31. Molodi	-do-
32. Polhni	-do-
33. Kudhmi	-do-
34. Sadiq	-do-
35. Hanif	-do-
36. Somai Manjhi	-do-
37. Khiru Kolh	-do-
38. Gulab Mahato	-do-
39. Thakuri	-do-
40. Prakash	-do-
41. Lukhri	-do-
42. Hari Saw	-do-
43. Bellu Das	-do-
44. Baldeo Das	-do-
45. Prabhu	-do-
46. Prayag	-do-
47. Munulal	-do-
48. Bira Lal	-do-
49. Mochu Lal	-do-
50. Bhola Manjhi	-do-
51. Mangar	-do-
52. Bhola Dusadh	-do-
53. Arjun	-do-
54. Bhuneshwar Turi	-do-
55. Chamelwa Turin	-do-
56 Suma	-do-
57. Birendra Roy	-do-
58. Ramia	do-
59. Kalvatia	-do-
60. Sudin	-do
61. Daso Rai	-do
62. Aso Kolh	-do-
63. Mohan Kolh	-do-
64. Nakul Dhanuk	-do-
65. Mangra Manjhi	-do-
66. Babulal	-do-
67. Nirpat Dusadh	-do-
68. Balki Dusadh	-do-
69. Kamdeo	-do-
70. Bhaiya Lal	-do-
71. Bijli	-do-
72. Sonia Chamain	-do-
73. Narain	-do-
74. Chamelwa Chamain	-do-
75. Somi	-do-
76. Sita Ram	-do-
77. Kishori Barhi	-do-
78. Nirpat Bhuinya	-do-
79. Gouri	-do-
80. Sukri Bhuni	-do-
81. Arjun Roy	-do-
82. Kameshwar Singh	-do-
83. Md. Basir	-do-
84. Md. Kudus	-do-

2. It is not disputed that in Gnidih Collieries consisting of inclines and open cast mines—namely Dhobidih mine, 17 B incline, 23 incline, Kolimaran incline, and Khandia mine, the coal produced had to be transported to Khandia and Kolimaran Railway sidings or to the coking coal plant situated near those sidings. Except Khandia mine which is situated just adjacent to Khandia Railway siding and which therefore directly stacks the produced coal on the railway siding, the others being situated one to six kilometers away from the sidings or coking plant, had to stack coal at a short distance from the pit mouth. From there the coal was transported by tipping trucks to the sidings or to the coking plant. Prior to the issue of Notification No. 488 dated 15-2-1975 by the Government of India in the Ministry of Labour, under the provisions of Contract Labour (Regulation and abolition) Act prohibiting coal loading through the contract labour, the company engaged contractors for transporting the stacked coal to the siding in their own tipping truck for the loading of which they were required to employ their own manpower. As many as seven contractor companies were employed for this purpose. Even after the said notification the company continued the process as before unmindful of the illegality.

3. Since 1-1-75 wage rates of the coal loaders were revised under National Coal Wage Agreement but the contractors did not pay them at the revised rates. Demand about regularisation and payments at lesser rates was raised in October 1976. From 5-11-1976 to 9-11-1976 the workers were not taken on work. When that dispute was pending before A.L.C. these workmen were completely stopped from work with effect from 1-4-1977. The company never formally appointed them as their workmen.

4. Union's case is that these four munshis and other tipping truck loaders, (hereinafter called as T.T. Loaders) were being paid at the rate of Rs. 4.50 per day while munshis were paid at the rate of Rs. 130 per month. Other benefits envisaged in National Coal Wage Agreement were not paid to them. The dispute was duly raised with the management and then before the A.L.C. They were illegally locked out with effect from 1-4-1977 Allegations of unfair labour practice and victimisation have been raised.

5. Management has challenged the validity of the reference in as much as no dispute was ever raised before the management, and also because there was no relationship of employer and employee between the company and these workers. The coal stacking points were far away from the mines hence these T.T. loaders could not be deemed to be working in mines. In that case Central Government had no jurisdiction to make the reference Manual coal loading through contractor's labour could not be dispensed with as required by the said notification because these workers did not allow the mechanical pay loader to be introduced till before 1-4-1977 nor they allowed the management to transfer their surplus labour existing elsewhere to these collieries. Due to overall surplus labour in other collieries of the company these contractor's labourers could not be absorbed or regularised as companies employees.

6. The point of the dispute not being at first raised before the management is in view of the demands admittedly made, neither factually substatinable nor of any legal consequence when before the A.L.C. the management admittedly participated in conciliation proceedings and were aware of the nature of the dispute and when they are not ready to concede even today In view of the latest law laid down by the Supreme Court, this plea against the validity of the reference of a non-existent dispute has no force, and is therefore not pressed in arguments by the learned counsel for the management.

7. He however pressed the plea of invalidity of reference for want of jurisdiction in the Central Government because the 'stacked coal, from where T.T. loaders loaded the tipping trucks, did not fall within the definition of Mine Hence they could not be deemed to be mine workers. As such the State Government and not the Central Government was the appropriate Government to refer such a dispute and consequently the State Tribunal and not the Central Tribunal had jurisdiction to entertain the same According to Jainath Rana W.W. 1, the dumping ground is hardly 100 to 150 ft away from the pit mouth the rail line from inside the mine goes straight upto the staking ground and the coal loaded with trolley from inside the mine is tipped at the staking ground by one continuous process. Mine as defined in S. 2(j) of Mines Act, as per clause (x) includes any premises..... adjacent or belonging to a mine, on which any process ancillary to the getting dressing or preparation for sale of minerals..... is being carried on' This ground is not alleged to be not belonging to the mines. The very fact that coal is being dumped there is indicative of the fact that it is part of the mine property. Distance of 100 to 150 ft. from the pit mouth is not a distance which can take it out of the folds of being adjacent specially when rail line and loaded trolleys go upto the tipping point. There the coal is staked for being transported to the railway siding by tipping trucks for being sold. Thus it is very much a part of the mine ad the persons working there are mine workers. Central Government is the appropriate Government and this Tribunal has jurisdiction. The objection is thus ruled out.

8. The next question is whether there was employer employee relationship between these workers and the company. Shri Jainath Rana W.W.1 had admitted that they were the employees of the contractors. According to the Government notification contractor labour system was abolished in respect of coal loaders with effect from 1-2-75. However, Shri P.N. Ghosh MW-1 has explained that they could not discontinue the system from that date. The contract labour did not allow mechanisation, they did not allow transfer of surplus labour of other collieries to come down to this colliery and it was not possible to absorb the contractor's labourers because there was a lot of surplus labour in the area waiting to be absorbed. Shri Ghosh informed the head office of the situation and continued the contractor's labour system for loading the staked coal in the tipping trucks. This continued upto 1-4-77.

9. The question is as to what is the legal effect of this continuance of the contract labour system even inspite of its abolition by a Government Notification with effect from 1-2-75. It is under Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, that the Central Government did issue the notification of abolition of contract labour with respect to coal loading. That section no where provides the consequences of non-compliance with such notification of abolition of contract labour. However, Sections 23 and 25 provide that the contravention of that notification would be an offence which will be cognizable according to Section 26 only on the complaint made by or with the previous sanction in writing of the Inspector and that too within the period of three months of the breach, according to Section 27 of the Act The period of limitation has passed long ago and neither the Inspector filed any complaint nor any attempt was made to obtain his sanction for the prosecution of the officers of the company for continuing the contract labour system even after its abolition Proviso to sub-section (1) of Section 25 of the Act says that a person contravening the notification relating to abolition shall not be liable if he proves that he exercised all due deligence to prevent the commission of such an offence. Shri Ghosh has spelt out the situation that compelled him to continue the contract labour system with the sanction of the higher authorities. It is mute question whether those reasons would amount to exercising due deligence for preventing the commission of such an offence. This proviso indicates that even after declared abolition the bar is not so absolute as to rule out continuance of that system forthwith without adverting to the forces operating against such immediate discontinuance. Interest of the industry may require it's continuance till arrangements are made for suitable alternatives to take the ground. That is why the offence has been made non-cognizable and requires sanction or complaint by the Inspector. Considering all these aspects I am of the view that the notification to be issued under Section 10 is only directory in nature and not mandatory. Thus the fact that Contract Labour System continued for about 2 more years even after it's abolition by a notification was almost un-consequential in its effect on the relationship between the company and the contractor's labourers.

10. The Act no where provides that on the abolition of the contract labour system the contractor's labourers shall be ipso facto absorbed by the company abolishing the contract Such a provision has not been made by the legislature deliberately because it may give rise to various complications. As in the present case the company had already surplus labour elsewhere which they wanted to absorb. It will be too much

to ask the industry to absorb the contractor's labourers even when the industry itself has its own surplus labour to be absorbed. It may be, as in the present case, that the company wanted to go in for mechanised working of the loading system which would render all these contractor's labourers as unnecessary dead weight to be carried by the industry. Sri Gupta has stated on oath that he wanted to bring pay loader (an atomatic loading machine) but the contractor's labourers did not allow it to work. Ultimately by 1-4-77 the company diverted one of its pay loaders to this area for mechanised loading and when it could be successfully installed the management did do away with the contract labour system for coal loading. It is for these and similar reasons that the Act has not provided that on the abolition of contract labour system the contractor's labourers would inso facto become absorbed workmen of the company. This omission appears to be deliberate if read with specific provisions enacted in the Coking Coal Nationalisation Act and other such Acts which take care of continued service security and emoluments of the workmen of the earstwhile owners.

11. Under the circumstances a heavy burden lay on the union and the workmen to show that they were actually appointed by the company on some date after 1-2-75 as their own workmen. They have failed to establish it. Neither there is any identity card with any of these workmen nor any appointment letter. Their personal files have not been opened and there is no evidence to show that they were being paid as the workers of the company. The payment if any was being made on behalf of the contractor and under the personal supervision of an officer of the company as required by the Act. It is not correct that such payment was being made on Sundays. The management's witness has categorically stated that no cash transactions are done on holidays. The union leader who appeared in the witness box could not say whether the payment that was being made to the workers was debited by the company to the account of the contractor or not.

12. Considering all these factors it is clear that the relationship of employer and employer never came into existence between these 84 workmen and the Central Coalfields Limited. Therefore the fact that they became idle from 1-4-77 does not amount to illegal lock out by the company. The workmen are not entitled to any relief of this count. As there was no relationship of Employer and employee between these labourers and the company no dispute between them could amount to an industrial dispute and as no industrial dispute came into existence the Central Government acquired no jurisdiction to refer the same to this Tribunal. The reference part (2) is thus no maintainable.

13. As for reference part (1) it goes without saying that after coming into force of National Coal Wage Agreement the contractor's coal loaders should have been paid at the rate specified therein. If the payment has not been made accordingly, the workers should make a demand from the contractor for paying the difference and if the contractor fails, the difference can be claimed by the workers from the principal employers through Application under Section 33C(2) of the Industrial Disputes Act. The reference is answered accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer
[No. L-20012/113/77-D. III(A)]

S.O. 2981.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th August, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 8 of 1979

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Jamadoba Colliery of M/s Tata Iron & Steel Co. Ltd., P. O. Jamadoba, District Dhanbad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the Management—None.

For the Workmen—None

STATE: Bihar INDUSTRY: Coal.

Jabalpur, dated the 7th August, 1979

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012/225/78-D. III(A) dated, the 19th January, 1979, for the adjudication of the following industrial dispute:

"Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad in correcting the date of appointment of Shri Haider, Pump Khalasi (Ticket No. 25996) from August, 1938 to 11th March, 1940 is justified? If not, to what relief is the said workmen entitled?"

2. The parties filed a settlement out of court on 1-8-1979. I have gone through the terms of settlement. They appear to be fair and proper. Award is given in terms of the settlement which shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L-20012/225/78-D. III(A)]
S. H. S. IYER, Desk Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1, DHANBAD

Reference No. 8 of 1979

Employers in relation to the Management of Jamadoba Colliery of M/s Tata Iron & Steel Co. Limited., P.O. Jamadoba, District Dhanbad.

Their Workmen

That the parties abovenamed have come to an amicable settlement on the following terms:

1. That the date of appointment of Sri Haider, Pump Khalasi (T. No. 25996) will be taken as 10th August, 1938.
2. That the date of appointment namely 10th August, 1938 will be mentioned in all relevant records maintained in the Colliery concerning the workmen.
3. That the above terms of settlement finally resolves the dispute referred to the Honourable Tribunal and there remains no further dispute which needs adjudication by the Honourable Tribunal.

It is, therefore, prayed that the above terms of settlement may kindly be approved and an Award passed in terms thereof.

For Union
(C. P. Raysharma)
for Workmen
(Haidar)
for Employer.
Sd. Illegible.

नई दिल्ली, 1 सितम्बर 1979

का० आ० 2982.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) द्वितीय संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ?

2 निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में,—

(1) नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि अभिकरण-कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार है, तब उसकी सच्चाई की जांच वह स्वयं कर सकेगा या ऐसा करने के लिए इस नियम के अधीन किसी जांच सेवक की नियुक्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—जहां कि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहां उपनियम (7) से लेकर उप-नियम (20) तक में और उपनियम (22) में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है";

(2) नियम 11 के उप-नियम 5 (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"5(ग) जहां कि अनुशासन प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेदों की जांच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए कोई जांच प्राधिकारी नियुक्त करता है वहां वह आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी सरकारी सेवक या विधि-व्यवसायी को, आदेश द्वारा, नियुक्त कर सकेगा, जो "उपस्थापक आफिसर" के नाम से ज्ञात होगा";

(3) नियम 11 के उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(8) अभिकरण कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए किसी सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि-व्यवसायी तब तक नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापक आफिसर विधि व्यवसायी नहीं है अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे";

3. नियम 24 के उप-नियम (2) के परन्तुक (1) और (2) में से निम्नलिखित शब्दों का, जहां कहीं वे आए है, लोप किया जाएगा, अर्थात :—

"प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, नियम 12 के उप-नियम (4) के उपबन्धों के यावतशक्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात"।

4. नियम 26 के परन्तुक (2) में से निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात :—

"तथा संबंधित व्यक्ति को ऐसे अभ्यावेदन जैसे कि वह अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध करना चाहताहै करने का अवसर देने के पश्चात"।

[सं० 3/11/76 ई० आई एण्ड ई० पी०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 1st September, 1979

S.O. 2982.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 viz.—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978.—

(1) for sub-rule (2) of rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"(2) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiry into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against agency employee, it may itself, inquire or appoint under this rule a public servant to inquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the disciplinary authority itself holds inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) to the inquiry authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority";

(2) for sub-rule 5(c) of rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"5(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a public servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of articles of charge.";

(3) for sub-rule (8) of rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"(8) The agency employee may take the assistance of any public servant to present the case on its behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the presenting officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority having regard to the circumstnces of the case, so permits";

3. In provisos (i) and (ii) of sub-rule (2) of rule 24, the following words, wherever they occur, shall be omitted, namely :—

"after giving the appellant a reasonable opportunity as far as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 12 of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such enquiry".

4. In the proviso (ii) of rule 26, the following words shall be omitted, namely :—

"after giving the person concerned an opportunity of making any representation which he may wish to make against such penalty".

[F. No. 3(11)76-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग प्रभाग)

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1978

का. आ. 2983.—भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 53 (2) के अनुसार केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है, जो नीचे उद्धृत की जाती है:—

पहली जुलाई 1977 से 30 जून 1978 तक के

वर्ष के भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज पर

वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय 1 आर्थिक स्थिति-1977-78

इस वर्ष के दौरान किस की दर में उल्लेखनीय सुधार पाया गया । अनाजों तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति और सुधरी । पहले इन दोनों की स्थिति अर्थव्यवस्था में अत्यधिक शोचनीय हुआ करती थी । मुद्रा उपलब्धि में काफी अधिक वृद्धि होने के बावजूद वस्तुओं की मूल्य प्रवृत्तियां आम तौर पर काफी संतोषजनक थीं । इसका कारण यह था कि कुछ अत्यधिक उपभोक्ता वस्तुओं और दुर्लभ कच्चे माल की पूर्ति उदार आयातों और भीतरी आवाजाही पर लगाये गये प्रतिबन्धों में ढील दिये जाने के कारण काफी अच्छी रही ।

2. इन संतोषजनक परिस्थितियों के साथ साथ वर्तमान स्थिति के कुछ चिन्ताजनक पहलू भी थे । औद्योगिक वृद्धि की गति में अवरोध रहा है और उद्योग क्षेत्र की रुग्णता में वृद्धि हुई है । देशी निवेश की अपेक्षा देशी बचत में वृद्धि के कारण हुई प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में और अधिक वृद्धि तथा सार्वजनिक क्षेत्र के जो खाद्यान्न स्टाक निकाले जाते हैं उनमें कमी आयी-यह स्थिति अर्थव्यवस्था में पायी गई थोड़ी-सी मंदी की द्योतक है; किन्तु यह कहा जा सकता है कि मंदी की यह स्थिति विकासपरक बजट संबंधी तथा अन्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक समयान्तर के कारण उत्पन्न हुई है । वस्तुतः इस वर्ष की अन्तिम तिमाही में औद्योगिक उत्पादन की गति में तेजी के संकेत पाये गये हैं और योजना व्यय में जैसे-जैसे वृद्धि होगी, तेजी की यह प्रवृत्ति इस वर्ष में बाद में और सशक्त होगी । इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि लगातार दूसरे वर्ष भी मुद्रा उपलब्धि में काफी अधिक वृद्धि हुई है तब इस दिशा में निरंतर सतर्कता बरतने की आवश्यकता सुनिश्चित होती है ।

3. इस वर्ष के दौरान इस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए कई नीतिगत प्रयास किये गये हैं । निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से कतिपय वर्तमान नियंत्रणों और प्रतिबंधों को शिथिल किया गया आयात नीति काफी उदार बनायी गई । औद्योगिक लाइसेंसीकरण के लिए निर्धारित छूट सीमाओं को बढ़ाया गया । अनुपूरक राजकोषीय और मुद्रागत प्रयासों से ऋण की लागत में कमी आयी । इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र तथा रोजगार प्रधान कार्यों के विकास पर जोर देते हुए अधिक संतुलन लाने का प्रयास किया गया । नयी औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के लिए अलग से आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया । छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के प्रमुख उद्देश्यों में बेरोजगारी और व्यापक रूप से विद्यमान न्यून रोजगारी को दूर करना तथा अगले दस वर्षों में समाज के बहुत अधिक निर्धन वर्गों के जीवन स्तर को बढ़ाना भी है । इस दिशा में प्रयास जारी रखने होंगे ।

4. बाह्य दृष्टि से रुपया सापेक्ष रूप में प्रायः स्थिर रहा है । भारत के प्रमुख व्यापार सहयोगियों के मुद्रा समूह के संदर्भ में 1975 से रुपये का मूल्य सुनिश्चित किये जाने के कारण यह स्थिरता आ सकी । आलोच्य वर्ष के दौरान दो मामूली समायोजनों को छोड़कर स्टर्लिंग के संदर्भ में (जो मध्यवर्ती मुद्रा है) रुपये की विनिमय दर काफी स्थिर रही । किन्तु प्रमुख मुद्राओं, विशेषकर अमेरिकी डालर के मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव होने के कारण जून 1978 से विनिमय दर में कुछ और परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है । विशिष्ट मुद्रा समूह के संदर्भ में रुपये के विनिमय मूल्य को बनाये रखने की नीति के कारण निर्यातों से अर्जित किये जानेवाले रुपये की वसूली में अनिश्चितता की स्थिति कम हो गई है और इस कारण भारत का विदेशी व्यापार संरक्षित हो गया है । फिर भी 1977-78 में विश्व की जो स्थिति विद्यमान थी वह निर्यात की वृद्धि को बनाये रखने के अनुकूल नहीं थी । प्रमुख औद्योगिक देशों में मंदी की स्थिति होने के कारण विश्व व्यापार की मात्रा में होनेवाली वृद्धि 1976 के 11 प्रतिशत से गिरकर 1977 में लगभग 4 प्रतिशत हो गयी है । औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को जब मंदी का सामना करना पड़ा तब संरक्षण की प्रवृत्ति और सशक्त हो गयी । इसके अलावा कुछ ऐसी निर्यात वस्तुओं के मामले में प्रतिकूल स्थितियां पायी गयीं जिन के कारण पिछले वर्ष निर्यातों में काफी अधिक वृद्धि हुई थी । इसके विपरीत पहले से अधिक उदार आयात नीति के कारण काफी अधिक आयात होने लगे जिसके परिणामस्वरूप 1977-78 में विदेश व्यापार के लेखे में पुनः घाटे का सामान्य स्वरूप पाया गया । साथ ही अप्रैल-जून 1978 में प्रारक्षित निधियों की वृद्धि के दर में उल्लेखनीय गिरावट आने के संकेत भी मिलने लगे ।

राष्ट्रीय आय और उत्पादन

5. 1977-79 (अप्रैल-मार्च) के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर 6 प्रतिशत के आसपास होने की आशा है । यह वृद्धि दर 1976-77 में 1.6 प्रतिशत थी । वृद्धि की यह उच्चतर दर कृषि क्षेत्र के अच्छे कार्य के कारण हो सकी । इसके विपरीत औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर इस वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत कम थी । 1976-77 की स्थिति भिन्न थी । तब प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आयी थी और औद्योगिक उत्पादन

में काफी अधिक वृद्धि हुई थी । १९७५-७६ में १९७७-७८ की तरह ही राष्ट्रीय आय की वृद्धि में कृषि का योगदान उल्लेखनीय था, जब कि उद्योग क्षेत्र पीछे रह गया था ।

बचत और निवेश

६. प्रारंभिक प्राक्कलनों के अनुसार स्थायी मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में देशी बचत का अनुपात १९७६-७७ (परिशोधित) में स्थित १७.९ प्रतिशत से गिरकर १९७७-७८ में १५.७ प्रतिशत हो गया इसका प्रमुख कारण यह था कि घरेलू क्षेत्र की बचत-आय अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आ गयी थी । प्रमुखत: अनिवार्य जमा योजना के अधीन चूकौतियों के कारण सरकार पर किये गये दावे जैसी वित्तीय आस्तियो, जमाराशि और चलमुद्रा में कम वृद्धि होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई । जहां सार्वजनिक क्षेत्र की बचत के अनुपात में भी सीमान्त रूप से गिरावट आयी वहां देशी कपनी क्षेत्र की बचत का अनुपात पिछले वर्ष के स्तर पर ही अपरिवर्तित रहा । यह स्थिति सारणी १ से स्पष्ट होती है । राष्ट्रीय आय में वित्तीय साधनो के वितरण का अनुपात भी पिछले वर्ष की तुलना में कम था (जहां पिछले वर्ष १.८ प्रतिशत था वहां इस वर्ष १ ४ प्रतिशत हो गया अत: समग्र निवेश में कमी आयी जो बचत की अपेक्षा कुछ कम थी । निवेश की स्थिति का संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नही है उपर्युक्त गिरावट के अश का यह कारण हो सकता है कि वस्त्र, इस्पात और सीमेन्ट जैसे उद्योग क्षेत्र के स्टाकों में कम निवेश हुआ ।

सारणी : १

देशी बचत और निवेश के प्राक्कलन

(अनंतिम)

वर्तमान मूल्यो पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मे प्रतिशत स्थायी मूल्य

वित्तीय वर्ष	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
1. घरेलू क्षेत्र	8 2	10 0	12 5	10 4
2. सार्वजनिक क्षेत्र	4 2	5 3	5 0	4 8
3 देशी निजी कंपनी क्षेत्र	1 0	0 3	0 4	0.4
4. कुल देशी बचत (1+2+3)	13 4	15 6	17 9	15 6
5. विदेशी साधनों की प्राप्ति	+0 9	+0.3	—1 8	—1.4
6 कुल निवेश (4+5)	14 3	15 3	16 1	14.2

टिप्पणी :—1974-75 से 1976-77 तक के अनुमानो को अंशत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के राष्ट्रीय आय संबंधी प्राक्कलनो के परिवर्तन के कारण और अंशत बचत तथा निवेश के विभिन्न घटकों के संशोधित आंकड़े अपलब्ध होने के कारण परिशोधित किया गया है।

कृषि उत्पादन

७. नवंबर १९७७ में दक्षिण-पूर्व तटवर्ती प्रदेश भयानक तूफान का शिकार हुआ । फिर भी १९७७-७८ के दौरान सामान्य मौसमी स्थितियां कृषि के लिए अनुकूल थी । इस वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में ११ प्रतिशत और १२ प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई । इससे तत्संबंधी सूचकांक (आधार: १९६९-७० में समाप्त होने वाले तीन वर्ष = १००) इस वर्ष १३१ के आस-पास पहुंचा । यह सूचकांक १९७५-७६ में १२५.५ के शिखर स्तर पर पंहुचे सूचकांक से भी अधिक है । अद्यतन प्राप्त आधिकारिक प्राक्कलनों के अनुसार खाद्यानों के उत्पादन की मात्रा लगभग १२५० लाख टन है जब कि १९७६-७७ में उक्तत मात्रा १,११६ लाख टन थी । आशा है कि खरीफ अनाजों के उत्पादन की मात्रा १९६७-७७ के ६६६ लाख टन की तुलना में लगभग ७७० लाख टन होगी जब कि रबी खाद्यानों के उत्पादन की मात्रा इस वर्ष बढ़कर ४८० लाख टन के नये शिखर पर पहुंचेगी । रबी खाद्यान्नों के उत्पादन की मात्रा १९७६-७७ में ४५० लाख टन और १९७५-७६ में ४६६ लाख टन थी जो उस समय का शिखर स्तर थी । सारणी २ में १९७४-७५ से लेकर प्रमुख कृषि वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित आंकड़े दिये गये हैं:

८. नकदी फसलों में से गन्ने का उत्पादन काफी अच्छा था । गन्ने के उत्पादन की मात्रा १६५ लाख टन (गुड़ के रूप मे) परिकल्पित है । यह मात्रा अब तक के उत्पादन की अपेक्षा अधिकतम है । प्रमुख पाच तिलहनों (मूंगफली, तोरिया सरसो, तिल अलसी और एरंड) के अनुमानित उत्पादन की मात्रा ९४ लाखा टन है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा १६ लाख टन अधिक, किन्तु १९७५-७६ के शिखर स्तर से सीमांत रूप से कम होगी । अब रूई के उत्पादन की मात्रा ६८ लाख गांठे निर्धारित है । जूट के उत्पादन के संबंध मे यह अनुमान है कि उसकी मात्रा ७१ लाख गांठे होंगी जो आवश्यकताओ की पूर्ति करने मात्र के लिए पर्याप्त होगी ।

९. कृषि क्षेत्र के संतोषजनक कार्य का प्रमुख कारण अनुकूल मौसम था । इसके अन्य कारण इस प्रकार थे : विकसित टैक्नोलाजी का प्रयोग किया गया और उर्वरको तथा अन्य मूलभूत वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा अच्छी थी । १९६६-६७ से १९७६-७७ तक की अवधि के दौरान उर्वरको की खपत की मात्रा तिगुनी हुई अर्थात वह ११ लाख टन से बढ़कर ३४ लाख टन हो गई । इस वृद्धि के साथ-साथ उर्वरको की अधिक संतुलित किस्म का प्रयोग किया जाने लगा ।

सारणी : २

कृषि उत्पादन—चुनी हुई वस्तुएं

	इकाई	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78 (अनंतिम)
खरीफ खाद्यान्न	10 लाख टन	59.1	74.2	66.6	77.0
रबी खाद्यान्न	,,	40.7	46.6	45.0	48.0
कुल खाद्यान्न	,,	99.8	120.8	111.6	125.0
दालों से भिन्न अनाज	,,	89.8	107.7	100.4	112.2
चावल	,,	39.6	48.7	42.8	50.0
गेहूं	,,	24.1	28.9	29.1	31.0
दालें	,,	10.0	13.0	11.2	12.8
खाद्यान्नों से भिन्न वस्तुएं :					
रूई	10 लाख गांठें-प्रति गांठ–170 कि०ग्रा०	7.2	5.9	5.8	6.8*
जूट और मेस्ता	10 लाख गांठें-प्रति गांठ–180 कि०ग्रा०	5.9	5.9	7.1	7.1@
तिलहन (5 प्रमुख तिलहन)	10 लाख टन	8.5	9.9	7.8	9.4‡
मूंगफली छिलके सहित	,,	5.1	6.8	5.3	6.0†
गन्ना (गुड़ के रूप में)	,,	14.7	14.4	15.8	16.5

*रूई सलाहकार मंडल के प्राक्कलन
@अंतिम प्राक्कलन
†आधिकारिक प्राक्कलन
‡व्यापार प्राक्कलन

पहले नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर अधिक निर्भरता रहती थी ; अब वह फोस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग से कम हो गयी। शुद्ध सिंचित भूमि जहां १९६६-६७ में २७१ लाख हेक्टेयर थी वहां १९७४-७५ में ३३७ लाख हेक्टेयर हो गयी। कृषि उत्पादन में पहले से जो अधिक तीव्रता आयी है उसका उदाहरण ग्रीष्मकालीन चावल की फसल के उत्पादन में हुई वृद्धि है। इस फसल के उत्पादन की मात्रा जहां कुछ साल पहले केवल १५ लाख टन के आसपास थी वहां अब बढ़कर ५० लाख टन से अधिक हो जाने का अनुमान है।

१०. किन्तु इस दिशा में कुछ कमजोर पहलू निरन्तर पाये जाते रहे हैं। इन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू मोटे अनाजों और दालों का उत्पादन है जिसकी प्रवृत्ति गेहूं और चावल के उत्पादन के समान नहीं है। विशेष रूप से दालों का उत्पादन पिछले १० वर्षों में बहुत कम घटता-बढ़ता रहा है। इन १० वर्षों का औसत उत्पादन केवल १११.४ लाख टन रहा है। मोटे अनाज प्रमुख सूखी फसलें हैं। उनके उत्पादन में निरन्तर उतार-चढ़ाव रहता है। और वे फसलें मौसमी तत्वों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। दालों और मोटे अनाजों के दोनों समूह विशेष महत्व रखते हैं—पहला तो पौष्टिकता की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है और दूसरे का महत्व इसलिए है कि वह सारे देश में निर्धन वर्गों के लोगों का परंपरागत स्थायी भोजन है। नयी कृषि नीतियों पर अमल करते समय इन खाद्यान्नों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंचाई की व्यापकता भी असमान है और काफी बड़ा क्षेत्र अब भी वर्षा पर निर्भर करता है। नयी टैकनालाजी के अनुसंधान प्रयास में वाणिज्यिक फसलों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है; लेकिन सोयाबीन जैसे कुछ तिलहन और रूई इसके अपवाद हैं। रूई के क्षेत्र में लंबे रेशेवाली और अधिक उपज की कुछ किस्में प्रयोग में लायी गयी हैं। अतः इन वस्तुओं की उपज और उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास निरन्तर जारी रहने चाहिए ; साथ ही रूई और वनस्पति तेलों/तिलहनों की अधिक पूर्ति करने के लिए पिछले वर्ष उनके जो आयात शुरू किये गये उनको भी अपर्याप्त देशी उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में कुछ और समय तक जारी रखना होगा।

वसूली के कार्य और स्टाक

११. आलोच्य वर्ष के दौरान यद्यपि अनिवार्य वसूली की व्यवस्था नहीं थी फिर भी सरकारी एजेंसियों द्वारा वास्तव में खरीदे गये चावल और गेहूं की मात्रा काफी अधिक थी। १९७७-७८ के मौसम (अप्रैल—जून) के दौरान ५४ लाख टन का गेहूं खरीदा गया जबकि पिछले मौसम में खरीदे गये गेहूं की मात्रा ६६ लाख टन थी। १९७८-७९ के रबी मौसम में जून १९७८ के अंत तक ५३ लाख टन गेहूं की वसूली की गयी है जब कि १९७७-७८ की इसी अवधि में ४८ लाख टन गेहूं की वसूली की गयी थी। २४ जून १९७८ तक कुल ४७ लाख टन चावल की वसूली की गयी जबकि १९७६-७७ के खरीफ विपणन मौसम में ४३ लाख टन चावल की वसूली की गयी। इस तथ्य के बावजूद कि इन वस्तुओं का बाजार अब खुला है और इनके यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सरकार ने इन अनाजों का जो उपर्युक्त क्रय किया वह मूल्य-समर्थन की मात्रा का सूचक है। खाद्यानों की संतोषजनक पूर्ति की स्थिति के कारण इस वर्ष उनका आयात करना आवश्यक नहीं था।

१२. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यानों के जो स्टाक जून १९७७ के अंत में २०७ लाख टन के अधिकतम स्तर तक पहुंच चुके थे वे अक्तूबर १९७७ के अंत में घटकर १७४ लाख टन हो गये और जनवरी १९७९ के अंत तक इसी स्तर पर बने रहे। इसके बाद अगले तीन महीनों में और

घटते हुए उक्त स्टाक अप्रैल १९७८ के अंत में १८८ लाख टन हो गये । परन्तु वे पुन बढ़ते हुए जून १९७८ के अंत तक १९० लाख टन तक पहुंच गये । सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो खाद्यान्न खरीद जाते हैं वे जहां १९७६ में ९३ लाख टन थे वहां १९७७ में बढ़कर ११६ लाख टन हो गये । जनवरी—जून १९७८ के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जिन खाद्यानों की वसूली की गयी उनकी मात्रा ५६ लाख टन थी जो पिछले वर्ष की उक्त अवधि में वसूली गयी मात्रा के बराबर ही थी ।

औद्योगिक उत्पादन

१३ कृषि उत्पादन के विपरीत १९७७ में औद्योगिक उत्पादन का स्तर असंतोषजनक था । औद्योगिक उत्पादन में ५.३ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई । यह वृद्धि पिछले वर्ष की १०.६ प्रतिशत की वृद्धि* की आधी थी । इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक (आधार: १९७० = १००) के मासिक औसत में १९७७ में केवल ७.० प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १९७६ में उसमें १२.७ प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी । औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में जो मंदी आयी वह १९७७ के उत्तरार्ध में (जुलाई—दिसंबर) न केवल बनी रही बल्कि वास्तव में बढ़ती ही गयी । इस वर्ष के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध में औद्योगिक उत्पादन के औसत सूचकांक में २.० प्रतिशत की गिरावट आयी । यह प्रवृत्ति पिछले छ: वर्षों में पायी गयी स्थिति के बिल्कुल विपरीत थी । पिछले छ: वर्षों में से हर वर्ष जुलाई—दिसंबर की अवधि का औसत सूचकांक उसके पहले के छ: महीनों के औसत की तुलना में बढ़ता हुआ पाया गया था । इस वर्ष औद्योगिक सूचकांक में जो कमी आयी वह सभी प्रमुख औद्योगिक समूहों में पायी गयी ।

१४ औद्योगिक समूहों में १९७७ में वृद्धि की जो गति पायी गयी वह विशेष रूप से मूल उद्योगों (वजन ३२.२८ में कम थी । इन उद्योगों में जहां १९७६ में १४.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां १९७७ में केवल ४.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई । मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग समूह (वजन २०.९५) की वृद्धि दर काफी कम थी और उपभोक्ता वस्तुओं के समूह (वजन ३१.५२) की वृद्धि दर १९७६ के १०.२ प्रतिशत के मुकाबले १९७७ में ६.४ प्रतिशत थी । पूंजीगत वस्तुओं के समूह (वजन १५.२५) की वृद्धि दर १९७७ में ९.७ प्रतिशत थी जब कि पिछले वर्ष उक्त दर १० ५ प्रतिशत थी ।

१५. औद्योगिक विकास में कई कारणों से गिरावट पायी गई । निवेश में मंदी आयी । देश के कुछ ऐसे भागों में जहां काफी अधिक उद्योग विद्यमान हैं बिजली की बहुत अधिक कमी थी । कोयला और सीमेंट जैसी कुछ प्रमुख वस्तुओं की कमी थी । इन सब के अलावा औद्योगिक अशान्ति के कारण भी औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

१६-१९७८ के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्षेत्र में कुछ सुधार होने का संकेत मिलता है । आशा है कि जैसे-जैसे योजनागत परिव्यय में वृद्धि होगी, इस प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु उसमें और तीव्रता आएगी । मीयादी ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश नियम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) द्वारा प्रदत्त सहायता संबंधी आंकड़ों से भी यह विदित होता है कि निजी निवेश में पुन: थोड़ा सा सुधार होने लगा है । इन संस्थाओं द्वारा जुलाई १९७७ से मार्च १९७८ तक की अवधि के दौरान मंजूर किये गये कुल ऋण १९७६-७७ की उसी अवधि में मंजूर किये गये ऋणों से १९ १ प्रतिशत अधिक थे इन संस्थाओं द्वारा विपरीत राशि में ११ २ प्रतिशत की वृद्धि हुई । उद्योग क्षेत्र में, विशेष रूप से निर्माण उद्योग में, जो सुधार हुआ है उसका प्रमाण सीमेंट और कोयले के प्रयोग की मात्रा में हुई वृद्धि है । इन दोनों वस्तुओं के प्रयोग में १९७७-७८ में क्रमश ७ प्रतिशत और ११ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई ।

क्षमता और स्टाक

१७ उद्योग क्षेत्र के परिचालन संबंधी पहलुओं अर्थात क्षमता के उपयोग की मात्रा और स्टाकों के स्तरों आदि की जानकारी आंशिक है; अत: उक्त जानकारी मूलत: विवरणात्मक रूप से प्रस्तुत है । उपलब्ध आंकड़ों से विदित होता है कि एल्यूमिनियम और विक्रेय इस्पात जैसे कुछ उद्योगों में प्रमुखत: बिजली की कमी के कारण क्षमता के उपयोग में गिरावट आयी है । चूंकि साइकिल टायर, सूत के धागे और कपड़े, मशीनी उपकरणों और कपड़े की मशीनों आदि के उद्योगों में १९७६ में बहुत अधिक स्टाक जमा हो गये थे अत: संबंधित उद्योग अपने उत्पादन में कमी लाये और वर्तमान स्टाकों को बाहर लाने लगे । उदाहरण के लिये वर्ष के अंत में जो सूती कपड़ा बिका नहीं था उसका स्टाक १९७६ में स्थित २,०५५ लाख मीटर की तुलना में १९७७ में १,५१४ लाख मीटर था । सूती धागे का अनबिका स्टाक ११० लाख किलोग्राम के मुकाबले ९३ लाख किलोग्राम था । कुछ ऐसे उद्योग भी थे जो उच्चतर क्षमता के साथ कार्य कर रहे थे । इन उद्योगों में बिजली के पंखों, रेफ्रिजरेटर, सूखी बैटरियों, सिगरेट और मोटर कारों के उद्योग शामिल थे । चीनी उद्योग का उत्पादन उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था । इस कारण और साथ ही चीनी के निर्यातों में गिरावट आने से चीनी के स्टाकों में काफी अधिक वृद्धि की स्थिति पायी गयी । चीनी के स्टाक जहां पिछले मौसम के अंत में ८.४५ लाख टन थे वहां १९७६-७७ के अंत में बढ़कर १५.७६ लाख टन हो गये । जून १९७८ में चीनी उद्योग के पास ४५.५ लाख टन के स्टाक थे जबकि एक वर्ष पहले २५.० लाख टन विद्यमान थे । गंभीर रुप से क्षमता के अवरोध का सामना करने वाला उद्योग सीमेंट उद्योग था । इस उद्योग में लगभग ९० प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाता था । सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने उसका आयात करने का निश्चय किया । परिणामत: १९७७ के अंत में २.५ लाख टन सीमेंट के स्टाक थे जो पिछले वर्ष के अंत में स्थित २.३ लाख टन स्टाक से सीमांत रूप से अधिक थे ।

औद्योगिक रुग्णता

१८ जहां सामान्य विकास की स्थिति से अलग अलग औद्योगिक इकाइयों का परिचालन व्ययसाध्य हो सकता है वहां औद्योगिक रुग्णता गंभीर चिन्ता का विषय हो गयी है । रुगणता की यह व्यापकता इस बात से स्पष्ट है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती रही है । उक्त इकाइयां मूल्यह्रास की व्यवस्था करने से पहले भी हानि उठाती रही हैं और निकट भविष्य में उन इकाइयों के इसी प्रकार बने रहने की आशा है । दिसंबर १९७६ और

* 1977-78 के वित्तीय वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि 3 4 प्रतिशत थी जबकि वह 1976-77 में 10 4 प्रतिशत थी ।

सितंबर १९७७ के बीच ऐसी इकाइयो की संख्या२४१ से बढ़कर २७० हो गयी और उनका बकाया बैंक ऋण ६०९ करोड़ रुपयो मे (जो बड़े और मझौले उद्योगो को दिये गये बैंक ऋण का ११ प्रतिशत है)बढ़कर ७७४ करोड़ रुपये (१४ प्रतिशत) हो गया है । ये आकड़े केवल कुच्छेक उद्योगों से संबंधित है । अनुमान है कि लघु उद्योग क्षेत्र की ८,००० इकाइयो मे २०० करोड़ रुपयो तक की बैंक निधियां अवरुद्ध हो गयी है । अधिक मात्रा मे विद्यमान और बढ़ती हुई बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य मे रुग्ण इकाइयों को बन्द कर देने से समस्या का हल नही निकलता है । इसके विपरीत क्षमता की संभावना युक्त रुग्ण इकाइयों को पुनः स्वस्थ बनाने का कार्य बड़ा जटिल है और इसके लिए कई दृष्टियों से समन्वित प्रयास करना होगा । इस प्रकार का प्रयास करते समय अलग-अलग इकाइयों की स्थितियों को ध्यान मे रखना होगा ।

१९. औद्योगिक रुग्णता के कारण या तो आंतरिक (इकाइयो के सदर्भ मे) अथवा बाह्य (उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र के संबंध मे) या दोनों हो सकते है । जहां तक आंतरिक रुग्णता का प्रश्न है उसके कई कारण है, जैसे गलत ढ़ग से बनायी गयी योजना और उसका कार्यान्वयन, उपयुक्त वित्तीय व्यवस्थाओ का अभाव, क्षमता विहीन प्रबंध आदि । इसके विपरीत बाह्याय कारणो मे समग्र आर्थिक परिवेश, मूलभूत कमजोरी, मांग की कमी, पूर्ति मे अवरोध, अनुपयुक्त मूल्य नीतिया आदि सम्मिलित है । उपयुक्त सरकारी नीतियो द्वारा इन कमजोरियो को दूर किया जा सकता है । किन्तु सभी औद्योगिक इकाइयां समान रूप से इन बाह्य करणों से प्रभावित नही होती; क्योकि उनके आकार, व्यापकता, आतरिक क्षमता और लचीलेपन में अंतर है । किन्तु इन विभेदो के कारण सरकारी नीतियो मे स्पष्टत: आवश्यक और उपयोगी परिवर्तन लाने मे विलंब नही किया जाना चाहिए । वित्तीय संस्थाए, औद्योगिक रुग्णता का योजनाबद्ध और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हुए एवं प्राधिकारियो को उससे अवगत कराते हुए इस प्रक्रिया में सहायता पहुचा सकती हैं ।

२०. रुग्ण इकाइयो को ऋण प्रदान करने के मामले मे बैंको और वित्तीय संस्थाओ को तीन प्रकार की समस्याएं होती है: उनकी आस्तियां कमजोर हो जाती है, ऋणो के अवरुद्ध हो जाने से उनकी ऋण योग्य निधियों की पुनर्निवेश प्रक्रिया मे कमी आ जाती है और ब्याज से प्राप्त आय मे गिरावट आती है । बैंक और वित्तीय संस्थाए अधिकांश रुग्ण खातो को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाती है । वाणिज्य बैंको और वित्तीय संस्थाओ मे इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा रुग्ण उद्योगों की समस्या के समाधान के लिये संयुक्त कार्यक्रम बनाने मे सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्रवाइयां की गयी है । फिर भी रुग्ण यूनिटो के पुन:स्थापन के बोझ का वहन करने में वाणिज्य बैंकों की क्षमता पर पड़ने वाले कुछ मूलभूत अवरोधों को स्वीकार करना चाहिये । सभी परिस्थितियों मे रुग्ण यूनिटो की सहायता करना बैंको के लिये न तो संभव है और न ही व्यावहारिक । इस संदर्भ मे रोजगार का संरक्षण करना मात्र कोई मानदंड नही हो सकता । वस्तुत: इकाइयों की दीर्घकालीन क्षमता का वास्तविक अर्थ मे मूल्यांकन करना जरूरी है ।

२१. आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के निर्माण के उद्देश्य से बनाये गये कुछ उद्योगों के मामले मे लागत के संबंध मे बहुत कम ध्यान दिया गया है । विदेशी मुद्रा के अभाव के परिप्रेक्ष्य मे शायद यह ठीक ही था । यह स्थिति कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के मामले में उचित भी हो सकती है । उदारीकृत आयातों के कारण कुछ संरक्षित उद्योग कठिनाई भी अनुभव कर सकते है । इन सारी समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे उद्योग अपनी वस्तुओं को सस्ता बनाने का प्रयास करें । यह कहना अतिरंजित नही होगा कि दीर्घकालीन विकास और स्थायिता को बनाये रखने के लिए लागत की चेतना विकसित की जानी चाहिए । निवेशों मे संतुलन लाने के लिए बेहतर प्रबंध और अतिरिक्त साधनों के अलावा उत्पादित वस्तुओं की अधिक लाभप्रत्चा, उनकी लागत मे कमी और उनकी गुणवत्ता मे सुधार की आवश्यकता है ।

विदेशी व्यापार-निर्यात की प्रवृत्तियां

२२. वित्तीय वर्ष १९७७-७८ के दौरान व्यापार मे पुन: घाटे की स्थिति उभरी । अनंतिम आंकड़ो के अनुसार उक्त घाटे की राशि ५८० करोड़ रुपये थी जबकि १९७६-७७ मे ७३ करोड़ रुपयो का मामूली उद्देश्य विद्यमान था । इस वर्ष के घाटे का कारण यह था कि निर्यातों से होनेवाली प्राप्तियों मे कमी आयी और आयात नीति को काफी उदार बना देने के कारण आयातों मे वृद्धि हुई ।

२३. वर्ष के उत्तरार्ध से निर्यात की वृद्धि दर मे गिरावट आयी । इसका मुख्य कारण विश्व की आर्थिक स्थिति थी जिसमें औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के विकास की गति बहुत धीमी थी और संरक्षणात्मक प्रवृत्तियां पुन: उभर आयी थी । देशी खपत के लिए वस्तुओ की निरंतर पूर्ति होती रहे और और मूल्यों में स्थिरता आए—इस उद्देश्य से कुछ वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने या उसे विनियमित करने की नीति अपनाई गई; उसके कारण भी निर्यातों मे अवरोध आया । यह स्थिति वनस्पति तेल और तिलहन, ताजी सब्जी और चाय जैसी वस्तुओ के निर्यातों के प्रतिबंध के संदर्भ मे पायी गयी । इन वस्तुओं के निर्यात के लिए एक उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी । विदेशों मे विद्यमान स्थितियों से विशेष रूप से सूती कपड़ो और तैयार सूती वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । विविध-रेशा करार को अंतिम रुप देने मे विलंब होने और कुछ आयातक देशों द्वारा एक-पक्षीय प्रतिबंध लगा दिये जाने के कारण इन वस्तुओं के निर्यात मे अनुमानत: ५०-६० करोड़ रुपयों की कमी आई । कुछ पश्चिमी देशों मे चमड़े के बहुत अधिक स्टाक रहने के कारण चमड़े के हमारे निर्यातो मे लगभग ३० करोड़ रुपयों की कमी आयी । लोहे और इस्पात के निर्यातों मे भी गिरावट आयी; इंजीनियरी निर्यातों मे हालांकि कुछ गिरावट आयी, फिर भी वे अधिक प्रभावित नहीं हुए; क्योंकि पश्चिम एशिया के देशो मे इन वस्तुओं की बराबर मांग रहती थी । उक्त देश भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं के प्रमुख खरीदार है । इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि उन देशों से काफी अधिक नागरिक निर्माण ठेके प्राप्त हुए थे ।

२४. इन बाधाओं के बावजूद १९७७-७८ में समग्र भारतीय निर्यात संपूर्णत: असंतोषजनक नही थे । इसका प्रमुख कारण यह था कि चाय, कांफी, मसाले और काजू जैसी कुछ प्रमुख वस्तुओं के निर्यातों से उनके अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों मे तीव्र वृद्धि होने के कारण उच्चतर मूल्य प्राप्त हुआ । चाय के मूल्य पिछले एक दशक मे अपरिवर्तित रहे । किन्तु इस वर्ष उसके मूल्यों मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई । यद्यपि सरकार ने १९७७-७८ के लिए चाय के निर्यातों पर २,२५० लाख किलोग्राम की उच्चतम सीमा का प्रतिबंध लगाया और उस पर निर्यात शुल्क भी लगाया फिर भी चाय के निर्यातों से १९७७-७८ मे ५६० करोड़ रुपयों तक की आमदनी होने की आशा है जबकि १९७६-७७ मे उससे २९३ करोड़ रुपयों की आमदनी हुई थी ।

केवल चीनी एक ऐसी कृषि जन्य वस्तु थी जिसके निर्यात में बहुत अधिक कमी आयी । चीनी के निर्यातों में हुई इस कमी के कारण इस प्रकार थे : विश्व बाजार में चीनी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हुई, आयात करने वाले देशों में बहुत अधिक पुराने स्टाक थे और चीनी के स्थान पर दूसरी वस्तु का विकास और प्रयोग होने लगा । चांदी के निर्यात से १९७५-१९७६ और १९७६-७७ में औसतन लगभग १६० करोड़ रुपयों की आमदनी हुई और वह १९७७-७८ में गिरकर ८० करोड़ रुपये से थोड़ी सी अधिक रह गई । रत्नों और आभूषणो के निर्यात से काफी आमदनी होने की आशा है । अत: इस आयात को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चे माल उपलब्ध कराने जैसी प्रक्रियाओं द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है ।

आयात

२५. पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लगभग २० प्रतिशत अधिक आयात होने की आशा है । इस संदर्भ में एक प्रमुख विशेषता यह थी कि देशी कमी को दूर करने के लिए खाद्य तेल जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं का भारी मात्रा में आयात किया गया । खाद्य तेलों के आयातों की राशि जहां अप्रैल—दिसंबर १९७६ में ६४ करोड़ रुपये थी वहां अप्रैल—दिसंबर १९७७ में बढ़कर ५१४ करोड़ रुपयें हो गई । पिछले तीन वर्षों में आयातों का जो स्वरुप था वह छठे दशक मे और सातवें दशक के प्रारंभ में विद्यमान स्वरुप से बिल्कुल अलग था । उस समय खाद्यान्नों, उर्वरकों और खनिज तेलों के आयात के लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा का बड़ा भारी अंश खर्च हुआ था । खाद्यान्नों के उत्पादन और उनके स्टाकों की वृद्धि के कारण इस समय उनके आयात आवश्यक नहीं रह गये हैं । तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की सफलता तथा उर्वरकों के उत्पादन की वृद्धि के कारण ईंधन तथा उर्वरकों के आयातों की आवश्यकता भी कम हो गयी है । इस बीच प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधि में निरंतर वृद्धि होने और औद्योगिक विकास में सहायता पहुंचाने की आवश्यकता के कारण आयात नीति को एक नयी दिशा दी गयी है । इस नयी नीति मे लाइसेंसीकरण पद्धति को युक्तिसंगत बनाने, नियंत्रणों को कम करने, क्रियाविधियों को सरल बनाने और प्रशासनिक अधिकार को विकेंद्रीकृत करने पर जोर दिया गया है । यह एक अधिक स्वच्छंद आयात नीति के प्रारंभ की दिशा में पहला कदम है । पहली बार भारतीय पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग देशी बाजार में प्रतियोगिता का सामना करेगा । औद्योगिक कच्चे माल, पुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं के आयातों में इससे वृद्धि होने की आशा है ।

अदृश्य प्राप्तियां

२६. १९७४-७५ से जो अदृश्य प्राप्तियां हुई हैं उनसे हमारी विदेशी अदायगी की स्थिति में विशेष सुधार हुआ है । *विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के प्राक्कलनों के अनुसार केवल बैंकों के माध्यम से व्यापारेतर क्षेत्रों से प्राप्त सकल राशि (अर्थात् आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त राशि को छोड़कर) जहां १९७४-७५ में स्थित ६५४ करोड़ रुपयों से बढ़कर १९७५-७६ में १,१९८ करोड़ रुपये हो गयी थी वहां १९७६-७७ और १९७७-७८ में और बढ़कर क्रमशः १,५८९ करोड़ रुपये तथा २,११७ करोड़ रुपये हो गयी है । इन प्राप्तियों के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं : निजी एकपक्षीय अंतरण, यात्रा से प्राप्तियां, परामर्श और मंविदागत सेवाओं सहित तकनीकी और व्यावसायिक सेवाओं से आमदनी और धर्मार्थ तथा अन्य दान राशियां । निजी एक पक्षीय अंतरण में मुख्यत: परिवार के भरण-पोषण के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय द्वारा प्रेषित राशि आती है । विदेशी भारतीय जो राशि प्रेषित करते हैं उसका एक अंश बैंकों में रहनेवाले अनिवासी रुपया खातों में प्राप्त होता है । उक्त खातों में मार्च १९७५ के अंत में ३१ करोड़ रुपये जमा थे और मार्च १९७६ के अंत में ६४ करोड़ रुपये जमा थे; किन्तु मार्च १९७७ और मार्च १९७८ के अंत में उन खातों में क्रमश: १८५ करोड़ रुपये और ३२० करोड़ रुपये जमा थे । नवंबर १९७५ से विदेशों में रहनेवाले भारतीय और भारतीय मूल के अनिवासी व्यक्ति विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत भारत स्थित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते रख सकते हैं । इन खातों में सीधे प्राप्त राशि मार्च १९७८ के अंत तक १२३ लाख पौंड और १,४९८ लाख डालर थी (ये दोनों मिलकर मार्च १९७८ के अंत में विद्यमान विनिमय दरों के अनुसार १४३ करोड़ रुपये के बराबर होते हैं) । विदेशी मुद्रा खातों में जमा हुई इस राशि को इस पैरा में प्रारंभ में दी गयी व्यापारेतर सकल प्राप्तियों के आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है ।

२७. नौकरियों के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या इस उद्देश्य के लिए दिये गये 'पी' फार्मों से विदित होती है । यह संख्या जहां १९७४-७५ में २०,५०४ थी वहां १९७५-७६ में बढ़कर ३०,४०६ और १९७६-७७ में दुगुनी होकर ७२,४९१ हो गयी । १९७७-७८ (मार्च १९७८ तक) में आप्रवासियों की संख्या ८६,५०५ थी; अत: नौकरियों के लिए जानेवाले भारतीयों की संख्या की वृद्धि दर में निश्चित रूप से गिरावट आ गयी है । आप्रवासी कामगारों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया जानेवाले कामगारों को आमतौर पर सीमित अवधि तक विशिष्ट कार्यों के निमित्त मेजबान देशों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है । इस कारण और दूसरे देशों में विद्यमान रोजगार संबंधी सामान्य स्थितियों के कारण भी परिवार के भरण पोषण के लिए भारत में भेजी जाने वाली राशि संतुलित हो जाने की आशा है । इसके विपरीत यात्राओं से प्राप्त होने वाली राशि मे वृद्धि बनी रहने की आशा है ; क्योंकि काफी अधिक संख्या में पर्यटक इस देश में आ रहे हैं और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली औसत राशि में भी वृद्धि होती है । यह स्थिति इस कारण विशेष महत्वपूर्ण है कि पश्चिम एशिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है । विदेशों में किये गये निजी निवेशों से प्राप्त होने वाली आमदनी में भी निरन्तर वृद्धि होने की संभावना है ; किन्तु आधिकारिक निवेशों से प्राप्त होनेवाली आमदनी का स्तर प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों की स्थितियों के अनुरूप होगा । विदेशों में भारतीयों द्वारा जो तकनीकी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनसे होनेवाली प्राप्तियों की तात्कालिक मध्यावधि संभावना भी उज्जवल है । इसके अलावा परिवहन से होनेवाली सकल प्राप्तियां भी विदेश व्यापार की मात्रा और भारतीय जहाजों द्वारा किये जाने वाले ऐसे व्यापार के अंश की वृद्धि के साथ साथ बढ़ने की आशा है ।

विदेशी सहायता

२८. विदेशी सहायता की कुल वितरित राशि में इस वर्ष ३११ करोड़ रुपयों की कमी आयी और उक्त राशि घटकर १,२८८ करोड़ रुपये हो गयी । अतिरिक्त ऋण परिशोधन और ब्याज की अदायगियां काफी अधिक थीं ; अत: प्राप्त शुद्ध राशि जहां १९७६-७७ में ८४४ करोड़ रुपये थी वहां १९७७-७८ में गिरकर ४६७ करोड़ रुपये हो गई । भारत सहायता संघ में सकल विदेशी सहायता एक वर्ष की अवधि में २१ खरब डालर से बढ़कर १९७८-७९ में ३२ खरब डालर हो जाने का संकेत प्राप्त है । (यहां वर्षों से वित्तीय वर्ष का अर्थ लिया जाता है)

*निजी एकपक्षीय अंतरणों के अलावा यात्रा, परिवहन, निवेश आमदनी और तकनीकी सेवाओं से प्राप्त राशि इस स्थिति का कारण है । यात्रा, परिवहन और निवेश आमदनी से प्राप्त राशियों का अंश अप्रैल–जून 1975 मे स्थित 359 करोड़ रुपयों की सकल अदृश्य प्राप्तियों में 35 प्रतिशत था जबकि 1976 की इसी तिमाही मे हुई 468 करोड़ रुपयों की कुल प्राप्ति में उक्त अंश 42 प्रतिशत था । दोनों तिमाहियों में निजी एकपक्षीय अंतरणों मात्र का अंश 34-35 प्रतिशत था ।

प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियां

२९ प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधिया जनवरी १९७६ से निरन्तर बढती रही है और वे जून १९७८ के अन्त मे ४,५१८ करोड रुपये हो गयी है। किन्तु जुलाई १९७७ से जून १९७८ तक के वर्ष के दौरान प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो की वृद्धि की गति धीमी पायी गयी है। आधिकारिक विदेशी मुद्रा निधियो मे इस अवधि मे ९३७ करोड रुपयों की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष हुई १,८३१ करोड रुपयो की वृद्धि की तुलना मे आधी से केवल थोडी-सी अधिक थी। इन निधियो की वृद्धि मे जो गिरावट आयी वह इस वर्ष की अंतिम तिमाही मे विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। मार्च १९७८ के अत और जून १९७८ के अत के बीच अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये विशेष आहरण अधिकार सबधी लेन-देनो और विकासशील देशों के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गयी सोने की बिक्री से प्राप्त लाभ मे अपने हिस्से के रूप मे भारत द्वारा खरीदे गये सोने के संदर्भ मे १४८ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा का परि-व्यय हुआ। यदि इन लेन-देनो को छोड दिया जाए तो उक्त तिमाही मे विदेशी मुद्रा निधियो मे हुई वृद्धि केवल १६७ करोड रुपये थी। १९७७ की इसी अवधि मे अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये विशेष आहरण अधिकार सबंधी लेन-देनो को छोड देने पर आधिकारिक विदेशी मुद्रा निधियों मे हुई वृद्धि ७२७ करोड रुपये थी।

३०. ऐसे संकेत प्राप्त है कि प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो मे होनेवाली वृद्धि मे हाल ही की अवधि मे जो मंदी आयी उसमे आगामी महीनो मे कोई अतर आने की सभावना नही है। सबसे पहले उदारीकृत आयात नीति के कारण आयातो मे बहुत अधिक वृद्धि होने की आशा की जा सकती है। इस बात के प्रमाण कुछ-कुछ मिलने लगे है। अनतिम आकडो के अनुसार आयातों के लिए बैंको के माध्यम से अप्रैल—जून १९७८ मे की गयी अदायगियो की राशि १,०२९ करोड रुपये थी जो १९७७ के इन्ही महीनों मे हुई अदायगियों की तुलना मे ३१ प्रतिशत अधिक थी। साथ ही, १९७८-७९ मे जो निर्यात होगे उनमे १९७७-७८ मे हुई वृद्धि भी संभवत: नही होगी। प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए रिजर्व बैंक के साथ जो वायदा सविदा करते है उनकी बकाया राशि से निर्यातो से प्राप्त होनेवाली राशि का प्रारभिक संकेत मिलता है। ऐसी वायदा सविदाओं के मामले मे अप्रैल १९७८ के अंत मे हर प्रमुख विश्वमुद्रा की बकाया राशि एक वर्ष पहले की बकाया राशि से कम थी।

३१ प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधि की अनुकूल स्थिति के कारण भारत जुलाई १९७७ के ऋण कोटे मे स्थित शेष अंश और बकाया स्वर्ण कोटे को पुन: खरीद कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति अपने दायित्व मे कमी लाया। इस प्रकार पुन: खरीदी गयी राशि कुल २४९ करोड रुपये थी। पिछले वर्ष के दौरान १९७४ की तेल सुविधा के अन्तर्गत और प्रथम ऋण कोटे के अंश के रूप मे पुन: खरीदी गयी राशि २३८ करोड रुपये थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गये लेन-देनो को यदि छोड़ दिया जाए तो आशा है कि जुलाई १९७७—जून १९७८ के दौरान आधिकारिक विदेशी मुद्रा निधियो मे १ १८५ करोड रुपयों की वृद्धि हुई होगी, जबकि पिछले वर्ष उक्त वृद्धि की राशि २,०६९ करोड रुपये थी। १९७५ की तेल सुविधा के अंतर्गत २,०१३ लाख विशेष आहरण अधिकार की बकाया राशि भी १६ जुलाई, १९७९ को पुन: खरीदी जाएगी।

ऋण की प्रवृत्तियां

३२ इस वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंको द्वारा दिये गये ऋण मे महत्वपूर्ण घट-बढ़ पायी गयी। अप्रैल के अंत तक उक्त वितरण के विस्तार मे मदी का सकेत पाया गया। सकल ऋण मे १० महीने की अवधि (जुलाई—अप्रैल) मे १,१९२ करोड रुपयो की वृद्धि (८ ८ प्रतिशत) हुई जबकि पिछले वर्ष की उक्त अवधि मे १,८८० करोड रुपयो की वृद्धि (१५ ८ प्रतिशत) हुई थी। यह स्थिति प्रमुखत: खाद्यान्नो की सार्वजनिक प्रणाली और वितरण के लिए दिये गए ऋणो मे पायी गयी, उक्त ऋणो मे इस वर्ष ५४४ करोड रुपयो की गिरावट आयी, जबकि पिछले वर्ष उनमे २६ करोड रुपयो की बढोतरी हुई थी। मई और जून १९७८ के बाद के दो महीनो मे सकल ऋण राशि मे ७८९ करोड रुपयो की जो बढोतरी हुई वह १९७६-७७ के तदनुरूप महीनो मे हुई १४७ करोड रुपयो की वृद्धि की तुलना मे काफी अधिक थी। यह वृद्धि अधिकाशत: (भले ही पूर्ण रूप से न हो) खाद्य ऋण मे पायी गयी। खाद्य ऋण मे इन दो महीनो की अवधि मे पिछले वर्ष हुई २५५ करोड रुपयो की वृद्धि के मुकाबले ५२६ करोड रुपयो की वृद्धि हुई।

३३ सकल ऋण मे हुई धीमी वृद्धि के साथ जमा राशियो की वृद्धि के स्वरुप मे भी परिवर्तन आया। जुलाई—अप्रैल १९७७-७८ की अवधि मे कुल जमा-राशियो मे ३,३७३ करोड रुपयो की वृद्धि हुई जबकि अगले दो महीनो मे लगभग ६५६ करोड रुपयो की वृद्धि हुई। इसके विपरीत पिछले वर्ष के तदनुरूप महीनो मे क्रमश: २,९५२ करोड रुपयो और ७७३ करोड रुपयो की वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष के पहले दस महीनो मे जमाराशियो मे हुई तीव्र वृद्धि के साथ ऋण मे आयी कमी का यह परिणाम हुआ कि बैंकिग प्रणाली मे भारी मात्रा मे चल निधि निर्मित हो गयी। यह तथ्य इससे भी प्रमाणित होता है कि बैंको ने अप्रैल १९७८ के दौरान सांविधिक अपेक्षा के अतिरिक्त लगभग ३ प्रतिशत का चल निधि अनुपात बनाये रखा। बैंको ने रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणो की काफी मात्रा मे चुकौती कर दी, रिजर्व बैंक से लिये गये कुल उधारो की राशि अप्रैल १९७८ के अंत मे १५५ करोड रुपये थी जबकि अप्रैल १९७७ के अत मे उक्त राशि ६१४ करोड़ रुपये थी।

३४ इसके विपरीत मई और जून १९७८ के महीनो के दौरान रिजर्व बैंक से लिये जानेवाले अपने उधारो मे बैंको ने १८० करोड रुपयो की वृद्धि की जब कि पिछले वर्ष के तदनुरूप महीनो मे बैंको ने रिजर्व बैंक को लगभग ५१ करोड़ रुपयों के ऋणो की चुकौती की थी। इसके अतिरिक्त इसी अवधि मे सरकारी और अनुमोदित प्रतिभूतियो मे किये जानेवाले अपने निवेशों मे भी बैंक ६१७ करोड रुपयो की गिरावट लाये जब कि पिछले वर्ष ऐसे निवेशो की राशि मे १२२ करोड रुपयो की वृद्धि की गयी थी।

३५ बैंकिंग क्षेत्र के जमा, ऋण आदि परिवर्तनशील घटको मे आये अंतर के कारण ऋण जमा-अनुपात अप्रैल १९७८ के अत मे कम होकर ६६ प्रतिशत हो गया जब कि एक वर्ष पहले यह ७३ ३ प्रतिशत था। जून १९७८ के अंत तक यह अनुपात बढकर ६७ ५ प्रतिशत हो गया। फिर भी यह अनुपात जून १९७७ के अत मे विद्यमान ७१ ४ प्रतिशत के अनुपात की तुलना मे कम ही था।

३६ सारणी ३ मे समग्र वर्ष की अनुसूचित वाणिज्य बैंको की जमाराशियो और उनके द्वारा दिये गये ऋण मे हुए परिवर्तन का ब्योरा दिया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान ऋण मे हुई सकल वृद्धि लगभग १९७६-७७ के बराबर ही रही, यद्यपि प्रतिशत की दृष्टि से इस वर्ष हुई वृद्धि २ ५ प्रतिशत कम थी। किन्तु खाद्येतर ऋणों मे हुई वृद्धि समग्र राशि और

प्रतिशत दोनों ही दृष्टियों से पिछले वर्ष की मुकाबले उच्च थी । सरकारी क्षेत्र के अन्य प्रमुख व्यापारिक कार्यों के लिए भारतीय रूई निगम को और उर्वरक के वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम को दी गई ऋण राशियों में की गई कटौती के लिए खाद्येतर ऋण के आंकड़ों में जो समायोजन किया गया उससे निगम को दी गयी ऋण राशियों में की गयी कटौती के लिए इसी प्रकार का चित्र सामने आता है—अर्थात् समग्र राशि और

सारणी 3

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋण में घट-बढ़

(करोड़ रुपये)

	1976-77			1977-78	
	निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को		परिवर्तन जून 1976 की तुलना में जून 1977 में)	जून 1976 के अंतिम शुक्रवार को	परिवर्तन (जून 1977 की तुलना में जून 1978 में)
	जून 1976	जून 1977			
ऋण में हुई सकल वृद्धि	11620	13607 (17.1)	+1987	15589	+1982 (14.6)
उसमें से					
खाताधारकों की वसूली	2185	2536	+351	2518	—18
खाद्येतर	9435	11071	+1636 (17.3)	13071	+2000 (+18.1)
भारतीय रूई निगम को रूई के लिए और भारतीय खाद्य निगम को उर्वरक के लिए दिया गया ऋण जो उपर्युक्त में शामिल नहीं है	9409	10847	+1438 (15.3)	12683	+1838 (16.9)
कुल जमा वृद्धि	15178	18903	+3725 (24.5)	22932	+4029 (21.3)
बैंक ऋण/जमा अनुपात	75.6	71.4		67.5	

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं।)

प्रतिशत दोनों ही दृष्टियों से पिछले वर्ष की तुलना में उनमें अधिक वृद्धि हुई है । दूसरी ओर अलोच्य वर्ष के दौरान जमा-राशि में वृद्धि की दर विशेष रूप से कम थी ।

राज्य सहकारी बैंकों को ऋण

३७. १९७७-७८ के दौरान सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता में भारी वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक द्वारा मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गई अल्पावधि ऋण सीमाएं पिछले वर्ष के ६९६ करोड़ रुपयों से बढ़कर ७४९ करोड़ रुपये हो गयी । कैलेंडर वर्ष १९७७ के दौरान मंजूर किये गये मध्यावधि ऋणों की राशि २१.३४ करोड़ रुपये थी; इसमें से राज्य सहकारी बैंकों द्वारा वास्तव में १२.२३ करोड़ रुपये लिये गये । वर्ष १९७८ के लिए विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को ३० जून १९७८ तक १९.०९ करोड़ रुपयों के मध्यावधि ऋण मंजूर किये गये । वर्ष १९७७-७८ के दौरान राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से राज्य सरकारों को सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए २१.१३ करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की गई । उक्त अवधि के दौरान शेयर पूंजी में अंशदान के लिए मंजूर की गई राशि में से राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों की राशि २०,८० करोड़ रुपये थी । राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ-कालीन प्रवर्तन) निधि से कृषि पुनर्वास और विकास निगम को ६५ करोड़ रुपयों के दीर्घावधि ऋण प्रदान किये गये । आलोच्य वर्ष के दौरान चुकाई गई और ली गई राशि क्रमशः २०.८० करोड़ रुपये और ६५.०० करोड़ रुपये थी । ३० जून १९७८ तक २१६.८० करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी ।

३८. सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने और अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने, विशेषकर ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को बढ़ाने, सहकारी संस्थाओं के ब्याज दर विन्यास को औचित्यपूर्ण बनाने और अंतिम ऋणदाता पर पड़नेवाले ऋण की लागत संबंधी बोझ को कम करने पर प्रमुख बल दिया जाता रहा । प्रथम लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सक्षम प्राथमिक ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देश्यीय समितियों के रूप में पुनः गठित करने, सहकारी बैंकों की पुनर्व्यवस्था करने, सरकारी शेयर पूंजी की व्यवस्था करने और कृषि ऋण सघन विकास के अधीन चयनात्मक आधार पर रिजर्व बैंक से

सारणी : 4

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और वितरण

(करोड़ रुपये)

मदें	1976-77 (लेखे)	1977-78 (परिशोधित अनुमान)		1978-79 (बजट अनुमान)@	
		राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I कुल प्राप्तियां (अ+आ)	22217	24011	+8.1	26227**	+9.2
अ. राजस्व प्राप्तियां	15858	17245	+8.7	18897	+9.6
उनमें से :					
कर प्राप्तियां	12294	13236	+7.7	14687	+11.0
आ. पूंजीगत प्राप्तियां	6359	6766	+6.4	7330	+8.3
II. कुल वितरण	22298	25276	+13.4	27574	+9.1
उनमें से :					
अ. विकास परिव्यय (क+ख)	10672	12798	+19.9	14276	+11.5
(क) राजस्व	7501	8898	+18.6	9753	+9.6
(ख) पूंजीगत	3171	3900	+23.0	4523	+16.0
आ विकासेतर परिव्यय (क+ख)	7189	7847	+9.2	8887	+13.3
(क) राजस्व	6855	7526	+9.8	8278	+10.0
(ख) पूंजीगत	334	321	+3.9	609@@	+89.7
III समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—) (I—II)	81	—1265		—1347*	

@इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव, 27 अप्रैल, 1978 को केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कर-रियायतों (25 करोड़ रुपये) का प्रभाव और 1 अगस्त 1978 को लोकसभा में प्रस्तुत अतिरिक्त व्यय के अनुदानों की पूरक मांग का प्रभाव शामिल है।

@@इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कोटे में की जाने वाली वृद्धि के कारण और मुद्रा मूल्य के समायोजन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 245 करोड़ रुपये की अदायगी का प्रावधान शामिल है।

*यदि असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, पंजाब और राजस्थान के संदर्भ में बजट में शामिल न किये गये परिव्यय और महाराष्ट्र तथा केरल के मामले में अनुदानों की पूरक मांगों को हिसाब में लिया जाए तो इस घाटे में 122 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी।

**इसमें रिजर्व बैंक द्वारा चलायी गयी पहली छः नीलामियों में सोने की बिक्री से प्राप्त राशि शामिल है।

टिप्पणियां. 1 इन आंकड़ों में ऐसे संघशासित क्षेत्र शामिल नहीं हैं जहां विधानमंडल हैं।

2 केन्द्रीय सरकार के बजट में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अंतर-सरकारी अन्तरणों के लिए आंकड़े समायोजित किये गये हैं। इन समायोजनों से सम्बन्धित समग्र स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

3 कुछ राज्यों के संदर्भ में अंतिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, अतः आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट।

प्राप्त होनेवाली पुनर्वित्त सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी रहे। सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और उन्हें कृषि उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों से संबद्ध करने के लिए वित्तीय साधनों का प्रयोग किया गया। ऋण लेनेवालों से क्रमिक रूप से १० प्रतिशत का जो वर्तमान शेयर अनुपात वसूल किया जाता है उससे चूंकि छोटे किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर ऋणदाताओं को कठिनाई हो रही थी इस लिए उसे घटाकर ५ प्रतिशत कर दिया गया।

सरकार के वित्त

३९. राजकोषिय वर्ष १९७७-७८ के दौरान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों (ऐसे संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर जहां विधान मंडल हैं) के बजट संबंधी कार्यकलापों से वार्षिक योजना परिव्यय में भारी वृद्धि पायी गई अर्थात् उसमें पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में इस वर्ष १,९०० करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। साथ ही विकासेतर व्यय में भी थोड़ी सी तीव्र वृद्धि पायी गई। कुल प्राप्तियों में जो वृद्धि हुई वह व्यय में हुई वृद्धि से कम थी; इसके परिणामस्वरूप समग्र स्थिति में कमी आई और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की राशि मिलकर १९७७-७८ में १२६५ करोड़ रुपये हो गयी जबकि १९७६-७७ में यह राशि केवल ८१ करोड़ रुपये थी। सारणी ४ में इस स्थिति का ब्योरा दिया गया है।

४०. हालांकि १९७७-७८ के परिशोधित बजट अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बजट घाटे की कुल राशि १,२६५ करोड़ रुपये थी फिर भी रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार उक्त घाटे की कुल राशि ८८४ करोड़ रुपये थी। इसमें केन्द्रीय सरकार के घाटे की राशि ८०१ करोड़ रुपये और राज्य सरकारों के घाटे की राशि ८३ करोड़ रुपये सम्मिलित थी।

* इन आंकड़ों की पुष्टि करने वाले प्राप्तियों और वितरणों से संबंधित आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार का वित्त

४१. वार्षिक योजना के परिव्यय के लिए केन्द्रीय बजट में की गयी कुल व्यवस्था में ९८० करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई; इसमें से राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के योजना परिव्यय के लिए दी जानेवाली सहायता का अंश लगभग दो-तिहाई था। १९७८-७९ के भारत सरकार के बजट में विकास परिव्यय में और वृद्धि की गयी है इसके अलावा बजट में किये गये राजकोषीय उपायों का यह प्रयास रहा कि नई कंपनियों के ईक्विटी शेयरों में निवेश के लिए कर संबंधी रियायतें प्रदान कर जोखिम पूंजी की उपलब्ध मात्रा को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार के निवेश कर-योग्य आय का हिसाब लगाने में काफी सीमा तक कटौती के पात्र हैं। बैंकों की ब्याज संबंधी आय पर लगाये जाने वाले कर को हटा देना बजट में सम्मिलित एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय था। यह स्मरण होगा कि १९७४ में उस समय यह कर लगाया गया था जब उच्च ब्याज दरों का मुद्रागत प्रतिबंधों के उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता था; इस कर का भार बैंक के ऋणदाताओं पर पड़ा; क्योंकि इससे ऋण की लागत बढ़ गई थी। निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक उत्पादन की लागत को कम करने की नीति के परिप्रेक्ष्य में उक्त कर को हटाया गया।

४२. नये वित्तीय साधन जुटाने के लिए बजट प्रमुखतः परोक्ष करों पर निर्भर रहा है। किन्तु इस दिशा में काफी व्यापक मात्रा में कर लगाने के बावजूद कुल प्राप्तियों में आलोच्य वर्ष में प्रत्याशित वृद्धि कुल वितरणों में अपेक्षित वृद्धि की तुलना में कम रही। इसके परिणामस्वरूप १९७८-७९ के केन्द्रीय सरकार के बजट में १,५३७ करोड़ रुपयों* की खाई रह गई है जो पिछले वर्ष के भारी घाटे के अतिरिक्त हुई है। इस स्थिति का जो मुद्रागत प्रभाव होगा वह गम्भीर होगा।

राज्य सरकारों का वित्त

४३. बाईस राज्य सरकारों की संयुक्त बजट संबंधी स्थिति से यह विदित होता है कि वे केन्द्रीय करों में रहने वाले अपने हिस्से और अनुदानों तथा ऋणों के रूप में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली निधि पर अधिकाधिक निर्भर रहती हैं। १९७७-७८ के परिशोधित अनुमानों के अनुसार उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत १,०५९ करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। इस वर्ष उक्त राशि में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की राशि में हुई वृद्धि की तुलना में दुगुनी से थोड़ी-सी अधिक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अधिकांश अतिरिक्त ऋण सहायता का उद्देश्य यह था कि कतिपय राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये ओवरड्राफ्टों को चुकाया जा सके, राज्य सरकारों के पास अपनी योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध साधनों में विद्यमान खाई की पूर्ति की जा सके और देश के विभिन्न भागों में आई प्राकृतिक विपत्तियों के परिणामस्वरूप किये जाने वाले राहत कार्यों का सहायता पहुंचाई जा सके। इसके विपरीत अपने नये कर संबंधी उपायों से अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। नये कर संबंधी उपायों से जुटाये गये कुल अतिरिक्त साधन जहां १९७६-७७ में १०७ करोड़ रुपये थे वहां १९७७-७८ में उक्त साधन केवल ६५ करोड़ रुपये थे। १९७८-७९ के बजटों से इस दिशा में कोई उल्लेखनीय सुधार होने का संकेत नहीं मिलता।

४४. १९७८-७९ में राज्य सरकारों की बजट व्यवस्थाओं के अनुसार उनकी प्राप्तियों की वृद्धि की गति और धीमी हो गई है। विकासात्मक और विकासेतर व्यय की वृद्धि दर में गिरावट आने के बावजूद यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों की समग्र बजट स्थिति में लगातार दूसरे वर्ष २५७ करोड़ रुपयों** का भारी घाटा परिलक्षित होगा।

अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट

४५. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को इस उद्देश्य से अस्थायी वित्तीय सहायता की सुविधा उपलब्ध करायी थी कि वितरित राशि की तुलना में प्राप्तियों की मात्रा कम होने के कारण उत्पन्न असंतुलनों को दूर किया जाए। कतिपय राज्य सरकारें हाल ही के वर्षों में ऋण संबंधी अपनी पात्रताओं से अधिक उधार निरन्तर लेती रही हैं। जून १९७७ के अन्त में विद्यमान ३२० करोड़ रुपयों की राशि के ऐसे ओवरड्राफ्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अग्रिम रूप से वितरित सहायता से चुका दिये गये। इस वर्ष के परवर्ती भाग में ओवरड्राफ्ट फिर से उभर आये और वे अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर लम्बी अवधियों के लिए थे। रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों से बार-बार यह अनुरोध किये जाने के बावजूद कि वे लगातार अधिक मात्रा में ओवरड्राफ्ट का प्रश्रय

* इसमें २७ अप्रैल १९७८ को घोषित कर रियायतों (२१ करोड़ रुपये), १ अगस्त १९७८ को लोक सभा में प्रस्तुत अतिरिक्त व्यय के अनुदानों की पूरक मांग और रिजर्व बैंक द्वारा चलाई गई पहली छः नीलामियों में सोने की बिक्री से प्राप्त राशि का प्रभाव शामिल है।

**यदि असम, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, पंजाब और राजस्थान के बजट में शामिल न किये गये कुल ५४ करोड़ रुपयों के परिव्यय और केरल तथा महाराष्ट्र के मामले में क्रमशः २१ करोड़ रुपयों और ०.१ करोड़ रुपये के अनुदानों की पूरक मांगों को हिसाब में लिया जाए तो घाटे की यह राशि बढ़कर ३७९ करोड़ रुपये हो जाएगी। केन्द्रीय सरकार ने पहली अगस्त, १९७८ को राज्य सरकारों के ३१ मार्च १९७८ तक के घाटे की पूर्ति करने के लिए ४३० करोड़ रुपयों का विशेष ऋण प्रदान किया है। इसके अलावा राज्य सरकारों के लिए १४ करोड़ रुपयों के अतिरिक्त अनुदानों और २ करोड़ रुपयों के एक दूसरे ऋण को भी मंजूरी दी गयी है। यदि राज्य सरकारों को दिये गये इन ऋणों और अनुदानों को १९७८-७९ में उनकी प्राप्तियों के रूप में माना जाय तो उनकी समग्र बजट स्थिति १९७८-७९ में ६७ करोड़ रुपयों के अधिशेष में बदल जाने की संभावना है।

लेने से बचें, ओवरड्राफ्टों का बकाया स्तर १४ अप्रैल १९७८ को ५३८ करोड़ रुपयों के सर्वाधिक स्तर पर था ।*

४६. निरन्तर भारी मात्रा में ओवरड्राफ्ट लेने का कारण यह है कि राज्य सरकारों की प्राप्तियों और वितरणों के बीच मूलभूत असंतुलन बना रहता है । इससे अमतौर पर यह संकेत मिलता है कि अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्तियां न होने पर भी सामान्यतः वित्तीय अनुशासन का थोड़ा-बहुत अभाव रहता है इस प्रकार के ओवरड्राफ्ट वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राज्यों द्वारा बनाये गये वार्षिक वित्तीय कार्यक्रमों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता राशि के अतिरिक्त होते हैं । इस प्रकार लिये जाने वाले अतिरिक्त साधनों से निश्चित रूप से घाटे के वित्तपोषण के समग्र स्तर तथा राज्यों के बीच उचित वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । यह स्थिति पिछले कुछ समय से थोड़ी बहुत असामान्य रही है, क्योंकि १९७७ के मध्य में जो राज्य सरकारें सत्ता में आई वे यह समझती हैं कि उन्हें विरासत में काफी असंतुलित बजट स्थिति प्राप्त हुई है । इस संदर्भ में यह उचित होगा कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें सभी संबंधित बातों पर ध्यान देते हुए अत्यधिक उच्च स्तर पर विद्यमान ओवरड्राफ्टों को समाप्त करने के लिए मिल-जुलकर कोई व्यवस्थाएं ढूंढ निकालें ।* परन्तु उसके बाद राज्य सरकारों को चाहिए कि वे केन्द्रीय सरकार के साथ स्वीकृत व्यवस्थाओं का अनुपालन करें तथा अनधिकृत रूप से ओवरड्राफ्टों का प्रश्रय लिये बिना अज्ञात परिस्थितियों के विपरीत प्रभाव का सामना करने के लिए हर सम्भव कदम उठायें ।

बाजार ऋण

४७. १९७७-७८ के दौरान केन्द्रीय सरकार ने काफी बड़ी राशि के लिए बाजार ऋण संबंधी अपना कार्यक्रम बनाया था । इन ऋणों से १,१८३ करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो एक वर्ष की अवधि में ३३४ करोड़ रुपयों की वृद्धि के द्योतक हैं । परन्तु राज्य सरकारों द्वारा जुटाये गये बाजार ऋणों की शुद्ध राशि १७९ करोड़ रुपयों के आसपास ही थी । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित संस्थाओं की कुल ऋण राशि ६३० करोड़ रुपये थी ।

४८. आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने बाजार में दो बार प्रवेश किया और उसने तीन बार रिजर्व बैंक को प्रतिभूतियों का विक्रय किया जिसका उद्देश्य यह था कि बाद में निवेशकों को उन्हें आवंटित किया जाए । इन पांच किस्तों से जुटाई गई सकल राशि १,३१२ करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की तुलना में १८८ करोड़ रुपये या १७.७ प्रतिशत अधिक थी ।

४९. राज्य सरकारों द्वारा १९७७-७८ के दौरान लिये गये सकल ऋणों की राशि २८४ करोड़ रुपये थी जिसमें से २३४ करोड़ रुपये नकदी अभिदान के रूप में और ५० करोड़ रुपये ऋण परिवर्तन के रूप में प्राप्त हुए थे । अवधि समाप्त ऋणों के मामले में १०५ करोड़ रुपये चुकाये गये; इससे शुद्ध बाजार ऋणों की राशि १७९ करोड़ रुपये रह गयी ।

५०. १९७७-७८ के लिए केन्द्रीय सरकार ने लगभग १,६५० करोड़ रुपयों के शुद्ध बाजार ऋण का कार्यक्रम बनाया है । केन्द्रीय सरकार ने सबसे पहले कुल ५५२ करोड़ रुपयों की राशि के लिए तीन ऋण अर्थात् ६ प्रतिशत ऋण १९८८ (तीसरा निर्गम), ६-१/४ प्रतिशत ऋण १९९५ और ६-३/४ प्रतिशत ऋण २००६ जारी करने के लिए १५ मई १९७८ को बाजार में प्रवेश किया । इन ऋणों के लिए नकदी में अभिदान स्वीकार किया गया । २०० करोड़ रुपयों की कुल राशि के लिए इन तीन ऋणों की अगली किस्तें २५ मई, १९७९ को रिजर्व बैंक को इस उद्देश्य से जारी की गयीं कि उन्हें बाद में बाजार में जारी किया जाए । ४४० करोड़ रुपयों की कुल राशि के लिए केन्द्रीय सरकार के ऋण कार्यक्रम की तीसरी किस्त १ जुलाई १९७८ को जारी की गई । इसके लिए नकदी में और पिछले ऋणों के परिवर्तन के रूप में अभिदान स्वीकार किया गया । इससे ९३ करोड़ रुपये ऋण-परिवर्तन के रूप में प्राप्त हुए ।

वित्तीय प्राप्तियां

५१. बजट ही एकमात्र ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के बीच वित्तीय साधनों का अंतरण किया जाता है । वाणिज्य बैंकों की शाखाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं ; ऐसे वाणिज्य बैंकों तथा मीयादी ऋण प्रदान करने वाली राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं जैसी वित्तीय संस्थाओं के जरिए भी पूंजी प्राप्त होती है । इन संस्थाओं से प्राप्त होने वाले वित्त की मात्रा काफी अधिक रहती है किन्तु उक्त वित्त के वितरण को विनियमित करने की संभावना सीमित रहती है ।

५२. बैंकों और मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के ऋण-कार्यों का भौगोलिक स्वरूप मूलतः ऋण लेने वाले यूनिटों के स्थान के आधार पर उत्पन्न मांग द्वारा निर्धारित किया जाता है । किन्तु किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाओं द्वारा न केवल ऋण प्रदान कर, बल्कि उस राज्य में विकास कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं के बांडों और डिबेंचरों में अभिदानों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है । ऐसे निवेशों से इन संस्थाओं के आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने में सहायता मिलती है जिससे कि वे अपने कार्यक्रमों का स्वयं वित्तपोषण कर सकें । पिछले वर्षों में राज्य सरकारों और राज्य स्तर के निकायों की प्रतिभूतियों में, विशेष रूप से पिछड़े राज्यों में बैंकों के निवेशों में भारी वृद्धि हुई है ।

५३. क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की दिशा में किया गया दूसरा नीतिगत उपाय है विशेष रूप से ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों की स्थापना, जहां अब तक इस प्रकार की संस्थागत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं पहुंचा है । ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालयों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से वाणिज्य बैंकों के शाखा विस्तार का जो सूत्र बनाया गया था उसे १९७७ के प्रारम्भ में परिवर्तन कर दिया गया । परिवर्तित सूत्र में बैंक रहित केन्द्रों पर बल दिया गया ।

* राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट २७ जून १९७८ को ५०५ करोड़ रुपये थे । उन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता से २९ जून १९७८ को चुका दिया गया ।

* संबंधित राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से बार-बार जो ओवरड्राफ्ट लेती है उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के बजटों में ३१ मार्च १९७८ को विद्यमान घाटे की पूर्ति करने के लिए ४३० करोड़ रुपयों का विशेष ऋण प्रदान किया है । पहली अगस्त १९७८ को लोक सभा में प्रस्तुत अनुदानों की पूरक मांग में इसकी व्यवस्था की गई ।

इसका उद्देश्य यह था कि ऐसे स्थानों पर बैंकों के जमाव की प्रवृत्ति का रोका जा सके जो तकनीकी अर्थों में तो ग्रामीण है किन्तु जहां पहले से ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हैं । परिवर्तित सूत्र के अधीन बैंक रहित केन्द्रों में शाखाओं की निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही बैंक शहरी केन्द्रों और बैंक युक्त केन्द्रों में शाखाएं खोल सकते हैं । प्रसंगवश, इस नीतिगत परिवर्तन से काफी जल्दी परिणाम सामने आये; क्योंकि कुल कार्यालयों में वाणिज्य बैंकों के ग्रामीण कार्यालयों का जो अनुपात १९७५ तक ३६ प्रतिशत के आसपास रुका हुआ था वह जून, १९७७ में बढ़कर ३८.५ प्रतिशत और १९७७ के अन्त तक और बढ़कर ४१ प्रतिशत हो गया । वर्ष १९७८ के लिए बैंकों से कहा गया कि वे अपनी स्थिति को समेकित करें और शाखा विस्तार के कार्यक्रम की लम्बी-चौड़ी योजना न बनाएं । बैंक रहित केन्द्रों के चुनाव के संबंध में भी बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे जिलों पर बल दें जहां प्रति कार्यालय सेवा प्राप्त जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में बैंकिंग सुविधा अपर्याप्त है । शहरी और महानगरीय केन्द्रों में नई शाखाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने पर और प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के विनियोजन में सुधार लाने के लिए बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे मार्च, १९७९ तक कम से कम ६० प्रतिशत ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में जुटाये गये करें जिससे कि ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में जुटाये गये साधनों का उत्पादक विनियोजन उन्हीं क्षेत्रों में हो । बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके कुल ऋण का कम से कम एक-तिहाई भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया जाता है । यद्यपि बैंक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मूलभूत बैंकिंग सुविधा का जो उपयोग किया गया है वह अपर्याप्त है । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या अकेले वित्तीय संस्थाओं के कार्यों से हल नहीं की जा सकती ।

५४. ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगी हुई विभिन्न ऋण संस्थाओं के कार्यकलापों को अधिक एकीकृत करने की आवश्यकता पहले की अपेक्षा अब अधिक स्पष्ट हो गई है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य प्रणाली की समीक्षा और कृषि के वित्तपोषण में बहुविध एजेंसी दृष्टिकोण का अध्ययन करने वाली समितियों की सिफारिशों के आधार पर आगामी ५-१० वर्षों के लिए ग्रामीण विकास के लिए अपेक्षित अन्तर संस्थागत दृष्टिकोण की स्थूल रूपरेखा बनाई गई है । शिखर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच निकट सम्पर्क होना चाहिए और जहां सम्भव हो, इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि शिखर बैंक और वाणिज्य बैंक संयुक्त रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रवर्तन करें । वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की अपेक्षा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर हो और सम्बन्धित बैंकों के परामर्श से वर्तमान वाणिज्य बैंकों के ग्रामीण कार्यालयों को क्रमिक रूप से उनमें अन्तरित कर दिया जाए । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी एक प्रकार की संस्था को ही ग्रामीण कार्य सौंपा जाना चाहिए । जहां ग्रामीण क्षेत्र के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं की अधिक प्रभावशाली भूमिका की परिकल्पना की गई है वहां वाणिज्य बैंक अपनी ओर से और सहकारी संस्थाओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा भी कृषि का वित्तपोषण करते रहेंगे । इस प्रकार का वित्तपोषण कार्य बड़े कृषकों तक सीमित नहीं होना चाहिए ।

मुद्रा उपलब्धि

५५. जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में निरन्तर वृद्धि होती रही । उसमें पिछले वर्ष हुई २,३३२ करोड़ रुपयों (१६.६ प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में आलोच्य वर्ष के दौरान ३,००८ करोड़ रुपयों (१८.४ प्रतिशत) की वृद्धि हुई । मुद्रा उपलब्धि की यह वृद्धि दर पिछले पांच वर्षों की अवधि (१९७२-७३ से १९७६-७७ तक) में पायी गयी १३.४ प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर के मुकाबले उच्च थी । वास्तविक राष्ट्रीय आय में लगभग ५ प्रतिशत की केवल थोड़ीसी वृद्धि हुई; इस संदर्भ में मुद्रा उपलब्धि के विस्तार की दर इस तथ्य के बावजूद कि कृषिजन्य वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा उनकी पूर्ति अधिक तेजी से बढ़ती (और घटती) है, चिन्ताजनक है ।

५६. मीयादी जमाराशियों की वृद्धि दर स्पष्ट रूप से कम होकर १७.८ प्रतिशत (अर्थात २,२६१ करोड़ रुपये) हो गई । इसके परिणामस्वरूप स्थूल मुद्रा (एम ३) (इसमें मुद्रा उपलब्धि और बैंकों की मयादी जमाराशियां शामिल हैं) में हुई वृद्धि पिछले वर्ष के २१.२ प्रतिशत से कम होकर १८.१ प्रतिशत हो गई ।

५७. चालू वर्ष के दौरान मुद्रा उपलब्धि का जो अपेक्षाकृत अधिक विस्तार हुआ उसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि बैंकिंग तंत्र की मुद्रेतर देयताओं की वृद्धि की गति में भारी कमी के साथ ही विस्तार के मुख्य स्रोतों में आई वृद्धि के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई । उदाहरणार्थ १९७७-७८ में मुद्रेतर देयताओं में केवल २,७४९ करोड़ रुपयों (१४.५ प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि १९७६-७७ में ४,२४१ करोड़ रुपयों (२८.९ प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । इसका प्रमुख कारण यह था कि मीयादी जमाराशियों में धीमी वृद्धि हुई और कुछ सीमा तक यह भी कारण था कि भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयताओं में ५४० करोड़ रुपयों की तीव्र गिरावट आई ।

५८ यदि १९७६-७७ के साथ तुलना की जाए तो सभी प्रमुख प्रभावकारी तत्वों अर्थात सरकार को बैंकों द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण, वाणिज्य क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण और बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों की वृद्धि की दरें आलोच्य वर्ष में कम थीं । सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा ३८३ करोड़ रुपये कम थी जबकि सरकार को दूसरे बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में ३२३ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इसके विवरण सारणी ५ में दिये गये हैं ।

मूल्य प्रवृत्तियां

५९ यह उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष के दौरान मूल्यों में तनाव की स्थिति नहीं पाई गई । मूल्यों में यह स्थिरता विभिन्न उपायों के माध्यम से प्राप्त की गई । इन उपायों का एक महत्वपूर्ण तत्व वस्तुओं की पूर्ति की प्रभावशाली व्यवस्था थी । वनस्पति तेलों जैसी अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और तिलहनों तथा कपास जैसे औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति में विद्यमान कमी को समय पर किये गये आयातों से पूरा किया गया । इससे कुछ सीमा तक विशेष रूप से प्रत्यक्ष उपयोग के संदर्भ में परम्परेतर तेलों के प्रयोग में उपभोक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा; किन्तु सामान्यतः यह नीति सफल रही है । सब्जियों और चाय जैसी उपभोक्ता

वस्तुओं की देश मे उपलब्ध मात्रा और विदेशो मे उनकी भारी माग को निर्यातो द्वारा विनियमित किया गया । इसके साथ ही खाद्यानो के यातायात पर लगे सभी प्रतिबन्धों को उठा लेने से भी खाद्यानो क मूल्यो मे विद्यमान अन्तर क्षेत्रगत विषमताओ को दूर करने मे काफी सहायता मिली ।

६०. जून १९७८ के अन्त मे प्रचलित मूल्यो की जून १९७७ के अन्त मे स्थित मूल्यो से अलग-अलग बिन्दु के आधार पर तुलना करने से थोक मूल्यो (आधार : १९७०-७१ =१००) के सूचकाक मे ३.११ प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित होती है । १९७६-७७ के इसी प्रकार के सूचकाक से तुलना करने पर ८.६ प्रतिशत की वृद्धि पाई जाती है । १९७७-७८ मे निर्मित वस्तुओं और प्राथमिक वस्तुओं मे लगभग समान रूप से (क्रमश: २.७ प्रतिशत और २ ९ प्रतिशत) गिरावट आई । निर्मित वस्तुओ मे जिन प्रमुख मदों के कारण गिरावट आई वे खाद्य वस्तुए थी । चीनी मे ४.३ प्रतिशत और खाद्य तेलों मे १३ ० प्रतिशत की गिरावट आई । प्राथमिक वस्तु समूह के अधीन खाद्य वस्तुओ मे गिरावट (०.७ प्रतिशत) पाई गई । उक्त समूह में जिस एक मद मे भारी वृद्धि (२६.१ प्रतिशत) पाई गई वह दाले थी ।

६१ साप्ताहिक औसतो के अनुसार मासिक औसत सूचकाक मे अगस्त से नवम्बर १९७७ तक गिरावट पाई गई । परवर्ती महीने मे सूचकाक मे थोडी-सी वृद्धि परिलक्षित हुई और जनवरी १९७८ मे सूचकाक घटकर नवम्बर १९७७ के स्तर पर पहुच गया। फरवरी १९७८ मे इस सूचकाक मे १ ६ प्रतिशत की भारी गिरावट आयी । उसके बाद उक्त सूचकाक मे सामान्यत: वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, किन्तु अप्रैल १९७८ मे उसमे ०.४ प्रतिशत की गिरावट आयी और जून १९७८ मे वह १८४.० (अनंतिम) पर पहुच गया । अलग-अलग वस्तुओं में से दालों मे जनवरी से गिरावट पायी गयी; किन्तु उनमे अप्रैल के बाद थोड़ी सी वृद्धि हुई । दालों के जिस मूल्य सूचकाक मे मार्च तक तीव्र वृद्धि हुई थी उसमे अगले दो महीनों मे ८.३ प्रतिशत की गिरावट आयी और जून में पुन: उसमे वृद्धि पायी गयी । दालों के सूचकांक का समग्र स्तर जून १९७८ मे औसतन २३७ २ था जबकि जून १९७७ मे उक्त सूचकाक १८९.० था ।

६२ सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि अप्रैल १९७६ स तेजी से बढ़ने के बाद फिलहाल मूल्यो मे काफी स्थिरता आयी है । सभी पण्यो का सूचकांक जून १९७८ के अंत मे १८४ ८ था जबकि उक्त सूचकाक जून १९७७ के अत मे १८८ ८ और जून १९७६ के अंत मे १७३ ९ था । १९७८-७९ के बजट मे परिकल्पित घाटे की वित्त व्यवस्था के पश्चात् अर्थ-व्यवस्था मे अधिक मात्रा मे पायी जानेवाली चल निधि के परिप्रेक्ष्य मे मूल्यों के क्षेत्र मे सतोष कर लेने की कोई गुजाइश नही है ।

६३ उपभोक्ता मूल्य सूचकाको मे होनेवाल उतार-चढ़ाव हमेशा थोक मूल्य सूचकांको के उतार-चढ़ावों के अनुरूप नही होते; क्योंकि उन दोनों के वस्तुगत स्वरूप और वजन की प्रणाली मे अंतर है । औद्योगिक श्रमिको के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : १९६० = १००) मे (जुलाई १९७७ की तुलना मे जून १९७८ मे) ० ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष के तदनुरूप अवधि मे उसमे ७ ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । शहरी श्रमेतर कर्मचारियो के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मे (जुलाई १९७७ की तुलना मे मई १९७८ मे) १ ७ प्रतिशत की सीमात वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि मे उक्त सूचकाक मे ५ १ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

ऋण नीति

६४. आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये ऋण नीति संबधी उपाय समग्र नीति विन्यास के अनुरूप किये गये थे । इन उपायों के द्वारा जिन दो प्रमुख उद्देश्यो की पूर्ति करने का प्रयास किया गया वे निम्न प्रकार थे: उत्पादक कार्य-

सारणी 5

मुद्रा उपलब्धि और परिवर्तन के स्रोत (अनंतिम)

(करोड़ रुपये)

	निम्नलिखित के अत मे बकाया			घट-बढ़	
	जून 1976	जून 1977@	जून 1978@	1976-77	1977-78
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. एम 1 (जनता के पास मुद्रा उपलब्धि) (अ+आ)	14038	16370	19378	+2332 (+16 6)	+3008 (+18 4)
अ जनता के पास चल मुद्रा	7235	8298	9295	+1063 (+14 7)	+997 (+12 0)
आ जमा रकम	6803	8072	10083	+1269 (+18 7)	+2011 (+24 9)
II. एम 1 मे परिवर्तन के स्रोत (1+2+3+4+5)					
1 बैंको द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण (अ+आ)	10841	12407	13913	+1566 (+14 4)	+1506 (+12 1)

1	2	3	4	5	6
अ. रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण (I–II)	7247	7929	8228	+682	+299
(i) सरकार पर दावे (क+ख)	7316	8000	8623	+684	+623
(क) केन्द्रीय सरकार	6996	7454	8498	+458	+1044
(ख) राज्य सरकारें	320	546	125	+226	+421
(ii) रिजर्व बैंक के पास सरकार की जमा राशियाँ (क+ख)	69	71	395	+2	+324
(क) केन्द्रीय सरकार	57	65	377	+8	+312
(ख) राज्य सरकारें	12	7	18	—5	+11
आ. दूसरे बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया ऋण	3594	4478	5685	+884	+1207
2. बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण (अ+आ)*	16029	18976	21976	+2947	+3000
				(+18.4)	(+15.8)
अ. रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गए ऋण	740	840	1066	+100	+226
आ. दूसरे बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण (i+ii+iii)	15288	18136	20910	+2848	+2774
(i) वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11492	13501	15504	+2009	+2003
(ii) सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	2106	2525	3020	+419	+495
(iii) वाणिज्य और सरकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	1690	2111	2386	+421	+275
3. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (अ+आ)	1274	3306	4567	+2032	+1261
				(+159.5)	(+38.1)
अ. रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (i–ii)	1280	3312	4573	+2032	+1261
(i) सकल विदेशी आस्तियाँ	1969	3761	4733	+1792	+972
(ii) मुद्रेतर विदेशी देयताएं	689	449	160	—240	—289
आ. दूसरे बैंकों की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	—6	—6	—6	—	—
4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	555	583	573	+28	—10
				(+5.0)	(—1.7)
5. बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रेतर देयताएं (अ+आ+इ)	14661	18902	21651	+4241	+2749
				(+28.9)	(+14.5)
अ. बैंकों के पास मीयादी जमा राशियाँ	9978	12736	14997	+2758	+2261
				(+27.6)	(+17.8)
आ. रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयताए	2458	3593	3053	+1135	—540
इ. दूसरे बैंकों की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं (निकाली गयी)	2226	2573	3601	+347	+1028
III. एम 3(एम 1+बकों के पास मीयादी जमा राशियाँ)	24016	28107	34375	+5091	+5268
				(+21.2)	(+18.1)

*इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये दिये गये ऋण शामिल हैं।

@अनंतिम

टिप्पणी: (1) कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े प्रतिशत घट-बढ़ से संबंधित हैं।

(2) अलग अलग मदों के आँकड़े जोड़ से मेल नहीं खाते, क्योंकि जोड़ को पूर्णांकित किया गया है।

कलापों की गति में तीव्रता लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करना और अधिक मात्रा में मुद्रा विस्तार होने की गुंजाइश को सीमित कर मूल्यों में स्थिरता लाना आलोच्य वर्ष के दौरान किया गया नीति संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय ब्याज दरों के समायोजन से संबंधित था । ऋणों पर जो ब्याज लिया जाता है उसकी दरों को पहले चयनात्मक रूप से कम किया गया और इसे कुछ अधिमान्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले कतिपय ऋणों और अग्रिमों तक सीमित रखा गया । इस प्रकार दिसम्बर १९७७ में बैंकों से यह कहा गया कि वे लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों, सड़क परिवहन चालकों एवं निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थित छोटी इकाइयों को दिये जाने वाले मीयादी ऋणों पर ११ प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज लें । ग्यारह प्रतिशत की यह अधिकतम ब्याज दर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा "व्यापक प्रयोजनों" के रूप में परिभाषित प्रयोजनों के लिए कृषकों को दिये जाने वाले मीयादी ऋणों के लिए भी लागू थी जबकि लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिए दिये जानेवाले मीयादी ऋणों के संदर्भ में निर्धारित अधिकतम ब्याज दर अपेक्षाकृत कम अर्थात १०.५ प्रतिशत थी । उक्त दरें उन सभी ऋणों के लिए (१ जनवरी १९७८ के बाद प्रदत्त) लागू की गयीं जिनकी अवधि संबंधित वर्गों में तीन वर्षों से अधिक नहीं हो, भले ही ऐसे ऋणों के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और कृषि पुनर्वित्त

और विकास निगम से उपलब्ध किसी पुनर्वित्त सुविधा का वास्तव में प्रयोग किया गया हो या नहीं । अलग-अलग रूप से सीध प्रदान किये गए अधिकतम रु. २,५०० तक के छोटे कृषि ऋणो क लिए बैंक दर पर रिजर्व बैंक की विशेष पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करायी गयी । पहली जनवरी, १९७८, के बाद प्रदान किय गये इस वर्ग क सभी प्रकार के ऋण, चाह उनकी अवधि कुछ भी क्यो न हो, इस "छोटे कृषको को उपलब्ध सुविधा" क अंतर्गत कुल ऋणो के ५० प्रतिशत तक के पुनर्वित्त के लिए पात्र थ; बैंको को यह भी सूचित किया गया कि ऐसे सभी ऋणो पर ११ प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज लिया जाये चाहे उनके संबध म वास्तव म पुनर्वित्त लिया गया हो या नही ।

ऋणों की ब्याज दरों को कम करना

६५ बैंको की ऋण संबधी ब्याज दरो मे केन्द्रीय बजट के साथ ही अधिकतम व्यापक रूप से गिरावट की घोषणा की गयी । निवेश के वातावरण मे सुधार लाने तथा उत्पादन की लागत को कम करने की राजकोषीय नीति के अनुरूप ऋण व्यवस्था को बनाने के लिए उठाये गये इस कदम की कई विशेषताए थी । पहली विशेषता यह थी कि मार्च, १९७६ मे निदिष्ट ऋण सबधी १६.५ प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर को कम कर १५ प्रतिशत कर दिया गया । पहले जहा छोटे बैंको (अर्थात २५ करोड रुपया से ५० करोड रुपयो तक की मांग और मीयादी देयताओं से युक्त) को उच्चतर अधिकतम दर पर ब्याज लने की अनुमति थी और बैंको के सबसे छोटे समूह (अर्थात २५ करोड रुपयो से कम राशि की माग और मीयादी देयताओ से युक्त) को इस उच्चतम ब्याज दर से पूर्णत: छूट प्राप्त थी वहां अब इन रियायतों को वापस ले लिया गया और केवल बैंको के सबसे छोटे समूह को १६ प्रतिशत की उच्चतर अधिकतम दर पर ब्याज लेने की अनुमति दी गयी । दूसरी विशेषता यह थी कि चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अधीन आने वाले संवेदनशील पण्यों पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर १५—१६ प्रतिशत की अधिकतम दर लाग की गयी जबकि पहले ऐसे अग्रिमों को उच्चतम ब्याज दर से छूट प्राप्त थी । इस प्रकार न केवल ऋण संबधी अधिकतम ब्याज दर को कम किया गया अपितु उन्हे अधिक व्यापक रूप में भी लाग कर दिया गया। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंको को ब्याज से प्राप्त होनेवाली आय पर से कर हटा देने की जो घोषणा बजट मे की गयी उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, रिजर्व बैंक ने बैंको को यह निदेश दिया कि वे ऋण संबधी अपनी ब्याज दरो मे आम तौर पर प्रतिशत की कमी लाये और जहा ऐसी कमी के परिणामस्वरूप संशोधित ब्याज दर ऋण संबंधी १२.१.२ प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर से सीमान्त रूप से कम हो जाए वहां उसकी सूचना रिजर्व बैंक को दी जाए । बैंको को यह भी सूचित किया गया कि वे अग्रिमो पर त्रैमासिक रूप से ही ब्याज जोड़े, न कि इससे कम अवधियों मे ।

६६ ऋण संबंधी कुछ अन्य ब्याज दरो मे भी कमी लाकर समायोजित किया गया । खाद्यानो की सार्वजनिक वसूली तथा वितरण के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर ली जानेवाली ब्याज दर को १२ प्रतिशत से कम कर ११ प्रतिशत कर दिया गया । इसके परिणामस्वरूप खाद्य ऋणो के लिए रिजर्व बैंक जिस दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है उसे भी १० प्रतिशत से घटाकर ६ प्रतिशत कर दिया गया। निर्यात ऋण तथा ऐसे ऋण पर प्रदान किये जानेवाले पुनर्वित्त की ब्याज दर मे भी १/२ प्रतिशत की कमी लायी गयी । आस्थगित अदायगी के आधार पर दिये जानेवाल निर्यात ऋण की ८ प्रतिशत की ब्याज दर तथा इसके पूर्व दिसम्बर, १९७७ मे घोषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋणो की ब्याज दर जैसी कतिपय अन्य दरे अपरिवर्तित रही ।

जमाराशियों की ब्याज दरों में संशोधन

६७ ऋणो की ब्याज दरो मे कटौती करने के साथ-साथ जमा राशियो की ब्याज दरो मे भी कुछ सशोधन किये गये । बैंको की ब्याज दरो के समग्र विन्यास तथा ऋणों की उच्चतम ब्याज दरो मे कमी लाने के परिणामस्वरूप बैंको की आय पर पडने वाल प्रभाव के संदर्भ मे संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक था । जमाराशियो की ब्याज दरो मे संशोधन करने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि बैंको के पास अपनी प्रारक्षित निधियो को मजबूत बनाने के लिये उपलब्ध अधिशेष निधियो की मात्रा पहले से ही कम थी । मूल्यो मे सापेक्ष स्थिरता आने के साथ-साथ ब्याज दरो मे भी वास्तविक अर्थो मे बढ़ोतरी पाई गई । अत: जमाराशियो की ब्याज दरो मे कमी लाई गई । पाच वर्षो तथा उनसे अधिक अवधि की जमाराशियो की ब्याज दरो मे कमी लाई गई । पाच वर्षो तथा उनसे अधिक अवधि की जमाराशियो पर सर्वाधिक ब्याज मिलता है और बैंको की कुल जमाराशियो मे उनका अश लगभग २० प्रतिशत था; इन जमाराशियो की ब्याज दर को १० प्रतिशत से घटाकर ९ प्रतिशत कर दिया गया । अन्य सावधि जमाराशियों के वर्गो के मामले में १/२ प्रतिशत की कमी की गई । ९१ दिनों और ३ वर्षो तक के बीच की अवधियो की जमाराशियो की ब्याज दरे अपरिवर्तित रही । जमाराशियो की ब्याज दरो मे किया गया सशोधन राजकोषीय नीति संबंधी उपायो के द्वारा बचत राशियों का पूंजी बाजार मे निवेश करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन के भी अनुरूप था। बैंक ऋणो पर त्रैमासिक रूप से ब्याज लने के संबंध मे दिये गये अनुदेशों के समान जमाराशियो पर दिये जाने वाले ब्याज का भी त्रैमासिक आधार पर ही हिसाब लगाया जाना चाहिए, न कि उससे कम अवधि मे, इससे बैंको के लिए निधि सम्बन्धी खर्च मे और कमी आ सकेगी ।

६८ बचत जमाराशियो के सदर्भ मे जुलाई १९७७ मे चेक सुविधा युक्त और चेक सुविधा रहित जमाराशियों के बीच किये गये अन्तर को हटा दिया गया, क्योंकि इस प्रकार दो तरह के खाते होने से बैंको को परिचालन संबंधी कठिनाइया होती थी । दोनो प्रकार की जमाराशियो को एक कर उनके लिए ४.५ प्रतिशत की एक समान ब्याज दर लागू की गई । बचत बैंक जमाराशियो के लिए उपलब्ध चेक सुविधाओ की मात्रा मे भी सीमा निर्धारित की गई । २४ करोड रुपयो से कम जमा देयताओं से युक्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को बचत जमाराशियों और ५ वर्षो तक की सावधि जमाराशियों पर क्रमश: ०.२५ प्रतिशत और ०.५१ प्रतिशत अधिक ब्याज अदा करने की अनुमति दी गई । अनुसूचित सहकारी बैंको, मध्यवर्ती सहकारी बैंको और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंको को भी बचत तथा सावधि जमाराशियों पर २५ करोड रुपयों और अधिक राशि की मांग और मीयादी देयताओ से युक्त वाणिज्य बैंकों द्वारा देय

निर्दिष्ट ब्याज दरों के मुकाबले क्रमश: ०.२५ प्रतिशत, ०.५० प्रतिशत और १.० प्रतिशत अधिक ब्याज अदा करने की अनुमति दी गई।

६९. बैंकों की ऋण संबंधी दरों के विन्यास में की गई कटौती के तत्काल बाद ही अन्य दरों में भी परिवर्तन किए गये। मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं ने भी अपनी दरों में तदनुरूप कटौतियां की और जमाराशियां स्वीकार करने वाली कम्पनियों में सामान्यत: अपनी दरों में कमी लाने की प्रवृत्ति पाई गई ताकि बैंकों की जमाराशि संबंधी ब्याज दरों से अलग ब्याज दरें बनाये रखी जा सकें। भारतीय बैंक संघ ने मांग राशि की उच्चतम ब्याज दर को १० प्रतिशत से कम कर ८-१/२ प्रतिशत कर दिया। सहभागिता प्रमाणपत्रों और बैंकों तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं में पुन: भुनाये जाने वाले बिलों की उच्चतम ब्याज दर को रिजर्व बैंक ने भी १२ प्रतिशत से कम कर १० प्रतिशत कर देने की घोषणा की।

७०. जमाराशियों की ब्याज दरों की गई सामान्य कटौती के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना में पुन: समायोजन किया गया। पहली मार्च, १९७८ से इस योजना के अन्तर्गत केवल दो वर्गों की जमाराशियां स्वीकार की जाती हैं। वे हैं १ वर्ष और उससे अधिक अवधि और ३ वर्षों तक की ६ प्रतिशत ब्याजयुक्त जमाराशियां तथा ३ वर्षों से अधिक अवधि और ५ वर्षों तक की ७-१/२ प्रतिशत ब्याजयुक्त जमाराशियां। एक वर्ष से कम तथा ५ वर्षों से अधिक अवधि की जमाराशियां अब इस योजना के अन्तर्गत नहीं आती।

पुनर्वित्त में समायोजन

७१. चूंकि बैंकिंग तंत्र में अधिक मात्रा में चलनिधि होने के संकेत अधिक स्पष्ट रूप से उभर आये; अत: रिजर्व बैंक ने मुद्रा विस्तार की संभावना को रोकने के लिए कदम उठाये। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये गये कदमों में कोई कमी न आये। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से रिजर्व बैंक की संभावना उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिबंधात्मक कदम उठाये गये। मई, १९७९ में यह घोषित किया गया कि खाद्य ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त तभी उपलब्ध होगा जब खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली और वितरण से संबंधित कुल बकाया ऋण राशि २,००० करोड़ रुपये हो; यह राशि अब तक १,५०० करोड़ रुपये निर्धारित थी। दूसरी बात यह है कि बैंकों को उनकी मांग और मियादी देयताओं के १ प्रतिशत के स्तर तक स्वमेव उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधा को वापस ले लिया गया और समस्त पुनर्वित्त को विवेकाधीन तथा अस्थायी आधार पर रखा गया। यह स्मरण होगा कि जून, १९७७ में भी इस सुविधा को स्वमेव उपलब्ध होना इस शर्त के कारण थोड़ा बहुत प्रभावित हो गया था कि वह केवल सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर उपलब्ध होगी जिससे उक्त प्रतिभूतियां भारग्रस्त और सांविधिक चलमुद्रा अनुपात के लिए अपात्र हो जाएंगी।

७२. इस संदर्भ में उठाये गये एक और कदम का उद्देश्य यह था कि दो विशेष योजनाओं के अन्तर्गत भारत में भेजी जाने-वाली विदेशी मुद्रा का उपलब्धि पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे प्रभावहीन कर दिया जाए। बैंकों को यह निदेश दिया गया कि वे अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना तथा विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अन्तर्गत १ जून, १९७८ के बाद प्राप्त हुई शुद्ध कुल राशि में से आधी राशि के बराबर की रुपया राशि रिजर्व बैंक के पास जमा रखें। इस प्रकार रिजर्व बैंक में जमा की गई राशि पर ६.५ प्रतिशत का ब्याज अदा किया जाएगा। न्यूनतम ३ प्रतिशत की सांविधिक प्रारक्षित नकदी निधियों तथा १० प्रतिशत की वृद्धिशील प्रारक्षित राशि के अलावा रखी जाने वाली बैंकों की अतिरिक्त प्रारक्षित नकदी निधियों पर देय ६ प्रतिशत की ब्याज दर को भी बढ़ाकर ६.५ प्रतिशत कर दिया गया।

विशेष पुनर्वित्त योजना

७३. पूंजीगत वस्तुओं के आयातों को प्रोत्साहित करने के उपाय के रूप में सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत आयातक किसी भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक से और /या किसी भी मीयादी ऋण प्रदान करने वाली राष्ट्र स्तरीय संस्था से आयात की लागत के बराबर के मियादी ऋण रुपयों में प्राप्त कर सकते है। इन ऋणों की अवधि सामान्यत: १० वर्षों से अधिक नहीं होगी और इनकी ब्याज दर संप्रति ११ प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस नीति को समर्थन देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अप्रैल, १९७८ में एक विशेष पुनर्वित्त योजना की घोषणा की जिसके अन्तर्गत ऐसे ऋण प्रदान करने वाले बैंक इस प्रकार दो सम्पूर्ण ऋण के लिए बैंक दर पर पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त

७४. राज्य सहकारी बैंकों को रियायती शर्तों पर दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं को मार्च, १९७८ में और भी व्यापक बना दिया गया। मध्यावधि कृषि प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋण पर जो ब्याज लिया जाता है उसकी दर बैंक दर से २-१/२ प्रतिशत कम निर्धारित की गई है जबकि इसके पहले उक्त दर बैंक दर से १-१/२ प्रतिशत कम थी। मौसमी कृषि कार्यों का वित्तपोषण करने के निमित्त दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दर भी पहले जहां बैंक दर से २ प्रतिशत कम थी वहां उसे बैंक दर से ३ प्रतिशत कम कर दिया गया है। यह आशा की जाती है कि इन कटौतियों से होने वाले लाभ तथा सरकार द्वारा ब्याज कर को हटा देने तथा जमाराशियों की ब्याज दरों में कटौती करने के कारण अनुसूचित सहकारी बैंकों को प्राप्त होने वाले लाभों को विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों के अन्तिम उधारकर्ताओं को उपलब्ध कर दिया जाएगा।

७५. अन्तिम उधारकर्ताओं को ऋण की जो लागत वहन करनी पड़ती है उसे कम करने की दिशा में की गई एक कार्रवाई यह थी कि कुटीर और लघु उद्योगों के बाईस स्थूल वर्गों में संलग्न औद्योगिक सहकारी इकाइयों (बुनकर इकाइयों से भिन्न) का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले पुनर्वित्त की ब्याज दर को अगस्त, १९७७ में बैंक दर से घटाकर बैंक दर से १-१/२ प्रतिशत कम और मार्च, १९७८ में और घटाकर बैंक दर से २-१/२ प्रतिशत कम कर दिया गया। इस नीति के अनुरूप यह भी निश्चय किया गया कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, कृषक सेवा समितियों और बड़े आकार वाली बहु उद्देशीय समितियों को बुनाई के कार्य में अथवा कुटीर और लघु उद्योग संबंधी कार्यों के २२ निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग में लगे हुए ग्रामीण कारीगरों का वित्तपोषण करने के लिए बैंक दर से ३ प्रतिशत कम दर पर रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाए।

सोने की बिक्री

७६. देशी बाजार में सोने का मूल्य जहां कुछ समय तक उच्च स्तर पर रहा वहां १९७७ के उत्तरार्ध में बढने लगा और अप्रैल १९७८ में वह बढकर (बम्बई बाजार में) प्रति १० ग्राम रुपये ७२४ हो गया। सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी बढ़ रहे थे, किन्तु उनमें अपेक्षाकृत कम तेजी से वृद्धि पायी गयी। मूल्यों में अंतर के कारण तस्करी की गतिविधियों के बढ़ने की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने स्वर्ण भंडारों में सोने की बिक्री करने का निर्णय किया। यह आशा की गयी कि इस प्रकार की बिक्री से बजट घाटे का मुद्रागत प्रभाव कम होगा। यह बिक्री रिजर्व बैंक द्वारा हर पखवाड़े में नीलामी के माध्यम से की जाती है तथा इस श्रृंखला की पहली नीलामी ३ मई १९७९ को हुई थी। लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से हर नीलामी के लिए मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं तथा नीलाम किया जाने वाला सोना ९९५ शुद्धता वाली १०० ग्राम की ईंटों में होता है। बोली लगाने के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सोना प्रारंभ में क्रमश: १००० ग्राम तथा ५००० ग्राम था, किन्तु १४ जून १९७८ में चौथी नीलामी के बाद उसे बदलकर ५०० ग्राम तथा २५०० ग्राम कर दिया गया। बोली लगाने वालों को अपेक्षित सोने की मात्रा और अपने मूल्य का उल्लेख करना होता है और प्रत्येक विक्रेता को केवल एक बोली लगाने की अनुमति होती है। चौथी नीलामी से, पांच विक्रेताओं और/या प्रमाणित सुनारों को भी संयुक्त रूप से बोली लगाने तथा उनमें से एक को सोने की सुपुर्दगी लेने का अधिकार प्रदान करने की अनुमति है।

७७. जून १९७८ के अंत तक हुई सोने की पांच नीलामियों में कुल ६.४० टन सोना (४० ९४ करोड़ रुपयों के मूल्य का) बेचा गया जिसका प्रति १० ग्राम मूल्य ६२० रुपये से ६७५ रुपये तक रहा। पहली नीलामी के अवसर पर प्राप्त बोलियों की संख्या ४२६ थी जो तेजी से बढ़कर २८ जून को हुई नीलामी के समय १३६९ हो गई। पांच नीलामियों में स्वीकृत बोलियों की कुल संख्या ३६८८ है।* नीलामियों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे विक्रेताओं को नीलामियों में खरीदा गया सोना पुन: बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मूल्यांकन और संभावनाएं

७८ वर्ष १९७७-७८ के अंत में मिली-जुली आर्थिक स्थिति विद्यमान थी। १९७७-७८ में मूल्यों में स्थिरता के साथ-साथ काफी अधिक विकास की पृष्ठभूमि थी और वर्ष के अंत में खाद्यान्नों के स्टाक तथा प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियां पहले से अधिक थीं। इस परिवेश में अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व लचीलापन आ गया है। १९७८-७९ के केन्द्रीय बजट और वार्षिक योजना के अनुसार यह प्रत्याशी है कि सार्वजनिक विकास व्यय में काफी अधिक वृद्धि होगी। सामान्यत: निवेशों पर स्थिति का संतोषजनक प्रभाव पड़ना चाहिए। इसके विपरीत जब हम दीर्घकालीन दृष्टि से देखते हैं तब मूल्य स्थिरता के साथ और प्रगति होने की संभावनाओं में थोड़ी बहुत अनिश्चित स्थितियां अब भी पायी जाती हैं।

७९ चूंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि दर को बनाये रखना मूलत: कठिन होगा अत: अर्थव्यवस्था की प्रगति में मंदी आ सकती है। मौसमी कारणों के अलावा हमारे कृषि क्षेत्र की मूलभूत कमजोरियां तथा नयी टैक्नोलोजी के असमान विस्तार के कारण कृषि उत्पादन के विकास में बाधा आ सकती है। विकास की गतिविधियां को विकेन्द्रीकृत कर छोटे छोटे खंडों तक पहुंचा दिया गया है। अत: अब जिलों तथा गांवों के स्तर पर प्रशासन, विपणन, ऋण और विस्तार की मूलभूत सुविधाएं निर्मित होंगी। यह स्थिति अभी बन रही है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि कृषि विकास की प्रक्रिया अपने आप में काफी अधिक समर्थ हो गयी है।

८० कृषि उत्पादन में गिरावट आने से मूल्यों पर तत्काल जो प्रभाव पड़ता है उसका सामना निम्न प्रकार किया जा सकता है। भारी खाद्यान्न भंडारों से समय पर उचित मात्रा में खाद्यान्नों को निकालकर उनका वितरण किया जाए और खाद्यान्नों के आयात किये जाएं। किन्तु कुछ उद्योगों पर विशेषकर कृषि-जन्य वस्तुओं पर निर्भर रहने वाले उद्योगों पर कम संतोषजनक कृषि फसलों का जो चिंताजनक प्रभाव पड़ता है वह आगे भी जारी रहेगा। साथ ही, संबंधित कृषि समुदायों की आमदनी भी अपेक्षाकृत कम होगी। सौभाग्यवश १९७८-७९ की खरीफ फसल के लिए अब तक मानसून संतोषजनक रहा है।

८१. सामान्य रूप से निवेश क्षेत्र और तत्संबंधी कार्यकलापों में मामूली प्रगति के संकेत प्राप्त हैं। उद्योग क्षेत्र पुनर्विकास की तात्कालिक संभावना भी प्रशस्त है। फिर भी जब मांग में थोड़ी सी वृद्धि होने से औद्योगिक उत्पादन की गति बढ़ने लगती है तब बिजली की कमी बहुत अधिक महसूस होगी। इस क्षेत्र की ओर हमारा तत्काल ध्यान जाना जरूरी है। योजना प्रारूप में बिजली के उत्पादन की क्षमता की वृद्धि को महत्व दिया गया है। फिर भी इस संदर्भ में वर्तमान क्षमता का पूर्ण और अधिक सक्षम प्रयोग करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प प्रतीत नहीं होता।

८२ इस समय जो विकास नीति परिकल्पित है उसमें विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों के विकास के प्रति झुकाव के कारण अर्थव्यवस्था के स्वरूप में सुनिश्चित परिवर्तन की आशा है। किन्तु इस परिवर्तन में कुछ समय लग सकता है। इन नीतियों को कार्यान्वित करते समय अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं और विपणन व्यवस्थाओं की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। अत: प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल इन कठिनाइयों को दूर करने की कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।

८३ इन अनिश्चितताओं के बावजूद खाद्यान्नों के संचित स्टाकों और विदेशी मुद्रा साधनों के कारण आगामी महीनों में देश में विद्यमान अत्यधिक गरीबी को हटाने का एक विशेष अवसर प्राप्त है। इन दोनों साधनों में से कोई भी साधन अर्थव्यवस्था के आकार और स्वरूप तथा भारत जैसे देश के जीवन स्तरों को देखते हुए प्रचुर या अधिक नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही वर्तमान स्टाकों में यदि थोड़ी सी भी वृद्धि की जाए तो नयी समस्याएं उत्पन्न होंगी तथा वर्तमान अवसरों से भी हाथ धोने की संभावना होगी।

८४ फिलहाल, लगभग १६० लाख टन खाद्यान्नों के जो स्टाक उपलब्ध हैं वे प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से उत्पन्न

*जुलाई 1978 में हुई दो नीलामियां प्रति 10 ग्राम रु० 641 और रु० 655 के बीच के मूल्य पर कुल 2 97 टन सोना बेचा गया। इससे अब तक नीलामियों के द्वारा बेचे गये सोने की कुल मात्रा 9 37 टन थी जिसका मूल्य 60 10 करोड़ रुपये था। 8 अगस्त 1977 को सोने की बिक्री के लिए हुई आठवीं नीलामी में प्राप्त 1 823 बोलियों में से किसी भी बोली को रिजर्व बैंक ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे नियत मूल्य तक नहीं पहुंची।

आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काफी अधिक हैं । इस वर्ष स्टाकों में लगभग १२० लाख टन के जो स्टाक निकाले गये वे भी अपेक्षित क्रय और विक्रय की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं । बढ़ती हुई पूर्ति के साथ साथ जब मूल्य समर्थन के आधार पर खाद्यान्न खरीदे जाते हैं तब खाद्यान्नों के स्टाक बढ़ते हैं यदि कृषि उत्पादन को बड़ी तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो कृषि मूल्यों के लिए समर्थन की आवश्यकता होगी । इससे उत्पादन में स्थिरता आ सकेगी और कृषि तथा उद्योग के बीच ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो सकेंगी जिनसे कृषि बुरी तरह से प्रभावित हो । कृषकों को इन नीतियों से लाभान्वित कराने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वितरण प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जाए और इस समय उपलब्ध होने वाली कृषि संबंधी मूलभूत वस्तुओं के अधिक सक्षम उपयोग के लिए अनुकूल संस्थागत परिवर्तन किये जाएं । किन्तु यदि संस्थागत परिवर्तनों के बिना इस आधार पर कृषि मूल्य बढ़ाने की नीति जारी रहे कि उसे मूल्य वृद्धि के अनुरूप बनाना है तो इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

८५. खाद्यान्नों को स्टाकों में वृद्धि करने से भी कई समस्याएं खड़ी होती हैं । अगर स्टाकों को और बढ़ाना हो तो उनके भंडारण की क्षमता के संदर्भ में गंभीर बाधा खड़ी हो सकती है ; क्योंकि भंडारण की क्षमता पहले से ही अपर्याप्त है और स्तरीय भी नहीं है; उसे बहुत कम समय में बताया भी नहीं जा सकता । इसके अलावा समय के साथ ही खाद्यानों के स्टाकों के खराब हो जाने का भी प्रश्न उठता है । दूसरी समस्या वित्त-पोषण की है । खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद के लिए बैंकों द्वारा दिये गये ऋण का अब तक का सर्वोच्च स्तर जुलाई १९७७ में पाया गया । उस समय उक्त ऋण राशि २.५९ करोड़ रुपये (कुल बैंक ऋण का १९ प्रतिशत) थी और अब भी यह राशि २,५०० करोड़ रुपयों (१६ प्रतिशत) के आसपास है । जब बैंकिंग तंत्र के वित्तीय साधनों का बहुत अधिक अंश इस प्रकार खाद्यानों के स्टाकों में लगा दिया जाता है तब कुछ हद तक इससे दूसरे उत्पादक कार्यों के लिए किये जाने वाले निवेशों में कमी आ जाती है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि खाद्यानों के स्टाकों में केवल कमी कर देने से निवेशों में वृद्धि होगी । वस्तुतः वह इस बात पर निर्भर करता है कि खाद्यानों के स्टाक कैसे उपयोग किया जाता है और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में निवेशों का निर्माण करने और उनसे लाभ अर्जित करने की दिशा में कौन सी कार्रवाइयां की जाती हैं ।

८६. वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए खाद्यान्नों के स्टाकों का उत्पादक दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है । 'काम के लिए अन्न' कार्यक्रम के द्वारा इस दिशा में एक छोटा सा प्रारंभिक कदम उठाया गया है । यदि ग्रामीण विकास और ग्रामीण उद्योगों के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को तेजी से समग्र क्रियान्वित किया जाए तो उससे समाज के कमजोर और दलित वर्गों की आमदनी में काफी अधिक वृद्धि होगी और खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ेगी । परंतु इसके लिए प्रशासकीय तथा दूसरे अतिरिक्त क्षेत्रों की क्षमता को काफी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है । बहुत अधिक प्राथमिकता देकर इन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, अन्यथा पूर्वोक्त कई नयी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और उनका सामना करना पड़ेगा । विशेष रूप से इस समय जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अधिक नगर अभिमुख है उसे मज़बूत करने और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता होगी ।

८७. इस समय लगभग ९ महीनों तक के आयातों के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि के बराबर की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियां उपलब्ध हैं । यद्यपि चार महीने के आयातों के भुगतान की क्षमता को आम तौर पर प्रारक्षित निधियों का उचित मानदंड समझा जाता है, फिर भी भारतीय कृषि क्षेत्र के उत्पादन में तेजी से उतार-चढ़ाव होने और अर्थव्यवस्था में इन उतार चढ़ावों का प्रभाव पड़ने की संभावना के कारण भारत की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों के स्तर को थोड़ा बहुत ऊंचा रखने की आवश्यकता है । फिर भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनने के लिए इन साधनों का उदार एवं उद्देश्यपूर्ण प्रयोग करने की दिशा में कई कदम उठाये गये हैं । औद्योगिक विकास और मूल्य स्थिरता पर इन प्रयासों का वांछित प्रभाव पड़े—इसके लिए यह आवश्यक होगा कि कच्चे माल और उपभोगता वस्तुओं के आयातों के संबंधों में उदारतापूर्ण मार्ग अपनाया जाए और निरंतर इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखा जाए ।

८८. वर्तमान संदर्भ में यह बहुत आवश्यक है कि निर्यातों के प्रयास में कोई कमी न आये । वर्षों से बड़ी सावधानी से निर्यातों के विकास का जो वातावरण निर्मित किया गया है उसे भी सुरक्षित रखना है, हालांकि कुछ निर्यातों की लागत को अधिक लाभप्रद बनाने का प्रयास किया जाता है । यद्यपि भारत की व्यापक और वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए 'निर्यात प्रधान विकास' की संकल्पना अनुपयुक्त है फिर भी निर्यातों में निरंतर महत्वपूर्ण वृद्धि करना अत्यावश्यक है । यह इसलिए नहीं कि निर्यात कुछ उद्योग समूहों के लिए अधिक महत्व रखते हैं परंतु इसलिए कि प्रारंभिक रुग्णता को दूर किया जा सके और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दृष्टि से रोजगार को बढ़ाया जा सके । यदि काफी लम्बी अवधि तक विदेशी भुगतानों के वातावरण को अनुकूल बनाए रखना है तो उस स्थिति में भी निर्यातों में वृद्धि होती रहनी चाहिए । अभी दो वर्षों की अल्प अवधि में प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण हम इस क्षेत्र में अवश्य आश्वस्त हैं किन्तु हाल ही के महीनों में इन निधियों से प्राप्त होने वाले लाभ में काफी अधिक कमी हो जाने से और इस कारण से भी कि हम अब भी विदेशी सहायता पर काफी अधिक निर्भर करते हैं; यह स्थिति शीघ्र ही बदल जाएगी ।

८९. विकास निरंतर हो और वितरण न्यायपूर्ण हो—इसके लिए मूल्यों में उचित स्थिरता लाना अत्यावश्यक है । मूल्य स्थिरता को बढ़ाने के लिए निर्वाह वस्तुओं की पूर्ति और उनकी मांग के बीच संतुलन लाने की आवश्यकता है । नयी योजना के सिद्धांत में ग्रामीण विकास, लघु उद्योगों और बहुत छोटे कारखानों के विकास पर जोर दिया गया है । इससे बिजली, सिंचाई, सड़क और संचार जैसी कई मूलभूत आवश्यकताओं पर भारी मात्रा में निवेश होगा । इससे मुद्रा उपलब्धि में बहुत अधिक वृद्धि होगी और मांग की संभावना भी बढ़ेगी । किन्तु इसके साथ ही निर्वाह वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पायेगी । इस प्रकार के निवेश और अन्य निवेशों के लिए अधिक मात्रा में आयात करने होंगे और प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में से अधिक मात्रा में राशि निकलनी होगी ।

९०. वित्तीय सहायता के द्वारा विकास कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से मुद्रा नीति को बनाने की संभावना पर वर्तमान मुद्रागत स्थिति के संदर्भ में विचार करना होगा । पिछले तीन वर्षों में मुद्रा उपलब्धि में औसतन १५.६ प्रतिशत की वृद्धि दर पायी गयी है । मुद्रा उपलब्धि की इस वृद्धि दर को मुद्रास्फीति लाये बिना बनाये नहीं रखा जा सकता । वास्तविक उत्पादन वृद्धि की अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियों में भी यह संभव नहीं है । अतः ऋण नियंत्रणों में ढील लाने और ब्याज दरों

में और कमी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई आर्थिक औचित्य नहीं है । अगर बहुत कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध हो तो उत्पादन की पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग उन संदर्भों में भी हो सकता है जहां उनकी आवश्यकता न हो । इससे अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में भी कमी आयेगी । साथ ही न्यून ब्याज दरों से बैंकों की कार्यक्षमता भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है ।

९१. इस प्रकार वित्तीय और मुद्रागत नीतियों को सावधानी से निर्मित करना होगा जिससे कि अर्थव्यवस्था में विकास हो और ऐसे विकास के लिए आवश्यक मूलभूत परिवर्तन हो और साथ ही उचित मात्रा में मूल्य स्थिरता भी हो । यह भी आशा नहीं की जा सकती कि कुल निवेश और अन्य विकास परिव्यय में निर्वाह वस्तुओं की पूर्ति के साथ-साथ और उतनी ही मात्रा में वृद्धि हो पायेगी । मुद्रास्फीति के दबावों का सामना करने के लिए अवश्य ही मुद्रागत प्रतिबन्धों को जारी रखना होगा ।

अध्याय २ दूसरी गतिविधियां

९२. विदेशी मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पाई गईं : 'पी' फार्म से संबंधित कुछ अपेक्षाओं को सरल और उदार बनाया गया; विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को सिक्किम पर लागू किया गया, अनिवासी भारतीय और विदेश स्थित भारतीय मूल के व्यक्तियों को स्थायी निवास के लिए उनके भारत लौटने पर उनकी अपनी विदेशी मुद्राओं को भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया और चीन के साथ व्यापार संबंधी लेन-देन शुरू किये गये ।

उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा

९३. उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा प्रदान करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक संबंधी मानदण्ड पहले जहां अर्हता परीक्षा में ६० प्रतिशत था वहां उसे पहली अगस्त, १९७७ से कम कर ५५ प्रतिशत कर दिया गया है । अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के मामले में इस सीमा को और घटाकर ४९.५ प्रतिशत कर दिया गया है ।

९४. निर्वाह, प्रारम्भिक आवश्यकताओं और शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के पहले की अपेक्षाओं के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा को पहली अगस्त, १९७७ से निम्न प्रकार बढ़ा दिया गया है (इसके पहले स्वीकृत मदन कोष्ठकों में दर्शाया गया है) ।

	अमेरिका/कनाडा	ब्रिटेन	दूसरे देश
निर्वाह के लिए	अमेरिकी डालर 4000 (अमेरिकी डालर 3000) वार्षिक	अमेरिकी डालर 3000 (पौण्ड 1300) वार्षिक	अमेरिकी डालर 3000 (अमेरिकी डालर 2600) वार्षिक
प्रारम्भिक आवश्यकताओं के लिए	अमेरिकी डालर 300 (अमेरिकी डालर 250)	अमेरिकी डालर 250 (पौण्ड 100)	अमेरिकी डालर 250 (अमेरिकी डालर 200)
सत्र प्रारंभ होने के पहले की आवश्यकताओं के लिए।	अमेरिकी डालर 165 (अमेरिकी डालर 105)	अमेरिकी डालर 120 (पौंड 55)	अमेरिकी डालर 120 (अमेरिकी डालर 110)

९५. इसके अलावा विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रमाणित वास्तविक शिक्षण शुल्कों के आधार पर भी विदेशी मुद्रा दी जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं का क्रय और विक्रय

९६. प्राधिकृत व्यापारियों से पौंड स्टर्लिंग, अमेरिकी डालर, ड्यूश मार्क और जापानी येन के वायदा क्रय के संबंध में १६ अगस्त १९७७ से शुरू की गई नयी प्रणाली के अन्तर्गत रिजर्व बैंक त्रैमासिक आधार के बजाय पहले महीने से लेकर छठे महीने तक मासिक विकल्प के आधार पर वायदा स्टर्लिंग खरीदता है । यह क्रय महीने के किसी ऐसे दिन जिसके लिए विकल्प दिया गया है, उक्त विदेशी मुद्रा प्रदान करने के लिए किया जाता है । पौंड स्टर्लिंग की वायदा क्रय संविदाओं के मामले में निर्धारित क्रय दर के ऊपर प्रति मास हर १०० रुपये के लिए ०.००७५ पौंड का शुल्क अदा करने पर इस अवधि में एक या अधिक बार वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है । संविदा की तारीख से १२ महीनों से आगे अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं है । अमेरिकी डालर, ड्यूश मार्क और जापानी येन का वायदा क्रय मासिक विकल्प के आधार पर केवल छः महीनों तक के लिए होना चाहिए । पौंड स्टर्लिंग को छोड़कर दूसरी मुद्राओं की वायदा संविदाओं की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं है । प्राधिकृत व्यापारियों को अमेरिकी डालरों, ड्यूश मार्कों, और जापानी येन के हाजिर और वायदा क्रय की सुविधा १ सितम्बर १९७७ से बैंक के बम्बई स्थित कार्यालय के अलावा कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराई गई है ।

विदेशी मुद्रा की शेष राशि का अभ्यर्पण

९७. भारत में रहने वाले या भारत के निवासी व्यक्तियों के पास रहने वाली विदेशी मुद्रा प्राधिकृत व्यापारी को अभ्यर्पित की जानी चाहिए । यह शर्त १५ जून, १९७७ से नेपाल और भूटान की मुद्रा को छोड़कर शेष सभी मुद्राओं के लिए लागू की गई है ।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण सिक्किम पर लागू

९८. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९७३ को पहली सितम्बर, १९७७ से सिक्किम राज्य पर लागू कर दिया गया है । उसके अनुसार सिक्किम के निवासी जिस व्यक्ति के पास (वहां स्थायी रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को छोड़कर) उसकी कोई अपनी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियां या भारत के बाहर कोई अचल सम्पत्ति है तो ऐसे हर व्यक्ति को चाहिए कि वह पहली नवम्बर, १९७७ से पहले भारतीय रिजर्व बैंक को उन सबकी घोषणा करे । इसके अलावा कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर विदेशी मुद्रा के कोष सभी धारकों को चाहिए कि वे १ दिसम्बर, १९७७ को या

उससे पहले किसी प्राधिकृत व्यापारी को उस मुद्रा का अभ्यर्पण कर दें ।

आप्रवासियों की आस्तियों का अवरोधन

९९. विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अधीन ऐसे भारतीय राष्ट्रिको और भारत में स्थायी रूप से रहने वाले गैर भारतीय राष्ट्रिकतायुक्त ऐसे व्यक्तियों, जो किसी विदेश में आप्रवासी हुए, की भारत स्थित आस्तियों को अवरुद्ध माना गया था । ऐसे आप्रवासियों की आस्तियों को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, परन्तु उन्हें सामान्य अनिवासी खातों में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही आप्रवासी को विदेशी मुद्रा सुविधाएं प्रदान की गई हों या नहीं । यह भी निश्चय किया गया है कि जो व्यक्ति पहले भारत के बाहर आप्रवास कर चुके हैं उनके खातों को २९ सितम्बर, १९७७ से अनवरुद्ध कर दिया जाए और उन्हें सामान्य अनिवासी खातों के रूप में माना जाए ।

निर्यात प्रतिष्ठानों को विदेशी मुद्रा

१००. वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र प्राप्त निर्यात प्रतिष्ठानों को अब रिजर्व बैंक विकास कार्यों के लिए अक्तूबर, १९७७ से निर्बंध विदेशी मुद्रा प्रदान करता है । इस विदेशी मुद्रा की सीमा पिछले वर्ष के दौरान ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा किये गये निर्यातों के जहाज तक नि:शुल्क मूल्य के २.५ प्रतिशत तक होगी किन्तु अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तक होगी । वे प्रतिष्ठान एक लाख से अधिक परन्तु निर्यातों के जहाज तक नि:शुल्क मूल्य के २.५ प्रतिशत की समग्र पात्रता से अनधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं । यह विदेशी मुद्रा तब उनको मिल सकती है जब वे उसके बराबर की राशि की अपनी आपूरण पात्रता को अभ्यर्पित करें । निर्बंध विदेशी मुद्रा का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है : (१) बिक्री या बिक्री व अध्ययन दल विदेशों में भेजना; (२) विदेशों में उपयोग के लिए प्रकाशन जिनसे निर्यात प्रतिष्ठानों की वस्तुओं की छाप का प्रचार हो; इन प्रकाशनों में पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, फोल्डर आदि शामिल हैं; (३) विदेशों में समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापनों अथवा अन्य उपयोगी माध्यमों द्वारा वस्तुओं की छाप का प्रचार; विदेशों में प्रदर्शिनियों में भाग लेने और प्रदर्शन कक्षों में वस्तुओं को प्रदर्शित करने के संबंध में होने वाला व्यय; (५) परीक्षण उपकरणों और पुर्जों तथा मशीनों के आयात का व्यय बशर्ते कि देशी दृष्टिकोण से उनके आयात के लिए विधिवत् अनुमति दी गई हो और उन्हें सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए अत्यावश्यक समझा जाए । यह विदेशी मुद्रा सामान्य रूप से बैंक द्वारा दिये गये निर्बंध परमिटों के अतिरिक्त होगी ।

भारत लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा की पात्रता योजना

१०१. अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को स्थायी निवास के लिए उनके भारत लौटने पर भारत में उनकी विदेशी मुद्रा को प्रत्यावर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली नवम्बर, १९७७ से 'स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की विदेशी मुद्रा पात्रता' योजना शुरू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जिनके लिए विदेशी मुद्रा अन्यथा सहज रूप में उपलब्ध नहीं होती, विदेशी मुद्रा दी जानी है । ऐसे व्यक्तियों द्वारा आवास परिवर्तन की स्थिति में नियमित बैंकिंग तंत्र के माध्यम से प्रेषित विदेशी मुद्रा या लाई गई विदेशी मुद्रा के २५ प्रतिशत की दर पर इस योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा संबंधी पात्रता का निर्धारण किया जाता है । इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए उन व्यक्तियों के रुपया अनिवासी (विदेशी) खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों की जमाराशियों को भी हिसाब में लिया जाता है । ऐसे व्यक्तियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत जारी की गयी विदेशी मुद्रा का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है; (क) ऐसे व्यक्ति, उसके पति या उसकी पत्नि और आश्रित बच्चों की व्यक्तिगत कारणों से की जाने वाली विदेश यात्रा; (ख) ऐसे व्यक्ति, उसके पति या उसकी पत्नी और आश्रित बच्चों की विदेशों में चिकित्सा; (ग) ऐसे व्यक्ति के आश्रित बच्चों या पालित बच्चों की विदेशों में शिक्षा; (घ) जन्म दिवस, धार्मिक उत्सव और शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर स्थायी रूप से विदेशों में रहने वाले निकट रिश्तेदारों को उपहार भेजना और (ङ.) व्यावसायिक प्रयोग के लिए विशेष उपकरणों का आयात; इस संबंध में शर्त यह है कि आयात लाइसेंसीकरण संबंधी औपचारिकताओं का पालन हो । इस योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा का उपयोग भारत में आवेदक के लौटने की तारीख से १० वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

१०२. भारत के जो निवासी प्रस्तावित यात्रा के प्रारम्भ होने की तारीख से पहले दो वर्ष के भीतर भारत के बाहर किसी स्थान की यात्रा पर नहीं गये हों वे पहली नवम्बर १९७७ से विदेश यात्रा योजना १९७० के अन्तर्गत विदेश यात्रा करने के पात्र हैं (विदेश यात्रा योजना को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार से श्रीलंका, बंगला देश, मालदीव, मारीशस और सीशेल्स की जो यात्रायें की जाती हैं उन्हें इस प्रयोजन के लिए विदेश यात्रा नहीं माना जाता और नेपाल की सभी यात्राओं को विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा की पात्रता को निर्धारित करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता) । इसके अलावा इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध विदेशी मुद्रा को बढ़ाकर ५०० अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष कर दिया गया है चाहे यात्रा किसी भी जहाज से क्यों न की जाए । जिन यात्रियों के पास हवाई/जहाजरानी कम्पनियों द्वारा दी गयी नि:शुल्क या छूट प्राप्त टिकटें हैं उन्हें और उक्त कम्पनियों के कर्मचारी वर्ग को भी विदेशी मुद्रा संबंधी पात्रता उपलब्ध करायी गयी है किन्तु शर्त यह है कि वे विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत विदेशों में यात्रा करने के पात्र हों ।

१०३. विदेश यात्रा योजना की सुविधा प्राप्त करने के लिए जो क्रियाविधि विद्यमान है उसे और सरल बनाने के लिए १८ नवम्बर १९७७ को एक आदेश जारी किया गया जो पहली दिसम्बर १९७७ से अमल में आया । इस आदेश के अन्तर्गत यात्री को चाहिए कि वह विदेशी मुद्रा के नामित प्राधिकृत व्यापारी की किसी अधिसूचित शाखा की जांच के लिए अपने वर्तमान पासपोर्ट के साथ निर्धारित फार्म में घोषणा प्रस्तुत करे और उसमें विदेश यात्रा की अपनी पात्रता का पुष्टीकरण प्राप्त करे । पहली दिसम्बर १९७७ को सरकारी क्षेत्र के १० बड़े बैंकों को भारत स्थित प्रमुख शहरों में अपनी निर्दिष्ट शाखाओं द्वारा उपर्युक्त कार्य करने के लिए नामित किया गया है । पहली मई १९७८ से भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों को छोड़कर राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ निर्दिष्ट शाखाओं को परिवर्तित विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत पात्रता संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं ।

१०४. पहली जनवरी १९७८ से विदेश यात्रा योजना को और उदार बना दिया गया है । अब कोई भारतीय हर दूसरे वर्ष विदेश यात्रा कर सकता है और विदेश यात्रा योजना के अधीन तथा १८ नवम्बर १९७७ को जारी किये गये आदेशों के अधीन आने वाली विदेश यात्राओं को छोड़कर अन्य सभी विदेश यात्राओं पर उदारीकृत योजना के अन्तर्गत विदेश यात्रा के लिए यात्री की पात्रता को निर्धारित करने के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा । इसके परिणामस्वरूप जिन सरकारी अधिकारियों और कम्पनियों के कार्यपालकों को अधिकारिक या व्यावसायिक आधार पर बार-बार विदेश यात्रा करनी होती है वे अब विदेश यात्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं । इसके अलावा अब तक की तरह पिछली विदेश यात्रा से वापस आने की तारीख महत्व नहीं रखती; किन्तु विदेश यात्रा योजना के अधीन किसी यात्री की पात्रता को निर्धारित करने के लिए अब पिछली विदेश यात्रा के प्रस्थान की तारीख को हिसाब में लिया जाता है ।

विदेशी बैंकों द्वारा रुपया आहरण

१०५. भारत में स्थित प्राधिकृत व्यापारियों के जिन कार्यालयों और शाखाओं में अनिवासी रुपया खाता रखा गया है उन्हें छोड़कर अन्य कार्यालयों और शाखाओं से जहां प्राधिकृत व्यापारियों के विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा रुपया निकाला जाता है अदायगी करने वाले कार्यालय/शाखाएं, प्रधान कार्यालय या क्षेत्र कार्यालय में से किसी कार्यालय में रखे गये केन्द्रीय खाते से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है । प्रधान कार्यालय या क्षेत्र कार्यालय दावे प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति करता है, किन्तु यह प्रथा ऐसे मामलों में लागू नहीं होती जहां विदेशी बैंक आहरण सूचनाएं जारी करते हैं और उन सूचनाओं की प्राप्ति पर अदायगी करने के लिए निधियों को पहले ही अलग रख दिया जाता है । अदायगी करने वाली शाखाओं को खाता रखने वाले कार्यालय से दावा करने और प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने में लगने वाले अपरिहार्य विलम्ब के कारण विदेशी बैंक को प्रच्छन्न रूप से भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारियों से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने का अवसर मिलता है । इसके अतिरिक्त प्रतिपूर्ति में होने वाले ऐसे विलम्ब से विदेशी बैंकों को मुद्रा की सट्टेबाजी करने और यदि खाते की मुद्रा की तुलना में रुपये का संभाव्य मूल्य अनुकूल हो सकता हो तो तब तक दावे की राशि प्रेषित करने में विलम्ब करने का भी अवसर मिलता है । इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ प्राधिकृत व्यापारी अपने प्रतिनिधियों से ऐसे आहरणों पर अदायगी कमीशन ले रहे हैं अथवा मूल्य की अमुक तिथियां निर्धारित कर देते हैं जिससे कि खाते रखने वाले कार्यालय की बहियों में अदायगियों को इस रूप में दर्शाया जा सके मानो अदायगियां उस कार्यालय में उन्हीं तारीखों को की गयी हों जब वे हिताधिकारी को वास्तव में की गयी थीं । किन्तु भारी मात्रा में भारत को भेजी जाने वाली राशि के फलस्वरूप तीव्र प्रतियोगिता होने के कारण कुछ प्राधिकृत व्यापारियों को अक्सर कमीशन की अदायगी को या मूल्य की तिथि निर्धारण प्रक्रिया को छोड़ना पड़ता है । अतः प्रच्छन्न ओवर-ड्राफ्टों की पूर्ति नहीं हो पाती या खाते में जमा करने में विलम्ब हो जाता है । इनमें से किसी भी एक कारण से विदेशी मुद्रा की हानि होती है । प्राधिकृत व्यापारियों के बीच इस अस्वस्थ प्रतियोगिता को जिसमें उनके विदेशी प्रतिनिधियों और शाखाओं के भारत में प्रच्छन्न रूप से ओवर-ड्राफ्टों का लाभ उठाने की संभावना रहती है, समाप्त करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने सभी प्राधिकृत व्यापारियों को यह निदेश दिया है कि वे निम्नलिखित उपायों में से कोई एक उपाय १ सितम्बर १९७८ से अपनाएं । (क) विदेशी प्रतिनिधियों से यह कहा जाना चाहिए कि ऐसे कार्यालय या शाखा को छोड़कर जहां आहरणकर्ता बैंक का अनिवासी रुपया खाता रहता है, भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के कार्यालयों और शाखाओं के नाम जब कभी रुपया ड्राफ्ट/भुगतान आदेश जारी किए जाएं तब वे आहरण संबंधी सूचनाएं जारी करें । इस प्रकार की आहरण संबंधी सूचनाएं प्राप्त होने पर खातों में अलग से निधियां रखी जाएं ताकि बाहर के कार्यालयों के प्रतिपूर्ति दावों को यथासमय निबटाया जा सके । (ख) प्राधिकृत व्यापारियों को इस प्रकार की अदायगियों के लिए 'मूल्य तिथि निर्धारण' की प्रक्रिया को एक लेखा प्रणाली के रूप में अपनाना चाहिए या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हिताधिकारियों को वास्तविक रूप से की जाने वाली अदायगियों की तारीखों को ही केन्द्रीय खातों से अदायगियों की प्रतिपूर्ति होती है, अन्य आन्तरिक सूचना-प्रेषण या संप्रेषण पद्धतियां अपनानी चाहिए । (ग) यदि इनमें से कोई उपाय संभव न हो तो प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी आहरणकर्ता बैंकों से निधि परिव्यय की क्षतिपूर्ति के लिए ०.१५ प्रतिशत से अन्यून दर पर आहरण राशि पर भुगतान कमीशन (प्रति आहरण न्यूनतम ५० पैसे) लेना चाहिए चाहे केन्द्रीय रुपया खातों में वास्तव में रहने वाली जमाराशियों का स्तर कुछ भी क्यों न हो ।

१०६. उक्त निदेश भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और विदेशी बैंकों के विदेश स्थित प्रधान कार्यालयों/शाखाओं द्वारा किये जाने वाले रुपया आहरणों पर भी लागू किये गये हैं ।

पौंड स्टर्लिंग के क्रय और विक्रय की रिजर्व बैंक की दरें

१०७. पौंड स्टर्लिंग के क्रय और विक्रय की रिजर्व बैंक की दरों को २४ मई १९७८ से संशोधित कर प्रति रु. १०० क्रमशः ६.५३५९ पौंड (हाजिर) और ६.४९३५ पौंड (हाजिर) कर दिया गया है । मध्य दर प्रति पौंड रु. १५.३५ है ।* वायदा क्रय की दरों को भी हाजिर क्रय दरों पर प्रति माह हर १०० रुपये पर ०.००५० पौंड के अन्तर को जोड़कर संशोधित किया गया है ।

१०८ रिजर्व बैंक को सूचित किये बिना निम्नलिखित प्रकार के प्रेषणों के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को कतिपय शक्तियां प्रदान की गयी हैं ।

(१) **कमीशन प्रेषण**

कतिपय शर्तों पर भारत से किये जाने वाले निर्यातों पर विदेशों में विक्रय एजेंटों को बिलों से प्राप्त राशि में से कटौती कर या अशोध्य साख-पत्र में इस प्रकार के भुगतान की व्यवस्था होने पर बीजक पर ५ प्रतिशत तक की कटौती कर कमीशन की अदायगी ।

(२) **फुटकर प्रेषण**

(१) प्रतिष्ठित निर्यातकों की ओर से विदेशों में विज्ञापनों के संबंध में प्रेषित की जाने वाली राशि की जो सीमा ५०० अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष है उसे बढ़ाकर किसी कैलेंडर वर्ष में १,००० अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष कर दिया गया है ।

* इन दरों को ३१ जुलाई १९७८ से संशोधित कर प्रति रु १०० क्रमशः ६.४५१६ पौंड (हाजिर) और ६.४१०३ पौंड (हाजिर) कर दिया गया है । मध्य दर प्रति पौंड रु. १५.५५ है ।

(२) **निविदा प्रलेखों का व्यय**

प्राधिकृत व्यापारियो को निविदा प्रलेखो के व्यय/पंजीकरण शुल्को की वास्तविक राशि को प्रेषित करने की अनुमति दी गयी है चाहे उसका मूल्य कुछ भी क्यों न हो; किन्तु शर्त यह है कि उक्त राशि निविदा आमंत्रित करने वाले निकाय या विदेश में उसके विधिवत् प्राधिकृत एजेंट या संबंधित देश में भारत सरकार के दूतावास, वाणिज्य दूतावास या अन्य किसी राजनयिक मिशन को प्रेषित की जाय ।

(३) **निविदा प्रलेखों के अनुवाद के शुल्क**

प्राधिकृत व्यापारी अपने निर्यात घटको की ओर से किसी एक समय मे अनुवाद संबंधी शुल्को के लिए १०० अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष राशि प्रेषित कर सकते है बशर्ते कि वह राशि भारत सरकार के दूतावास, वाणिज्य दूतावास या किसी अन्य राजनयिक या व्यापारिक मिशन को भेजी जाए ।

(४) **निर्यात सूचना**

प्राधिकृत व्यापारी अपने निर्यातक घटको की ओर से विदेशी व्यापार संघो, वाणिज्य मंडलों, सरकारी विभागों या सरकारी स्वामित्व के अधीन रहने वाले सगठनों को इस प्रकार की सूचना प्रदान करने के संबंध मे वास्तविक व्यय के लिए किसी एक समय मे ५० अमेरिकी डालर या उसके समकक्ष राशि प्रेषित कर सकते है ।

(३) **डाक/हवाई पार्सल द्वारा उपहारों का निर्यात**

प्राधिकृत व्यापारी अपने घटकों को आवेदन करने पर कतिपय शर्तों पर रु. ५०० से अनधिक मूल्य के उपहार पार्सलों के निर्यात के संदर्भ मे अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी कर सकते है ।

(४) **नमूनों का आयात**

वर्तमान आयात नीति (१९७८-७९) के अनुसार उन मामलों में आयात लाइसेंसों के बिना नमूनों के अयात की अनुमति है जहा :

(क) मूल्य रु. ५०० से अधिक न हो;

(ख) आयात डाक पार्सल या हवाई पार्सल द्वारा किया जाता हो;

(ग) आयातक पजीकृत निर्माता-निर्यातक हो ।

प्राधिकृत व्यापारी अपने ऐसे ग्राहको की ओर से जो उन नमूनों के आयातों के लिए पंजीकृत निर्माता-निर्यातक है, साख-पत्र जारी कर सकते है/राशि प्रेषित कर सकते है ।

(५) **निजी आयात**

कोई व्यक्ति या सस्था या अस्पताल अपने उपयोग के लिए डाक द्वारा या किसी दूसरे प्रकार से कुछ प्रतिबन्धित श्रेणियों को छोड़कर अन्य वस्तुओं का जो निजी आयात करते है उन पर प्राधिकृत व्यापारी राशि प्रेषित कर सकते हैं ।

पाकिस्तान से निजी आयात

१०९. प्राधिकृत व्यापारी दूसरे देशों से किये जाने वाले आयातो के समान ही निजी आयातों के लिए पाकिस्तान को राशि प्रेषित कर सकते है ।

हंगरी के साथ व्यापार

११०. भारत और हगरी के बीच १ जनवरी १९६९ से परिवर्तनीय मुद्रा मे व्यापार किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप हगरी द्विपक्षीय खाता वर्ग का देश नही रहा है और उसे बाह्य समूह मे रखा गया है ।

भारत पोलैंड व्यापार करार

१११. भारत सरकार और पोलैंड जनवादी गणराज्य ने एक नया व्यापार और भुगतान करार किया है जो १ जनवरी १९७८ से तीन वर्षो की अवधि तक लागू है । इस करार के अधीन दोनों देशों के बीच होने वाले सभी व्यावसायिक और अव्यावसायिक लेनदेनों के लिए अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में भुगतान किया जाता है ।

भारत तथा कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के बीच व्यापार एवं भुगतान संबंधी लेनदेन

११२ भारत सरकार तथा कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य (उत्तर कोरिया) ने व्यापार एवं भुगतान संबंधी एक नया करार किया है । इसके अनुसार इन दो देशों के बीच समस्त व्यापार एव भुगतान संबंधी लेनदेन पहली मार्च १९७८ से मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा मे निबटाये जाते है । इसके परिणामस्वरूप उत्तर कोरिया द्विपक्षीय खाता वर्ग का देश नही रहा है और उसे बाह्य समूह मे रखा गया है ।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना

११३. रुपयों में रखी गयी जमाराशियो की ब्याज दरो मे १ मार्च १९७८ से कमी लाने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अन्तर्गत रखी गयी सावधि जमाराशियों की ब्याज दरो मे भी संशोधन किया गया और उनके लिए रुपया जमाराशियो के लिए विद्यमान ब्याज दरें लागू की गयी ।

निर्बंध विदेशी मुद्रा परमिट

११४ इस उद्देश्य से कि छोटे निर्यातको को निर्बन्ध विदेशी मुद्रा परमिट की सुविधा उपलब्ध करायी जाए, वार्षिक निर्यात संबंधी राशि की सीमाओं को कम किया गया है । 'चुनी हुई सूची' की वस्तुओ के वार्षिक निर्यात की राशि और विदेशो में निर्माण कार्य की संविदाओं से प्राप्त होने वाली राशि में से प्रत्यावर्तित की जानेवाली शुद्ध विदेशी मुद्रा की वार्षिक सीमाओं को १५ लाख रुपयों से कम कर १० लाख रुपये कर दिया गया है । 'चुनी हुई सूची से इतर' वर्ग की वस्तुओ के निर्यात की वार्षिक राशि की सीमा को भी ७५ लाख रुपयों से कम कर ५० लाख रुपये कर दिया गया है । निर्बन्ध परमिट योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आबंटन की सीमा को भी ४०,००० रुपयो से बढ़ाकर ७५,००० रुपये कर दिया गया है । ये सभी परिवर्तन ५ अप्रैल १९७८ से लागू है ।

विदेश यात्रा के लिए 'पी' फार्म

११५ 'पी' फार्म प्राप्त करने से संबंधित कतिपय अपेक्षाओं को सरल तथा उदार बनाने के उद्देश्य से ११ अप्रैल १९७८ से निम्नलिखित परिवर्तन लागू किये गये है :

(१) जो विद्यार्थी अपने दूर के रिश्तेदारों या मित्रों के आतिथ्य पर अध्ययन करने के लिए विदेश जाना चाहते हों वे 'पी' फार्म अनुमोदन के पात्र हैं । इसके पहले निकट रिश्तेदारों की वित्तीय सहायता की गारन्टी पर अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को ही कतिपय शर्तों पर यात्रा अनुमोदन प्रदान किया जाता था ।

(२) विदेशों में रहने वाले निकट रिश्तेदारों की सूची में निम्नलिखित रिश्तेदारों अर्थात पोता-पोती- पुत्र/पुत्री के सास/ससुर और यात्री (अथवा उसके पति/पत्नि) के सगे चचेरे/ममेरे भाई सगी/चचेरी/ममेरी/मौसेरी बहन को सम्मिलित किया गया है और इन रिश्तेदारों द्वारा आतिथ्य का वचन दिये जाने पर यात्री 'पी' फार्म अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं ।

(३) प्रायोजकों से प्राप्त निमंत्रण पत्र के आधार पर अनुमोदित रिश्तेदारों की सूचि में न आने वाले रिश्तेदार या किसी मित्र के आतिथ्य पर विदेश जाने वाले व्यक्तियों को 'पी' फार्म अनुमोदन प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाती है भले ही यात्रा टिकट के किराये की राशि भारत में ही भेजी गयी हो परन्तु हवाई कम्पनी के विदेश स्थित एजेंटों/कार्यालयों को ऐसी राशि अदा की गयी हो और पूर्वदत्त टिकट-सूचना जारी की गयी हो । किसी भी हवाई कम्पनी की ऐसी पूर्वदत्त टिकट सूचनाएं स्वीकार की जा सकती है ।

चीन के साथ व्यापार संबंधी लेनदेन

११६. भारत और चीन (तिब्बत क्षेत्र को छोड़कर) के बीच पुन: व्यापार प्रारम्भ हो जाने के कारण चीन (तिब्बत क्षेत्र को छोड़कर) को निर्यात किये जा सकते हैं बशर्ते कि नियमित जी आर/पीपी फार्म संबंधी क्रियाविधियों का अनुपालन किया जाए । प्राधिकृत व्यापारी चीन (तिब्बत क्षेत्र को छोड़कर) से किये जाने वाले आयातों के संदर्भ में संबंधित विनियमों के अनुसार साख पत्र खोल सकते है और राशि प्रेषित कर सकते हैं । निर्यातों में प्रत्यक्षत संबंधित राशियां अर्थात निर्यातों पर कमीशन नियंत्रण प्रभार, निर्यात संबंधी दावे, विविधा प्रलेखों के व्यय और निर्यात बिलों पर हुए विधिक/फुटकर व्यय की राशियां आदि संबंधित विनियमों के अनुसार भेजी जा सकती है प्राधिकृत व्यापारी विनियमों के अनुसार चीन के साथ भारत के व्यापार के संदर्भ में गारंटियां भी जारी कर सकते हैं । चीन को अन्य प्रकार की राशियां भेजने और चीन के निवासी व्यक्तियों, फर्मों, बैंकों या चीन के राष्ट्रिकों के साथ दूसरे प्रकार के लेनदेन करने पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी है । चीन को की जाने वाली अदायगियों और चीन से प्राप्त होने वाली राशि के संदर्भ में चीन को बाह्य वर्ग के देशों में सम्मिलित माना जाता है ।

टिप्पणियां : (१) ७ अगस्त १९७८ से विदेशों में कहीं भी जाने वाले भारत के निवासियों के मामले में 'पी' फार्म पर पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । किन्तु रिकार्ड के लिए एक संशोधित 'पी' फार्म भरने की आवश्यकता है । उन मामलों में जहां रुपये में किराया अदा करना नहीं होता, जैसे नि:शुल्क टिकट, पूर्वदत्त टिकट सूचना और भारत के बाहर जारी की गयी टिकटों पर की जाने वाली यात्राओं के मामले में इसकी भी आवश्यकता नहीं है । किराये के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा भी हटा दी गयी है ।

(२) विनिमय केंद्र और प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक अब नेपाल, भूटान और बंगला देश के सिवाय विदेश जाने वाले सभी यात्रियों को २०० रुपये के बराबर और बंगला देश जाने वाले यात्रियों को केवल १०० रुपये के बराबर के विदेशी मुद्रा नोट/सिक्के बेचेंगे ।

जुलाई 1977 से जून 1978 तक की अवधि के सांख्यिकीय आंकड़े

I विदेशों में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिये जारी किये गये नये परमिट

देश	तकनीकी पाठ्यक्रम		गैर तकनीकी पाठयक्रम	
	विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा (हजार रुपयों में)	विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा (हजार रुपयों में)
ब्रिटेन और यूरोप	454	11,558	432	3,461
अमेरिका और कनाडा	716	21,138	767	17,822
अन्य देश	136	2,339	133	909
जोड़	1,306	25,035	1.332	22,192

II अध्ययन/प्रशिक्षण को छोड़कर दूसरे उद्देश्यों के लिए जारी किये गये विदेश यात्रा परमिट

	उन व्यक्तियों की संख्या जिनको परमिट जारी किये गये	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा (हजार रुपयों में)
1. कारोबार	27,196	2,49,200
2. डाक्टरी चिकित्सा	305	9,255
3. अध्ययन दौरे	1,238	14,531
4. सम्मेलनों में भाग लेना	1,976	10,222
5 विविध	14,886	61,037
जोड़	45,601	3,44,245

III 'पी' फार्म के आवेदन पत्र*

उद्देश्य	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके 'पी' फार्म आवेदनपत्र अनुमोदित किये गये
1 परिवार के प्रमुख से मिलना	17,897
2 रिश्तेदारों से मिलना	16,201
3. निर्यात संवर्धन	1,113
4. विदेशों में नौकरी	88,915
5. स्थायी निवास के लिए आप्रवास	14,624
6 विद्यार्थी-प्रशिक्षणार्थी	2,320
7 विविध	20,726
जोड़	1,61,796

IV विदेश यात्रा योजना, 1970

उन व्यक्तियों की संख्या जिनके लिए अनुमोदन दिया गया	99,437

*इन मामलों में कोई विदेशी मुद्रा प्रदान नहीं की जाती।

विदेशी कम्पनियों के भारतीयकरण में प्रगति

११७. पहली जनवरी १९७८ को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अमल में आने के बाद ४० प्रतिशत से अधिक अनिवासी हितयुक्त ८८१ विदेशी कंपनियों तथा भारतीय कम्पनियों से अधिनियम की धारा २९(२) के अनुसरण में भारत में अपने कारोबार जारी रखने की अनुमति मांगते हुए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । सरकार द्वारा निर्धारित नीति सम्बन्धी निर्देशक सिद्धांतों के अनुसरण में ८१४ कम्पनियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अंतिम कार्रवाई कर दी गयी है । शेष ६७ मामले विचाराधीन हैं । इनमें दवाई उद्योग की ३३ कम्पनियां शामिल हैं जिनके आवेदन पत्रों पर दवाई और औषधि निर्माण उद्योग कंपनियों से संबंधित समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा रहा है ।

११८. जिन आवेदन पत्रों को निबटाया जा चुका है उनमें से ७५ आवेदन पत्र उन कंपनियों से प्राप्त हुए जिन्हें ऐसी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी जबकि ५४ कम्पनियां ऐसी थीं जिन्होंने आवेदन पत्र तो दे दिये थे परन्तु भारत में अपने कारोबार का समापन करने की प्रक्रिया में थीं । ६६ मामलों में विदेशी शेयर पूंजी को अपेक्षित मात्रा तक कम कर दिया जा चुका था जबकि २४६ मामलों में यह पाया गया कि निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत इस प्रकार कमी लाने की आवश्यकता नहीं थी । अतः उन कंपनियों को भारतीयकरण के संबंध में कोई शर्त निर्दिष्ट किये बिना ही भारत में अपने कार्यकलाप जारी रखने की अनुमति दी गयी । ३० कंपनियों के आवेदन पत्रों को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि वे कंपनियां या तो पिछले कई वर्षों से भारत में कोई कारोबार नहीं कर रही थीं या वे ऐसे कार्यों में लगी हुई थीं जिनके लिए विदेशी निवेश को जारी रखना वांछनीय नहीं समझा गया ।

११९. ३४३ कंपनियों को ७४ प्रतिशत, ५१ प्रतिशत या ४० प्रतिशत के अपेक्षित स्तर तक (कंपनी के कार्य के स्वरूप पर निर्भर) विदेशी ईक्विटी को कम करने के लिए निदेश जारी किये गये । इनमें से ८३ कंपनियों ने उक्त अपेक्षित कमी कर दी है और ८० अन्य कम्पनियां इस निदेश के अनुपालन के अन्तिम चरण पर हैं । शेष अधिकांश मामलों में उक्त स्तर तक कम करने के लिए निर्धारित अवधि या तो अब तक समाप्त नहीं हुई है या कम्पनियों ने पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं जिनकी जांच हो रही है । अन्य मामलों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है ।

मुद्रा पेटिका

१२०. आलोच्य वर्ष के दौरान १९१ मुद्रा पेटिकाएं या कोष खोले गये; इनमें से १५३ भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा, २९ सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा और ९ कोषागारों, उपकोषागारों द्वारा परिचालित थे । नयी मुद्रा पेटिकाएं २५ राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में खोली गयी; खोली गयी कुल मुद्रा पेटिकाओं में से केरल में २१, पश्चिम बंगाल में १४, मध्य प्रदेश में १९ और पंजाब तथा तमिलनाडु में से प्रत्येक में १७ थीं ।

१२१. जून १९७८ के अंत में देश में स्थित मुद्रा पेटिकाओं/कोषों की कुल संख्या ३,६०९ थी । इनमें से १० रिजर्व बैंक द्वारा, २९८ कोषागारों/उप कोषागारों द्वारा, २,१६१ स्टेट बैंक समूह के बैंकों द्वारा और १४० सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा परिचालित थे ।

उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण

१२२. १६ जनवरी १९७८ को अधिघोषित एक अध्यादेश द्वारा रुपये १,०००, रुपये ५,००० और रुपये १०,००० के मूल्य वर्गों के मुद्रा नोटों का चलन बंद कर दिया गया। विमुद्रीकरण के समय संचालन में रहने वाले उच्च मूल्य वर्गों के नोटों का मूल्य १४५.४२ करोड़ रुपये था । इसमें से ७४.९४ करोड़ रुपये के मूल्य के नोट रिजर्व बैंक, सरकारी राजकोषों और अन्य बैंकों के पास थे ।

१२३. उक्त अध्यादेश लागू होने के समय से ३० जून १९७८ तक रिजर्व बैंक के पास परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किये गये उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की मूल्य राशि १२४.४५ करोड़ रुपये थी । इसमें से बैंकों और कोषागारों द्वारा घोषित कुल राशि ६४.९४ करोड़ रुपये थी । परिवर्तन के लिए प्रस्तुत कुल १२४.४५ करोड़ रुपयों की राशि में से रिजर्व बैंक द्वारा कम मूल्य वर्ग के नोटों में परिवर्तन के लिए ११६.३१ करोड़ रुपयों की राशि पारित की गयी । इस राशि में बैंकों और सरकारी कोषागारों द्वारा घोषित नोटों के संदर्भ में परिवर्तित की गयी ६०.२१ करोड़ रुपयों की राशि शामिल है (आंकड़े अनन्तिम हैं) ।

गैर बैंकिंग कंपनियों से संबंधित अध्ययन दल की रिपोर्ट—वित्तीय और विविध गैर बैंकिंग कम्पनियों को नये निदेश

१२४. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि गैर बैंकिंग कंपनियों से संबंधित अध्ययन दल की ऐसी सिफारिशों को जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ के वर्तमान अध्याय ३ आ के भीतर कार्यान्वित की जा सकती है, अमल में लाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को निदेशों के दो सेट जारी किये जा रहे थे। दिनांक २० जून १९७७ की बैंक की अधिसूचना सं. डीएनबीसी ३८ और ३९/डीजी (एच)—७७ में दिये गये निदेश १ जुलाई, १९७७ से अमल में आये। उक्त नये निदेशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नप्रकार है : (१) "मुक्त प्रारक्षित निधियां" पद की परिभाषा को संशोधित किया गया है ताकि केवल उन्ही निधियों को उसमें शामिल किया जाए जिनका स्वरूप प्रारक्षित निधियों का है किन्तु जो व्यवस्थित निधियां नही है और जिन्हे अर्जित लाभों में से विनियोजित किया गया है; उक्त लाभों में वे लाभ शामिल है जो आस्तियों की वास्तविक बिक्री में प्राप्त हुए है, न कि आस्तियों के पुनर्मूल्यन के माध्यम से। (२) कम्पनियों द्वारा जिसे अधिकतम अवधि के लिए जमाराशियां स्वीकार की जा सकती है उसे सभी प्रकार की कम्पनियों के मामले में ३६ महीने तक सीमित कर दिया गया है; किन्तु आवास वित्त कंपनियों के मामले में अधिकतम अवधि ६० महीने है। लेकिन न्यूनतम अवधि को सभी मामलों में छः महीने तक ही अपरिवर्तित रखा गया है। (३) जिन अंतर कंपनी उधारो को पहले के निदेशों के प्रतिबंधक उपबंधों से पूरी तरह छूट दी गयी थी उन्हें अब उन मामलों को छोड़कर जमाराशि के रूप में समझा जायेगा जहां इस प्रकार के उधार भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से लिये जाते है। (४) सुरक्षित उधारों के संबंध में दी गयी छूट को वापस ले लिया गया है। केवल बांडो और डिबेन्चरो के रूप में लिये गये ऐसे उधारो जिन्हे अचल संपत्ति के बंधक द्वारा रक्षा प्राप्त है और ईक्विटी शेयरो में परिवर्तनीय आरक्षित बांडो/डिबेन्चरो के रूप में लिये गये उधारो के लिए छूट प्राप्त होगी। (५) किराया-खरीद वित्त कंपनियों द्वारा प्राप्त जमाराशियों पर पहले उच्चतम सीमा के प्रतिबन्धों की शर्त नहीं थी। उक्त जमाराशियों को अब उच्चतम सीमा के प्रतिबंधों के अंतर्गत लाया गया है। ऐसी कंपनियां अब अपनी शुद्ध स्वाधिकृत निधियों की १० गुनी तक जमाराशियां स्वीकार कर सकती है। (६) निवेश कंपनियों को उपलब्ध उच्चतम सीमा को कम कर दिया गया है। उक्त कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कुल जमाराशियों को १ अप्रैल १९७९ तक दो चरणों में अपनी शुद्ध स्वाधिकृत निधियो के २५ प्रतिशत तक कम कर दें। (७) जिस अवधि तक जमाराशि रही हो उस अवधि के लिए या निकटतम समाप्त वर्ष के लिए कंपनी सामान्यतः जिस दर पर ब्याज अदा करती उससे २ प्रतिशत कम ब्याज दर अवधि समाप्ति से पूर्व जमाराशियों की चुकौती के मामले में निर्धारित की गयी है। यह वाणिज्य बैंकों पर लागू उपबन्धों के अनुरूप है।

१२५. नये निदेशों के कार्यान्वयन के दौरान यह पाया गया कि कुछ ऐसी कंपनियां थीं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५ झ (ग) में दी गयी वित्तीय संस्था की परिभाषा के अधीन तो आती थी किन्तु उन्हें निदेशावली में निर्दिष्ट कंपनियों की किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सका; क्योंकि वे धारा ४५ झ (ग) में निर्दिष्ट कारोबार में से एक से अधिक प्रकार के कारोबार कर रही थीं और उनमें से कोई भी कारोबार प्रमुख नहीं था। ऐसी कंपनियों को इस निदेशावली के अन्तर्गत लाने के लिए एक नयापैरा जोड़कर वित्तीय कंपनियों को जारी किये गये निदेशों को ३० मार्च १९७८ से संशोधित किया गया। इस संशोधन से अब उक्त निदेश व्यापक हो गये है जिससे कि वे ऐसी सभी श्रेणियों की कंपनियों पर जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ में परिभाषित "वित्तीय संस्था" के अन्तर्गत आती है, लागू किये जा सकें।

१२६. इसके साथ ही १ जुलाई, १९७७ से नये निदेशों के अमल में आने से भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त कंपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए "गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी और विविध गैर बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियमावली, १९७७" जारी की। उक्त नियमों के अनुसार यदि संबंधित कम्पनियां जनता से जमाराशियां आमंत्रित करती है या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आमंत्रित कराती है तो उन्हे एक अंग्रेजी समाचार पत्र और स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में अनिवार्यतः विज्ञापन देना होगा। इस प्रकार जारी किये जानेवाले विज्ञापन की एक प्रति रिजर्व बैंक के पास भेजी जानी चाहिये। कंपनियों को विज्ञापन में पर्याप्त विवरण/जानकारी देनी चाहिए ताकि संभाव्य जमाकर्ताओं को कंपनियों की वित्तीय स्थिति, प्रबंध व्यवस्था आदि का स्पष्ट चित्र मिल सके और साथ ही कंपनियों को विज्ञापन में कुछ ऐसी घोषणाएं भी करनी चाहिए जिससे जमाकर्ता ऐसी कंपनियों के पास जमाराशि रखने के संबंध में कानूनी स्थिति को समझ सके। यद्यपि उक्त नियमावली कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५८ क के अधीन बनायी गयी है तथापि उनको कार्यान्वित करने का अधिकार रिजर्व बैंक को होगा। उक्त नियमावली के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए बैंक के अधिकारियों को उचित अधिकार प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है।

कम्पनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, १९७५ में संशोधन

१२७. वित्तेतर कंपनियां जमाराशि स्वीकार करने का जो कार्य करती है उसे कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५८ क और उसके अधीन बनायी गयी कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, १९७५ के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि राज अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली में किये जाने वाले संशोधनों को सरकार द्वारा अधिनियम में संशोधन किये जाने तक स्थगित रखा गया था ताकि सरकार कठिनाइयों के मामलों में छूट प्रदान कर सके/समय सीमा बढ़ा सके। उक्त अधिनियम रिजर्व बैंक के परामर्श से दिसम्बर १९७७ में संशोधित किया गया जिससे कि किसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५८ क के उपबन्धों से छूट देने/समय सीमा बढ़ाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो सके। कंपनियों के किसी वर्ग के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करते समय भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करना होगा।

१२८. तदनंतर कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली को १ अप्रैल १९७८ से संशोधित किया गया है। इन संशोधनों के अनुसार शेयरधारियो से सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली जमाराशियों/व्यक्तिगत हैसियत से निदेशकों की गारंटी प्राप्त जमाराशियों और अरक्षित डिबेन्चरों पर प्राप्त जमाराशियों के संदर्भ में उच्चतम सीमा १ अप्रैल १९७९ से १५ प्रतिशत से कम होकर १० प्रतिशत रहेगी और १ अप्रैल

१९८० से पूरी तरह हटा दी जाएगी । अत: उस तारीख से वित्तेतर कंपनियों के ४० प्रतिशत की वर्तमान समग्र सीमा के मुकाबले उनकी स्वाधिकृत निधियों के २५ प्रतिशत तक किसी भी रूप में जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति होगी ।

१२९. इसके अलावा उक्त कंपनियों पर यह दायित्व होगा कि वे एक वर्ष के भीतर (पहली अप्रैल और ३१ मार्च के बीच) चुकाये जाने योग्य जमाराशियों के १० प्रतिशत तक की चल आस्तियां बनाये रखें । इस प्रकार रखी जाने वाली चल आस्तियां भार या गहन रहित हों और उन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी भाररहित प्रतिभूति या किसी अन्य न्यासी प्रतिभूति में निवेश के रूप में या किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में चालू या दूसरी जमाराशि के रूप में रखा जाए ।

१३०. इन कंपनियों को अपने द्वारा जारी किये जानेवाले किसी भी विज्ञापन में अतिरिक्त विवरण/जानकारी देनी होगी/घोषणा करनी होगी जिससे कि संभाव्य जमाकर्ता के सामने कम्पनियों की वित्तीय स्थिति और प्रबंध व्यवस्था का स्पष्ट चित्र उभर सके और वह ऐसी कंपनियों के पास जमाराशियां रखने की कानूनी स्थिति को समझ सके ।

गैर बैंकिंग कम्पनियों के सम्बन्ध में अध्ययन दल की दूसरी सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

१३१. जैसा कि पहले सूचित किया गया था, हनामी चिट और मुद्रा संचलन योजनाओं पर प्रतिबन्ध लगाने से संबंधित विधेयक को अन्तिम रूप दिया गया और उसे संसद में पेश किया गया है ।

१३२. उपर्युक्त विधेयक के अलावा बैंकिंग आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर और बाद में राज अध्ययन दल द्वारा की गयी जांच के आधार पर भी देश-भर में समान रूप से परम्परागत चिट फंड करोबार चलाने के कार्य को विनियमित करने से सम्बन्धित नमूना विधेयक को विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य प्रतिनिधि निकायों से प्राप्त सिफारिशों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दे दिया गया है । अब विधि मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

१३३. गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कारोबार को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित व्यापक विधान तैयार किया जा रहा है ।

अनिगमित निकायों द्वारा जमराशियों का स्वीकरण

१३४. कतिपय काननी अडचनों को देखते हुए भारत सरकार ने अनिगमित निकायों द्वारा किसी निर्धारित संख्या से अधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव को छोड़ दिया है । नवम्बर १९७७ में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श कर उक्त मामले की समीक्षा की और प्रस्ताव पुन: लाया गया है । तदनुसार, उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ में व्यापक संशोधन प्रेषित किये । उन्हें अब बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, १९७८ में समाविष्ट किया गया है । उक्त विधेयक संसद में शीघ्र ही पेश किये जाने की आशा है ।

गैर बैंकिंग कम्पनियों के पास जमाराशियां : १९७४-७५

१३५: ३१ मार्च १९७५ को समाप्त वर्ष के लिए गैर बैंकिंग कम्पनियों के पास विद्यमान जमाराशियों के संबंध में किये गये सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आता है कि उक्त वर्ष के दौरान सूचना देने वाली कम्पनियो की कुल संख्या में ३७६ की वृद्धि हुई और वह ४,६१२ हो गयी । उच्चतम सीमा के प्रतिबन्ध से छूट प्राप्त श्रेणियों के अन्तर्गत विद्यमान जमाराशियों/ऋणो में १६८.१ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और उनकी कुल राशि मार्च १९७४ के अन्त में स्थित १,०२८.६ करोड रुपयों से बढकर मार्च १९७५ के अन्त में १,१९६.७ करोड रुपये हो गयी । मार्च १९७५ के अन्त में उच्चतम सीमा के प्रतिबंधो के क्षेत्र में आनेवाली जमराशिया ८९८.३ करोड़ रुपये थी जबकि छूट प्राप्त जमाराशि/ऋण राशि ६९८.४ करोड रुपये थी ।

१३६ ३१ मार्च १९७५ को सूचना देनेवाली २,९५९ वित्तेतर कम्पनियों की छूट प्राप्त जमाराशि सहित कुल जमाराशि/ऋण-राशि ७५४.३ करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष सूचना देनेवाली ३,०४८ कम्पनियों की उक्त राशि ७२४.६ करोड़ रुपये थी । निदेशों के अधीन दी गयी उच्चतम सीमा के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आने वाली जमाराशियां ३९३.६ करोड़ रुपये थी ।

१३७. वित्तीय कम्पनियों के मामले में ३१ मार्च १९७५ को सूचना देने वाली १,६५३ कम्पनियों की छूट प्राप्त जमाराशि सहित जमाराशि/ऋणराशि ४४२.४ करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष के अन्त में १,१८८ कम्पनियों के संदर्भ में उक्त राशि ३०४.० करोड़ रुपये थी । छूट प्राप्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली जमाराशियों को छोडकर जमाराशि १०४.७ करोड़ रुपये थी ।

सर्वेक्षण

१३८. आलोच्य वर्ष के दौरान आर्थिक विभाग के क्षेत्र सर्वेक्षण प्रभाग ने निम्नलिखित पाच सर्वेक्षण किये: (१) जून १९७७ में रिजर्व बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संबंधी समिति के अनुरोध पर सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के संदर्भ में क्षेत्र अध्ययन किया गया । इसके अलावा आर्थिक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में भी क्षेत्र अध्ययन किये गये । उक्त प्रभाग ने समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री एकत्र की और उसकी जांच भी की । यह प्रभाग पूर्ण रूप से इस कार्य के साथ जुड़ा रहा । उक्त समिति की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गयी । (२) ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को अत्यावश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से प्राप्त होने वाले लाभों का मूल्यांकन करने के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य समाप्त किया गया; उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है । (३) पुणे जिले में २ कृषि सेवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली के संबंध में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया गया; इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है । (४) पांच चुने हुए जिलों में ऋण राहत संबंधी विधान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार के अनुरोध पर शुरू किये गये वृत्त अध्ययनों से संबंधित प्रारम्भिक कार्य को उक्त प्रभाग ने अन्तिम रूप दे दिया है । महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में पहले वृत्त अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य समाप्त हुआ । संबंधित रिपोर्ट तैयार की जा रही है । (५) इसके साथ ही प्रभाग ने तीन जिलों अर्थात् सिओनी (मध्य प्रदेश), फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) और जैसलमेर (राजस्थान) में अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत जिला ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के प्रारम्भिक कार्य को भी अन्तिम रूप दे दिया है । सिओनी में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य समाप्त हो गया है । भूमि विकास बैंकों के ऋणदाताओं को अल्पावधि सहकारी ऋण की उपलब्धता के संबंध में जो क्षेत्र अध्ययन किया गया उसकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

१३९ भुगतान संतुलन प्रभाग विदेशी निवेश सर्वेक्षण के लिए विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और भारतीय मिश्रित पूंजी कम्पनियों से त्रैमासिक रिपोर्टें मंगाता रहा । वर्ष १९७४-७५ से संबंधित सर्वेक्षण के लिए विवरणियों की जांच की जा रही है । रु १०,००० से कम या उसके बराबर के मूल्य की विदेशी मुद्रा के प्रयोजनवार ब्योरे उपलब्ध नहीं है उनकी अवगणित प्राप्तियों का अप्रैल-जून १९७८ की तिमाही के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया । जनवरी-मार्च १९७७ की तिमाही के लिए इसी प्रकार के सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

१४० बैंकिंग प्रभाग वाणिज्य बैंकों के कार्यों से संबंधित विभिन्न पहलुओं अर्थात अग्रिम और जमा राशि, जमाराशियों के स्वामित्व, जमा खातों में नामे, निवेश आदि से संबंधित कई सर्वेक्षण कार्य करता रहा ।

केन्द्रीय बोर्ड

१४१. श्री एम नरसिंहम ३० नवम्बर १९७७ को कारोबार समाप्त होने पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यभार से मुक्त हुए । श्री नरसिंहम ने बैंक के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जो सेवाएं अर्पित की उनकी सराहना में बोर्ड उनका अभिनन्दन करता है ।

१४२ डा आई. जी पटेल पहली दिसम्बर १९७७ से पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किये गये ।

१४३. डा आर के हजारी २६ नवम्बर १९७७ को अपनी सेवा अवधि समाप्त होने पर बैंक के उप गवर्नर के रूप में अपने पद भार से मुक्त हुए । डा हजारी ने अपने कार्य काल में बैंक की जो सेवा की है उसकी सराहना में बोर्ड उनका अभिनन्दन करता है ।

१४४. भारत सरकार ने श्री मा. रामकृष्णय्या को पांच वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया । श्री रामकृष्णय्या ने २ जनवरी १९७८ को अपना पद भार संभाला ।

१४५. श्री सी रामकृष्ण और डा के. कानूनगो २२ जुलाई १९७७ को अपनी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के पद से सेवा निवृत्त हुए । बोर्ड सेवानिवृत्त हुए निदेशकों द्वारा अपने सेवा काल के दौरान की गयी बहुमूल्य सेवाओं की सराहना करता है ।

१४६. २२ जुलाई १९७७ को स्थानीय बोर्ड का पुनर्गठन किये जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ८(१) (ख) के अधीन प्रो एम एल दानवाला और श्री एम. वी अरुणाचलम को बैंक के क्रमश: पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किया गया और श्री ए एन. हक्सर तथा डा. भरत राम को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की उपर्युक्त धारा के अधीन क्रमश: पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में पुन: नामित किया गया । श्री एम वी अरुणाचलम को श्री सी रामकृष्ण के स्थान पर नामित किया गया । उक्त अधिनियम की धारा ८(१) (ग) के अधीन बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में २२ जुलाई १९७७ से सर्वश्री जहांगीर पी. पटेल, एस. एल किलोस्कर, एयर चीफ मार्शल पी सी लाल (अवकाश प्राप्त) और डा. वी. वेंकटप्पय्या को नामित किया गया और श्री एम पी चितले, डा डी. पी सिंह और डा. वी कुरियन को पुन: नामित किया गया । डा वी. वेंकटप्पय्या की नियुक्ति डा के कानूनगो के स्थान पर की गयी ।

१४७ आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुई, उनमें से दो बम्बई में तथा एक-एक मद्रास, चंडीगढ़, कलकत्ता, जयपुर और नयी दिल्ली में हुई । केन्द्रीय बोर्ड की समिति की ५१ बैठकें हुई; उनमें से दो नयी दिल्ली में, एक कलकत्ता में तथा शेष बम्बई में हुई ।

स्थानीय बोर्ड

१४८ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा (१) के अनुसार भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के चारों स्थानीय बोर्डों को २२ जुलाई १९७७ से पुनर्गठित किया । प्रो एम एल. दानवाला को श्री एम. एस पद्मनाभन के स्थान पर पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड में और सर्वश्री सी श्रीकृष्णा तथा एन एस. भट्ट को क्रमश: सर्वश्री सी. रामकृष्ण तथा एम के रामचन्द्रा के स्थान पर दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड में नियुक्त किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ९ बी उपधारा (३) के साथ पढ़ी जाने वाली उप धारा (१) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया गया :

पश्चिमी क्षेत्र

१. श्री के सी. मैत्रा
२. श्री चार्ल्स एम कोरिया

पूर्वी क्षेत्र

१ श्री ए एन. हक्सर
२. डा सदाशिव मिश्र
३. श्री जी. साहा
४. श्री जी.सी.फुकन

उत्तरी क्षेत्र

१ डा भरत राम
२ श्री के एन. सप्रू
३. श्री प्रेम पंथी
४. श्री जी सी. फुकन

दक्षिणी क्षेत्र

१ श्री एम वी. अरुणाचलम
२ श्री सी आर. रामस्वामी

१४९ श्री एफ. हक को पहली नवम्बर १९७७ से पश्चिमी के स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया ।

१५० श्री वी वी. विवेटिया को २५ अगस्त १९७७ से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

१५१. श्री डब्ल्यू.एस. ताबे को पहली जून १९७८ से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

नये कार्यालय भवन

१५२. बंबई स्थित भारत सरकार की टकसाल के अहाते में बन रहे बैंक के बहुमंजिले कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । लिफ्ट, वातानुकूलन, आदि से संबंधित विभिन्न गौण निर्माण कार्य किये जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि यह भवन कार्यालय के उपयोग के लिए मार्च १९७९ के आसपास तैयार हो जाएगा । हैदराबाद स्थित मुख्य कार्यालय भवन पूरा हो चुका है और हैदराबाद के कार्यालय के विभाग नये भवन में कार्य करने लग गये हैं । अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गौहाटी और त्रिवेन्द्रम में कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है । आलोच्य वर्ष के दौरान जयपुर में एक और भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है । चंडीगढ़ कार्यालय भवन के योजना प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यह आशा है कि वहां निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होगा ।

१५३. प्राथमिकता के आधार पर पुणे स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय का विस्तार किया जा रहा है । यह कार्य सितम्बर १९७७ में प्रारम्भ किया गया था और यह आशा की जाती है कि भवन अक्तूबर १९७८ तक महाविद्यालय के उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा ।

आवास-भवन

१५४ लिपिको तथा अधीनस्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मुशीराबाद, हैदराबाद में १४१ क्वार्टरों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही यह कालोनी आवास के लिए तैयार हो जाएगी । इन क्वार्टरों को मिलाकर बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये क्वार्टरों की कुल संख्या ४,८३२ हो गयी है । इनके अतिरिक्त भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जयपुर, नयी दिल्ली और त्रिवेन्द्रम में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है । बैंक ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास १८८ फ्लैटों की लागत राशि भी जमा की है और ये फ्लैट संप्रति हौज खास, नयी दिल्ली में निर्माणाधीन हैं । आशा है कि ये फ्लैट दिसम्बर १९७८ तक तैयार हो जाएंगे ।

कार्यालयों के उपयोग के लिए पट्टे पर लिये गये भवन

१५५ कार्यालय स्थान की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से अहमदाबाद, चंडीगढ़, कोचीन और लखनऊ में अतिरिक्त कार्यालय स्थान ले लिया गया है ।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई

१५६. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय अपने कार्यक्रमों में विदेशी मुद्रा और ऋण प्रबन्धन संबंधी विशिष्ट विषयों पर बराबर बल देता रहा; कार्यकारी पूंजी के लिए ऋण प्रदान करना, परियोजनागत मूल्यांकन, कार्मिक प्रबन्ध और औद्योगिक संबंध जैसे क्षेत्र बैंकों के लिए अधिक महत्व रखते हैं; इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया । केवल विदेशी मुद्रा के विषय पर महाविद्यालय ने प्रारम्भिक तथा उच्च स्तरों के लगभग १५ कार्यक्रम चलाये । इनमें इस वर्ष प्रारम्भ किया गया विदेशी मुद्रा "बाजार" कार्यक्रम भी शामिल है जिसका उद्देश्य यह है कि बैंक के विदेशी मुद्रा विभागों के अधिकारी 'व्यापारियों' के द्वारा किये जाने वाले विदेशी मुद्रागत लेनदेनों के अनुरूप विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य करने की निपुणता हासिल कर सकें ।

१५७. महाविद्यालय ने जिन अन्य नये कार्यक्रमों की व्यवस्था की वे इस प्रकार थे : (क) नियमित कानूनी समस्याओं को सुलझाने में कार्यकारी बैंकरों की सहायता करने के उद्देश्य से बैंकरों के लिए विधि संबंधी कार्यक्रम; (ख) जो वाणिज्यिक और विकास बैंकर रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करते हैं उनके लिए ऐसी इकाइयों के पुनःस्थापन पर विचार गोष्ठी, (ग) विदेश व्यापार पर एक विचारगोष्ठी जिससे कि बैंकर आयातों एवं निर्यातों का वित्तपोषण करते समय होने वाली समस्याओं का पता लगा सकें और उनका समाधान कर सकें; और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए ऋण संबंधी पर्यवेक्षण और उसकी अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित कार्यक्रम ।

१५८. महाविद्यालय निम्नलिखित विषयों पर पहले की तरह विभिन्न कार्यक्रम चलाता रहा : विकास बैंकिंग, कार्य-बजट तैयार करना, बैंकरों के लिए साख्यिकी और संगठन तथा पद्धतियां ।

१५९ एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि आलोच्य वर्ष के दौरान चलाये गये ६९ कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के २९ पाठ्यक्रम लिये गये और उनमें से संस्थाओं के भीतर के कार्यों के आधार पर २२ कार्यक्रम चलाये गये । उक्त कार्यक्रम प्रायोजक संस्थाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से बनाये गये थे । इनमें से छः कार्यक्रम उनके अपने केन्द्रों पर ही चलाये गये । "बैंकिंग व्यवस्था में औद्योगिक संबंध" विषय से संबंधित कार्यक्रम बम्बई के अतिरिक्त तीन और केन्द्रों में चलाया गया और कार्यकारी पूंजी के लिए ऋण प्रदान करने से संबंधित कार्यक्रम बम्बई और मद्रास दोनों केन्द्रों में चलाये गये ।

१६०. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय रिजर्व बैंक के अपने अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की भी पहले की तरह पूर्ति करता रहा और महाविद्यालय ने उनके लाभ के लिए केन्द्रीय बैंकिंग कार्यक्रम और उच्च केन्द्रीय बैंकिंग कार्यक्रम तथा आर्थिक सिद्धान्त और आर्थिक विश्लेषण की परिमाणात्मक प्रणालियों तथा ऋण संबंधी मूल्यांकन से संबंधित कार्यक्रम चलाये ।

१६१. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान के सहयोग से बैंकों के महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में एक कार्यशाला चलायी ।

१६२ प्रकाशनों के क्षेत्र में महाविद्यालय ने "गाइडलाइन्स फार इटर्नल बैंक इन्सपेक्शन" का संशोधित, विस्तृत और अद्यतन संस्करण प्रकाशित किया है ।

१६३ आलोच्य वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंकों, विकास वित्त संस्थाओं और सरकारी विभागों तथा विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों के २,०५९ अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, इससे १९५४ में महाविद्यालय की स्थापना होने से लेकर अब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या १४,३२५ हो गयी ।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

१६४. आलोच्य वर्ष के दौरान कृषि बैंकिंग महाविद्यालय ने अपने कार्यकलापों को और बढ़ाया और उसने पिछले वर्ष के

४२ कार्यक्रमो के मुकाबले इस वर्ष ५९ कार्यक्रम चलाये । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी सामान्य ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत आयोजित कृषि परियोजना पाठ्यक्रमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न स्तरो के कर्मचारियो के लिए विशेष रूप से बनाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर पहले की तरह बल दिया जाता रहा ।

१६५. विभिन्न चुने हुए जिलों में कृषि ऋण संबंधी सघन विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप कृषि बैंकिंग महाविद्यालय से यह अनुरोध किया गया कि वह इस विषय पर कार्रवाई करने वाले कतिपय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए पुणे में पाठ्यक्रम का आयोजन करने के अलावा दो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको के लिए शिमोगा में तथा धूले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अधिकारियों के लिए धूले में एक-एक विशेष कार्यक्रम चलाये ।

१६६. महाविद्यालय ने कार्य संबंधी बजट तैयार करने पर एक कार्यक्रम, वृक्ष-फसलों का वित्तपोषण करने पर एक कार्यक्रम और गोवा राज्य सहकारी बैंक तथा गोवा में स्थित चार शहरी सहकारी बैंको के बोर्डों के ऐसे सदस्यों के लिए जो अधिकारी वर्ग के नहीं हैं, एक कार्य अभिमुखता कार्यक्रम जैसे कई नये कार्यक्रम चलायें । इन कार्यक्रमो के प्रति इनमें भाग लेने वालो ने काफी अभिरुचि दर्शायी ।

१६७. प्रशिक्षको की प्रशिक्षण संस्था के रूप में उभरने वाली अपनी नयी भूमिका के संदर्भ में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय ने वाणिज्य और सहकारी बैंको के महाविद्यालयों के कृषि वित्त संबंधी प्रशिक्षको के लिए दो नये कार्यक्रम चलाये । कृषि बैंकिंग महाविद्यालय द्वारा जून १९७७ में आयोजित वाणिज्य और सहकारी बैंको के प्रशिक्षण महाविद्यालयो के प्रधानाचार्यों के दो दिन के सम्मेलन में लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप यह कदम उठाया गया; उक्त सम्मेलन में कृषि वित्त संबंधी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया था ।

१६८. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारियों तथा रिजर्व बैंक के अपने अधिकारियो के लिए भी नियमित कार्यक्रम आयोजित करता रहा तथा विभिन्न बैंकों से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों के कारण व्यापक विषयों पर बाहर के केन्द्रों में भी कार्यक्रम चलाये ।

१६९. सितम्बर १९६९ में महाविद्यालय की स्थापना हुई; तब से लेकर अब तक इस महाविद्यालय में विभिन्न बैंको तथा अन्य संस्थाओं के ८,६२८ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और आलोच्य वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों की संख्या १,६७२ है ।

स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास

१७०. स्टाफ अधिकारी विकास कार्यक्रम, निरीक्षण अधिकारी कार्यक्रम, अंतर-गतिशीलता कार्यक्रम और सहायक कोषाधिकारियो के कार्यक्रम जैसे अपने नियमित कार्यक्रमो की श्रृंखला के अलावा महाविद्यालय ने नये भर्ती हुए ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' के अधिकारियों (सीधे भर्ती हुए) के लिए कई प्रवेश पाठ्यक्रम भी चलाये । प्रवेश पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरणों और अवधि का सावधानी से पुनरीक्षण किया गया तथा पाठ्यक्रमों के स्वरूप में इस प्रकार परिवर्तन किया गया कि उनकी उपयोगिता बढ़ सके । सीधे भर्ती हुए अधिकारियों के लिए दो वर्ष तक होने वाले संस्थागत और विभागीय प्रशिक्षण की संपूर्ण योजना का परीक्षित अधिकारियों तथा पिछले दलों के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में बारीकी से मूल्यांकन किया गया और उसमें संपूर्ण परिवर्तन किया गया ।

१७१. महाविद्यालय पहले की तरह सरकारी क्षेत्र के बैंको के अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य, मध्यवर्ती और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंको के प्रबन्ध कर्मचारियो के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहा । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अस्थायी रूप से कृषि बैंकिंग महाविद्यालय द्वारा इस महाविद्यालय को अन्तरित किये गये थे ।

१७२. पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष स्टाफ महाविद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमो में विदेशी केन्द्रीय बैंको के अधिकारियों ने भाग लिया । बैंक आफ युगांडा के दो अधिकारियो तथा बैंक आफ घाना के एक अधिकारी ने निरीक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया । भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी पहली बार विदेशी मुद्रा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किये गये ।

१७३ १९६३ में जब महाविद्यालय की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक यहां जिन कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनकी कुल संख्या ६,५३३ है और आलोच्य वर्ष के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियो की संख्या ५५९ थी ।

आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

१७४. आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तरो के लिपिक कर्मचारियों के लिए पहले की तरह प्रवेश और उच्च पाठ्यक्रम चलाते रहे । इनके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को स्टाफ अधिकारी ग्रेड 'ए' की अर्हता संबंधी लिखित परीक्षा में बैठने के लिए चुना गया था उनके लिए भी प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये । ग्रेड 'ए' और 'बी' के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों (सीधे भर्ती हुए) के लिए उचित तथा योजनाबद्ध ढंग से विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी भी आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सौंपी गयी ।

१७५. आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कुल १४,६६८ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है ।

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान

१७६ विशेष कार्यक्रमों, परियोजनाओं, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि की सहायता से प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने अपने कार्यकलाप जारी रखे । सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंको की कार्य-बजट तैयार करने की प्रणाली का गहन अध्ययन आलोच्य वर्ष के दौरान किया गया । इसी प्रकार दस राष्ट्रीयकृत बैंको की कार्य-बजट प्रणाली का पुनरीक्षण भी किया गया ।

१७७. इस संस्थान ने एशियन डेवेलपमेन्ट बैंक की ओर से नेपाल के एग्रिकल्चरल डेवेलपमेन्ट बैंक के लिए कृषि ऋण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया ।

१७८. भर्ती संबंधी जांच परीक्षा के क्षेत्र में ३०० से भी अधिक परीक्षायें चलायी गयीं और उनमें भाग लेने वाले उम्मीदवारो की संख्या ४,५०,००० से अधिक थी । इस वर्ष की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ९ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने शाखा प्रबन्धकों, क्षेत्र अधिकारियों, क्षेत्र लिपिकों/सहायकों की भर्ती करने में संस्थान की सेवाओं का लाभ उठाया ।

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

१७९. अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय संघों, प्रबन्ध संस्थानों तथा इसी प्रकार के अन्य निकायों द्वारा आयोजित प्रबन्ध विकास से संबंधित अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में बैंक पूर्ववत् अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता रहा । इसके अलावा बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के आर्थिक विकास संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थान और बैंक आफ इंग्लैंड द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । पश्चिम जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंडस् और फ्रांस की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में अल्पकालीन अध्ययन के लिए भी बैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया । विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों के नामित अधिकारियों को भी बैंक पूर्ववत् प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करता रहा । भारत सरकार के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहकारिता कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण के लिए दि अफगानिस्तान बैंक द्वारा प्रतिनियुक्त पांच प्रशिक्षणार्थियों के एक दल का इस संदर्भ में विशेष उल्लेख किया जा सकता है । इनके अतिरिक्त नेपाल, बंगला देश, मलेशिया, फिलिपाइन्स, थाइलैंड, सियरा लिओन, सूडान, तंजानियां युगांडा और जांबिया से भी प्रशिक्षणार्थी आये ।

आवास ऋण योजना

१८०. वर्ष १९६१ में इस योजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक मंजूर किये गये 'समिति' और 'व्यक्तिगत' ऋणों की कुल राशि क्रमशः रु. ६,९१,७४,६८९.०० और रु. ५,३४,६९,६४९,०० है । कुल ४,३८७ कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ।

१८१.१ जुलाई १९७७ से ३० जून १९७८ तक की अवधि के दौरान निम्न प्रकार आवास ऋण मंजूर किये गये :—

सहकारी गृह निर्माण समितिया	समितियों की संख्या	राशि रु०
(क) नयी सहकारी समितियां	2	8,45,736.00
पहले ही गठित सहकारी गृह निर्माण समितियो के लिए मंजूर किए गये अतिरिक्त ऋण	5	2,76,792.00
		11,22,528.00

अलग-अलग कर्मचारियों को प्रदान किये गये ऋण	कर्मचारियों की संख्या	राशि रु०
(ख) नये ऋण	174	53,95,572.00
ऐसे कर्मचारियों को प्रदत्त अतिरिक्त ऋण जिन्होंने पहले ही ऋण प्राप्त किये है	53	10,21,520.00
		64,17,092.00

मालिक-कर्मचारी संबंध

१८२. दो मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय संघों, अर्थात् श्रेणी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगर महासंघ ने जुलाई १९७७ के अन्त में अपने मांग घोषणा पत्र पर समझौता वार्ता प्रारम्भ कराने के लिए देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया । आन्दोलन संबंधी कार्यक्रम वर्ष १९७७ के अन्त तक बीच-बीच में चलाया जाता रहा और उसके बाद मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किये जाने पर उसे स्थगित कर दिया गया । मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने १३ जनवरी १९७८ को बैंक के प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ एवं अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार महासंघ के प्रतिनिधियों के बीच समझौता संबंधी कार्रवाई शुरू की । मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा बैंक तथा अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार संगठन के बीच भी इसी प्रकार की समझौता बैठकें प्रारम्भ की गयी है । इन संगठनों के साथ विचार-विमर्श/समझौता वार्ता की प्रक्रिया जारी है ।

१८३. अधिकारियों, स्टाफ अधिकारियों और कामगार कर्मचारियों के अखिल भारतीय/स्थानीय स्तरों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ भी समझौता सम्मेलन पहले की तरह आयोजित किये जाते रहे । दिनांक १७ अप्रैल १९७८ को गवर्नर के साथ स्टाफ अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई । बैंक/गवर्नर के साथ अधिकारियों के संघ की बैठकें ७ नवम्बर १९७७ और ३ फरवरी १९७८ को हुई ।

गृह पत्रिका

१८४. बैंक की गृह पत्रिका 'विकाउट रिजर्व' को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुद्रण और अभिकल्पन की उत्कृष्टता के लिए गृह पत्रिकाओं के वर्ग में १९वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया ।

प्रेस संपर्क

१८५. प्रेस संपर्क अनुभाग बैंक के विभिन्न विभागों एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं अर्थात् कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम के प्रचार तथा प्रेस संपर्क कार्य का समन्वय करता रहा । अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किये जाने वाले अपने नियमित पाक्षिक रिजर्व बैंक न्यूज लेटर के अतिरिक्त इस अनुभाग ने आलोच्य वर्ष के दौरान कृषि तथा उससे संबंधित कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में वाणिज्य बैंकों द्वारा की गयी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए एक सचित्र विवरणात्मक पुस्तिका भी प्रकाशित की । बैंक जमाराशियों को बीमाकृत करने की आवश्यकता को सरल भाषा में स्पष्ट करते हुए एक फोल्डर पुस्तिका भी प्रकाशित की गयी । भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को विदेशी मुद्रा नियंत्रण से

संबंधित जिन औपचारिकताओं का पालन करना है उन पर पिछले वर्ष प्रकाशित फोल्डर पुस्तिका को इस वर्ष जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी भाषाओं में प्रकाशित किया गया । प्रेस संपर्क अनुभाग की सहायता और सहयोग से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने मुर्गीपालन तथा डेरी विकास की योजनाएं तैयार करने के संबंध में दो पत्रक प्रकाशित किये । भारतीय राष्ट्रिकता या मूल के अनिवासी व्यक्तियों को भारत में निधियां प्रेषित करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर लागू होने वाले विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी विनियमों से संबंधित विवरणिकाओं के संशोधित संस्करण भी आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशित किये गये ।

हिन्दी का संवर्धन

१८६. आलोच्य वर्ष के दौरान राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, १९७६ के उपबन्धों को बैंक के आन्तरिक कामकाज में क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने के लिए बैंक ने विभिन्न कदम उठाये । इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं : (१) जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में सूचित किया गया था, क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्थित बैंक के कार्यालयों में शीघ्र ही हिन्दी कक्षों की स्थापना की जाएगी । ऐसे कक्षों तथा केन्द्रीय कार्यालय के हिन्दी प्रभाग के लिए हिन्दी अधिकारियों का चयन किया जा चुका और उनकी नियुक्ति की जा रही है, (२) क्षेत्र 'क' में स्थित बैंक के कार्यालयों के कर्मचारियों को अब ग्रेड 'ए' और 'बी' के स्टाफ अधिकारियों के स्तर तक प्रस्तुत किये जाने वाले अनुभागीय टिप्पणों तथा प्रारूप लेखन में हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते कि संबंधित अधिकारी हिन्दी का ज्ञान रखते हों, (३) हिन्दी टिप्पण, प्रारूप लेखन आदि का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से चुने हुए अधिकारियों तथा लिपिकों के लिए कानपुर और नयी दिल्ली कार्यालयों में दो दिन की हिन्दी कार्यशालाएं चलायी गयीं । इन कार्यशालाओं के प्रति कर्मचारियों की अभिरुचि अत्यन्त उत्साहजनक रही है । अत: यह भी विचार है कि क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्थित हमारे कार्यालयों में ऐसी और कार्यशालाएं चलायी जाएं । मार्गदर्शन के लिए कार्यशाला सामग्री भी तैयार की गयी ।

१८७. बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये : (१) क्षेत्र 'ख' में स्थित कार्यालयों को यह सूचित किया गया है कि वे श्रेणी तृतीय और चतुर्थ के कर्मचारियों से संबंधित समस्त परिपत्रों, कार्यालय आदेशों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी करें । क्षेत्र 'क' में स्थित कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय के प्रशासन और कार्मिक विभाग, लेखा और व्यय विभाग तथा परिसर विभाग ऐसे परिपत्र आदि पहले से ही द्विभाषिक रूप में जारी कर रहे हैं । जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, क्षेत्र 'क' में स्थित कार्यालयों से यह अनुरोध किया गया है कि वे, जहां तक हो सके, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से संबंधित परिपत्र और कार्यालय आदेश द्विभाषिक रूप में जारी करें । (२) लघु उद्योगों के लिए बनायी गयी ऋण गारंटी योजना के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट ऋण संस्थाओं से संबंधित परिपत्र औद्योगिक वित्त विभाग द्वारा अब द्विभाषिक रूप में जारी किये जा रहे हैं । सभी बैंकों और राज्य सरकारों, सहकारी समितियों के पंजीयकों आदि को संबोधित परिपत्र क्रमश: बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा कृषि ऋण विभाग द्वारा पहले से ही द्विभाषिक रूप में जारी किये जा रहे हैं । (३) यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्थित समस्त कार्यालय आदि अपना तार का पता अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी पंजीकृत करायें । इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

१८८. राजभाषा अधिनियम, १९६३ की धारा ३ में उल्लिखित प्रेस विज्ञप्तियां, नोट, सारांश, अधिसूचनाएं, सूचनाएं, लाइसेंस आदि प्रलेख पहले की तरह द्विभाषिक रूप में जारी किये जाते रहे । बैंक के सभी कार्यालय, विभाग, आदि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही देते रहे । क्षेत्र 'क' में स्थित कार्यालय क्षेत्र 'क' और 'ख' के साथ चयनात्मक रूप से अपना मूल पत्राचार हिन्दी में करने लगे हैं ।

१८९. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें हुईं और इन बैठकों में बैंक तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करने के बाद हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्णय किये गये । बैंक के नयी दिल्ली, कानपुर, जयपुर और पटना कार्यालयों में स्थानीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य करती रहीं और बैंक द्वारा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में जारी किये गये अनुदेशों को कार्यान्वित करने में की गयी प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए समय-समय पर इन समितियों की बैठकें होती रहीं ।

१९०. बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अपनी सहयोगी संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों का हिन्दी संस्करण प्रकाशित करता रहा । इस वर्ष के दौरान मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट १९७५-७६ और १९७६-७७ हिन्दी में प्रकाशित की गयीं । हिन्दी खण्ड के साथ रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन और त्रैमासिक गृह पत्रिका 'विदाउट रिजर्व' का प्रकाशन होता रहा । पाक्षिक 'रिजर्व बैंक न्यूज लेटर' भी नियमित रूप से हिन्दी में प्रकाशित किया जाता रहा । कृषि ऋण विभाग द्वारा प्रकाशित को-आपरेटिव न्यूज डाइजेस्ट के जुलाई और दिसम्बर १९७७ के अंकों में हिन्दी खण्ड सम्मिलित किया गया । कार्यालयीन टिप्पण, पत्राचार आदि में सामान्य रूप से प्रयुक्त मुहावरों और अभिव्यक्तियों की एक प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) इस वर्ष प्रकाशित की गयी और उसकी प्रतियां समस्त कर्मचारियों को वितरित की गयीं । इस वर्ष अंग्रेजी-हिन्दी बैंकिंग शब्दावली का कार्य पूरा हुआ । उसका मुद्रण बाद में किया जाएगा ।

१९१. बैंक के स्टाफ के लिए स्वैच्छिक और अनिवार्य, दोनों प्रकार की हिन्दी शिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत हिन्दी कक्षाएं चलायी जाती रहीं । किन्तु क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्वैच्छिक योजना को भी अनिवार्य योजना में बदल दिया गया । कर्मचारियों को शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रमों की सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया । हमारे टंककों आशुलिपिकों और वैयक्तिक सहायकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि में प्रशिक्षित कराने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष के दौरान क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्थित हमारे कार्यालयों में अन्तर्सेवाकालीन अनिवार्य हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की गयी । मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षाओं/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर हमारे स्टाफ को मानदेय प्रदान करने की योजना जारी रही । यह निर्णय भी किया गया कि नयी दिल्ली और भायखला (बम्बई) में स्थित हमारे आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में लिपिक ग्रेड प्रथम और द्वितीय के लिए चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों में हिन्दी को एक विषय के रूप में शामिल किया जाए । इस निर्णय को मई/जून १९७८ से अमल में लाया गया है ।

१९२. यह भी निश्चय किया गया है कि यदि ग्रेड 'ए' और 'बी' में सीधे भर्ती होने वाले अधिकारियों ने पहले ही एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ मैट्रिक या उसकी समकक्ष परीक्षा या मैट्रिकुलेशन परीक्षा में हिन्दी के स्तर के बराबर स्वीकृत कोई हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न की हो तो उन अधिकारियों को बैंक की सेवा में आने की तारीख से ५ वर्ष की अवधि के भीतर भारत सरकार की प्राज्ञ परीक्षा या उसकी समकक्ष कोई हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । यदि वे निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण न करें तो उनकी वेतन वृद्धि को तब तक रोक दिया जायेगा जब तक कि वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते ।

बैंक की सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

१९३. मूल पात्रता संबंधी मानकों तथा अर्हता संबंधी मानदंडों में दी गयी छूट, बैंक की सेवा में आरक्षित पदों का अधिक व्यापक प्रचार और अनुसूचित जातियों या जनजातियों आदि के लिए सीमित रखी गयी विशेष भर्ती जैसे जिन उपायों का ब्योरा पिछली रिपोर्टों में दिया गया था वे इस वर्ष के दौरान भी जारी रहे । आलोच्य वर्ष के दौरान निर्णय किया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की घोषणा आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रभारित की जाए ताकि उन सुदूर क्षेत्रों में, जहां समाचार पत्र आसानी से उपलब्ध नहीं होते, रहने वाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संभाव्य उम्मीदवारों को ऐसे रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हो जाए । इसके परिणामस्वरूप बैंक की सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में और वृद्धि हुई है । जहां पहली जनवरी १९७७ को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या श्रेणी चतुर्थ, श्रेणी तृतीय और श्रेणी द्वितीय तथा प्रथम में क्रमशः १२९२, १९९५ और ८५ थी वहां पहली जनवरी १९७८ को बढ़कर क्रमशः १४६६, २१७४ और १०० हो गयी है ।

१९४. किन्तु श्रेणी तृतीय के विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में जो कमी रही है वह अभी पूरी नहीं हो पायी है । इसका कारण यह है कि बैंक के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों ने पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं किया था । लिपिक ग्रेड द्वितीय/सिक्का नोट परीक्षक ग्रेड द्वितीय और टकक संवर्गों में अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः आरक्षित लगभग २०० और २५ पदों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक विज्ञापन जारी किया गया और इस विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या काफी उत्साहवर्धक रही । ऐसी आशा है कि उक्त २ संवर्गों के लिए जब एक बार अखिल भारतीय स्तर पर सूची तैयार हो जाती है तो जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में इस प्रकार की भर्ती होना अभी शेष है, वहां उसे पूरा किया जा सकेगा ।

१९५. निर्धारित कोटे से अधिक स्टाफ आफिसर ग्रेड "ए" पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती करने की जिस नीति का उल्लेख पिछली रिपोर्टों में किया गया था वह आलोच्य वर्ष के दौरान भी जारी रही । इसके अलावा स्टाफ आफिसर ग्रेड "ए" तथा "बी" (सीधी भर्ती) के पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानदण्ड को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संदर्भ में कम कर सिर्फ स्नातक कर दिया गया है जब कि सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानदण्ड द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि है ।

१९६. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वले रिक्त पदों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की जो योजना है उसका इस वर्ष के दौरान पुनरीक्षण किया गया और यह निश्चय किया गया है कि स्टाफ आफिसर ग्रेड "ए" के संवर्ग में की जाने वाली पदोन्नति जहां अब तक चुनाव पर आधारित समझी जाती थी वहां अब पात्रता की शर्त पर वरीयता के आधार पर समझी जानी चाहिए ।

१९७. स्टाफ क्वार्टर के आबंटन में भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए १० प्रतिशत की दर पर निर्धारित आरक्षण की पूर्ति इस वर्ष पूर्ण रूप से की गयी ।

१९८. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कार्यरत संपर्क अधिकारी ने पटना, गौहाटी, बंगलूर, भायखला, नागपुर तथा अहमदाबाद स्थित बैंक के कार्यालयों द्वारा रखी गयी सूचियों का भी निरीक्षण किया ।

लेखा

१९९. ३० जून १९७८ को समाप्त हुए लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समायोजन करने के बाद बैंक को ६६१.८१ करोड़ रुपयों की आय हुई जबकि पिछले वर्ष उसे ५८७.२६ करोड़ रुपयों की आय हुई थी । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपयों में)

	वर्ष	
	1977–78	1976–77
(i) राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	27.79	15.51
(ii) राज्य सरकारों को (उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर), तथा वाणिज्य और सहकारी बैंकों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	101.42	126.75
(iii) रुपया प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा रुपया खजाना बिलों पर बट्टा	275.56	263.46
(iv) विदेशी प्रतिभूतियों, निवेशों और खजाना बिलों पर ब्याज तथा बट्टा	313.53	190.94
(v) कमीशन और लाभ तथा विदेशी मुद्रा विनिमय द्वारा प्राप्त आय	1.49	6.51
(vi) अन्य आय	8.65	10.01
	728.44	613.18
घटाइये रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों द्वारा रखी गयी अतिरिक्त औरात दैनिक जमाराशियों पर दिया गया ब्याज	66 63	25.92
	661 81	587.26
घटाइये : नीचे के पैरा 2 में उल्लिखित निधियों में अंतरण	345.00	290.00
	316.81	297.26

२०० राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि तथा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में वर्ष १९७७-७८ के दौरान क्रमश: ११५ करोड़ रुपयो, २० करोड रुपयो और २०० करोड रुपयो का अशदान किया गया जबकि वर्ष १९७६-७७ के दौरान उक्त अशदान की राशि क्रमश: ९५ करोड़ रुपय, और १७५ करोड रुपये थी ।

२०१ इस वर्ष किये गये ११६ ८१ करोड रुपयो के व्यय को ३१६ ८१ करोड रुपयो की शेष आय में से निकालने के बाद (पिछले वर्ष की शेष आय २९७ २६ करोड रुपय थी तथा व्यय-राशि ९७ २६ करोड रुपये थी) केन्द्रीय सरकार को अदा करने के लिए अलग रख गये लाभ की अधिशेष राशि (पिछले वर्ष के समान ही) २०० करोड रुपये थी

२०२ पिछले वर्ष की ५८७ २६ करोड रुपयो की कुल आय मे इस वर्ष ७४:५५ करोड रुपयो की वृद्धि हुई और वह बढ़कर ६६१ ८१ करोड रुपये हो गयी । इस वृद्धि के मुख्य कारण निम्न प्रकार थे :

(१) इस वर्ष के दौरान बढ़ायी गयी प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो पर उच्चतर ब्याज प्राप्त हुआ ।

(२) रुपया खजाना बिलो पर प्राप्त उच्चतर बट्टा, अनुसूचित बैंको को रिजर्व बैंक के पास जो अतिरिक्त नकदी प्रारक्षित निधि रखनी होती है उस पर अधिक ब्याज अदा किये जाने से उक्त बट्टे की राशि आशिक रूप से समायोजित हुई ।

२०३ व्यय में १९ ५५ करोड रुपयो की वृद्धि हुई उसका प्रमुख कारण स्थापना व्यय तथा चेक/ड्राफ्ट फार्मों आदि के मुद्रण के व्यय में हुई वृद्धि थी ।

लेखा परीक्षक

२०४ बैंक की लेखा परीक्षा मेसर्स के एस अय्यर एण्ड कम्पनी, बम्बई, मेसर्स के एन गुटगुटिया एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, मेसर्स रघुनाथ राय एण्ड कम्पनी, नयी दिल्ली तथा मेसर्स सुन्दरम एण्ड श्रीनिवासन, मद्रास द्वारा की गयी । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) की धारा ५० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जारी किये गये दिनाक ९ मई १९७८ के अपने पत्र सख्या १(२) एकाउन्ट्स द्वारा भारत सरकार ने उन्हे लेखा परीक्षक के रूप मे पुन: नियुक्त किया था । इस वर्ष बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षको द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली स्थित कार्यालयो के अलावा नागपुर तथा लखनऊ की शाखाओ की लेखा बहियों की भी परीक्षा की गयी । लेखा परीक्षको का पारिश्रमिक केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई, कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास और नागपुर कार्यालयो मे से प्रत्येक कार्यालय के लिए १५,००० रुपये तथा लखनऊ शाखा के लिए १०,००० रुपये निश्चित किया गया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1978 तक का तुलन-पत्र

इशू विभाग

देयताए	रु०	पै०	रु०	पै०	आस्तियां	रु०	पै०	रु०	पै०
बैंकिंग विभाग मे रखे हुए नोट	12,81,13,106	00			सोने का सिक्का और बुलियन —				
सचलन मे नोट	9347,69,88,617	50			(क) भारत मे रखा हुआ	214,21,78,319	03		
					(ख) भारत के बाहर रखा हुआ				
जारी किये गये कुल नोट			9360,51,01,723	50	विदेशी प्रतिभूतियां	2145,32,65,142	40		
					जोड			2359,54,43,461	43
					रुपये का सिक्का			20,76 54,536	25
					भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतिया			6980,20,03,725	82
					देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र				
कुल देयताएं			9360,51,01,723	50	कुल आस्तियां			9360,51,01,723	50

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून, 1978 तक का तुलन-पत्र

बैंकिंग विभाग

देयताएं	रु० पै०	आस्तियां	रु० पै०
चुकता पूंजी	5,00,00,000.00	नोट	12,81,13,106.00
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00	रुपये का सिक्का	2,55,968.00
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	610,00,00,000.00	छोटा सिक्का	3,39,976.06
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	195,00,00,000.00	खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	915,00,00,000.00	(क) देशी	101,32,10,871.53
		(ख) विदेशी	..
जमाराशियां:—		(ग) सरकारी खजाना बिल	1138,94,67,266.11
(क) सरकारी		विदेशों में रखा हुआ बकाया*	1687,54,55,324.86
(i) केन्द्रीय सरकार	377,00,03,649.09	निवेश§	1092.51,85,845.67
(ii) राज्य सरकारें	18,17,96,325.01	ऋण और अग्रिम :—	
		(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ख) बैंक		(ii) राज्य सरकारों को†	14,59,00,000.00
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2137,76,92,605.39		
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	70,27,84,425.86	ऋण और अग्रिम :—	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	2,40,36,994.63	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को‡	334,71,18,525.02
(iv) अन्य बैंक	3,19,73,719.36	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को@	321,13,25,100.00
		(iii) दूसरों को	3,78,25,000.00
(ग) अन्य	2016,75,46,926.29	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
देय बिल	167,24,66,578.15	(क) ऋण और अग्रिम:—	
अन्य देयताएं£	625,14,20,026.04	(i) राज्य सरकारों को	110,78,59,592.00
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	19,10,92,529.33
		(iii) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	216,80,00,000.00
		(ख) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	7,86,77,345.00
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	138,47,68,085.00
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	688,45,34,579.00
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां‡	1404,05,92,136.24
कुल देयताएं	7292,97,21,249 82	कुल आस्तियां	7292,97,21,249.82

अंशतः चुकता शेयरों पर 50,000 पौंड के बराबर के रु० 7,67,495.05 की आकस्मिक देयता ।

£इनमें आकस्मिकता लेखा शामिल है ।

नकदी, सावधि जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

§(i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं ।

(ii) विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हुए रु० 685,60,82,902.22 शामिल हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

‡ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये रु० 2,76,00,000 00 शामिल हैं।

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

††अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अग्रिम दिये गये या उनमें जमा किये गये रु० 1121,47,05,750.00 शामिल हैं।

म० वि० हाटे
मुख्य लेखाकार
तारीख 28 जुलाई, 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
के ०ए म० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर
पी० आर० नांगिया, उप गवर्नर
मा० रामकृष्णय्या, उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून, 1978 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

	रु० पै०
आय	
ब्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन आदि*	316,80,54,544.74
	316,80,54,544 84
व्यय	
स्थापना व्यय	39,57,83,437.85
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	84,095.74
लेखा परीक्षा की फीस	1,00,000.00
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	2,03,30,413.15
विधि प्रभार	1,86,133.88
डाक और तार खर्च	23,13,773.87
कोष-प्रेषण	6,49,88,074.88
लेखन सामग्री आदि	60 71,170,.50
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट फार्म, आदि)	21,59,23,912.04
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और मरम्मत	1,51,33,435.77
एजेंसी प्रभार	42,01,56,195.18
कर्मचारी उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशदान	55,00,000.00
विविध व्यय	2,14,83,076.05
उपलब्ध शुद्ध शेष राशि	200,00,00,825.83
	316,80,54,544,.74
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	200,00,00,825.83

प्रारक्षित निधि लेखा

30 जून, 1978 को शेष	150,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित	कुछ नहीं
जोड़	150,00,00,000.00

*भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद ।

म० वि० हाटे
मुख्य लेखाकार
तारीख 28 जुलाई, 1978

आई० जी० पटेल, गवर्नर
के० एस० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर
पी० आर० नांगिया, उप गवर्नर
भा० रामकृष्णय्या, उप गवर्नर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1978 तक के रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र पर तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने केन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बम्बई (फोर्ट), मद्रास, नयी दिल्ली, नागपुर और लखनऊ के कार्यालयों के लेखों और उनसे संबंधित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही, दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के प्रबन्धकों द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलन-पत्र में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलन-पत्र की जांच कर ली है और यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और यह सतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिये गये हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य निर्धारित किया गया है। यह तुलनपत्र जहां तक हमारी जानकारी है, हमे दिये गये स्पष्टीकरणो और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

मेसर्स के० एस० अय्यर एण्ड कंपनी
मेसर्स के०एन०गुटगुटिया एण्ड कंपनी
मेसर्स रघुनाथ राय एण्ड कंपनी
मेसर्स सुन्दरम एण्ड श्रीनिवासन
} लेखा परीक्षक

तारीख 17 अगस्त, 1978

भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण

विवरण	निम्नांकित तारीख को समाप्त हुआ वर्ष			
	30 जून, 1976		30 जून, 1977	
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
इशू विभाग				
देयताएं :				
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	24,67,21,372.00		14,67,40,673.00	
संचलन में नोट	7150,33,90,123 50		8200,46,11,617.50	
जारी किये गये कुल नोट		7175,01,11,195.50		8215,13,52,320.50
कुल देयताएं		7175,01,11,495.50		8215,13,52,320.50
आस्तियां				
सोने का सिक्का और बुलियन :				
(क) भारत में रखा हुआ	182,52,50,617.44		187,80,46,227.22	
(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—		—	
विदेशी प्रतिभूतियां	546,73,97,231 21		1071,73,97,234.21	
रुपये का सिक्का	15,30,04,388.73		15,42,90,909 60	
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	6430,44 59,255.12		6940,16,17,949 47	
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र				
कुल आस्तियां		7175,01,11,495.50		8215,13 52,320 50
बैंकिंग विभाग				
देयताएं				
चुकता पूंजी	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	400,00,00,000.00			495,00,00,000.00
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	145,00,00,000.00		165,00,00,000.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	540,00,00,000.00		715,00,00,000.00	
जमा राशियां :				
(क) सरकारी :				
(i) केन्द्रीय सरकार	63,12,38,550.20		74,13,96,368.04	
(ii) राज्य सरकारें	138,78,48,015.79		87 45,19,350.11	
(ख) बैंक :				
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	758,54,09,484.28		1588,86,21,279.82	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	60,98,94,643.18		41,16,10,904.10	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,69,82,005.95		1,91,28,419.89	
(iv) अन्य बैंक	4,18,42,239.38		2,78,08,547.38	
(ग) अन्य	2130,62,82,282.95		2461,43,38,829.71	
देय बिल	79,91,90,407.09		157,67,77,542.38	
अन्य देयताएं	549,59,08,322.22(क)		587,41,16,192.89(क)	
कुल देयताएं		5027,45,95,951.04		6533,13,17,434.32

(क) इसमें आकस्मिकता लेखे शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण (जारी)

विवरण	निम्नांकित तारीख को समाप्त हुआ वर्ष			
	30 जून 1976		30 जून 1977	
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
आस्तियां				
नोट	24,67,21,372.00		14,67,40,673.00	
रुपये का सिक्का	4,01,936.00		3,17,577,00	
छोटा सिक्का	2,41,964.15		3,72,688.83	
खरीदे और भुनाये गये बिल :				
(क) देसी	138,07,60,341.67		111,99,55,457.60	
(ख) विदेशी	..		..	
सरकारी खजाना बिल	275,57,89,222.34		265,31,98,249.23	
विदेशों में रखा हुआ बकाया (घ)	1196,05,88,818.82		2180,87,88,502 19	
निवेश	565,41,66,698.86(ग)		651,09,92,341.93(ङ)	
ऋण और अग्रिम :—				
(i) केन्द्रीय सरकार को	..		..	
(ii) राज्य सरकारों को	130,06,06,000.00(च)		72,23,00,000.00(छ)	
(iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	941,98,48,796.30(ज)		962,18,07,161.46(झ)	
(iv) राज्य सहकारी बैंकों को (ञ)	156,18,63,494.00		247,74,27,833.00	
(v) दूसरों को	68,61,55,000.00		1,82,00,000.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ-कालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :				
(क) ऋण और अग्रिम :				
(i) राज्य सरकारों को	75,70,25,217.55		98,33,76,218.75	
(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,59,04,003 33		15,80,45,212.33	
(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..		..	
(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	138,40,00,000.00		172,60,00,000.00	
(ख) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	9,82,07,720.00		8,45,82,445.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	78,74,60,968.00		116,98,76,394.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घ कालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश				
(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	388,17,55,619.00		526,20,50,534.00	
(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	.		..	
अन्य आस्तियां	827,30,98,779.02(ट)		1086,72,86,056.00 (ठ)	
कुल आस्तियां		5027,15,95,951.04		6533,13,17,134.32

टिप्पणी : 30 जून 1976 —अंशतः चुकता शेयरों पर आकस्मिक देयता रु० 8,00,000.00 (पौंड 50,000 के स्टर्लिंग निवेशों को रु० 100-0.2500 पौंड की दर पर परिवर्तित किया गया)

30 जून 1977 —(i) अंशतः चुकता शेयरों पर 50,000 पौंड के बराबर के रु० 7,60,005.47 की आकस्मिक देयता

(ii) अंशतः चुकता स्टाकों पर 2,850,000 पौंड के बराबर के रु० 4,33,20,311.91 की आकस्मिक देयता

(ख) नकदी, सावधि जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है।

(घ) विदेशों में रखे हुए रु० 8,37,91,214 71 (50,000 पौंड 9,002,500 00 अमेरिकी डालर और 6,60,000.00 ड्यूश मार्क के समान राशि) शामिल है।

(ङ) इसमें विदेशी मुद्राओं में विदेशों में रखे हुए रु० 3,29,33,68,067.03 शामिल है।

(च) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं। परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवर ड्राफ्ट शामिल है।

(छ) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये रु० 10,30 00,000.00 शामिल हैं।

(झ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये रु० 8,76,00,000 00 शामिल है।

(ञ) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है।

(ट) इसमें कतिपय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अग्रिम दी गयी रु० 478,12,00,000.00 की राशि शामिल है ।

(ठ) इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अग्रिम दी गई या उनके पास जमा की गयी रु० 832,32,79,500.00 की राशि शामिल है।

30 जून, 1976 और 1977 को समाप्त वर्षों का लाभ-हानि लेखा

	1976		1977	
	रु०	पै०	रु०	पै०
आय				
ब्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क कमीशन, आदि	294,99,72,239.32£		297,26,15,033.13$	
व्यय	294,99,72,239.32		297,26,15,033.13	
स्थापना	35,49,37,921.61		35,51,16,731.43	
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फ़ीस और व्यय	81,484.98		78,764.35	
लेखा परीक्षकों की फ़ीस	80,000.00		80,000.00	
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	1,58,81,750.46		1,77,77,553.30	
विधि प्रभार	1,03,769.71		1,67,701.32	
डाक और तार खर्च	19,48 335.00		24,25,466.26	
कोष प्रेषण	46,78.237.46@		75 63,473.14	
लेखन सामग्री आदि	54,31,080.33		46,79,950.56	
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट फार्म, आदि)	14,38,45,495.76		19,37,48,200.38	
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और मरम्मत	1,31,96,766.72		1,32,85,511.02	
एजेंसी प्रभार	43,01,12,622.71*		35,50,33,446.77	
कर्मचारी और अधिवार्षिक निधियों में अंशदान	7,08,15,842.51**		50,00,000.00	
विविधि व्यय	1,82,15,270.04		1,76,57,337.40	
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि	190,00,00,136.95		200,00,00,897.20	
जोड़	294,99,72,239.32		297,26,15,033.13	
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	190,00,00,136.95		200,00,00,897.20	
प्रारक्षित निधि लेखा				
30 जून को शेष	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
लाभ-हानि लेखे से अंतरित	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
जोड़	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	

£ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं और धारा 46क, 46ख और 46ग के अधीन निधियों में 221 करोड़ रुपयों का अन्तरण करने के बाद।

@ पिछले वर्षों में अदा की गयी राशि के सन्दर्भ में वसूल किये गये रु० 1,07,58,076.26 का समायोजन करने के बाद।

*इसमें पहले के वर्षों के रु० 11,59,68,700.00 शामिल हैं।

**इसमें पिछले वर्षों की संचित उपदान देयता के कारण विनियोजित किये गये रु० 6,42,15,842.51 शामिल हैं।

$ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद।

[सं० एफ० 10/6/78-बी०ओ० I]
जे० सी० राय, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th November, 1978

S.O. 2983.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India for the year ended June 30th, 1978.

ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

For the year July 1, 1977—June 30, 1978

I. THE ECONOMIC SITUATION—1977-78

During the year, there was a marked improvement in the growth rate and the situation in respect of food and foreign exchange—the two most vulnerable aspects of the economy in the past—improved further. Though there was a sizeable increase in money supply, price trends were generally satisfactory, to a significant extent due to effective management of supplies of some essential consumer goods and critical raw materials through liberal imports and relaxation of restriction on internal movements.

2. Side by side with these satisfactory factors, there are, however, certain features of the current situation which give cause for concern. There has been a set back in the pace of industrial growth and the incidence of sickness in industry has showed an increase. The excess of domestic saving over domestic investment, seen in further increases in foreign exchange reserves and the failure to draw down public sector food stocks could be interpreted as indicating some sluggishness in the economy. However, there is reason to believe that this apparent sluggishness is related to the time lag needed for the expansionary budgetary and other policies to begin to take hold. In fact, there have been signs of quickening in the tempo of industrial production in the last quarter of the year and these could, with the acceleration of plan expenditures, gather strength later in the year. Against this background the fact that money supply recorded a sizeable increase for the second consecutive year points to the need for continued vigilance.

3. Several policy measures were taken during the year to deal with this undoubtedly difficult situation. In a move towards accelerating investment, some of the existing controls and restrictions were relaxed. Import policy was considerably liberalised; the exemption limits for industrial licensing were raised and complementary fiscal and monetary measures effected a reduction in the cost of credit. At the same time, a greater structural balance in the economy is aimed at through an emphasis on the development of the small scale sector and promotion of employment oriented activity. The new industrial policy has spelt out areas reserved for small scale industries. Amongst the major objectives of the draft sixth five year plan are the removal of unemployment and significant underemployment, and a rise in the standard of living of the poorest sections of the community in the next ten years. Efforts on these lines would have to continue.

4 Externally, the rupee has, by and large, remained relatively strong. This strength derived largelly from the determination of the value of the rupee, since 1975, in terms of a weighted basket of currencies of India's major trading partners. In the year under review, save for two minor adjustments, the exchange rate of the rupee in terms of sterling (which remains the intervention currency) continued fairly stable. Since June 1978, however, because of substantial fluctuations in the value of major currencies, especially the U.S. dollar, some further changes in the rate have become necessary. The policy of maintaining the exchange value of the rupee in terms of a basket of currencies has protected India's external trade by reducing the element of uncertainty in respect of rupee realisation of export earnings. The world situation in 1977-78 however, has not been conducive to a maintenance of export growth. Following recessionary conditions in major industrial countries, the growth in the volume of world trade dropped from 11 per cent in 1976 to about 4 per cent in 1977. Protectionist sentiments gathered strength in industrial economies as they faced a slow-down in growth. In addition, there were adverse developments in respect of some export commodities which had contributed substantially to the export growth in the previous year. Imports, on the other hand, had begun to respond to the more liberal policy with the result that the trade account reverted in 1977-78 to the normal pattern of a deficit, and there were already signs in April-June 1978 of a significant slow-down in the rate of accumulation of reserves.

National Income and Output

5 The growth rate of GNP during 1977-78 (April-March) is expected to be around 6 per cent; it was 1.6 per cent in 1976-77. The higher rate of growth reflected largely the performance of the agricultural sector, the growth of the industrial sector being lower over the year. The situation in 1976-77 was the reverse as agricultural production declined because of unfavourable weather conditions while industrial output recorded a substantial increase. In 1977-78, as in 1975-76, the contribution of agriculture to the growth in national income was pronounced while industry lagged behind.

Saving and Investment

6. According to preliminary estimates, domestic savings as a proportion of net national product at factor cost dropped from 17.9 per cent in 1976-77 (revised) to 15.6 per cent in 1977-78 mainly because of the marked fall in the saving-income ratio of the household sector. This followed from a lower growth in financial assets such as claims on Government, principally on account of repayments under the compulsory deposit scheme, as also in deposits and currency. While the ratio of public sector savings also declined marginally, that of the domestic corporate sector remained unchanged at the previous year's level, as may be seen from Table 1.

TABLE 1 : ESTIMATES OF DOMESTIC SAVINGS AND INVESTMENT

(Provisional)

As proportions to Net National Product at current prices : factor cost

Financial Year	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
1. Household Sector	8.2	10.0	12.5	10.4
2. Public Sector	4.2	5.3	5.0	4.8
3. Domestic Private Corporate Sector	1.0	0.3	0.4	0.4
4. Total Domestic Saving (1+2+3)	13.4	15.6	17.9	15.6
5. Inflow of Foreign Resources	+0.9	—0.3	—1.8	—1.4
6. Aggregate Investment (4+5)	14.3	15.3	16.1	14.2

Note : The ratios for 1974-75 to 1976-77 have been revised partly on account of the revision of CSO's national income estimates and partly owing to the availability of revised data relating to various components of savings and investment.

The ratio of outflow of resources to national income was also lower than in the previous year (1.4 per cent as against 1.8 per cent). Hence, there was a reduction in overall investment which was of a somewhat lower order than that in savings. While sufficient information is not available in regard to details of investment, presumably a part of the decline could be attributed to disinvestment of stocks in industries like textiles, steel and cement.

Agricultural Output

7. Despite the severe cyclone that hit the south-east coast in November 1977, the general climatic conditions were favourable to agriculture during 1977-78. The growth in agricultural production during the year is placed at between 11 and 12 per cent, taking the index (Base : triennium ending 1969-70=100) to around 131 for the year, which represents a significant rise over the earlier peak of 125.5 touched in 1975-76. The latest official estimates place foodgrains production at about 125 million tonnes, as against 111.6 million tonnes in 1976-77. The production of *kharif* foodgrains is expected to be around 77.0 million tonnes as compared with 66.6 million tonnes in 1976-77, while *rabi* foodgrains may rise to a new peak of 48.0 million tonnes as against 45.0 million tonnes in 1976-77 and the earlier peak of 46.6 million tonnes in 1975-76. Table 2 presents the data on the production of major agricultural commodities since 1974-75.

8. Among cash crops, the out-turn was particularly good in respect of sugarcane, where the estimate of production is 16.5 million tonnes (in terms of gur)—the highest recorded so far. The estimated output of 5 major oilseeds (groundnut, rapeseed/mustard, sesamum, linseed and castorseed) at 9.4 million tonnes would be 1.6 million tonnes higher than in the previous year, but marginally below the peak level of 1975-76. Cotton production is now placed at about 6.8 million bales. Jute production is estimated at 7.1 million bales, which may be just adequate to meet requirements.

9. Favourable climate was an important element in the good performance of agriculture. The other contributory

TABLE 2 : AGRICULTURAL PRODUCTION—SELECTED COMMODITIES

	Unit	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78 (Provisional)
Kharif Foodgrains	Million Tonnes	59.1	74.2	66.6	77.0
Rabi Foodgrains	,,	40.7	46.6	45.0	48.0
Total Foodgrains	,,	99.8	120.8	111.6	125.0
Cereals	,,	89.8	107.7	100.4	112.2
Rice	,,	39.6	48.7	42.8	50.0
Wheat	,,	24.1	28.9	29.1	31.0
Pulses	,,	10.0	13.0	11.2	12.8
Non-Foodgrains					
Cotton	Million bales of 170 kgs. each	7.2	5.9	5.8	6.8*
Jute & Mesta	Million bales of 180 kgs. each	5.9	5.9	7.1	7.1**
Oilseeds (5 major seeds)	Million tonnes	8.5	9.9	7.8	9.4$
Groundnut in shell	,,	5.1	6.8	5.3	6.0@
Sugarcane (in terms of gur)	,,	14.7	14.4	15.8	16.5

*Cotton Advisory Board Estimate

**Final Estimate

$Trade Estimate

@Official Estimate

factor were the adoption of improved technology and better availability of fertilizers and other inputs. Over the period 1966-67 to 1976-77, the consumption of fertilizers trebled from 1.1 million tonnes to 3.4 million tonnes. This improvement was accompanied by a more balanced composition of the fertilizers used, with the former dependence on nitrogenous fertilizers being reduced by larger use of phosphatic and potassic fertilizers. Net irrigated area increased from 27.1 million hectares in 1966-67 to 33.7 million hectares in 1974-75. Another instance of the greater intensity of agricultural production is the increase in the output of summer rice crop, now estimated at over 5 million tonnes as against only around 1.5 million tonnes a few years ago.

10. There are, however, some persistent weak features, the most important being in respect of coarse grains and pulses, the production trends in which are not comparable with those in wheat and rice. The output of pulses, especially, has moved within narrow ranges over the past decade, the 10 year average being only 11.14 million tonnes. Coarse grains, which are in the main dry crops, are subject to sharp fluctuations in output, being extremely sensitive to climatic factors. Both the pulses and coarse grains groups are of special importance—one for its nutritional value and the other for the reason that it is the traditional staple diet of the poorer sections of the population throughout the country. There is need for special attention to these foodgrains in the implementation of new agricultural strategies. The spread of irrigation is very uneven and large areas still depend on rainfall. Commercial crops have also been largely untouched by the research effort of the new agricultural technology, with the exception of some oilseeds like soyabean, and cotton in which some long-staple high-yielding varieties have been introduced. Thus, along with continuing efforts to raise their yields and output, imports of cotton and vegetable oils/oilseeds undertaken in the past year to ensure larger supplies may have to be continued for some time in the context of inadequate domestic production.

Procurement Operation and Stocks

11. Although there was no compulsory procurement levy during the year under review, actual purchases by Government agencies of both rice and wheat have been quite substantial. Purchases of wheat during 1977-78 season (April-June) aggregated 5.4 million tonnes as compared with 6.6 million tonnes in the preceding season. In the 1978-79 rabi season, 5.3 million tonnes of wheat have been procured upto end-June 1978 as compared with 4.8 million tonnes in the corresponding period of the 1977-78 season. Procurement of rice upto June 24, 1978 totalled 4.7 million tonnes, and was marginally higher than that during the corresponding period of the 1976-77 kharif marketing season at 4.3 million tonnes. These purchases were made by the Government, despite the fact that there was a free market in these commodities without any movement restrictions, which is indicative of the magnitude of price support extended through Government purchases. Owing to the comfortable supply position, no import of foodgrains was necessary during the year.

12. Stocks of foodgrains with the public distribution system, which had reached the record level of 20.7 million tonnes at the end of June 1977, declined to 17.4 million tonnes at the end of October 1977 and continued at this level till end-January 1978. Subsequently, stocks declined in the next three months to 14.8 million tonnes at end-April 1978 but again increased to 19.0 million tonnes by end-June 1978. Total off-take of foodgrains from the public distribution system increased from 9.3 million tonnes in 1976 to 11.6 million tonnes in 1977. During January-June 1978, total off-take of foodgrains from the public distribution system was of the order of 5.6 million tonnes, the same quantity as procured during the corresponding period of the last year.

Industrial Output

13. In contrast to agriculture, the level of industrial production in 1977 was poor, the increase being no more than 5.3 per cent, which was one half of the previous year's increase of 10.6 per cent.* This was reflected in the monthly average of the general index of industrial production (base : 1970 = 100) moving up by only 7.0 percentage points in 1977 as against a rise of 12.7 percentage points during 1976. The sluggishness in growth not only persisted in the second half of 1977 (July-December) but in fact was accentuated and, as compared to the first half of the year, the average index of industrial production recorded a decline of 2.0 per cent. This was in marked contrast to the trend in the past six years; in each of these years, the average index for the July-December period showed an increase over the average for the preceding six months. Further, this deceleration in growth was shared by all the major industrial groups.

14. Industrial group-wise, the pace of growth in 1977 was especially low in basic industries (weight 32.28) where the increase recorded in 1977 was just 4.5 per cent as against 14.3 per cent in 1976. In the intermediate goods group (weight 20.95) also the rate of increase has been substantially lower, while in consumer goods (weight 31.52), the rate of growth was 6.4 per cent in 1977 against 10.2 per cent in 1976. In the capital goods group (weight 15.25), the growth in 1977 was 9.7 per cent as against 10.5 per cent in the previous year.

15. The deceleration in industrial growth is attributable to a combination of factors. There was a slackening in investment. The shortage of power was especially pronounced in some parts of the country where the concentration of indutry is high. Further, some important inputs such as coal and cement were in short supply. Industrial unrest also affected production.

16. There is evidence of some pick-up in growth during the first half of 1978. This trend may be expected to persist and gather momentum as Plan outlays grow. The data relating to the assistance provided by all-India term lending institutions (the IFCI, the ICICI and the IDBI) also indicate some revival in private investment. Total loans sanctioned by these institutions in the period July 1977—March 1978 were 19.1 per cent higher than the total sanctions in the corresponding period of 1976-77 while disbursements showed an increase of 11.2 per cent. An indication of revival, especially in the construction industry, may also be seen in the off-take of cement and steel, which increased respectively by over 7 per cent and 11 per cent in 1977-78.

Capacity and Stocks

17. Information relating to the operational aspects of industry, such as the extent of capacity utilisation and stock levels, is fragmentary and, therefore, basically illustrative. Available data show a decline in the utilisation of capacity in respect of some industries such as aluminium and saleable steel, mainly on account of shortage of power. Industries such as bicycle tyres, cotton yarn and cloth, machine tools and textile machinery, which had faced a pile-up of stocks in 1976, slowed down production in 1977 and drew on existing stocks. The year-end stock position of unsold cotton cloth, for example, was 151.4 million metres in 1977 as compared to 205.5 million metres in 1976; and in cotton yarn (unsold) it was 9.3 million kgs. as against 11 million kgs. There were also instances of industries which operated at higher capacity. These included electric fans, refrigerators, dry batteries, cigarettes and automobiles. In the sugar industry, production touched a record level. This combined with a decline in exports, led to a sizeable increase in stocks. At the close of the 1976-77 season, sugar stocks increased to 15.79 lakh tonnes from 8.45 lakh tonnes at the end of the preceding season. In June 1978, stocks of sugar with the industry rose to 45.5 lakh tones, compared to 25.0 lakh tonnes a year earlier. Cement was an example of an industry facing severe capacity constraint with an utilisation rate of about 90 per cent. In view of growing demand the Government decided to import cement and as a result, the stocks of 2.5 lakh tonnes at the close of 1977 were marginally higher than the previous year-end stock level of 2.3 lakh tonnes.

Industrial Sickness

18. While the normal rhythm of growth would render the operation of some individual units uneconomic at times, the spread of industrial sciknes has become a matter of serious concern. The spread may be illustrated by the increase in the number of units enjoying credit facilities from scheduled commercial banks in excess of rupees one crore and which have been making cash losses even before providing for depreciation and are expected to so continue in the immediate future. Between December 1976 and September 1977, the number of such units increased from 241 to 270 and their outstanding bank credit rose from Rs. 609 crores (or 11 per cent of bank credit to large and medium industry) to Rs. 774 crores (or 14 per cent). These figures relate only to a section of industry. In the small-scale sector as many as 8,000 units are estimated to have been similarly afflicted, locking up bank funds to the tune of Rs. 200 crores. In the context of high and rising unemployment, the closure of affected units cannot be a general solution to the problem. On the other hand, the task of nursing potentially viable sick units back to health is a complex one requiring co-ordinated effort on many fronts which is designed, at the same time, to take account of individual specific situations.

19. The causes of industrial sickness could be either internal (relating to units) or external (relating to the industry or the sector) or both. In the former instance, causative factors are, *inter alia*, faulty original planning and its subsequent implementation, absence of appropriate financial arrangements, inefficient management, etc. On the other hand, external factors include the overall economic climate, structural weakness, lack of demand, supply constraints, inappropriate pricing policies, etc. These can be alleviated mainly through appropriate governmental policies. Not all industrial units, however, feel the impact of these external factors to the same extent because of differences in size, diversification, internal strength and resilience. But this diversity should not be allowed to delay such changes in government policies as are clearly called for and feasible. Financial institutions can assist this process by their systematic and objective analysis of industrial sickness and its feed back to appropriate authorities.

*For the financial year 1977-78 the rate of growth in industrial production was 34 per cent as against 10.4 per cent in 1976-77.

20. For banks and financial institutions, loans to sick units entail problems on three counts· a weakening of their assets portfolio, a reduction in the turn-round of their loanable funds because of the stickness of the loans and a fall if their interest income Banks and financial institutions undertake programmes for "nursing" most of their sick accounts Measures have been taken to strengthen this attitude in commercial banks and financial institutions and to help in the formulation of joint programmes for dealing with the problem of sick industries However, certain basic constraints on the ability of commercial banks to shoulder the burden of rehabilitation of sick units have to be recognised It is neither legitimate nor practical for banks to nurse sick units in all circumstances Protection of employment cannot obviously be the sole criterion in this regard and the long term viability of the units to be realistically assessed.

21 In case of some industries, promoted in the interest of import substitution, inadequate attention has been given to cost considerations This was, perhaps, justifiable in the context of foreign exchange shortage It could still be justified for strategic industries The possibility of some protected industries experiencing difficulties on account of liberalised imports cannot be ruled out The solution in these cases would lie on such industries attempting to make their products, competitive There is no gainsaying the fact that cost consciousness has to be developed and sustained in the interest of long term growth and stability But greater competitiveness and reduction in costs or improvements in the quality of production often require, apart from better management, additional financial resources for new balancing investment

Foreign Trade Export Trends

22 Foreign trade during the financial year 1977-78 was marked by the re-emergance of a trade deficit which, provisional data indicate to be of the order of Rs 580 crores, as against a modest surplus of Rs. 72 crores recorded in 1976-77. The deficit was the result of a deceleration in export receipts and a rise in imports following the considerable liberalisation effected in import policy

23 The deceleration in the export growth rate, which became pronounced from the second quarter of the year, followed in the main from the world economic situation marked by a low growth of industrial economies and the emergence of protectionist tendencies The policy to ban or regulate the export of some commodities to sustain supplies for domestic consumption and subserve price stability also acted as a restraint on exports This was the case with the export restriction on commodities such as vegetable oils and oilseeds, fresh vegetables and tea, the export of which was made subject to a ceiling The export item that was particularly affected by conditions abroad was cotton textiles, including garments, which suffered an estimated reduction of Rs 50—60 crores following the delay in finalising the Multi Fibre Agreement and the imposition of unilateral restrictions by some importing countries The build-up of inventories in some western countries affected the export of leather, which dropped by about Rs 30 crores. Exports of iron and steel also declined, engineering exports, though experiencing some deceleration, were not much affected because of the continuing demand in West Asian countries which are among the principal markets for Indian engineering products, and the higher civil construction contracts secured from that area.

24 Despite these handicaps, the overall performance of Indian exports in 1977-78 may be viewed as not altogether unsatisfactory The main factor for this was the higher unit value realised for some primary commodities such as tea, coffee, spices, cashew kernels, following a sharp rise in international prices Tea prices rose spectarularly, after a decade of stagnation. Although the Government imposed a ceiling of 225 million kgs on tea exports for 1977-78 and also levied an export duty, earnings from tea exports are expected to touch a high of Rs 560 crores in 1977-78 as against Rs. 293 crores earned in 1976-77 The only agricultural commodity whose export suffered, and that too drastically, was sugar. Abundant world supplies, large carry-over of stocks in importing countries, and the development of and penetration by substitutes contributed to this outcome Earning from the export of silver, which averaged about Rs. 160 crores during 1975 76 and 1976-77, dropped to just over Rs 80 crores in 1977 78 An export item expected to bring in substantial earnings is gem and jewelfery, which is being encouraged through special incentive measures such as the provision of raw material supplies at international prices

Imports

25 Imports are expected to show a rise of about 20 per cent over the previous year An important factor in this increase was the large import of essential commodities like edible oils to relieve domestic shortage Edible oil imports rose from Rs 64 crores in April-December 1976 to Rs 514 crores in April-December 1977 The composition of imports in the last three years has been significantly different from that in the sixties and the early seventies, when the import of food, fertilisers and mineral oils constituted a major draft on scarce foreign exchange resources With the increase in food production and food stocks, food imports have become unnecessary for the present, while the success of the exploration for oil and natural gas and the increase in fertilizer production have helped peg the requirements of fuel and fertilizer imports Meanwhile, with the continuing rise in foreign exchange reserves and the need to support industrial growth, a new orientation has been given to import policy The thrust of the new policy is towards rationalisation of the licensing system, easing of controls, simplification of procedures, and decentralisation of administrative authority This marks the beginning of a more open import policy, for the first time, the Indian capital goods industry will be exposed to competition in the domestic market Imports of industrial raw materials, components as well as capital goods may thus be expected to rise.

Invisible Receipts

26 Since 1974-75, current invisible receipts have materially assisted the improvement in our external payments position* Gross non-merchandise receipts through banks alone (*i.e.* excluding receipts through official channels) increased, according to the estimates of the Exchange Control Department, from Rs 654 crores in 1974 75 to Rs 1,198 crores in 1975 76, than to Rs 1 586 crores in 1975 76, and further to Rs 2,117 crores in 1977-78 Major components of these receipts are private unilateral transfers, travel receipts, earnings from technical and professional services including consulting and contracting, and chartiable and other donations Private unilateral transfers represent mainly remittances from Indians resident abroad for family maintenance A part of the remittances from overseas Indians is also received into non-resident rupee bank accounts, balances in which amounted to Rs 31 crores at the end-March 1975, Rs 64 crores at end March 1976, Rs 185 crores at end-March 1977, and Rs 320 crores at end March 1978 Since November 1975, Indians abroad and non residents of Indian origin are eligible to hold foreign currency accounts with banks in India under the Foreign Currency (Non-resident) Accounts Scheme; direct receipts under these accounts totalled £12.3 million and $ 149 8 million till the end of March 1r78 (these together equal Rs 143 crores at end-March 1978 rates of exchange) The accruals to the foreign currency accounts are not included in the figures for gross non-merchandise receipts given earlier in this paragraph.

*In addition to private unilateral transfers, receipts from travel, transportation, investment income and technical services have contributed to this outcome. Receipts from travel, transportation and investment income which together amounted to 35 per cent of gross current invisible receipts of Rs. 359 crores in April-June 1975 amounted to 42 per cent of the total receipts of Rs. 468 crores in the similar quarter of 1976, while private unilateral transfers alone accounted for 34-35 per cent in both the quarters

27. The number of Indians going aborad for employment, as represented by 'P' form clearances for the purposes, rose from 20,504 in 1974-75 to 30,406 in 1975-76 and then doubled to 72,491 in 1976-77. The growth rate has since perceptibly declined with the number of emigrants in 1977-78 (upto March 1978) at 86,505. Such emigrant workers, particularly those going to West Asia, are permitted to enter host countries for specific jobs generally for limited durations. Because of this and general employment conditions elsewhere, inward remittances for family maintenance may now be levelling off. The increase in travel receipts, on the other hand, may be expected to be sustained not only by the larger number of tourists visiting the country but by a rise in the average amounts spent by them, particularly in view of the growth in the number of visitors from West Asia. Income from private investments abroad is also likely to continue to increase, while official investment income receipts would move with the level of foreign currency reserves. The immediate medium-term outlook for receipts on account of Indian technical and professional services rendered in foreign countries is also bright. Further, gross receipts form transportation are also expected to increase with the quantum of foreign trade and its share carried in Indian bottoms.

External Assistance

28. Gross disbursements of external assistance was lower over the year by Rs. 311 crores to Rs. 1,288 crores. Additionally amortization and interest payments were of a noticeably larger order. Consequently, the net inflow declined from Rs. 844 crores in 1976-77 to Rs. 467 crores during 1977-78. At the Aid-India Consortium, gross external assistance is indicated to rise over the year from $ 2.1 billion to $2.3 billion in 1978-79 (all financial years).

Foreign Exchange Reserve

29. Foreign exchange reserves have been rising steadily since January 1976 to reach a record of Rs. 4,518 crores at the end of June 1978. During the year July 1977 to June 1978 there was, however, a distinct slowing down in the pace of reserve accumulation, the increase in official foreign currency holdings amounting to Rs. 937 crores or only a shade higher than half of the rise of Rs. 1,831 crores in the proceeding year The deceleration in the growth of reserves was particularly marked during the last quarter of the year. Between end-March and end-June 1978, the SDR designation transactions with the IMF and the purchase of gold connected with India's share in the profits from sales of the IMF gold for the benefit of developing countries involved a foreign currency outlay of Rs. 148 crores. Excluding the import of these transactions, the additions to foreign currency holdings during quarter amounted to only Rs. 167 crores. In the corresponding period of 1977, disregarding the impact of SDR designation transactions with the IMF, the additions to official foreign currency holdings worked out to Rs. 727 crores.

30. Indications are that the recent slow down in accretions to reserves is not likely to be reversed in the coming months. In the first place, imports may be expected to rise substantially in consequence of the liberalised import policy. There is already some evidence of this. According to provisional data, import payments effected through banks during April-June 1978 amounted to Rs. 1,029 crores, which were 31 per cent higher than those in the corresponding months of 1977. Further, exports in 1978-79 may not reach even the growth rate of 1977-78. An initial indication of export receipts is provided by the outstanding of forward contracts entered by authorised dealers with the Reserve Bank for sale of foreign exchange. The outstandings at the end of April 1978 in respect of such forward contracts in each of the major world currencies were lower than the outstandings a year earlier.

31. Following the comfortable reserve position, India reduced her obligations to the IMF in July 1977 by repurchasing the remaining part of the credit tranche drawals and the outstanding gold tranche drawal together amounting to Rs. 249 crores. During the preceding year, such repurchases on account of the 1974 oil facility and part of the first credit tranche had amounted to Rs. 238 crores. Excluding these transactions with the Fund, official foreign currency holdings would have increased by Rs. 1,185 crores during July 1977-June 1978, as against Rs. 2,069 crores in the preceding year. The repurchase of SDR 201.3 million under the 1975 oil facility drawings was also effected on July 16, 1978

Credit Trends

32. The main indicators relating to commercial banks showed substantial variations in the course of the year. There was evidence of slackness in credit expansion upto end-April ; the increase in gross credit in the 10 month period (July-April) was of the order of Rs. 1,193 crores (8.8 per cent as against an increase of Rs. 1,840 crores (15.8 per cent) in the corresponding period of the previous year. This was mainly on account of advances for public food procurement and distribution, which declined by Rs. 544 crores as against an increase of Rs. 96 crores in the previous year. In the subsequent two months of May and June 1978, gross credit rose by Rs. 789 crores, which was considerably larger than the increase of Rs. 147 crores in the corresponding months of 1976-77. This increase also was largely (though not entirely) attributable to food credit, which rose by Rs. 526 crores in the two month period as against Rs. 255 crores in the last year.

33. The lagged expansion in gross credit also combined with change in the growth pattern of deposits. In the period July-April 1977-78, aggregate deposits increased by Rs. 3,373 crores whereas in the next two months, the accretion was of the order of Rs. 656 crores. In contrast, the increase in deposits in the corresponding months of the previous year were Rs. 2,952 crores and Rs. 773 crores respectively. Thus, a slackness in credit combined with brisk deposit growth in the first ten months of the year resulted in considerable liquidity in the system. This was evidenced in the Bank's main considerable liquitenance of a liquidity ratio in excess of the statutory requirement by about 3 percentage points through April 1978. Banks also repaid borrowings from the Reserve Bank to a substantial extent, and the amount of total borrowing from the Reserve Bank at the end of April 1978 was Rs. 155 crores as against Rs. 614 crores in April 1977.

34. In the monthes of May and June 1978, on the other hand banks increased their borrowings from the Reserve Bank by Rs. 180 crores while in the corresponding months of the previous year they had repaid their borrowings from the Reserve Bank to the extent of Rs. 51 crores. In addition in the same period, banks brought down their investments in Government and approved securities by Rs. 617 crores as against an increase in investment of Rs. 122 crores in the previous year.

35. The effect of the changes in the banking variable may be seen in the credit-deposit ratio which stood at a low of 66 per cent at end-April 1978 whereas it was 73.3 per cent a year earlier. By end-June 1978, the ratio moved up to 67.5 per cent. This was, however, still lower than the ratio of 71.4 per cent at the end of June 1977.

36. Table 3 gives the details of the changes in scheduled commercial banks' deposit and credit for the year as a whole. Gross credit expansion during the year was almost of the some amount as in 1976-77, although in percentage terms, the growth was lower by 2.5 percentage points. However, the increase in non-food credit was higher than in the previous year both in absolute amount and in percentage terms. Further adjustments in the figure of non-food credit, with the

TABLE 3 : VARIATIONS IN SCHEDULED COMMERCIAL BANKS' DEPOSIT AND CREDIT

(Rupees crores)

	1976-77			1977-78	
	Last Friday of		Change (June 1977 Over June 1976)	Last Friday of June 1978	Change 1978 over June 1977)
	June 1976	June 1977			
Gross Credit Expansion	11620	13607	+1987 (17.1)	11589	+1982 (14 6)
Of which:					
Food Procurement	2185	2536	+351	2518	—18
Non-Food	9435	11071	+1636 (17 3)	13071	+2000 (18 1)
Excluding Credit for Cotton to CCI and Fertiliser to Food Corporation of India	9409	10847	+1438 (15 3)	12683	+1836 (16.9)
Aggregate-Deposit/growth	15178	18903	+3725 (24 5)	22932	+4029 (21.3)
Bank Credit/Deposit Ratio	75 6	71 4		67 5	

Figures in brackets indicate percentage variations.

deduction of the amounts lent for other major public sector trading activities (to the Cotton Corporation of India and the Food Corporation of India for fertilizer distribution) yields a similar picture—a larger increase than last year both in absolute amount and in percentage terms. On the other hand, the rate of growth in deposits during the year was distinctly lower.

Loans to State Co-operative Banks

37. During 1977-78, Reserve Bank's financial accommodation to co-operatives increased considerably. The short-term credit limits sanctioned by the Bank for financing seasonal agricultural operations to State Co-operative Banks increased to Rs 749 crores from Rs 696 crores last year. The medium-term credit limits sanctioned during the calendar year 1977 aggregated Rs. 21.34 crores, against which actual drawals by the State Co-operative Banks amounted to Rs. 12 23 crores The medium-term credit limits sanctioned up to June 30, 1978 to various State Co-operative Banks for the year 1978 aggregated to Rs. 19.09 crores During the year 1977-78, loans from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund aggregating Rs. 21.13 crores were sanctioned to State Governments for share capital contribution to the co-operative credit institutions. The loans drawn by the State Governments against the sanctions for contribution to share capital aggregated Rs. 2..80 crores during the period. The Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) was given a long-term loan of Rs. 65 crores from the National Agricultural Credit (LTO) Fund. Repayments and drawals during the year were Rs. 20.80 crores and Rs. 65 00 crores respectively The outstandings as on June 30, 1978 stood at Rs. 216 80 crores.

38. The main emphasis in the sphere of co-operative banking continued to be on reducing regional imbalances and ensuring increased flow of credit, more particularly to the weaker sections of the rural community, rationalisation of the interest rate structure of the co-operatives and reducing the cost of credit to the ultimate borrowers To fulfil the first objective, efforts continued to be directed towards reorganization of the primary agricultural credit societies into viable Primary Credit Societies (PACS)/Farmers' Service Societies (FSS)/ Large Sized Multi-Purposes Societies (LAMPS), rehabilitation of co-operative banks, provision of Government share capital, and enhanced refinance facilities from the Bank under the ACID programme, on selective basis. Resources were devoted to strengthen the co-operatives and link them with the agricultural production programmes. As the existing ratio of share-linking to borrowers at 10 per cent collected in a phased manner was causing hardships to the small farmers and economically weak borrowers, it was reduced to 5 per cent.

Government Finances

39. The budgetary operations of the Central and State Governments (existing Union Territories with legislatures) during the fiscal year 1977-78 reflected the impact of a sizeable increase in the annual plan outlay which rose by about Rs. 1,900 crores over the previous year's level. Simultaneously, there was also a slightly faster rate of increase in non-developmental expenditure. The increase in aggregate receipts was less pronounced than the increase in expenditure, resulting in a deterioration in the overall position, with the total budgetary deficit of the Centre and the States together amounting to Rs. 1,265 crores in 1977-78 as against only Rs. 81 crores in 1976-77. Table 4 gives the details of this position

40. While the revised budgetary estimates for 1977-78 placed the total budgetary deficit of Central and State Governments at Rs 1,265 crores, according to Resreve Bank records the total deficit was Rs. 884 crores * This was made up of a deficit of Rs 801 crores on account of Central Government and Rs. 83 crores on account of State Governments.

Central Government's Finances

41. The increase in total provision in the Central budget for outlay on the Annual Plan was of the order of Rs. 980 crores, about two-thirds of which represented assistance for the Plan outlay of the States and Union territories. The budget of the Government of India for 1978-79 has further stepped up development outlay. Further, the fiscal measures introduced in the budget have sought to enhance the availability of risk capital through tax concessions for investment in the equity shares of new companies. Such investments, upto a liberal limit, are eligible for deduction in the computation of taxable incomes. Another important measure included in the budget was the withdrawal of the tax on the interest income of banks. It may be recalled that this tax was imposed in 1974, when high interest rates were used as an instrument of monetary restraint, the incidence of the tax was on the borrowers from banks as it added to the cost of credit. The tax was withdrawn against the background for the policy of encouraging investment and reducing the cost of industrial production.

*Data on receipts and disbursements conforming to this figures are not yet available,

TABLE 4 : COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(Rupees Crores)

Items	1976-77 (Accounts)	1977-78 (Revised Estimates)		1978-79 (Budget Estimates) @	
		Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year
1	2	3	4	5	6
I. Total Receipt ((A+B)	22217	24011	+8.1	26227**	+9.2
A. Revenue Receipts	15858	17245	+8.7	18897	+9.6
Of which :					
Tax Receipts	12294	13236	+7.7	14687	+11.0
B. Capital Receipts	6359	6766	+6.4	7330	+8.3
II. Total Disbursements	22298	25276	+13.4	27574	+9.1
Of which :					
A. Developmental Outlay (a+b)	10672	12798	+19.9	14276	+11.5
(a) Revenue	7501	8898	+18.6	9753	+9.6
(b) Capital	3171	3900	+23.0	4523	+16.0
B. Non-Developmental Outlay (a+b)	7189	7847	+9.2	8887	+13.3
(a) Revenue	6855	7526	+9.8	8278.	+10.0
(b) Capital	334	321	—3.9	609@@	+89.7
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—) (I—II)	—81	—1265		—1347*	

42. The budget has relied principally on indirect taxes for mobilising fresh resources. But despite a fairly wide range of levies in this direction, the anticipated increase over the year in aggregate receipts, stands lower than the expected growth in aggregate disbursements. As a result, the Central Government budget for 1978-79 leaves a gap of Rs. 1,537 crores† which, coming on top of the sizeable deficit in the preceding year, might have serious monetary implicutious.

State Finances

43. The combined budgetary position of twenty-two State Governments shows an increasing reliance on transfers from the Centre by way of shares in Central taxes, grants and loans; the revised estimates for 1977-78 yield a total incremental figure of Rs. 1,059 crores under this head, which is slightly more than twice the increase in such transfers in the previous year. A major part of the additional loan assistance from the Centre intended to clear the over drafts of some State Governments with the Reserve Bank, cover the gap in States' resources for financing their Plans and for relief operations following natural calamities in several parts of the country. On the other hand, the States' attempts to raise additional resources through fresh tax measures on their own account have been discouraging. While the total additional resources raised through fresh tax measures in 1976-77 stood at Rs. 107 crores, the amount was only Rs. 65 crores in 1977-78. The budgets for 1978-79 do not indicate any significant improvement on this score.

44. The budgetary operations of the State Governments in 1978-79 are marked by a further slackening in the pace of growth in receipts. Despite a decline in the tempo of growth in developmental and non-developmental expenditure, the overall budgetary position of the States is expected to show,

@Includes effects of the budget proposals, effect of tax concessions (Rs. 25 crores) announced on April 27, 1978 by the Central Government and supplementary demands for grants for additional expenditure presented to the Lok Sabha on August, 1, 1978.

@@Includes a provision for payment to IMF of Rs. 245 crores on account of the increase in India's quota at the IMF and by way of currency valuation adjustment.

* This deficit would go up by Rs. 122 crores if unbudgeted outlays in respect of Assam, Haryana, Jammu and Kashmir, Kerala, Punjab and Rajasthan, and the supplementary demands for grants in respect of Maharashtra and Kerala are taken into account.

** Includes sale proceeds of gold from first six auctions conducted by the Reserve Bank.

Notes : 1. Data do not cover Union Territories with legislatures.

2. Figures are adjusted for inter-governmental transfers on the basis of data available in the Central Government Budget. These adjustments do not affect the combined overall position.

3. Figures are provisional pending receipt of final figures in respect of a few States.

Source: Budgets of the Central and State Governments.

†Including the effect of tax concessions on central finances (Rs. 21 crores) announced on April 27, 1978. Supplementary Demands for Grants for additional expenditure presented to the Lok Sabha on August 1, 1978 and sale proceeds of gold from first six auctions conducted by the Reserve Bank.

for the second year in succession, a substantial deficit of Rs. 257 crores.**

Ways and Means Advances and Overdrafts

45. Mention was made in last year's Report of the facility of temporary accommodation provided by the Reserve Bank to State Governments to enable them to tide over imbalances arising out of uneven flows of receipts in relation to disbursements. Some of the State Governments have, in recent years, been persistently overdrawing in excess of their borrowing entitlements. Such overdrafts amounting to Rs. 320 crores at the end of June 1977 were cleared through advance disbursement of Central Government assistance to the States. The overdrafts re-merged later in the year and persisted at higher levels and for longer durations. Despite repeated urgings by the Reserve Bank and the Central Government that the State Governments should avoid and eliminate recourse to overdrawing on a continuing basis, the outstanding level of overdrafts was at a peak level of Rs. 538 crores on April 14, 1978.@

46. The persistent large overdrafts are a reflection of a basic imbalance between the States' receipts and disbursements which normally, in the absence of unforeseen natural calamities, signify a certain absence of financial discipline. Such overdrafts amount to a draft on resources by the States in excess of what was agreed to with the Central Government in their annual financial programmes drawn up at the beginning of the financial year. Obviously, such excess draff has implications for the overall level of deficit financing, as well as for the distributive justice between the States. The situation is somewhat unusual over the recent past in that some State Governments, which came to power in mid-1977, feel that they inherited a substantially unbalanced budgetary legacy. In this context, it is appropriate that the Central and State Governments mutually work out arrangements for clearing the inordinately high level of overdrafts taking all relevant factors into account.* But, thereafter, the States should conform to the arrangement agreed upon with Centre and should take all possible steps to counter the adverse impact of unforeseen circumstances without any fresh recourse to unauthorised overdrafts.

Market Borrowings

47. During 1977-78 the market borrowing programme of the Central Govrnment was of a larger order, with net receipts at Rs. 1,183 crores going up over the year by Rs. 334 crores. The net amount of market loans raised by the State Governments, however, remained more less the same at Rs. 179 crores. The borrowings by institutions sponsored by the Central and State Governments totalled Rs. 630 crores.

48. The Centre approached the market twice during the year and made sales to the Reserve Bank thrice for subsequent release to investors. The gross amount raised in these five instalments aggregated to Rs. 1,312 crores, higher by Rs. 188 crores or 16.7 per cent over the previous year.

49. The gross borrowings of the State Governments during 1977-78 amounted to Rs. 284 crores, made up of Rs. 234 crores by way of cash and Rs. 50 crores on a conversion basis. Repayment of matured loans amounted to Rs. 105 crores, leaving the net market borrowings at Rs. 179 crores.

50. For 1978-79, the Centre's programme for net market borrowing is of the order of Rs. 1,650 crores. The first approach to the market was made on May 15, 1978 with the issue of three loans—6 per cent loan 1988 (third issue), 6-1/4 per cent loan 1995 and 6-3/4 per cent loan 2006 for an aggregate sum of Rs. 552 crores on cash basis. Further tranches of these three loans for an aggregate amount of Rs. 200 crores were issued to the Reserve Bank on May 25, 1978 for subsequent placement on the market. A third instalment of the Centre's borrowing programme was effected on July 1, 1978 for a total amount of Rs. 440 crores on a cash-cum-conversion basis, of which Rs. 93 crores were by way of conversion.

Financial Flows

51. The budget is not the only means through which a transfer of resources between different regions and sectors is effected. Capital flows also follow from the operations of financial institutions like commercial banks with a wide branch net-work and national level term financial institutions. While the magnitude of financial flows stemming from the operations of these institutions is significant, the scope for the regulation of the distribution of the flows is limited.

52. The geographic pattern of the lending operations of banks and term lending institutions is determined primarily by the demand factor, arising from the location of the borrowing units. However, the assistance of financial institutions to the economy of a State is not only through extension of credit but also through subscriptions to the bonds and debentures of institutions carrying out development programmes in the state. Such investments help in augmenting the resources of these institutions and hence in financing the programmes themselves. In recent years, there has been a considerable increase in the investment of banks in the securities of State Governments and State level bodies, especially in the backward States.

53. Another policy measure designed towards the reduction of regional inequalities in the establishment of bank offices, especially in the rural interior in areas hitherto not exposed to the influence of such institutional presence. The formula for branch expansion of commercial banks which was designed to increase the number of offices in rural areas was changed early in 1977, shifting the emphasis to unbanked centres. This was to counteract the tendency of banks to cluster in centres which, though technically rural, were already provided with banking facilities. Under the revised formula, banks can open branches in urban centres and banked centres only after fulfilling the requirement of a specified number of branches in unbanked rural centres. This shift in policy, incidentally, has yielded fairly quick results as the proportion of rural offices of commercial banks in total offices which had been stagnating at around 36 per cent since 1975 rose to 38.5 per cent in June 1977 and further to 41 per cent by end 1977. For 1978, banks were advised to consolidate their position and not plan on too large a programme of branch expansion. Even in the selec-

** If the unbudgeted outlays of Assam, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala, Punjab and Rajasthan aggregating Rs. 54 crores and the Supplementary Demands for Grants for Rs. 21 crores and Rs. 47 crores in the case of Kerala and Maharashtra respectively are taken into account, this deficit would increase to Rs. 379 crores.

Subsequently on August 1, 1978 the Central Government has made a special loan of Rs. 430 crores towards clearance of the States' deficit as on March 31, 1978. Besides, additional grants of Rs. 14 crores and another loan of Rs. 2 crores are also sanctioned to States. If these loans and grants to States are treated as their receipts in 1978-79, their overall budgetary position is likely to show a surplus of Rs. 67 crores in 1978-79.

@The States' overdrafts stood at Rs. 505 crores as on June, 27,1978 which were cleared on June 29, 1978 by Central Government assistance.

*With a view to avoiding frequent recurrence of overdrafts in the accounts of concerned State Governments with Reserve Bank of India, the Central Government has made a special loan of Rs. 430 crores towards the clearance of the States' budgetary deficit as on March 31, 1978. This provision was made in the Supplementary Demands for Grants presented to the Lok Sabha on August, 1, 1978.

tion of unbanked centres, banks have been asked to give emphasis to districts where the coverage of banking in terms of population served per office is inadequate in relation to the national average. The allotment of licences to new branches in urban and metropolitan centres has been further restricted. To improve the deployment of credit in rural areas, banks have also been directed to achieve a rural credit-deposit ratio of at least 60 per cent by March 1979 so as to ensure the productive deployment of the resources mobilised in rural and semi-urban areas in the same areas. Banks have also been asked to ensure that at least one-third of their total credit is extended to the priority sectors. Though banks are striving to achieve these objectives, the use made of available banking infrastructure in the rural interior is not adequate. It has to be recognised that the problem of regional imbalances cannot be solved solely through the operations of financial institutions.

54. The need is now more pronounced than even before for greater integration of the activities of different credit institutions catering to the rural and agricultural sectors. Based on the recommendations of the committees to review the working of regional rural banks and to study multi-agency approach in agricultural financing, the broad framework of an inter-institutional approach to rural development for the next 5—10 years has been evolved. There is to be a closer linkage between the apex co-operative banks and Regional Rural Banks, and wherever possible, joint sponsorship of these banks by the apex banks and commercial banks is to be encouraged. Regional Rural Banks are to function in rural areas in preference to branches of commercial banks and the transfer of the existing commercial banks' rural offices in a phased manner may be taken up in consultation with the concerned banks. This, however, does not mean any rigid compartmentalisation. While a more prominent role is envisaged in developing the rural sector for Regional Rural Banks and co-operatives, commerical banks will continue to finance agriculture, both on their own account and through co-operatives and Regional Rural Banks and such financing is not to be confined to big farmers.

Money Supply

55. The increase in money supply with the public has continued unabated with the rise of Rs. 3,008 crores (18.4 per cent) during the year as against Rs. 2,232 crores (16.6 per cent) in the last year. The rate of growth was higher than the annual average rate of growth in money supply of 13.4 per cent in the preceding five years period (1972-73 to 1976-77). In the context of a mere increase of about 5 per cent in real national income, the rate of expansion in money supply is disturbing, even allowing for the fact that supplies increase (and decrease) faster than production in the case of agricultural commodities.

56. The rate of growth in time deposits has preceptibly slackened to 17.8 per cent (i.e. Rs. 2,261 crores). In the result, the order of increase in broad money, (M_3) (comprising money supply plus time deposits of banks) has been lower at 18.1 per cent as against 21.2 per cent last year.

57. A striking feature of the relatively high order of expansion in money supply during the current year has been that it was the result as much of increases in the principal sources of expansion as on account of the substantial deceleration in the pace of growth of non-monetary liabilities of the banking system. The increase in non-monetary liabilities in 1977-78 was only 2,749 crores (14.5 per cent) as for instance, compared with Rs. 4,241 crores (28.9 per cent) in 1976-77. This was mainly because of the sluggish growth in time deposits and to some extent also to a sharp decline (of Rs. 540 crores) in the net non-monetary liabilities of the Reserve Bank of India.

58. Compared with 1976-77, the rates of growth in net bank credit to Government, bank credit to commercial sector and net foreign exchange assets of the banking sector—in other words, all the principal influencing factors—were lower in the year under review. The rise in net Reserve Bank credit to Government was lower by Rs. 383 crores than that during the previous year, while other banks' incremental credit to Government went up by Rs. 323 crores. Details are given in Table 5.

Price Trends

59. The price situation during the year was marked by an absence of strain. This relative stability was achieved through a variety of measures. Effective supply management was an important element of these. Shortages in essential consumer goods like vegetable oils and in industrial raw materials such as oilseeds and cotton were bridged through timely imports. This involved grappling with consumer resistance to some extent especially in the use of non-traditional oils in direct consumption; but by an large, the policy has been successful. Domestic availability of consumer items like vegetables and tea with sizeable foreign demand was ensured by regulation of exports. Also, the lifting of all restrictions on the movement of foodgrains helped, to a large extent, to even out inter-regional disparities in food prices.

60 A point-to-point comparison of the prices prevailing at end-June 1978 with the position as at the end of June 1977 shows a decline in the index number of wholesale prices (base : 1970-71 = 100) of 2.1 per cent. A similar comparison between the corresponding points of 1976-77 shows an increase of 8.6 per cent. The rate of decline in 1977-78 was more or less equal in manufactured products and in primary articles (2.7 per cent and 2.9 per cent, respectively). The prin-

TABLE 5 : MONEY SUPPLY AND SOURCES OF CHANGE

(provisional)

(Rupees Crores)

Item	Outstandings as at the end of			Variations	
	June 1976	June 1977@	June 1978@	1976-77	1977-78
1	2	3	4	5	6
I. M_1 (Money Supply with the public) (A+B)	14038	16370	19378	+2332 (+16.6)	+3008 (+18.4)
A. Currency with the public	7235	8298	9295	+1063 (+14.7)	+997 (+12.0)
B. Deposit Money	6803	8072	10083	+1269 (+18.7)	+2011 (+24.9)
II. Sources of changes in M_1 (1+2+3+4+5)					
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	10841	12407	13913	+1566 (+14.4)	+1506 (+12.1)
A. R.B.I.'s Net Credit to Government (i—ii)	7247	7929	8228	+682	+299
(i) Claims on Government (a+b)	7316	8000	8623	+684	+623
(a) Central Government	6996	7454	8498	+458	+1044
(b) State Governments	320	546	125	+226	—421
(ii) Government Deposit with RBI (a+b)	69	71	395	+2	+324
(a) Central Government	57	65	377	+8	+312
(b) State Governments	12	7	18	—5	+11
B. Other Banks' Credit to Government	3594	4478	5685	+884	+1207

1	2	3	4	5	6
2. **Bank Credit to Commercial Sector (A+B)†**	16029	18976	21976	+2947 (+18.4)	+3000 (+15.8)
A. RBI's credit to commercial sector	740	840	1066	+100	+226
B. Other Banks' credit to commercial sector (*i*+*ii*+*iii*)	15288	18136	20910	+2848	+2774
(*i*) Bank credit by Commercial Banks	11492	13501	15504	+2009	+2003
(*ii*) Bank credit by Co-operative Banks	2106	2525	3020	+419	+495
(*iii*) Investment by Commercial and Co-operative Banks in other securities	1690	2111	2386	+421	+275
3. **Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector (A+B)**	1274	3306	4567	+2032 (+159.5)	+1261 (+38.1)
A. RBI's Net Foreign Exchange Assets (*i*—*ii*)	1280	3312	4573	+2032	+1261
(*i*) Gross Foreign Assets	1969	3761	4733	+1792	+972
(*ii*) Non-monetary Foreign Liabilities	689	449	160	—240	—289
B. Other Banks' net Foreign Exchange Assets	—6	—6	—6	—	—
4. **Government's Currency Liabilities to the Public**	555	583	573	+28 (+5.0)	—10 (—1.7)
5. **Non-Monetary Liabilities of the Banking Sector (A+B+C)**	14661	18902	21651	+4241 (+28.9)	+2749 (+14.5)
A. Time Deposits with Banks	9978	12736	14997	+2758 (+27.6)	+2261 (+17.8)
B. Net Non-Monetary Liabilities of RBI	2458	3593	3053	+1135	—540
C. Net Non-Monetay Liabilities of other Banks (Derived)	2226	2573	3601	+347	+1028
III. M_3 (M_1+Time Deposits with Banks)	24016	29107	34375	+5091 (+21.2)	+5268 (+18.1)

†Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

@Provisional.

Notes : 1. Figures within brackets relate to percentage variations.

2. Constitent items may not add up to totals due to rounding off.

cipal items in the manufactured products accounting for the fall were food products. The decline in the case of sugar was 4.3 per cent and in edible oils 13.0 per cent. In the primary commodity group food articles showed a decline (0.7 per cent). The one item in the group to record a substantial rise (26.1 per cent) was pulses.

61. The monthly aggregate index, in terms of averages of weeks, declined from August to November 1977. In the following month, the index showed a small increase and in January 1978 the index reverted to the November 1977 level. In February 1978, the index fell sizeably by 1.6 per cent. Thereafter, the index was in general inclined upward, with the exception of April 1978 when it declined by 0.4 per cent and in June 1978 touched 184.0 (provisional). Among the individual commodities, cereals recorded a decline since January, but showed a slight rise after April; the price index of pulses, which had risen sharply until March, declined by 8.3 per cent in the next two months to rise again in June. The absolute level of the index for pulses was an average of 237.2 for June 1978 as against 189.0 for June 1977.

62. In sum, the current position is that prices, after rising sharply since April 1976, have tended to stabilise at a fairly high level. The index for all commodities as of end-June 1978 was 184.8 as against 188.8 at end-June 1977 and 173.9 at end-June 1976. In view of the higher liquidity in the economy that would follow from the order of deficit financing envisaged in the budget for 1978-79, there is clearly no scope for complacency on the price front.

63. Movements in consumer price indices do not always correspond with those in wholesale prices because of differences in the commodity composition and the weighting pattern. The Consumer Price Index (Base : 1960 = 100) for industrial workers increased by 0.6 per cent (June 1978 over July 1977) as compared with a rise of 7.7 per cent in the corresponding period last year. The index for Urban non-Manual Employees moved up marginally by 1.7 per cent (May 1978 over July 1977) as against an increase of 5.1 per cent in the same period last year.

Credit Policy

64. The credit policy measures implemented during the year were designed to fit into the overall policy framework. The two principal objectives that the measures sought to serve were the creation of conditions for increasing the tempo of productive activity and the promotion of price stability through limiting the scope for greater monetary expansion. The most important policy decision taken during the year related to the adjustment of interest rates. At first, the move for lowering lending rates was selective and restricted to certain types of credit and the loans to certain preferred sectors. Thus, in December 1977, banks were asked to charge a rate of interest not exceeding 11 per cent on term loans to small scale industrial units, road transport operators and small-units in specified backward areas. The ceiling rate of 11 per cent was also applied to term loans to agriculturists for what is defined by the ARDC as "diversified purposes," while in respect of term loans for minor irrigation and land development, the maximum rate was set lower at 10.5 per cent. These rates were made applicable for all new loans (granted after January 1, 1978), with maturity of not less than three years in the respective categories regardless of whether any refinance facility from the IDBI and the ARDC was actually utilised. A special refinance facility from the Reserve Bank was made available at the Bank rate for all small direct agricultural loans, individually not exceeding Rs. 2,500. All types of credit in this category, granted after January 1, 1978, irrespective of the term of the loans, were eligible for refinance upto 50 per cent of the total advance through this "small farmers window" ; it was also directed that all such loans, regardless of whether the refinance was actually used or not, were to be charged a rate not exceeding 11 per cent.

Lowering of Lending Rates

65. A more comprehensive reduction of banks lending rates was announced simultaneously with the Central budget. This step, which brought credit measures in line with the fiscal policy of improving investment climate and reducing the cost of production, included several features. In the first place, the maximum lending rate, first specified in March 1976 at 16.5 per cent, was reduced to 15.0 per cent. While formerly smaller banks (with demand and time liabilities of Rs. 25 crores to Rs. 50 crores) had been allowed a higher maximum rate and the smallest group of banks (with demand and time liabilities of less than Rs. 25 crores) had been totally exempted from the ceiling, these concessions were withdrawn and the smallest bank group alone allowed a higher maximum rate of 16 per cent. Another feature was the application of the maximum rate of 15-16 per cent to advance against sensitive commodities subject to selective credit controls, formerly exempted from the ceiling. Thus, the maximum lending rate was not only lowered but made more widely applicable. Further, to ensure the percolation of the benefit of the withdrawal of the tax on interest income of banks announced in the budget, the Reserve Bank directed banks to reduce their lending rates generally by about 1 per cent, and where such reduction meant a revised rate marginally below the minimum lending rate of 12-1/2 per cent, the Reserve Bank had to be informed. Banks were also advised to compound interest rates on advances at no greater frequency than on a quarterly basis.

66. Downward adjustments were also made in some other lending rates. The rate charged on credit for public food procurement and distribution was reduced from 12 per cent to 11 per cent. Consequently, the rate at which the Reserve Bank provided refinance for food credit was also cut from 10 per cent to 9 per cent. The rate of interest on export credit, as also that for the refinance provided against such credit, was reduced by 1/2 per cent. The rate on export credit on deferred payments basis remained unchanged at 8 per cent as also some other rates, such as those on the loans to priority areas announced earlier in December 1977.

Revision of Deposit Rates

67. Simultaneously with the reduction in lending rates, some revisions were also made in the deposit interest rates. This was necessary for maintaining a balance in the overall structure of bank interest rates and the resultant impact that the lowered ceiling on lending rates would have on the earnings of banks. This was a consideration of some importance as the surplus available to banks for strengthening their reserves was already low. With the relative stability in prices, there was also an increase in interest rates in real terms. A lowering of deposit rates was hence effected. The rate on deposits of 5 years and over, which earn the highest interest rate and which formed about one fifth of the total deposits of banks, was reduced from 10 per cent to 9 per cent. In other fixed deposit categories, the reduction was by 1/2 percentage point. The rates on deposits for maturities between 91 days and 3 years remained unchanged. The deposit rate revision was also in line with the encouragement given through fiscal policy measures to the flow of savings to the capital market. In keeping with the instructions regarding the charging of interest at quarterly rests for interest on bank loans, interest on bank deposits is also to be calculated no more frequently than quarterly, reducing further the cost of funds for the banks.

68. In respect of savings deposits, the distinction introduced in July 1977 between deposits with and without cheque facilities was dropped in view of operational difficulties experienced by banks in the segregation of accounts, and a single rate of 4.5 per cent made applicable to both. A limit was also prescribed to the extent of cheque facilities available to savings bank deposits. Scheduled commercial banks having deposits liabilities below Rs. 25 crores and Regional Rural Banks were allowed to pay 0.25 per cent and 0.50 per cent more respectively on savings deposits and fixed deposits upto 5 years. Scheduled co-operative banks, central co-operative banks and primary (urban) co-operative banks, were also allowed to pay on savings and fixed deposits 0.25 per cent, 0.50 per cent and 1.0 per cent more respectively, than the prescribed interest rates payable by commercial banks with demand and time liabilities of Rs. 25 crores and above.

69. The reduction brought about in the structure of bank lending rates was quickly followed by changes in other rates. Term lending institutions also effected a corresponding reduction, and companies accepting deposits genrally tended to reduce their rates to maintain the differential with bank deposit rates. The Indian Banks' Association effected a reduction in the ceiling rate of interest on call money from 10 per cent to 8-1/2 per cent. The Reserve Bank also announced a reduction from 12 per cent to 10 per cent in the ceiling rate of interest on participation certificates and on bills rediscounted with banks and other approved financial institutions.

70. An adjunct to the general reduction of deposit interest rates was a readjustment in the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme. With effect from March 1, 1978, only two categories of deposits are accepted or renewed under the cheme. These are, deposits for 1 year and above upto 3 years with interest at 6 per cent, and deposits above 3 years and upto 5 years with interest at 7-1/2 per cent. Deposits of below 1 year and over 5 years are no longer available under the Scheme.

Adjustment in Refinance

71. As the symptoms of excess liquidity in the system become more evident, the Reserve Bank sought to restrain the expansionist monetary potential without, at the same time, eroding the position taken regarding the encouragement of investment. In this context, the restrictionary steps taken related in the main to the potential availability of Reserve Bank accommodation. In May 1978, it was announced that refinance for food credit would be available only when the outstanding of the total credit for public food procurement and distribution stood at Rs. 2,000 crores, as against Rs. 1,500 crores hitherto. Secondly, the facility of automatic refinance available to banks upto a level of 1 per cent of their demand and time liabilities was withdrawn, and such refinance was placed on a discretionary and temporary basis. It may be recalled that even in June 1977, the automaticity of availment of this facility had been somewhat affected by the stipulation that it would be available only against Government and other approved securities, which would thus become encumbered and ineligible for the statutory liquidity ratio.

72. Another step taken at this time had the objective of neutralising the impact on money supply of inflow of foreign remittances under the two special schemes. Banks were directed to deposit with the Reserve Bank, in terms of rupees, the equivalent of one-half of the net aggregate amount received after June 1, 1978 under the Non-Resident (External) Rupees Account and the Foreign Currency (Non-Resident) Account Scheme. The amount so deposited with the Reserve Bank would be paid interest at 6.5 per cent. The interest on banks' additional cash reserves above the statutory minimum of 3 per cent and the incremental reserve of 10 per cent was also raised from 6 per cent to 6.5 per cent.

Special Refinance Scheme

73. As a measure to encourage the imports of capital goods, the Government has formulated a special scheme whereby importers can seek term loans for the rupee equivalent of the import cost from any scheduled commercial bank and/or any national level term lending institution. The period of the loans will ordinarily not exceed 10 years and the rate of interest is presently prescribed at 11 per cent. To lend support to this policy, the Reserve Bank announced in April 1978 a special refinance scheme whereby banks providing such loans would be entitled to full refinance at the Bank rate.

Refinance to Co-operatives

74. The concessional element in the refinance facilities provided to State Co-operative Banks was enhanced with effect from March 1978. The rate charged on the credit channelised for medium-term agricultural purposes provided at 2-1/2 per cent below the Bank rate, as against 1-1/2 per cent previously. The rate on the credit for financing seasonal agricultural operations was also reduced from 2 per cent below the Bank rate to 3 per cent below the Bank rate. The benefit of these reductions, as also the gains accruing to

scheduled co-operative banks from the abolition of the Interest tax by the Government and the reduction in deposit rates, is expected to be passed on to the ultimate borrowers, particularly in the weaker sections.

75. As a part of measures for reducing the cost of credit to the ultimate borrowers, the rate of interest on refinance to State Co-operative Banks for financing industrial co-operative units (other than weavers) engaged in twenty two broad groups of cottage and small-scale industries was reduced from the Bank rate to 1-1/2 per cent below the Bank rate in August 1977 and further to 2-1/2 per cent below the Bank rate in March 1978. In line with this policy, it was also decided to extend Reserve Bank refinance, at 3 per cent below the Bank rate to primary agricultural credit societies (PACS), farmers service societies (FSS) and large-sized multi-purpose societies (LAMPS) for financing rural artisans engaged in weaving or in any of the twenty-two specified broad groups of cottage and small-sacle industrial activities.

Gold Sales

76. The price of gold in the domestic market, which was ruling high for sometime, began to soar in the latter half of 1977, touching Rs. 724 per 10 grammes. (Bombay market), in April 1978. International prices of gold had also been increasing, but less sharply. In view of the scope price differentials present for smuggling activities, the Government decided to undertake sales from its stocks of gold. It was also envisaged that such sales would reduce the monetary impact of the budget deficit. The sales are through auctions conducted by the Reserve Bank on a fortnightly basis and the first of the series was held on May 3, 1978. Sealed tenders are invited for every auction from the licensed dealers, and the auctioned gold is in bars of 100 grammes with .995 fineness. The stipulated minimum and maximum for bids were initially 1000 grammes and 5000 grammes respectively but were changed to 500 grammes and 2500 grammes from the fourth auction of June 14, 1978. Bidders are required to specify the quantity and prices acceptable to them, and each dealer is allowed only one bid. With effect from the fourth auction, upto five dealers and/or certified goldsmiths are also allowed to submit joint bids and to authorise one among themselves to take delivery of the gold.

77. In the five gold auctions held upto the end of June 1978 a total quantity of 6.40 tonnes of gold (valued at Rs 40.94 crores) was sold at prices ranging from Rs. 620 to Rs. 675 per 10 grammes. The number of bids received increased sharply from 429 for the first auction to 1,369 for the auction held on June 28. The total number of bids accepted in the five auctions was 3,688*. To achieve the purpose of the auctions the re-sale of gold purchased in the auctions to other dealers has been banned.

Assessment and Prospects

78. The economic situation at the close of the year 1977-78 presents a mixed picture. In one sense, against the backbround of substantial growth with price stability in 1977-78 and even greater reserves of food and foreign exchange at the end of the year, the economy has acquired an unprecedented degree of resilience. The Central budget and the Annual Plan for 1978-79 anticipate a considerable increase in public developmental outlay; and this should have a salutary effect on investment in general. On the other hand, viewed in a somewhat longer-term perspective, some uncertainties regarding the prospects for further progress with stability still remain.

79. Primarily, as the rate of increase of agricultural production may be difficult to sustain, the growth of the economy could slacken. Apart from climatic factors, the structural weaknesses in our agriculture and the uneven spread of the new technology may constrain growth of agricultural production. A decentarilsed pattern of growth centred on small farms assumes an administrative, marketing, credit and extension infrastructure at the district and village levels, which has just begun to take shape. It cannot, therefore, be taken for granted that the process of agricultural growth has become substantially self-sustaining.

80. The effect on prices of any sluggishness in agricultural production in the immediate could be countered through timely and appropriate releases from the buffer stock of food and with imports. However, the depressing effect of less favourable agricultural harvests on some industries, capacietly those dependent on the products of agriculture, would still remain, as also the resultant lower incomes of the concerned farming communities. Fortunately, the course of the monsoon so far augurs well for the 1978-79 kharif crop.

81. There are already signs of a modest pick-up in investment and activity in general, and the immediate outlook for industry holds the possibility of a revival. However, even as the tempo of industrial production begins to pick up with some revival of demand, the constraint of power would come to be more keenly felt. This is an area requiring immediate attention. While the draft Plan accords importance to increase in power generation capacity, there is no alternative in the short run to ensure fuller and more efficient utilisation of the existing capacity.

82. The developmental strategy now envisaged involves a more deliberate change in the structure of the economy, by decentralisation and a bias towards the rural and small-scale sectors, which change can only be realised over a period of time. In implementing these policies, problems relating to inadequacies in infrastructural facilities and marketing arrangement are likely to arise. To ensure progress, therefore, prompt action to resolve these difficulties would be needed.

83. Notwithstanding these uncertainties, the accumulated food stock and foreign exchange resources do offer an unique opportunity for making a discernible dent on the extreme poverty in the country over the immediate months ahead. Neither of these two resources can be considred abundant or even large, in the context of the size and the structure of the economy, and the levels of living standards of a country like India. At the same time further accretions to stocks, even if relatively small, may pose fresh problems, apart from representing a waste of opportunities.

84. The present food stocks of about 19 million tonnes are large for the purpose of merely meeting the requirements arising from unfavourable seasonal conditions. The off-take from stocks of around 12 million tonnes in the current year is also not adequate for a desirable turnover. Meanwhile, as more price support purchases are made with rising supplies, food stocks increase. Given the drive towards increasing agricultural output at a rapid pace, support for agricultural prices would be necessary to give stability to production and to prevent the terms of trade between agriculture and industry moving to the detriment of the former. For enabling agriculurists to benefit from these policies, it would also be necessary to improve the efficiency of the distribution system and to stimulate institutional changes conducive to a more efficient use of the agricultural inputs that have now become available. However, if the policy of raising agricultural prices continues without the organisational changes, on the ground that cost increases need to be matched, it may prove counter-productive.

85. Additions to food stocks also involve several problems. A serious bottleneck could develop in respect of storage capacity if stocks should rise further, because the storage capacity—already inadequate and sub-standard—cannot increase in the shortrun. There is also the question of serious deterioration of the stocks with time. Another problem relates to finance. At the peak level reached so far, bank credit for public food procurement amounted to Rs. 2,590 crores in July 1977 (19 per cent of total bank credit), and even now it is around Rs. 2,500 crores (or 16 per cent). A crucial point in regard to the pre-emption of such a significant part of the resources of the banking system of food stocks is that investment in food stocks as, in any other stocks, while necessary up to a point, displaces other productive forms of investment. But by the same token, it does not follow that a mere reduction in food stocks will lead to an increase in such investments. This would depend on how food stocks are

*In the two auctions held in July 1978, a total of 2.97 tonnes of gold was sold at prices ranging from Rs. 641 to Rs. 655 per 10 grammes. This brings the total gold released through auctions so far to 9.37 tonnes valued at Rs. 60.10 crores. None of the 1,823 bids received at the eighth auction for sale of gold held on August 8, 1978 were accepted by Reserve Bank as they did not come up to the reserve price.

deployed or get utilised—and what is happening to the creation and exploitation of investment opportunities in the economy in general.

86. Food stocks could, in fact, be productively deployed in developing the rural sector. A small beginning has been made in this direction with the 'food for work' programme. The totality of the ambitious programmes for rural development and rural industries, if vigorously implemented, would significantly increase the incomes of the weaker and vulnerable sections of society—and consequently the demand for food. But this requires considerable strengthening of administrative and other over-heads. These weaknesses must be removed as a matter of highest priority as otherwise a host of new problems, as already mentioned, will arise and will have to be tackled. In particular, the public distribution system, at present predominantly urban biased, will need to be strengthened and broad-based.

87. The foreign exchange reserves are at present equivalent to about 9 months' import payments. Although import capability of 4 months is generally considered a reasonable norm for reserves, the susceptibility of Indian agriculture to sharp fluctuations in output and the effect of these fluctuations on the economy underline India's need for a somewhat higher level of foreign exchange reserves. Even so, several steps have been taken for a liberal and purposive use of these resources for strengthening the economy. For these measures to have the desired effect on industrial growth and price stability, it will be necessary to persist on a liberal path and to maintain a continuity of approach also regarding imports of raw materials and consumer goods.

88. In the present situation it is essential to ensure that there is no slackening of export efforts. The export orientation, carefully built-up over the years, needs to be sustained even while selectively improving the cost effectiveness of exports. Although the concept of "export-led growth" is inapplicable to a large and diverse economy like India's, a continued and significant increase in exports remains vital, not the least because exports are very significant for certain industrial groups, for countering incipient sickness and from the point of view of sustaining employment regionally as well as nationally. Exports also must continue to grow, if over the long run we are to ensure a reasonable comfort in external payments. Any complacency in this area, generated by the sharp increase in foreign exchange reserves over a relatively short period of two years, should be quickly dissipated by the considerable slowing down of the gain in reserves in recent months, and the remainder that we still rely on external assistance to a considerable extent.

89. An important prerequisite of sustained growth, with improvement in distributive justice, is a reasonable stability of prices. A close alignment between movements in supplies of wage goods and movements in overall demand needs to be attempted for fostering price stability. The new plan strategy, with its emphasis on rural development, small industries and tiny factories, implies sizeable investment on several elements of infrastructure such as power, irrigation, roads and communications. This would make for substantial additions to money supply, and consequently to potential demand, without concomitant spontaneous increases in the supply of wage goods. This and other investments would also require larger imports and draft on foreign exchange reserves.

90. The scope for adjustment of monetary policy to further aid development has to be judged in relation to the present monetary situation. The rate of increase in money supply over the past three years has averaged 15.6 per cent. This pace of expansion cannot, obviously, be sustained without inflationary implications, even under the most favourable conditions for the growth of real output. There is hence little economic justification for slackening credit restrictions or for the provision of incentives such as the further lowering of interest rates. The availability of bank credit at unduly low rates of interest could lead to the adoption of capital intensive techniques of production where these are not warranted, resulting in a reduction in additional employment opportunities. Furthermore, low rates of interest could also affect the viability of banks.

16, 1977, the Bank purchases forward sterling on monthly carefully fashioned to encourage and support the growth of the economy and the structural changes needed for such growth, while promoting reasonable price stability. Increases in aggregate investment and other developmental outlays may not be expected to be matched in time and quantum by the growth of supplies of wage goods. To deal with resultant inflationary pressures, monetary restraint will necessarily have to continue.

II. OTHER DEVELOPMENTS

92. In the sphere of Exchange Control, the important developments during the year were : the simplification and liberalisation of some of the requirements of Form 'P', extension of Foreign Exchange Regulation Act to Sikkim, incentives granted to non-resident Indians and persons of Indian origin abroad to repatriate their foreign currency holdings to India on their return to India for permanent settlement and trade transaction with China.

Foreign Exchange Release for Students going Abroad for Higher Studies

93. The minimum marks criterion for release of exchange to students proceeding abroad for higher studies has been reduced from 60 to 55 per cent in the qualifying examination effective August 1, 1977. In case of students belonging to Scheduled Castes and Tribes, this limit is further reduced to 49.5 per cent.

94. The Maintenance, Initial equipment and Pre-Session allowances have been increased as under (earlier scale is indicated in brackets) with effect from August 1, 1977.

	USA/Canada	UK	Other countries
Maintenance Allowance	US $ 4000 (US $ 3000) p.a.	US $ 3000 (£ 1300) p.a.	US $ 3000 (US $ 2600 p.a.
Initial Equipment Allowance	US $ 300 (US $ 250)	US $ 250 (£ 100)	US $ 250 (US $ 200)
Pre-Session Allowance	US $ 165 (US $ 105)	US $ 120 (£ 55)	US $ 120 (US $ 110)

95. In addition, exchange for tuition fees is released on the basis of actuals as certified by the foreign institutions.

Purchase and Sale of Foreign Currencies by Reserve Bank of India

96. Under the new procedure governing forward purchases of the Pound Sterling, U. S. Dollar, Deutsche Mark and Japanese Yen from authorised dealers introduced from August 16, 1977, the Bank purchases forward sterling on monthly option basis (instead of quarterly basis) from the first to the ninth month, for delivery on any day of the month for which the option has been given. One or more extensions are permitted in respect of forward purchase contracts in Pound Sterling on payment of a charge of £ 0.0075 per Rs. 100 per month on the contracted rate. Extension beyond twelve months from the contract date are not permitted. In respect of the U. S. Dollar, Deutche Mark and Japanse Yen, forward purchases are made only upto six months, on a monthly option basis. Extension of forward contracts in those currencies other than Pound Sterling are not permitted. The facility of spot and forward purchases of U. S. Dollars, Deutche Marks and Japanese Yen has also been made available to authorised dealers at the Bank's offices at Calcutta, Madras and New Delhi with effect from September 1, 1977 in addition to the Bombay office.

Surrender of Foreign Currency Balances

97. The obligation to surrender to an uthorised dealer, foreign exchange held/owned by persons in or resident in India has been extended with effect from June 15, 1977 to all currencies other than the currency of Nepal and Bhutan.

Extension of Exchange Control to Sikkim

98 The Foreign Exchange Regulation Act, 1973 was extended to the State of Sikkim with effect from Sepember 1, 1977 Accordingly, every person resident in Sikkim (other than foreign nationals temporarily resident there) who owned any foreign exchange or foreign securities or immovable property outside India had to declare to the Reserve Bank of India particulars of all such holdings before November 1, 1977 Further, the holders of foreign currency balances, barring certain exempted categories were required to surrender such balances to an authorised dealer on or before December 1, 1977.

Blocking of Assets of Emigrants

99 Under the Exchange Control Regulations, assets in India of Indian nationals as well as of persons of non-Indian nationality permanently resident in India, who emigrated or had emigrated to a foreign country were treated as blocked The assets of such emigrants should not be blocked, but allowed to be kept in ordinary non-resident accounts irrespective of whether the emigrant has been granted exchange facilities or not It has also been decided to de-block effective September 29, 1977 all the accounts of persons who have emigrated out of India in the past and treat them as ordinary non-resident accounts.

Release of Exchange to Export Houses

100 Export houses holding Export House Certificates issued by the Ministry of Commerce are eligible since October 1977 for release of blanket foreign exchange by the Reserve Bank for promotional activities to the extent of 2 5 per cent of the f o b value of their exports during the previous year subject to a maximum of Rs 1 lakh They may also avail of foreign exchange release in excess of Rs 1 lakh but not exceeding their overall entitlement of 2 5 per cent of f o b value of exports against surrender of their REP entitlements for equal amount The blanket release may be used for purposes such as (i) deputation of sales or sales-cum study teams abroad, (ii) publications for use abroad, including journals, brochures, pamphlets, folders etc for brand publicity of products of the Export House, (iii) brand publicity projects through advertisements in newspapers and periodicals abroad or through other useful media, (iv) expenditure in connection with participation in exhibitions abroad and display of exhibits in show rooms abroad and (v) cost of import of testing equipment, and spares and machinery, duly cleared from indigenous angle and considered essential for setting up common servicing centres This release is in addition to the blanket permits issued by the Bank in the normal course.

Exchange Entitlement Scheme for Returning Indians

101 In order to provide an incentive to non-resident Indians and persons of Indian origin to repatriate their foreign currency balances to India on their return to the country for permanent settlement, a scheme entitled 'Returning Indians Foreign Exchange Entitlement Scheme' has been introduced with effect from November 1, 1977 whereby exchange is released to such persons for certain specified purposes for which exchange is not otherwise freely available The foreign exchange entitlement under the Scheme is computed at 25 per cent of the foreign exchange remitted or brought in by such persons through normal banking channels on transfer of residence. In addition, balances in their rupee non resident (external) accounts and ECNR accounts are taken into account for the purpose Foreign exchange released under this Scheme can be utilised by such persons for purposes like (a) travel abroad for personal reasons by the person, his or her spouse, and dependant children, (b) medical treatment abroad for the person, his or her spouse, and dependant children; (c) foreign education of dependant children or wards of the person, (d) gift remittances to close relatives, permanently resident abroad, on occasions such as birthdays religious festivals, and weddings, (e) import of special appliances for professional use, subject to compliance with import licensing formalities The exchange under this Scheme should be utilised within a period of ten years from the date of return of the applicant to India.

102 With effect from November 1, 1977, residents of India who have not visited any place outside India during a period of two years prior to the date of commencement of the proposed journey are eligible to undertake a foreign trip under FTS, 1970 (visits to Sri Lanka, Bangladesh, Maldives, Mauritius and Seychelles otherwise than under FTS are not counted as foreign visit for this purpose and all visits to Nepal also not be taken into account for determining a person's eligibility for travel abroad under FTS) Also, the amount of exchange available under the Scheme has been increased to U S $ 500 or its equivalent irrespective of the carrier on which the journey is undertaken The foreign exchange entitlement has been made available also to those travellers holding free or rebated tickets given by the airline/shipping companies, including the staff of such companies, provided they are eligible to undertake a journey abroad under the FTS

103 In order to further simplify the procedure for availing of the Foreign Travel Scheme, an order has been issued on November 18, 1977 and came into force from December 1, 1977 Under this order, the intending traveller may submit the declaration in the prescribed form together with his current passport to any one of the notified branches of a designated authorised dealer in foreign exchange for verification and obtain confirmation about his eligibility to undertake a journey abroad As on December 1, 1977, ten major public sector banks have been designated to deal with the work through their specified branches in important towns in India Effective May 1, 1978, certain designated branches of nationalised banks excluding subsidiaries of State Bank of India, have been delegated powers to issue eligibility certificates under the revised Foreign Travel Scheme

104 With effect from January 1, 1978, the Foreign Travel Scheme has been further liberalised An Indian can now undertake foreign trips in alternate years and all foreign trips other than under the FTS and under the orders issued on November 18, 1977, being ignored for determining a traveller's eligibility for a foreign trip under the liberalised scheme. Consequently, the Government officials and company executives who have to travel abroad frequently on official or business grounds can now avail of the FTS Further, the date of arrival from the previous foreign trip is not relevant as hitherto, but the date of departure of the previous foreign trip under the FTS is now taken into account for determining a traveller's eligibility.

Rupee Drawings by Overseas Banks

105 Where rupee drawings are made by overseas correspondents of the authorised dealers on offices and branches of authorised dealers in India, other than the one where the non resident rupee account is maintained the paying offices/branches claim reimbursement from the central account maintained at the Head Office or area office as the case may be. The latter office provides reimbursement on receipt of the claims except where the practice of the overseas banks is to issue drawing advices on receipt of which funds are set apart in advance for meeting the payments The inevitable time-lag in the paying branches making claim and obtaining reimbursement from the account maintaining office lends scope to the overseas bank enjoying overdrafts with the authorised dealers in India in a concealed manner Besides, such time lag in reimbursement may also leave room for the overseas banks to speculate in the currency and delay remittance of cover funds if the outlook for the rupee vis-a-vis the funding currency is favourable In order to discourage such tendencies, some authorised dealers have been levying a payment commission on such drawings from their correspondents or resorting to value-dating so as to give effect to the payments in the books of the account maintaining office as if they were made at that office on the dates on which they were actually paid to the beneficiaries However, due to the acute competition arising from large remittances to India, some authorised dealers are often forced to waive the payment of commission or give up value-dating Thus, concealed overdrafts go uncompensated or the funding is delayed either of which causes foreign exchange loss In order to put an end to unhealthy competition among authorised dealers which lends scope to their overseas correspondents and branches to avail of concealed overdrafts in India, the Reserve Bank has directed effective September 1, 1978 all the authorised dealers to take any one of the following measures · (a) Overseas correspondents should be asked to issue drawing advices as and when rupee drafts/payment orders are issued on offices and branches of authorised dealers in India, other than the office or branch at which the non-resident rupee account of the drawing bank is main-

tained. On receipt of such drawig advices, funds should be set apart by the account to meet the reimbursement claims from the outlying offices in due course. (b) Authorised dealers should adopt 'value-dating' as a system of accounting for such payments or introduce other internal monitoring or communication systems to ensure that the payments are reimbursed from the central accounts on the dates of actual payment to the beneficiaries. (c) If either of these measures is not feasible, authorised dealers should charge the overseas drawing banks with a payment commission to compensate for the fund outlay at a rate not lower than 0.15 per cent on the amount of the drawings (with a minimum of 50 paise per drawing) regardless of the level of balances actually held in the central rupee accounts.

106. These directions are also made applicable to rupee drawings by overseas branches of Indian banks as well as overseas Head Office/branches of foreign banks.

Reserve Bank's Rates for Purchase and Sale of Pound Sterling

107. The Reserve Bank's buying and selling rates for Pound Sterling have been revised with effect from May 24, 1978 as £ 6.5359 (spot and £ 6.4935 (spot) per Rs. 100 respectively, middle rate being £ 1=Rs. 15.35.* Rates for forward purchases have also been revised by adding a difference of £ 0.0050 per Rs. 100 per month on the spot buying rates.

108. Authorised dealers have been delegated certain powers to effect the following types of remittances without reference to the Reserve Bank :

(1) Remittances of Commission.—Subject to certain conditions, the payment of commission to selling agents abroad on exports from India by deduction from the bill proceeds, or by deduction on the invoice upto 5 per cent if the irrevocable letter of credit provides for such payment.

(2) Sundry remittances.—(i) The limit of remittance upto US $ 500/- or its equivalent towards advertisements abroad on behalf of established exporters has been raised to US $ 1000/- or its equivalent in any calendar year.

(ii) Cost of tender documents.—Authorised dealers are permitted to remit the actul cost of tender documents/registration fees irrespective of the value involved provided the remittances are made in favour of the tender inviting body or its duly authorised agent abroad or the Embassy, Consulate or any other Diplomatic Mission maintained by Government of India in the country concerned.

(iii) Charges for translation of tender documents.—Authorised dealers can effect remittances upto US $ 100/- or its equivalent towards translation charges at any one time on behalf of their exporter constituents provided the beneficiary of the remittance is an Embassy, Consultate or any other Diplomatic or Trade Mission maintained by the Government of India.

(iv) Export information.—Authorised dealers can effect remittances upto US $ 50/- or its equivalent at any one time on behalf of their exporter constituents to overseas trade associations, Chambers of Commerce, Government Departments or Government-owned organisations towards actual cost of supplying such information.

(3) Export of gift parcels by post/airfreight.—Authorised dealers can issue to their constituents on application, the required certificates in respect of the export of gift parcels for value not exceeding Rs. 500 subject to certain conditions.

(4) Import of Samples.—In terms of the current import policy (1978-79), import of samples is allowed without import licences in cases where (a) the value does not exceed Rs. 500; (b) import is made by post parcel or by air-freight; (c) the importer is a registered manufacturer-exporter.

Authorised dealers can open letter of credit/make remittances on behalf of their customers who are registered manufacturer-exporters for such imports of samples.

(5) Private Imports.—Authorised dealers can make remittances against private imports made by post or otherwise by any individual or institution or hospital for his/its own use of any goods other than certain banned categories, subject to certain conditions.

Private Imports from Pakistan

109. Authorised dealers can effect remittances to Pakistan towards private imports as in the case of imports from other countries.

Trade with Hungary

110. Trade between India and Hungary is conducted in convertible currency with effect from January 1, 1978. Consequently Hungary has ceased to be a country in the Bilateral Group and has been placed in the External Group.

Indo-Polish Trade Agreement

111. The Government of India and the Polish People's Republic have concluded a new Trade and Payments Agreement valid for a period of three years effective January 1, 1978 under which payments in respect of all commercial and non-commercial transactions between the two countries continues to be settled in non-convertible Indian rupees.

Trade and Payment Transactions between India and DPRK

112. The Government of India and the Democratic Peoples Republic of Korea (North Korea) have concluded a new Trade and Payment Agreement in terms of which all trade and payment transactions between the two countries from March 1, 1978 onwards are settled in free convertible currency. Consequently North Korea has ceased to be a country in the Bilateral Group and has been placed in the External Group.

Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme

113. Consequent on the lowering of the interest rates on deposits held in rupees with effect from March 1, 1978 the rates of interest on fixed deposits under the FCNRA Scheme were revised and brought on par with the rates applicable to rupee deposits.

Blanket Exchange Permits

114. In order to make the blanket permit facility available to small exporters, the annual export turnover limits have been revised downwards. The limits for annual export turnover for 'Select List' goods and net annual foreign exchange repatriation from out of overseas construction contracts have been reduced from Rs. 15 lakhs to Rs. 10 lakhs. The annual export turnover for 'Non-Select List' goods has been reduced from Rs. 75 lakhs to Rs. 50 lakhs. The minimum allotment under the Blanket Permit Scheme has also been raised from Rs. 40,000 to Rs. 75,000. These changes are effective from April 5, 1978.

'P' Forms for Travel Abroad

115. For simplifying and liberalising some of the requirements for obtaining a 'P' form the following changes have been made with effect from April 11, 1978 :

(i) Students who wish to proceed abroad for studies with hospitality offered by persons who are distant relatives or friends are eligible for 'P' form clearance. Earlier, passage clearance was granted subject to certain conditions only to students proceeding abroad for studies on the guarantee of financial support by their close relatives.

(ii) The following relatives viz., grand-son, grand-daughter, son's/daughter's parent-in-law and first cousin of the traveller (or his/her spouse), have been added to the list of close relatives resident abroad against whose undertaking of hospitality, the travellers are eligible for 'P' form clearance.

(iii) Under the scheme for 'P' form clearance to persons going abroad on the hospitality of a relative not falling in the approved list or a friend on the basis of letter of invitation received from the sponsor, travel is permissible even if the passage fare is not remitted to India, but paid to the agents/offices of the carrier abroad and a Prepaid Ticket Advice (PTA) issued. Such PTAS are acceptable irrespective of the carrier.

*These rates have been further revised as £ 6.4516 (spot) and £ 6.4103 (spot) per Rs. 100 respectively, middle rate being £ 1-Rs. 15.55 with ecect from July 31, 1978.

Trade Transaction with China

116. Consequent upon resumption of trade between India and China (excluding Tibet Region), exports can be made to China (excluding Tibet Region) subject to compliance with the normal GR/PP form procedure. Authorised dealers can open letters of credit and make remittance towards imports from China (excluding Tibet Region) in conformity with the regulations. Remittances towards charges directly connected with exports viz. commission on exports, controlling charges, exports claims, cost of tender documents and legal/sundry expenses on export bills etc. may also be made in conformity with the regulations as applicable to such remittances. Authorised dealers can also issue guarantees on account of India's trade with China in conformity with the regulations. All other remittances to China and all other transactions with persons, firms and banks resident in China or nationals of China continue to be prohibited. In regard to approved methods for payments to and receipts from China, China is deemed to be included in the External Group of countries.

Progress of Indianisation of Foreign Companies

117. Since the Foreign Exchange Regulation Act came into force on January 1, 1974, applications have been received from 881 foreign companies and Indian companies with more than 40 per cent non-resident interest for permission

Notes : (i) Effective August 7, 1978, no prior approval on Form 'P' is required in case of residents of India going abroad to any destination. But a modified 'P' form is required to be completed for record purpose. Even this is not required in cases where no passage fare payment in rupees is involved such as travel undertaken on free tickets, PTAs and tickets issued outside India. Passage fare ceiling has also been abolished.

(ii) Exchange bureaux and authorised money changers can now sell foreign currency notes/coins upto the equivalent of Rs. 200/- to all travellers going abroad except Nepal, Bhutan and Bangladesh and equivalent of Rs. 100/- only to those going to Bangladesh.

STATISTICAL DATA FOR THE PERIOD JULY 1977 TO JUNE 1978

I. FRESH PERMITS ISSUED FOR STUDY/TRAINING ABROAD

Country	Technical Courses		Non-Technical Courses	
	Number of Students/ Trainees	Amount of exchange released (Rs. 000's)	Number of Students/ Trainees	Amount of exchange released (Rs. 000's)
	July 1977 to June 1978	July 1977 to June 1978	July 1977 to June 1978	July 1977 to June 1978
U.K. and Europe	454	11558	432	3461
U.S.A. and Canada	716	21138	767	17822
Other Countries	1,36	2339	133	909
Total	**13 06**	**35035**	**1,332**	**22,192**

II. PERMITS ISSUED FOR TRAVEL ABROAD FOR PURPOSES OTHER THAN STUDY/TRAINING

	Number of persons covered by permits issued	Amount of exchange released (Rs. 000's)
1. Business	27,196	249200
2. Medical Treatment	305	9255
3. Study Tours	1,238	14531
4. Attendence at Conferences	1,976	10222
5. Miscellaneous	14,886	61037
Total	**45,601**	**344245**

III. 'P' FORM APPLICATIONS*

Purpose	No. of persons covered by 'P' Forms approved
1. Joining head of family	17,897
2. Visits to relatives	16,201
3. Export promotion	1,113
4. Employment abroad	88,915
5. Emigration for permanent settlement	14,624
6. Students/Trainees	2,320
7. Miscellaneous	20,726
Total	**1,61,796**

IV. FOREIGN TRAVEL SCHEME

No. of persons covered by approvals granted	**99,437**

*No exchange is released in such cases.

to continue their business activities in India in terms of Section 29(2) of the Act. Applications from 814 companies have been finally disposed of in accordance with the policy guidelines laid down by the Government. The balance of 67 cases are under consideration. These include 33 companies in the drug industry whose applications are being processed in the light of the Government's recent decisions on the Report of the Committee on the Drugs and Pharmaceuticals Industry.

118. Of the applications disposed of, 75 were from companies which did not require such permission, while 54 companies which had filed applications were in the process of winding up their affairs in India. In 66 cases, foreign equity had already been diluted to the required extent, and in 246 cases it was found that dilution was not necessary under the guidelines and the companies were granted permission to continue their operations in India without any stipulation regarding Indianiastion. Applications from 30 companies were rejected, either because the companies were not carrying on business for the past several years or because they were engaged in activities in which the continuance of foreign investment was not considered desirable.

119. Directives for the dilution of foreign enquity to the required level of 74 per cent, 51 per cent or 40 per cent (depending on the nature of the activities of the companies) were issued to 343 companies. Of these, the required dilution has been carried out in 83 cases and 80 other companies are in an advanced stage of compliance. In most of the remaining cases, the period allowed for dilution has not yet expired or the companies have already submitted proposals which are under examination. The other cases are being followed up.

Currency Chests

120. During the year, 191 currency chests/repositories were opened; of these 153 were operated by the State Bank of India and associate banks, 29 by other public sector banks and 9 by Treasuries/Sub-treasuries. The new currency chests were located in 25 State/Union Territories; of the total, 21 were opened in Kerala, 14 in West Bengal, 19 in Madhya Pradesh and 17 each in Punjab and Tamil Nadu.

121. At the end of June 1978, the total number of currency chests/repositories operating in the country was 2,609. Of these, 10 were operated by the Reserve Bank, 298 by Treasuries/Sub-treasuries, 2,161 by the State Bank group of banks and 140 by other public sector banks.

Demonetisation of High Denomination Notes

122. By an ordinance promulgated on January 16, 1978, currency notes in the denominations of Rs. 1,000, Rs. 5,000 and Rs. 10,000 were withdrawn from circulation. At the time of the demonetisation, the total value of high denomination notes in circulation was Rs. 145.42 crores. Of this, Rs. 64.94 crores was held by banks including the Reserve Bank and Government treasuries.

123. Since the promulgation of the Ordinance upto June 30, 1978, the high denomination notes tendered for conversion to the Reserve Bank amounted to Rs. 124.45 crores. Of this, the total amount declared by banks and treasuries was of the order of Rs. 64.94 crores. Of the total amount of Rs 124.45 crores tendered for conversion, the amount passed by the Bank for exchange in lower denomination notes was Rs. 116.31 crores. This amount includes the sum of Rs. 60.21 crores exchanged in respect of notes declared by banks and Government treasuries (figures are provisional).

Report of the Study Group on Non-Banking companies—Fresh Directions to Financial and Miscellaneous Non-Banking Companies

124. It was stated in the last Report that in order to give effect to such of the recommendations of the Study Group on Non-Banking Companies as could be implemented within the existing framework of Chapter HIB of the Reserve Bank of India Act, 1934, two sets of directions were being issued to non-banking financial companies and miscellaneous non-banking companies. The directions contained in the Bank's notifications Nos. DNBC, 38 and 39/DG(H)77 dated June 20, 1977 came into force with effect from July 1, 1977. The salient features of the new directions are: (1) the definition of the term "free reserves" has been modified to include only those amounts which are in the nature of reserves but not provisions, and which have been appropriated out of earned profits including those received by the actual sale of assets but not through the revaluation of assets. (2) The maximum period for which deposits can be accepted by the companies has been restricted to 36 months in the case of all types of companies except housing finance companies in whose case the maximum period is 60 months. The minimum period, however, remains unchanged at six months in all cases. (3) Inter-company borrowings, which were completely exempt from the restrictive provisions of the earlier directions are now to be treated as deposits except in cases where such borrowings are restored to with the prior approval of the Reserve Bank of India. (4) The exemption in favour of secured borrowings has been withdrawn. Only borrowings in the form of bonds and debentures which are secured by mortage of immovable properties and such of the unsecured bonds/debentures as are convertible into equity shares will be exempt. (5) Deposits received by hire-purchase finance companies were not subject to ceiling restrictions earlier. These have now been brought within such restrictions. The companies can now accept deposits up to 10 times their net owned funds. (6) The ceiling available to investment companies has been reduced. They are required to bring down their aggregate deposits to 25 per cent of their net owned funds by April 1, 1979, in two stages. (7) In the case of premature repayment of deposits the rate of interest payable has been stipulated at 2 per cent lower than the rate which the company would have ordinarily paid had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run or for the nearest completed year. This accords with the provisions applicable to the commercial banks.

125. During the course of the administration of the new sets of directions it was noticed that there were certain companies which, while satisfying the definition of a 'financial institution' as given in section 45 I(c) of the Reserve Bank of India Act, 1934, could not be classified under any of the categories of companies specified in the directions as they were found to be carrying on more than one type of business specified in section 45 I(c) ibid, none of the types being their principal business. In order to cover such companies, the directions issued to financial companies were amended with effect from March 30, 1978 by insertion of a new paragraph. With this amendment the directions are comprehensive enough to cover all categories of companies which satisfy the definition of a 'financial institution' as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934.

126. Simultaneously with the coming into force of the revised sets of directions with effect from July 1, 1977, the Government of India, in consultation with the Bank, issued a set of Rules styled as "The Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies, Advertisement) Rules, 1977" for regulating the issue of advertisement by such companies. The Rules require the concerned companies to compulsorily issue advertisement in one English news paper and a vernacular newspaper in case they intend to invite or cause any other person to invite deposits from the public. A copy of the advertisement so issued is required to be filed with the Bank. The companies are required to furnish adequate particulars/information in the advertisement so as to enable the prospective depositors to have a clear picture of the financial position, management, etc. of the companies and also include in the advertisement certain declarations to enable the depositors to comprehend the legal implications of keeping deposits with such companies. Although the said Rules have been made under section 58A of the Companies Act, 1956, their administration will vest in the Bank, the question of delegating appropriate authority to the Bank's officials for filing complaints for violation of the Rules has been taken up with the Government of India.

Amendments to the Companies (Acceptance of Deposits) Rules 1975

127. The deposit-acceptance activities of non-financial companies are regulated by the provisions of section 58A of the Companies Act, 1956 and the Companies (Acceptance of eposits) Rules, 1975 made thereunder. It was stated in the last Report that the amendments to the Rules to implement the recommendations of the Raj Study Group were deferred by the Goverment pending amendment to the Act

to enable the Government to grant exemption/extension of time in cases of hardship. The Act was amended in December 1977 in consultation with the Bank, to confer powers on the Government to grant exemption/extension of time to a company or class of companies from the provisions of section 58A of the Companies Act, 1956. The Government is required to consult the Reserve Bank of India while exercising the powers in relation to a class of companies.

128. Subsequently, the Companies (Acceptance of Deposits) Rules have been amended with effect from April 1, 1978. In terms of the amendments, the ceiling in respect of deposits received by public companies from shareholders/deposits guaranteed by the directors in their personal capacity as also those against unsecured debentures will stand reduced from 15 per cent to 10 per cent with effect from April 1, 1979 and completely withdrawn from April 1, 1980. Thus, from that date, non-financial companies will be permitted to accept deposits of any kind up to 25 per cent of their net owned funds as against the present overall limit of 40 per cent.

129. Besides, the companies will be under an obligation to maintain liquid assets up to 10 per cent of the deposits which mature for repayment within a year (between April 1, and March 31) in the form of current or other deposits with a scheduled commercial bank free from any charge or lien or investment in any unencumbered securities of Central or State Government or any other trustee securities.

130. These companies will also be required to furnish additional particulars/information/decalartion in any advertisement issued by them so as to enable the prospective depositors to have a clearer picture of the financial position and management of the companies as also to comprehend the legal implications of keeping deposits with such companies.

Follow-up Action on the Other Recommendations of the Study Group on Non-Banking Companies

131. As reported earlier, the Bill for the banning of prize chits and money circulation schemes was finalised and has since been introduced in the Parliament.

132. Besides the above, a model Bill to regulate the conduct of conventional chit fund business throughout the country on a uniform basis as recommended by the Banking Commission and subsequently further examined by the Raj Study Group has been finalised having regard to the recommendations/suggestions received from various State Governments and other representative bodies. It is now being scrutinised by the Ministry of Law.

133. The drafting of the proposed comprehensive legislation for regulating the conduct of business by non-banking financial institutions is in progress.

Acceptance of Deposits by Unincorporated Bodies

134. The proposal for prohibiting the acceptance of deposits by unincorporated bodies from more than a specified number of depositors was dropped by the Government of India in view of certain legal impediments. The matter was reviewed in November 1977 by the Government of India in consultation with the Bank and the proposal has been revised. Accordingly, a comprehensive set of amendments to the Reserve Bank of India Act, 1934 for giving effect to the proposals were forwarded by the Bank to the Government of India and these have since been incorporated in the Banking Laws (Amendment) Bill 1978, which is expected to be introduced in Parliament shortly.

Deposits with Non-Banking Companies, 1974-75

135. The survey of deposits with non-banking companies for the year ended March 31, 1975 reveals that the total number of reporting companies increased during the year by 376 to 4,612. The aggregate amount of deposits/loans under categories exempted from the ceiling restrictions increased by Rs. 168.1 crores from Rs. 1,028.6 crores at the end of March 1974 to Rs. 1,196.7 crores at the end of March 1975. The deposits falling within the purview of the ceiling restrictions amounted to Rs. 498.3 crores while exempted deposit /loans accounted for Rs. 698.4 crores at the end of March 1975.

136. The aggregate deposits including exempted deposits/loans of 2,959 reporting non-financial companies stood at Rs. 754.3 crores as on March 31, 1975 as against Rs. 724.6 crores in respect of 3,048 reporting companies as at the end of the previous year. The deposits falling within the purview of the ceiling restrictions under the directions amounted to Rs. 393.6 crores.

137. As regards financial companies, the aggregate deposits including exempted deposits/loans of 1,653 reporting companies amounted to Rs. 443.4 crores as on March 31, 1975 as against Rs. 304.0 crores in respect of 1,188 companies as at the end of the previous year. The deposits other than those under exempted categories amounted to Rs. 104.7 crores Surveys.

138. During the year under review the Division of Field Surveys of the Economic Department conducted five surveys viz., (i) Field studies in respect of seven Regional Rural Banks (RRBs) at the instance of the Committee on RRBs set up by the Bank in June 1977. In addition, field studies in respect of five RRBs were conducted by the Regional Offices of the Economic Department. The Division also collected and processed the material required by the Committee and was associated with it throughout. The Report of the Committee was submitted to the Bank. (ii) In order to assess the extent of benefits derived from the public distribution arrangements of essential commodities by the weaker sections in the rural areas, a field survey in Ahmednagar district of Maharashtra was completed; the report is under preparation. (iii) A pilot survey on the working of two Agro-Service Centres in Pune district was conducted, the report is under preparation. (iv) The Division has finalised the preliminary work relating to the case studies undertaken at the instance of the Government of India to assess the impact of debt relief legislation in five selected districts. The field work relating to the first case study in Amaravati district of Maharashtra is completed; the report is under preparation. (v) The Division has also finalised preliminary work relating to the field study for assessing the implementation of district credit plans under the Lead Bank Scheme in three districts viz, Seoni (M.P.), Farukhabad (U.P.) and Jaisalmer (Rajasthan). The field investigation in Seoni has been completed. The report of the field study on the availability of short-term co-operative credit to borrowers of land development banks is being finalised.

139. The Division of Balance of Payments continued to call for quarterly reports from branches of foreign companies and Indian Joint Stock Companies for the Foreign Investment Survey. The returns for the Survey covering the year 1974-75 are being processed. The Survey of Unclassified Receipts, covering inward remittances of foreign exchange in amounts below Rs. 10,000 or equivalent for which no purpose-wise details are available, was initiated for the quarter April-June 1978. The report on a similar survey for the quarter January-March 1977 is under preparation.

140. The Banking Division continued to conduct various surveys relating to different aspects of the operations of commercial banks viz., advances and deposits, ownership of deposits, debits to deposit accounts, investments, etc.

Central Board

141. Shri M. Narasimham relinquished charge of his office as Governor of the Bank as at the close of business on November 30, 1977. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Shri Narasimham during his tenure as Governor of the Bank.

142. Dr. I. G. Patel was appointed as Governor of the Bank for a term of five years with effect from December 1, 1977.

143. Dr. R. K. Hazari relinquished charge of his office as Deputy Governor of the Bank on expiry of his term on November 26, 1977. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Dr. Hazari during his association with the Bank.

144. Shri M. Ramakrishnayya was appointed by the Government of India as Deputy Governor of the Bank for a term of five years. Shri Ramakrishnavya assumed charge of his office on January 2, 1978.

145. Shri C. Ramakrishna and Dr. K. Kanungo retired as Directors of the Central Board of the Bank on the expiry of their terms of appointment on July 22, 1977. The Board places on record their high appreciation of the valuable services rendered by the retiring Directors all through their association with the Bank.

146. On the reconstitution of the Local Boards on July 22, 1977, Prof. M. L. Dantwala and Shri M. V. Arunachalam were nominated as Directors of the Central Board of the Bank under Section 8(1)(b) of the Reserve Bank of India Act, 1934 to represent Western and Southern Area Local Board of the Bank respectively, and Shri A. N. Haksar and Dr. Bharat Ram were renominated on the Central Board under the same Section of the Reserve Bank of India Act to represent Eastern and Northern Area Local Boards, respectively. Shri M. V. Arunachalam was nominated vice Shri C. Ramakrishna. Sarvashri Jehangir P. Patel, S. L. Kirloskar, Air Chief Marshal P. C. Lal (Retd.) and Dr. B. Venkatappiah were nominated and Shri M. P. Chitale, Dr. D. P. Singh and Dr. V. Kurien were renominated as Directors on the Central Board of the Bank under Section 8(1)(c) of the Act with effect from July 22, 1977. The appointment of Dr. B. Venkatappiah was vice Dr. K. Kanungo.

147. Seven meetings of the Central Board were held during the year, out of which two were held in Bombay and one each, at Madras, Chandigarh, Calcutta, Jaipur and New Delhi. The Committee of the Central Board held 51 meetings, of which two were held in New Delhi, one in Calcutta and the rest in Bombay.

Local Boards

148. In terms of Section (1) of the RBI Act, 1934 the Government of India reconstituted all the four Local Boards of the Bank with effect from July 22, 1977. Prof. M. L. Dantwala was appointed on the Western Area Local Board *vice* Shri M. S. Padmanabhan, and Sarvashri C. Sri Krishna and N. S. Bhatt were appointed on the Southern Area Local Board *vice* Sarvashri C. Ramakrishna and M. K. Ramachandra, respectively, while the following members were reappointed under sub-section ()) read with sub-section (3) of Section 9 of the RBI Act, 1934.

WESTERN AREA

1. Shri K. C. Maitra
2. Shri Charles M. Correa

EASTERN AREA

1. Shri A. N. Haksar
2. Dr. Sadasiv Misra
3. Shri G. Saha
4. Shri G. C. Phukan

NORTHERN AREA

1. Dr. Bharat Ram
2. Shri K. N. Sapru
3. Shri Prem Pandhi
4. Dr. Rama Mohan Lall.

SOUTHERN AREA

1. Shri M. V. Arunachalam
2. Shri C. R. Ramaswamy

149. Shri F. Haque was appointed as member of the Western Area Local Board with effect from November 1, 1977.

150. Shri V.V. Divatia was appointed as Executive Director of the Bank with effect from August 25, 1977.

151. Shri W. S. Tambe was appointed as Executive Director of the Bank with effect from June 1, 1978.

New Office Premises

152. The structural work of the Bank's multi storeyed office building under construction in the compound of the India Government Mint at Bombay has been completed. Work relating to various subsidiary trades such as lifts, air-conditioning, etc. is in progress and the building is expected to be ready for occupation around March 1979. The main office building at Hyderabad has been completed and the departments have started functioning in the new premises. Construction is in progress in respect of the office buildings at Ahmedabad, Bhubaneshwar, Gauhati and Trivandrum. One more project at Jaipur has been taken up during the year. The plans of the Chandigarh office building have been finalised and construction is expected to commence shortly.

153. The College of Agricultural Banking, Pune is being expanded on a priority basis. The work was taken in hand in September 1977 and the buildings are expected to be ready for occupation by October, 1978.

Residential Quarters

154. Construction of 141 quarters for clerical and subordinate staff at Musheerabad, Hyderabad is almost complete and the colony will be ready for occupation shortly. With this, the total number of quarters provided by the Bank for its staff at various Centres stands at 4,832. In addition, construction of staff quarters at Bhubaneswar, Chandigarh, Jaipur, New Delhi and Trivandrum is in progress. The Bank has also deposited with the Delhi Development Authority the cost of 188 flats which are presently under construction at Hauz Khas, New Delhi. These flats are expected to be ready by December 1978.

Leased Premises for Office Use

155. For meeting the increased need of office space, additional office accommodation has been taken on lease at Ahmedabad, Chandigarh, Cochin and Lucknow.

Bankers Training College, Bombay (BTC)

156. In its programmes during the year the BTC continued its thrust on disciplines of foreign exchange and credit management and the special attention to areas of growing importance to banks such as Lending for Working Capital, Project Appraisal, Personnel Management and Industrial Relations. On the subject of foreign exchange alone, the College organised as many as 15 programmes—both orientation and advanced—including a foreign exchange 'course' introduced to enable officers in the foreign exchange departments of banks to acquire the skills of 'dealing' in foreign exchange through simulation exchange transaction taking place at the desks of traders'.

157. The other new programmes arranged by the College were : (a) Law for Bankers to assist operational bankers in tackling routine legal problems ; (b) a Seminar on Rehabilitation of Sick Industrial Units for commercial and development bankers handling loans to these ; (c) a Seminar on Foreign Trade to enable bankers to identify the different problems faced by them whilst financing exports and imports and to seek solutions ; and (d) Credit Supervision and Follow up for a nationalised bank.

158. Among the programmes continued to be conducted by the College were those on Development Banking, Performance Budgeting, Statistics for Bankers, and Organisation and Methods.

159. A note worthy feature was that out of the 68 programmes conducted during the year covering 29 different types of courses, as many as 22 were offered on an in-company basis tailored to suit the specific requirements for the sponsoring institutions. Six of these programmes were held at their own centres. The Industrial Relations in Banking programme was held in three other centres besides Bombay, and the Lending for Working Capital programme in both Bombay and Madras.

160. The BTC also continued to cater to the training requirements of the Bank's own officers and organised for their benefit the Central Banking and the Central Banking Advanced programmes, and programmes in Economic Theory and Quantitative Methods in Economic Analysis, and Credit Appraisal.

161. The BTC, in collaboration with the National Institute of Bank Management, conducted a Workshop on Course Designing for the faculty members of colleges for banks.

162. In the area of publications, the College has brought out a revised, enlarged and updated version of 'Guidelines for Internal Bank Inspection'.

163. During the year, 2,059 officers from the Reserve Bank, commercial banks, development finance institutions and government departments, as well as from foreign central and commercial banks received training, raising the total number of persons trained to 14,325 since the inception of the College in 1954.

College of Agricultural Banking, Pune (CAB)

164. During the year, the CAB further accelerated the pace of its activities and conducted as many as 59 programmes as against 42 held last year. The emphasis continued to be on Agricultural Projects Courses, instituted under the general line of credit sanctioned to the ARDC by the IDA/World Bank, and training programmes specially designed for the different levels of personnel of Regional Rural Banks.

165. Consequent on the introduction of the Agricultural Credit Intensive Development (ACID) Programmes in various selected districts, the CAB was called upon to arrange two special programmes, one in Shimoga for two district central co-operative banks and the other in Dhule for the officers of Dhule District Central Co-operative Bank, besides a course in Pune for the trainers of certain Co-operative Training Centres handling this subject.

166. Several new programmes were introduced during the year by the College, such as a programme on performance budgeting, a programme on financing of tree crops and an orientation programme for non-official members of the boards of the Goa State Co-operative Bank and of four urban co-operative banks in Goa. These programmes evoked considerable interest among the participants.

167. In the context of its new emerging role as a trainers' training institution, the CAB held two new programmes for trainers in agricultural finance in commercial and co-operative banks' colleges. This was a sequal to one of the decisions reached in a two-day Conference of the Principals of training colleges of commercial and co-operative banks convened by the CAB in June 1977, when several matters concerning training in agricultural finance and co-ordination of training programmes were discussed.

168. The CAB also continued to organise its regular programmes for managerial staff of the State and Central co-operative banks and the officers of the Reserve Bank itself, as also outstation programmes on wide-ranging subjects in response to specific requests received from various banks.

169. Since its inception in September 1969, the College has imparted training to 8,628 officers from different banks and other institutions, the number trained during the year being 1,672.

Staff College, Madras

170. Apart from conducting its series of regular programmes like Staff Officers' Development Programme, Inspecting Officers' Programme, Inter-Mobility Programme and Assistant Treasurers' Programme, the College arranged a number of Induction Programmes for newly appointed Officers in Grades 'A' and 'B' (Direct Recruits). The syllabus and duration of the Induction Programmes were carefully reviewed and the course was re-designed to enhance its utlity. The whole scheme of training for the directly recruited officers, covering institutional and departmental training spread over a period of two years, was critically evaluated in the light of feedback received from the officers as well as the trainee-officers of previous batches and thoroughly revised.

171. The College also continued to conduct crash programmes for the officers of public sector banks and programmes for the managerial staff of State, Central and primary (urban) co-operative banks, temporarily transferred from the CAB.

172. As in the previous year, there was participation from foreign central banks in the courses offered by the Staff College this year. Two officers from the Bank of Uganda and one from the Bank of Ghana attended an Inspecting Officers' Programme. Also, for the first time, officers from the Ministry of Finance, Government of India, were nominated to the Foreign Exchange Programmes.

173. The total number of employees who have received training at the College since its inception in 1963 stands at 6,533, the number trained during the year being 559.

Zonal Training Centres (ZTCs)

174. The ZTCs continued to hold Induction and Advanced courses for the clerical staff at Junior and Senior levels. Besides, preparatory training courses meant for candidates selected to appear at the qualifying written test for Staff Officers Grade 'A' were also organised. The ZTCs were also entrusted with the responsibility for properly and systematically monitoring the departmental training programme for trainee-officers in Grades 'A' and 'B' (DR).

175. The ZTCs have so far trained a total of 14,668 staff since their inception.

National Institute of Bank Management

176. The National Institute of Bank Management continued its activities in the area of training with special programmes, projects, workshops, conferences, etc. An extensive study of the performance budgeting system of the major public sector banks was conducted during the year. On similar lines, a review of the performance budgeting system of ten nationalised banks was also undertaken.

177. On behalf of the Asian Development Bank, the Institute completed an assignment of setting up an Agricultural Credit Training Institute for Agricultural Development Bank of Nepal.

178. In the area of recruitment testing, the number of projects handled was over 300 involving over 4,50,000 candidates. A special feature of this year was that as many as 9 Regional Rural Banks availed of the services of the Institute for recruitment of branch managers, field officers, field assistants, clerks/assistants.

Deputation of Staff

179. The Bank continued to depute its officers to short-term courses on management development organised by the All-India and State level Associations, Management Institutes and similar bodies. Besides, the Bank also availed itself of the training programmes offered by the Economic Development Institute of IBRD, the IMF Institute and the Bank of England by deputing its officers to participate in them. Opportunity was also taken to depute officers for study visits to banking and financial institutions in West Germany, the U.S.A., the U.K., Italy, Switzerland, Netherlands and France. The Bank also, continued to extend training and study facilities to the nominees of foreign central and commercial banks. Particular mention may be made of a batch of five trainees deputed by Da Afghanistan Bank for training under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme of the Government of India. Besides, there were trainees from Nepal, Bangladesh, Malaysia, Philippines, Thailand, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.

Housing Loan Scheme

180. The total amount of society and individual loans sanctioned since the introduction of the Scheme in 1961 amounts to Rs. 6,91,74,689.00 and Rs. 5,34,69,649.00 respectively. In all 4,387 employees have availed of this facility.

181. During the period July 1, 1977 to June 30, 1978 Housing Loans were sanctioned as under :—

Co-operative Housing Societies	No. of societies	Amount Rs.
(A) New Co-operative Societies	2	8,45,736.00
Additional loans to Co-operative Housing Societies already formed	5	2,76,792.00
		11,22,528.00
Individual members of staff	No. of employees	Amount Rs.
(B) New loans	174	53,95,572.00
Additional loans to employees who had already availed of loans earlier	53	10,21,520.00
		64,17,092.00

Employer-Employee Relations

182. The two recognised All India Associations viz., All India Reserve Bank Employees Association and All India Reserve Bank Workers' Federation, representing workmen-employees in Classes II, III and IV launched a country-wide agitation from the end of July 1977 onwards, to press for commencement of negotiations on their Charter of Demands. The agitational programme was observed intermittently till the end of 1977 when it was suspended at the intervention of the Chief Labour Commissioner (Central). The Chief Labour Commissioner (Central) initiated conciliation proceedings on January 13, 1978 between the representatives of the Bank and those of the All India Reserve Bank Employees Association and the All India Reserve Bank Workers' Federation. Similar conciliation meetings have been initiated by the Chief Labour Commissioner between the Bank and All India Reserve Bank Workers Organisation also. The process of discussions|negotiations with these organisations continues.

183. Conciliation conferences also continued to be held with the representatives of the Associations of the Officer, Staff Officers and Workmen staff at All India level|local levels. A meeting was held with the Governor by the Staff Officers' Association on April 17, 1978. The Officers' Association held meetings with the Bank|Governor on November 7, 1977 and February 3, 1978.

House Magazine

184. The Bank's house magazine, 'Without Reserve, was awarded the first prize in the 19th National Awards in the category of house magazines for excellence in printing and designing by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

Press Relations

185. The Press Relations Section continued to co-ordinate the publicity and press relations work of different departments of the Bank and its associate institutions viz., ARDC and DICGC. Apart from regular fortnightly RBI. News letter brought out in English and Hindi, the Section published during the year an informative pictorial brochure highlighting the progress made by commercial banks in extending financial assistance to agriculture and allied activities. It also brought out a folder-leaflet explaining in simple language the needs for insurance of Banks deposit. The folder leaflet on the exchange control formalities to be observed by foreign visitors to India, brought out last year was published in German, French, Spanish and Arabic. With the assistance and co-operation of the Press Relations Section, the Agricultural Refinance and Development Corporation, published two pamphlets on the formulation of schemes for poultry farming and dairy development. Revised editions of the brochures on Facilities for Non-residents of Indian Nationality or Origin for Remittance of Funds to India and Exchange Control Regulations as Applicable to Indians Abroad were also published during the year.

Promotion of Hindi

186. During the year, the Bank took various measures for implementing the provisions of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 in the internal work of the Bank in a phased manner. The more significant of these measures are (i) as indicated in the last Report, Hindi Cells would be set up shortly in the Bank's offices in Regions A and B. Hindi Officers for such Cells and Central Office Hindi Division have already been selected and are being posted; (ii) the staff in the Bank's offices in Region A are now allowed to use Hindi for sectional notings and drafts on cases which go upto the level of Staff Officers in Grades A and B provided the concerned officers are conversant with Hindi ; (iii) in order to impart training in noting, drafting etc. in Hindi, Hindi workshops were conducted for a duration of two days in the Kanpur and New Delhi offices for the benefit of selected officers and clerks. The response to these workshops was very encouraging. It is also proposed to conduct more such workshops in our offices in Regions A and B. Workshop material was prepared for guidance.

187. The following steps were taken for the progressive use of Hindi in the Bank : (i) The offices in Region B have been advised to issue bilingually all circulars, office orders, etc. relating to staff in Classes III and IV. Offices in Region A and the Department of Administration and Personnel (D.A. & P.), the Department of Accounts and Expenditure (D.A. & E.) and the Premises Department in the Central Office have already been issuing such circulars etc. in bilingual form. Offices in Region A have already been requested to consider issuing circulars and office orders intended for all categories of staff bilingually to the extent possible as was indicated in the last years Report. (ii) Circulars meant for credit institutions specified for the purpose of Credit Guarantee Scheme for small scale industries are now being issued by the Industrial Finance Department in bilingual form. The circulars to all banks and those to the State Governments, Registrars for Co-operative Societies, etc. are already being issued bilingually by the Department of Banking Operations and Development (DBOD) and the Agricultural Credit Department (ACD) respectively. (iii) A decision has been taken to register the telegraphic addresses of all the offices, etc. in Regions A and B in Hindi in addition to English. Necessary action is being taken in this regard.

188. The documents, such as press communiques|notes|summaries, notifications, notices, licences, etc. enumerated in Section 3 of the Official Languages Act, 1963 were continued to be issued bilingually. All Bank's offices, departments, etc. continue to reply to letters received in Hindi in the same language. The offices in Region A started using Hindi selectively for their originating correspondence with Regions A and B.

189. The Official Languages Implementation (OLI) Committee of the Bank held three meetings during the year and took various decisions for furthering the use of Hindi in the Bank and its associate institutions after reviewing the progress made therein. The Local O.L.I. Committees continued to function in the Bank's New Delhi, Kanpur, Jaipur and Patna offices and held meetings periodically to review the progress made in implementing the instructions issued by the Bank regarding use of Hindi.

190 The Bank continued to bring out the Hindi version of its Annual Report and those of the associate institutions. The Report on Currency and Finance, 1975-76 and 1976-77 were also brought out in Hindi during this year. The 'RBI Monthly Bulletin' and the quarterly house journal 'Without Reserve' continued to be brought out with Hindi Section. Fortnightly 'RBI Newsletter' was being published regularly in Hindi also. 'Co-operative News Digest' being published by the ACD carried Hindi Sections in the July and December 1977 issues. During the year, an Administrative Glossary (English Hindi) of phrases and expressions commonly used in office notings, correspondence, etc. was brought out and copies distributed to all the staff The English Hindi, glossary of banking terms was completed during the year and is to be printed.

191. Hindi classes continued to be conducted under both voluntary and compulsory Hindi Teaching Schemes for the Bank's staff. The voluntary scheme was, however merged with the compulsory scheme in Regions A and B. The employees were also encouraged to avail of the Hindi correspondence courses conducted by the Ministry of Education A scheme of compulsory in-service training in Hindi type

writing/stenography for making out typists stenographers and personal assistants proficient therein was put into operation in our offices in Regions A and B during this year The scheme of payment of honorarium to our staff for passing the recognised Hindi examinations|Hindi typewriting|Hindi short hand examination was continued A decision was also taken to include Hindi as a subject in the courses for Clerks Grades I and II conducted at the Zonal Training Centres functioning at New Delhi and Byculla (Bombay) This has been made effective from May|June 1978

192 It has also been decided that the direct recruit officers in Grades A' and 'B' should pass the Pragya examination of the Government of India or any equivalent Hindi examination within a period of 5 years from the date of their joining the Bank unless they have already passed Matriculation or it equivalent examination with Hindi as a subject or a Hindi examination recognised as equivalent to the Hindi standard at Matriculation examination In the even of their failure to pass the above examination within the prescribed period their increments would be withheld until such time as they pass the examination

Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Bank's Service

193 Special measures, such as relaxations in the basic eligibility standards and qualifying norms wider publicity of reserved posts in the Bank's service, special recruitment confined to Scheduled Castes or Tribes etc, detailed in the earlier reports were continued during this year also It was also decided during the year under report to arrange for the announcement of reserved vacancies for Scheduled Castes and Tribes from various stations of All India Radio so that prospective applicants from Scheduled Castes and Tribes living in remote areas, where newspapers may not be easily available, may become aware of such vacanies The representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the Bank have, as a result, registered a further increase Compared to the position as on January 1, 1977, the representation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees has increased from 1,292 in Class IV, 1995 in Class III and 85 in Classes II and I to 1 466 2,174 and 100 respectively as on January 1, 1978

194 The backlog in the recruitment of Scheduled Tribes in various Class III cadres, however, still remains to be cleared This has been because Scheduled Tribes candidates have not been responding to the advertisements issued by some of the regional offices of the Bank in adequate numbers An all India advertisement for about 200 and 25 reserved vacancies for Scheduled Tribes in the cadres of Clerks Gr II/Coin Note Examiners Gr II and Typists respectively was issued and the response to this advertisement has been found to be encouraging It is hoped that once the all India list is ready for the above 2 cadres, it would be possible to clear the accumulated backlog at the regional offices where such backlog exists

195 The policy of recruiting additional candidates belonging to Scheduled Castes and Tribes as Staff Officers Gr 'A' over and above the prescribed quota, referred to in earlier reports, was continued during the year under review Besides, the educational standard prescribed for the posts of Staff Officers Gr A' and 'B' (DR) has been relaxed in favour of Scheduled Castes and Tribes to mere graduation as against second class graduation prescribed in favour of general candidates

196 The Scheme of reservation in favour of Scheduled Castes and Tribes in vacancies filled by promotion was reviewed during the year and it has been decided that promotion to the cadre of Staff Officers in Gr 'A', which was hitherto treated as one based on selection, should be treated as one based on seniority subject to suitability

197 In the allotment of staff quarters also, the prescribed rate of reservation of 10 per cent in favour of Scheduled Castes and Tribes has been fully met during the year

198 During the year under report, the Liaison Officer for Scheduled Castes and Tribes in the Bank inspected the rosters etc. maintained in the Bank's offices at Patna Gauhati, Bangalore, Byculla Nagpur and Ahmedabad

Accounts

199 During the accounting year ended June 30, 1978 the Bank's income, after making adjustments for various provisions, amounted to Rs 661 81 crores as compared with last year's income of Rs 587 26 crores The details of the income from various sources are as follows

(Amount in rupees crores)

	Year	
	1977-78	1976-77
(i) Interest on Ways and Means Advances to State Governments	27 79	15 5
(ii) Interst on Loans and Advances to State Governments (Other than on Ways & Means Advances referredt o at item (i) above) and Commercial and Co-operative Banks	101 42	126 75
(iii) Interest on Rupee Securities and Discount on Rupee Treasury Bills	275 56	263 46
(iv) Interest and Discount on Foreign Securities, Investments and Tresury Bills	313 53	190 94
(v) Commission and Profit and gain by exchange	1 49	6 51
(vi) Other income	8 65	10 01
	728 44	613 18
Less Interest paid to the Scheduled Banks on the additional average daily balance maintained by them with the Reserve Bank	66 63	25 92
	661 81	587 26
Less Transfers to Funds as stated in paragraph 2 below	345 00	290 00
	316 61	297 26

200 The contributions to the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund were Rs 115 crores, Rs 30 crores and Rs 200 crores during the year 1977-78 as against Rs 95 crores, Rs 20 crores and Rs 175 crores respectively during the year 1976-77.

201 Out of the balance of income amounting to Rs 316 81 crores after allowing for the total expenditure of Rs 116 81 crores during the year (as against the balance of income amounting to Rs 297 26 crores and expenditure of Rs 97 26 crores in the previous year) the surplus of profit set aside for payment to the Central Government was Rs 200 crores (same as last year)

202 The rise of Rs 74 55 crores in the total income from the level of Rs 587 26 crores last year to Rs 661 81 crores was largely due to:

(i) higher interest earned on the increased foreign exchange reserves during the year, and

(ii) higher discount earned on Rupee Treasury Bills partly set off by increased payment of interest to the scheduled banks on the additional cash reserves required to be maintained by them with the Bank

203 The rise of Rs 19 55 crores in the expenditure was mainly due to the increased establishment cost and the expenditure on printing cheque/draft forms etc

Auditors

204 The accounts of the Bank have been audited by M/s K S Aiyar & Co, Bombay, M/s K N Gutgutia and Co, Calcutta, M/s Raghu Nath Rai & Co, New Delhi and M/s Sundaram and Srinivasan, Madras who were re-appointed by the Government of India as Auditors vide their letter No 1(2)/Accts dated May 9, 1978 issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) In addition to Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi Offices, books of accounts of Nagpur and Lucknow branches have been audited by the Bank's statutory auditors this year The remuneration of the auditors has been fixed at Rs 15,000 each for Central Office, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras and Nagpur and Rs 10,000 for Lucknow branch

RESERVE BANK

LIABILITIES

	Rs. P.	Rs. P.
Notes held in the Banking Department	12,81,13,106.00	
Notes in circulation	9347,69,88,617.50	
Total Notes issued		9360,51,01,723.50
Total Liabilities		**9360,51,01,723 50**
Capital Paid-up		5,00,00,000.00
Reserve Fund		150,00,00,000.00
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund		610,00,00,000 00
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund		195,00,00,000.00
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund		915,00,00,000.00
Deposits :—		
(*a*) Government		
(*i*) Central Government		377,00,03,649.09
(*ii*) State Governments		18,17,96,325.01
(*b*) Banks		
(*i*) Scheduled Commercial Banks		2137,76,92,605.39
(*ii*) Scheduled State Co-operative Banks		70,27,84,425.86
(*iii*) Non-Scheduled State Co-operative Baks		2,40,36,994.63
(*iv*) Other Banks		3,19,73,719.36
(*c*) Others		2016,75,46,926.29
Bills Payable		167,24,66,578.15
Other Liabilities‡		625,14,20,026.04
Total Liabilities		7292,97,21,249.82

Contingent Liability :
On partly paid shares Rs. 7,67,495.05 per equivalent of £ 50,000.

M.V. HATE, Chief Accountant

I. G. PATEL, Governor
K. S. KRISHNASWAMY, Deputy Governor
P. R. NANGIA, Deputy Governor
M. RAMAKRISHNAYYA, Deputy Governor

Dated the 28th July, 1978.

OF INDIA

AS AT 30TH JUNE 1978

DEPARTMENT

ASSETS

	Rs. P.	Rs. P.
Gold Coin and Bullion :—		
(*a*) Held in India	214,21,78,319.03	
(*b*) Held outside India	.. ..	
Foreign Securities	2145,32,65,142.40	
Total		2359,54,43,461.43
Rupee Coin		20,76,54,536.25
Government of India Rupee Securities		6980,20,03,725.82
Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper		.. ..
Total Assets		**9360,51,01,723.50**
Notes		12,81,13,106.00
Rupee Coin		2,55,968.00
Small Coin		3,39,976.06
Bills Purchased and Discounted :—		
(*a*) Internal		101,32,10,871.53
(*b*) External		.. ..
(*c*) Government Treasury Bills		1138,94,67,266.11
Balances Held Abroad*		1687,54,55,324.86
Investments**		1092,51,85,845.67
Loans and Advances to:—		
(*i*) Central Government		.. ..
(*ii*) State Governments@		14,59,00,000.00
Loans and Advances to :—		
(*i*) Scheduled Commercial Banks†		334,71,18,525.02
(*ii*) State Co-operative Banks‡‡		321,13,25,100.00
(*iii*) Others		3,78,25,000.00
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund		
(*a*) Loans and Advances to :—		
(*i*) State Governments		110,78,59,592.00
(*ii*) State Co-operative Banks		19,10,92,529.33
(*iii*) Central Land Mortgage Banks		.. ..
(*iv*) Agricultural Refinance and Development Corporation		216,80,00,000.00
(*b*) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures		7,86,77,345.00
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund		
Loans and Advances to State-Coperative Banks.		138,47,68,085.00
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-term Operations') Fund		
(a) Loans and Advances to the Development Bank		688,45,34,579.00
(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank		..
Other Assets£		1404,05,92,136.24
Total Assets		7092,97,21,249.82

‡Includes Contingency Account

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** (i) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.

(ii) Includes Rs. 685,60,82,902.22 held abroad in foreign currencies.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund.

† Includes Rs. 2,76,00,000.00 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

†† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Cerdit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

£ Includes Rs. 1121,47,05,750.00 advanced to or deposited with Scheduled commercial banks under speical arrangements.

RESERVE BANK OF INDIA

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1978

INCOME	Rs. P.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc	316,80,54,544.74
	316,80,54,544.74

EXPENDITURE	
Establishment	39,57,83,437.85
Director's and Local Board Members' Fees and Expenses	84,095.74
Auditors' Fees	1,00,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc	2,03,30,413.15
Law Charges	1,86,133.88
Postage and Telegraph Charges	23,13,773.87
Remittance of Treasure	6,49,88,074.88
Stationery, etc.	60,71,170 50
Security Printing (Cheques, Note Forms, etc)	21,59,23,912 04
Depreciation and Repairs to Bank Property	1,51,33,435.77
Agency Charges	42,01,56,195.18
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds	55,00,000.00
Miscellaneous Expenses	2,14,83,076.05
Net available balance	200,00,00,825.83
	316,80,54,544.74

Surplus Payable to the Central Government	200,00,00,825.83

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balance on 30th June 1978	150,00,00,000.00
By transfer from Profit and Loss Account	Nil
Total	150,00,00,000.00

*After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

M. V. HATE	I. G. PATEL	Governor
Chief Accountant	K. S. KRISHNASWAMY	Deputy Governor
	P. R. NANGIA	Deputy Governor
Dated the 28th July, 1978.	M. RAMAKRISHNAYYA	Deputy Governor

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June 1978.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and of the Offices at Calcutta, Bombay (Fort), Madras, New Delhi, Nagpur and Lucknow and with the returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and Branches, which returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information from the Central Board, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed there under and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank.

Messrs K. S. AIYAR & CO.
Messrs K. N. GUTGUTIA & CO.
Messrs RAGHU NATH RAI & CO.
Messrs SUNDARAM & SRINIVASAN
} Auditors.

Dated the 17th August, 1978.

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET

Particulars	For the year ended June, 30, 1976				For the year ended June 30, 1977			
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
ISSUE DEPARTMENT								
LIABILITIES								
Notes held in the Banking Department	24,67,21,372.00				14,67,40,673.00			
Notes in circulation	7150,33,90,123.50				8200,46,11,647.50			
Total notes issued			7175,01,11,495.50				8215,13,52,320.50	
Total Liabilities			7175,01,11,495.50				8215,13,52,320.50	
ASSETS								
Gold Coin and Bullion								
(a) Held in India	182,52,50,617 44				187,80,46,227.22			
(b) Held outside India	..				..			
Foreign Securities	546,73,97,234.21				1071,73,97,234.21			
Rupee Coin	15,30,04,388.73				15,42,90,909.60			
Government of India Rupee Securities	6430,44,59,255.12				6940,16,17,949.47			
Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper	..				..			
Total Assets			7175,01,11,495.50				8215,13,52,320.50	
BANKING DEPARTMENT								
LIABILITIES								
Capital Paid-up	5,00,00,000.00				5,00,00,000 00			
Reserve-Fund	150,00,00,000.00				150,00,00,000.00			
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	400,00,00,000.00				495,00,00,000.00			
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	145,00,00,000.00				165,00,00,000 00			
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	540,00,00,000 00				715,00,00,000.00			
Deposits								
(a) Government								
(i) Central	63,12,38,550.20				74,43,96,368.04			
(ii) State	138,78,48,015.79				87,45,19,350.11			
(b) Banks								
(i) Scheduled Commercial Banks	758,54,09,484.28				1588,86,21,279 82			
(ii) Scheduled State Co-op. Banks	60,98,94,643.18				41,16,10,904 10			
(iii) Non-Scheduled State Co-op. Banks	1,69,82,005.95				1,91,28,419.89			
(iv) Other Banks	4,18,42,239.38				2,78,08,547.38			
(c) Others	2130,62,82,282 95				2461,43,38,829 71			
Bills Payable	79,91,90,407.09				157,67,77,542.38			
Other Liabilities	549,59,08,322.22(a)				587,41,16,192.89(a)			
Total Liabilities			5027,45,95,951 04				6533,13,17,434.32	

(a) Includes Contingency Accounts.

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET (Concld.)

Particulars	For the year ended June 30, 1976 Rs. P.	Rs. P.	For the year ended June 30, 1977 Rs. P.	Rs. P.
ASSETS				
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund :				
(a) Loans and Advances to the Development Banks	388,17,55,619.00		526,20,50,534.00	
(b) Investment in Bonds/Debentures issued by the development Banks	..		..	
Other Assets	827 30 98,779.02(k)		1086,72,86,056.00(l)	
Total Assets		5027,45,95,951.04		6533,13,17,434.32

NOTE : June 30, 1976—Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,00,000 00 (Sterling investment of £50,000 converted @ Rs. 100=£6.2500)

June 30, 1977—Contingent liability :

(i) on partly paid shares Rs. 7,60,005.47 equivalent of £ 50,000

(ii) on partly paid stock Rs. 4,33,20,311.91 equivalent of £ 2,850,000

(b) Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

(c) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.

(d) Includes Rs. 8,37,91,214.71 (equivalent of £ 50,000, US $ 9,002,500.00 and DM 6,60,000.00) held abroad.

(e) Includes Rs. 3,29,33,68,067.03 held abroad in foreign currencies.

(f) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund, but including Temporary Overdrafts to State Governments.

(g) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund.

(h) Includes Rs. 10,30,00,000.00 advanced to Scheduled Commercial Banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

(i) Includes Rs. 8,76,00,000.00 advanced to Scheduled Commercial Banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

(j) Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

(k) Includes an amount of Rs. 478,12,00,000.00 advanced to Certain Scheduled Commercial Banks under special arrangements.

(l) Includes an amount of Rs. 832,32,79,500.00 advanced or deposited with Scheduled Commercial Banks under special arrangements.

ASSETS				
Notes	24,67,21,372.00		14,67,40,673.00	
Rupee Coin	4,01,936.00		3,17,577.00	
Small Coin	2,41,964.15		3,72,688.83	
Bills Purchased and Discounted				
(a) Internal	138,07,60,341.67		111,99,55,457.60	
(b) External	..		..	
Government Treasury Bills	275,57,89,222.34		265,31,98,249.23	
Balances held abroad (b)	1196,05,88,818.82		2180,87,88,502.19	
Investments	565,41,66,698.86(cd)		651,09,92,431.93(ce)	
Loans and Advances to :				
(i) Central Government	..		..	
(ii) State Governments	130,06,06,000.00(f)		72,23,00,000.00(g)	
(iii) Scheduled Commercial Banks	941,98,48,796.30(h)		962,18,07,161.46(i)	
(iv) State Cooperative Banks (j)	156,18,63,494.00		247,74,27,833.00	
(v) Others	68,61,55,000.00		1,82,00,000.00	
Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund				
(a) Loans and Advances to :				
(i) State Governments	75,70,25,217.55		98,33,76,218.75	
(ii) State Co-operative Banks	12,59,04,003.33		15,80,45,212.33	
(iii) Central Land Mortgage Banks	..		..	
(iv) Agricultural Refinance and Development Corporation	138,40,00,000.00		172,60,00,000.00	
(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,82,07,720.00		8,45,82,445.00	
Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund to State Co-operative Banks	78,74,60,968.00		116,98,76,394.00	

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1976 AND 1977

	1976	1977
	Rs. P.	Rs. P.
INCOME		
Interest, Discount, Exchange, Commission etc.	294,99,72,239.32£	297,26,15,033.13$
	294,99,72,239.32	297,26,15,033.13
EXPENDITURE		
Establishment	35,49,37,921.61	35,51,16,731.43
Directors' and Local Board Members' Fees & Expenses	81,484.98	78,764.35
Auditors' Fees	80,000.00	80,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.,	1,58,81,750.46	1,77,77,553.30
Law Charges	1,03,769.71	1,67,701.32
Postage and Telegraph Charges	19,48,335.00	24,25,466.26
Remittance of Treasure	46,78,237.46@	75,63,473.14
Stationery, etc.	54,31,080.33	46,79,950.56
Security Printing (cheque, Note Forms, etc.)	14,38,45,495.76	19,37,48,200.38
Depreciation and Repairs to Bank Property	1,31,96,766.72	1,32,85,511.02
Agency Charges	43,01,12,622.71*	35,50,33,446.77
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds	7,08,15,842.51**	50,00,000.00
Miscellaneous Expenses	1,82,15,270.04	1,76,57,337.40
Net Available Balance	190,00,00,136.95	200,00,00,897.20
TOTAL	294,99,72,239.32	297,26,15,033.13

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1976 AND 1977 (Contd.)

	1976	1977
	Rs. P.	Rs. P.
EXPENDITURE		
Surplus Payable to the Central Government	190,00,00,136.95	200,00,00,897.20
RESERVE FUND ACCOUNT		
By Balance on 30th June	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00
By Transfer from Profit and Loss Account	Nil	Nil
TOTAL	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00

£After making usual or necessary provisions in terms of Section 47, of the Reserve Bank of India Act and transfer of Rs. 221 crores to funds under Sections 46A, 46B and 46C.

@After adjusting recovery of Rs. 1,07,58,076.26 against Payments made in previous years.

*Includes Rs. 11,59,68,700.00 relating to earlier years.

**Includes Rs. 6,42,15,842.51 appropriated on account of accrued gratuity liability for past years.

$After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

[No. F. 10/6/78-BOI]

J.C. ROY, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979